Wednesday, May 5, 1976

LOK SABHA DEBATES

(Fifth Series)

Vol. LXI

[May 3 to 17, 1976/Vaisakha 13 to 27, 1898 (Saka)]

Sixteenth Session, 1976/1898 (Saka)

(Vol. LXI Contains Nos. 31—40)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

No. 33, Wednesday, May 5, 1976/Vaisakha 15, 1898 (Saka)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions :	
*Starred Questions Nos. 669 to 674, 676, 677 and 679 to 681	1—32
Written Answers to Questions :	
Starred Questions Nos. 668, 675, 678 and 682 to 688 . .	32-39
Unstarred Questions Nos. 3306 to 3348 and 3350 to 3390 .	39—111
Papers laid on the Table	111—13
Election to Committee—	
Coir Board	113-14
Demands for Grants, 1976-77—	
Ministry of Agriculture & Irrigation—	
Shri Sakti Kumar Sarkar	114—18
Shri Chandrika Prasad	118—24
Shri Shiv Shanker Prasad Yadav	124—29
Shri Shanker Dayal Singh	129—36
Shri P. Venkatasubbaiah	136—41
Shri S. P. Bhattacharyya	141-46
Shri Shyam Sunder Mohapatra	146—50
Shri Narsingh Narain Pandey	150—58
Shri Ranabahadur Singh	158—63
Shri Krishnarao Patil	163—66
Shri Jagdish Narain Mandal	166—69
Shri P. Narasimha Reddy	169—73
Shri Bhagat Ram Manhar	173—78
Shri K. Pradhani	178—82
Shri Md. Jamilurrahman	182—99
Shri Annasaheb P. Shinde	199—219

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	Columns
Shri C. D. Gautam	220—24
Shri Biramali Patnaik	224—28
Shri Raghunandan Lal Bhatia	228—32
Shri Dalip Singh	232—36
Prof. S. L. Saksena	236—42
Shri N. P. Yadav	242—47
Shri D. K. Panda	247—51
Shri Jagannath Mishra	251—54
Shri M. S. Sanjeevi Rao	255—57
Shri Ram Bhagat Paswan	257—61
Shri S. N. Singh Deo	261—62
Shri R. N. Barman	262—66
Shri D. P. Jadeja	266—69
Shri Tayyab Hussain	269—81
Shri Swami Brahmanandji	281—83
Shri B. R. Shukla	283—86
Shri Biswanarayan Shastri	287—90
Shri Jagjivan Ram	290
Business Advisory Committee—	
Sixty-first Report	286

LOK SABHA

Wednesday, May 5, 1976/Vaisakha 15, 1898 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

*669. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 में देश के किन-किन नगरों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ देहाती क्षेत्र भी आएंगे, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दूरदर्शन ट्रांसमिटिंग केन्द्र मार्च, 1977 तक जयपुर, हैदराबाद, रायपुर और कटक में तथा जून, 1977 तक मुजफ्फरपुर, गुलबर्गा और सम्बलपुर में स्थापित हो जाने की सम्भावना है। कुछ ही महीनों में मसूरी में भी एक रिले केन्द्र चालू करने का प्रस्ताव है जो बिजली की पर्याप्त सप्लाई की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) : 'नासा' उपग्रह वापस ले लिए जाने के बाद 'साइट' क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए जो 6 स्थलीय ट्रांसमिटर स्थापित करने का प्रस्ताव है, उन से 'साइट' के अन्तर्गत आने वाले लगभग 40 प्रतिशत गांवों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होगी। इन ट्रांसमिटरों में से प्रत्येक की रेंज 40–70 किलोमीटर होगी, जो भू-भागों, आदि पर निर्भर होगी। इस प्रकार इन ट्रांसमिटरों से इनकी रेंज में आने वाले 'साइट' के गांवों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में अन्य गांवों में भी दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होगी।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष जी, जो मैंने प्रश्न पूछा था, उसका आंशिक उत्तर तो मुझे अवश्य मिला है लेकिन आश्चर्य यह है कि मेरे पहले प्रश्नों के उत्तर में कई बार यह कहा गया है कि पटना में 1976 में दूरदर्शन सेवा प्रारम्भ हो जायेगी, और बाद में यह कहा गया कि 1977 में यह सेवा प्रारम्भ हो जायेगी। मंत्री महोदय ने आज जो उत्तर दिया है, उस में जयपुर, हैदराबाद रायपुर और कटक का नाम तो उपलब्ध है लेकिन पटना का नाम उस में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुजफ्फरपुर का नाम उस में है।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष जी, मुजफ्फरपुर और पटना में फर्क है। सरकार से इस सम्बन्ध में दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह है कि जैसा पहले प्रश्नों के उत्तर में कहा गया था कि 1977 से पटना में भी टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत हो जायेगी और केन्द्र की स्थापना की जायेगी, उस सम्बन्ध में क्या प्रगति है ?

दूसरे यह कि देहाती क्षेत्रों में भी लोग अधिक-से-अधिक ये कार्यक्रम देखें, क्योंकि इससे बढ़कर शिक्षा का और कोई माध्यम नहीं हो सकता है, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी कि इसका लाभ 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों को प्राप्त हो और 50 प्रतिशत लाभ देहाती क्षेत्रों को प्राप्त हो ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, यह जो कार्यक्रम "सेटेलाइट" के अन्तर्गत बनाया गया है, यह पूर्ण रूप से देहाती क्षेत्रों के लिए ही बनाया गया है, शहरी क्षेत्रों से इसका कोई विशेष मतलब नहीं है । इसलिए मुजफ्फरपुर में 'सेटेलाइट' के ट्रांसमिटर लगाने की जो योजना बनाई जा रही है, वह इसलिए की जा रही है कि पटना के बजाय यदि मुजफ्फरपुर में लगाया जाये तो वहां से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र कवर होंगे और पटना में लगाने से उतने ग्रामीण क्षेत्र कवर नहीं होंगे । इसलिए मुजफ्फरपुर मे लगाने का प्रस्ताव है ।

श्री शंकर दयाल सिंह : इस बार सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जो रिपोर्ट 1975–76 की आई है, उसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि—दूरदर्शन केन्द्रों ने अपने नियमित कार्यक्रमों और उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों दोनो में आर्थिक विकास के लिये संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया ।

मैं सरकार से जानना चाहता हू कि देश में 5 लाख से अधिक गांवो में से केवल 2400 गांव ऐसे हैं जहां उपग्रह दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है और वहीं पर हमारे कार्यक्रम पहुंच सकते हैं । 1976–77 में जो योजना देहाती क्षेत्रों के लिये बना रहे हैं, उस से कितने अधिक गांव लाभान्वित होंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने अपने मूल उत्तर में इसकी ओर इंगित किया था कि हम जो जमीन से ट्रांसमिशन करेंगे टैरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन, आज के जो उपग्रह के लाभान्वित गांव हैं, उस में केवल 40 प्रतिशत गांव को इस साल इस से लाभ पहुंचेगा, बाकी 60 प्रतिशत गांवों तक लाभ नहीं पहुंच पायेगा । इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे गांव हैं, करीब 8,000 गांव जहां आजकल उपग्रह दूरदर्शन की सेवा नहीं पहुंचती है, उनमें यह सेवा पहुंचने लगेगी । इसमें बड़ा सवाल यह है कि जिन गांवों में पहले उपग्रह दूर-दर्शन की सेवा नहीं पहुंचती थी, अब ग्राउंड स्टेशन के द्वारा टेलिविजन का प्रोग्राम शुरू होगा, तो उन में टेलीविजन सेट लगाने होंगे । जब तक हर गांव में कम्युनिटी व्यूइंग सैट नहीं लगाये जायेंगे, तब तक इस सेवा का कोई महत्व या फायदा नहीं होगा । इसलिये हम आज इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि दूरदर्शन सेवा के अन्तर्गत आने वाले 40 प्रतिशत गांवों के अतिरिक्त जो गांव हैं उनके लिये इस टैरेसट्रियल ट्रांसमिटर्स के अन्तर्गत हम कम्युनिटी व्यूइंग सैटों का इंतजाम करें ताकि वहां के रेंज में जो गांव आते हैं, वहां ट्रांसमिटर बेकार न हो जायें और वहां यह सेवा उपलब्ध हो सके और गांव वाले लाभ उठा सकें ।

SHRI K. LAKKAPPA: So far as some States are concerned, they are not getting any benefit out of the expansion of T.V. activities. An ideal base is Bangalore therefore. I would like to know whether the Ministry will consider locating a T.V. centre in Bangalore for the benefit of the city as also for the benefit of the rural areas.

MR. SPEAKER: It is a suggestion?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: It is really a suggestion, but I may inform the Hon. Member that a transmitter is being put up at Gulbarga, which is an area which was selected originally for the SITE programme, and this will be transmitting programmes to Bangalore also.

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार

ने यह तय किया है कि मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन ट्रांसमिटिंग केन्द्र स्थापित किया जायेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह जो केन्द्र स्थापित किया जायेगा, इसकी शक्ति क्या होगी और क्या यह मुजफ्फरपुर का केन्द्र चम्पारन और छपरा के गांव के लोगों को भी प्रभावित करेगा या नहीं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुजफ्फरपुर में जो ट्रांसमिटर लग रहा है, उसकी शक्ति 1 किलोवाट होगी और हैदराबाद व जयपुर में जो लग रहे हैं उनकी शक्ति 10 किलोवाट की होगी, जैसी कि दिल्ली की शक्ति है। माननीय सदस्य ने जिन जगहों के नाम लिये हैं छपरा वगैरा के, मुझे मालूम नहीं है कि यह ट्रांसमिशन वहां पहुंचेगा या नहीं। मैंने मूल उत्तर में कहा था कि 50 से 70 किलो मीटर तक यह ट्रांसमिशन जा सकता है। अगर ये स्थान मुजफ्फरपुर से इस दूरी में आ जायेंगे तो यह वहां पहुंच जायेगा।

SHRI JAGANATH RAO: At present under SITE only a few villages in the rural area are covered. May I know how many more villages will be covered and within what radius? In Orissa we have got a Coexial between Calcutt and Madras. Can that Co-axial be utilised, so that more villages adjoining the Co-axial could also be benefited by this?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I have indicated that, out of 2,400 original SITE villages, 40 per cent would be covered in this programme which will start, after some break, from ground transmitter. But, in addition to the 40 per cent of villages, there would be about 8,000 additional villages that would be covered. Therefore, the total coverage of villages by ground transmission would come to about 10,000, instead of 2,400 that are there at present. Here, we will use all possible means to expand this transmission area provided we are able to locate sufficient number of community sets. As I said it will not be useful at all to have the transmitter spread all over without any means of looking at the transmission.

Indo-Nepal Joint Committee for Pancheshwar Hydel Project

*670. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether New Delhi and Kathmandu have agreed to set up a joint committee of experts for investigation of the 950-MW Pancheshwar hydel project on the Mahakali river which marks the border of Western Nepal with India; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C PANT): (a) and (b). Nepal and India have agreed to set up a joint six-Member Expert Group for the purpose of directing the investigations on the Pancheshwar Project.

SHRI N. E. HORO: Part (b) of my question has not been answered fully. I would like to know how much money we are expected to invest in this project, how much area in our country will be covered by this project and, roughly, what percentage of benefit are we going to receive after this project is completed.

SHRI K. C. PANT: The exact area that will be covered or submerged by the project and the other details how much power will be generated and so on and so forth, have to be decided. There has been a preliminary investigation carried out by the U.P. Government since the Sixties, but no project report is there. Only recently, during the Foreign Minister's visit to Nepal, there was an agreement with the Nepal Government that we might investigate the project further. Now during the recent visit of officials, with Secretary (Power) as Chairman—this was in March 1976—it was decided to set up a six-member expert group, of which I spoke. This six-membera expert group will go into the work already done, will review that and then will proceed further with investigation of the site and preparing a project report. It is too premature to give any definite outline.

Setting up of Atomic Power Plants by Indian technicians and in collaboration with foreign countries

*671. SHRI SHANKERRAO SAVANT: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) which atomic power plants are being set up by Indian technicians only and which are being set up in collaboration with foreign countries; and

(a) the cost of each of them?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT): (a) The following atomic power projects are being set up by Indian technicians only:

Madras Atomic Power Project	Unit—I
Madras Atomic Power Project	Unit—2
Narora Atomic Power Project	Unit—1
Narora Atomic Power Project	Unit—2

Rajasthan Atomic Power Project is being set up by Indian engineers with the assistance of Canadian consultants which was available util 1973. Unit-1 of the station has already started commercial operation since December, 1973, while Unit-II is expected to attain criticality in 1977.

(b) The sanctioned cost of each of the above projects is as follows:—

		Rs. crore
Rajasthan Atomic Power Project	Unit—I	60·40
Rajasthan Atomic Power Project	Unit—2	66·85
Madras Atomic Power Project	Unit—I	77·09
Madras Atomic Power Project	Unit—2	70·63
Narora Atomic Power Project	Units-1&2	209·89

SHRI SHANKERRAO SAVANT: It is heartening to note that most of these plants have been put up by our own technicians, but some part of the machinery of these plants must have been imported. I would like to know, what is the foreign exchange component in the construction of these plants and from which countries it has been obtained or is being obtained.

SHRI K. C. PANT: There has been progressive indigenisation. In the case of RAP I, the indigenous content was 40 per cent, RAP 2 60 per cent MAP Unit 80 per cent and in the case of Narora project it was 85 per cent. The foreign exchange content in terms of crores of rupees is RAP 1-30.64, RAP 2-24.92, MAP 1-6.03, MAP 2-5.88 and Narora—2.41.

SHRI SHANKERRAO SAVANT: By which date these are likely to be commissioned?

SHRI K. C. PANT MAP-I will be commissioned by the end of 1978, MAP Unit-2 by the middle of 1979, Narora Unit-I by 1981 and Unit-2 by 1982.

SHRI R. S PANDEY I congratulate the Indian technicians for their ability to put up these atomic power projects indigenously. Before that, there were certain atomic power plants which were established and some components were imported but it was found by Indian technicians that they were defective. Is that not a fact?

SHRI K. C. PANT. Tarapur was a turnkey project constructed and commissioned by an American firm. For Rajasthan, we had Canadian consultants. But as I said, RAP Unit-I was completed in 1973, Unit-2 is being constructed and commissioned entirely by Indian engineers including erection

of the machinery and so on and so forth. Indigenous production has gone up as I indicated earlier.

SHRI B. K DASCHOWDHURY: In view of the indigenous technology and the experience available in our country, as my friend just now said, what are the difficulties in setting up more atomic power plants in different parts of the country? For example there has been a long demand to have an atomic power plant on the Bengal Bihar border for the eastern sector. May I know from the hon. Minister, what is the reaction of the Government, particularly in view of the fact that the cost of such power plants is not so much prohibitive?

SHRI K. C. PANT: At each point of time, the mix-up of the power projects —how much thermal, how much hydel and how much nuclear—in each region has to be decided within the framework of the Five Year Plans and sometimes within the framework of a longer period, i.e. ten years It is very difficult to say when new nuclear stations will come up in particular region. But as regards the eastern region is concerned, for the present, at any rate, a view has been taken that because of availability of coal and because of certain hydel resources, it may be easier to build power stations on the basis of either the hydel availability or coal for the time being. There are regions in the country like Gujarat etc. where there is neither coal and the hydel resources are also a few and it may be better in the national interest to allow nuclear stations to go to such areas first.

Statement by Maharashtra Chief Minister regarding ban on Shiv Sena

*672. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by the Maharashtra Chief Minister recently in Bombay that it was for the Centre to take the decision to ban the Shiv Sena; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHAMANANDA REDDY): (a) Yes, Sir.

(b) The Central Government remains in touch with the State Governments regarding activities of organisations which tend to create disaffection between different sections of the community or otherwise create conditions of disorder prejudicial to country's security and integrity, with a view to keeping close watch for appropriate action under law.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: The laughter in the House is so eloquent that it speaks for itself, that the answer is rather bogus.

So, I would like to know from the hon. Minister in what way Shiv Sena is different from those organizations which were banned immediately after the promulgation of Emergency. It is a known fact that the chief of Shiv Sena, Bal Thakeray, said openly that he believes in Hitler who is his ideal and he also said that he is the father of the sons of the soil theory and he based himself on the extreme parochial sentiments and he aroused a threat to the national unity and this organization, I really fail to understand, in what way the Government differentiates from RSS, Anand Marg or various other varieties of Naxalite extremists which were banned and why this delay when the Government of Maharashtra already has comunmicated their view to the Centre?

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: Such of those organizations as have come to adverse notice and where it is felt by the Government that action should be taken in the interests of the security of the country,—all of you are aware that on 3rd July several of

these—RSS, Anand Marg, JEI and other organizations have been banned. It is known that Shiv Sena had indulged in activities which are parochial and chauvinistic and which are sometimes considered to be insecure from the point of view of linguistic minorities, etc., I can say that the activities of Shiv Sena also are under close watch... (*Interruptions*) and the Government will not hesitate to take any action when called for. And it is also to be borne in mind that the head of this organization has welcomed the emergency and has expressed his support to the 20-point programme.

SHRI K. LAKKAPPA: Mr. Speaker, Sir,......

MR. Speaker Let him have his second supplementary.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: The last part of the answer is highly objectionable because the Chief Minister of Maharashtra who has had communication with the Centre was asked in a Press Conference about his opinion about the so-called support lent by Mr. Bal Thakeray emergency and the 20-point economic programme. I quote. He said:

> "I do not consider him to be like-minded ...."

That is Bal Thakeray. He has again said:

> "It has come........

That is the support to the 20-point economic programme and emergency.

> "It has come in a cryptic manner and I must try to find out the truth."

This was said on 12th November 1975.

Now, here is a Minister .....

SHRI K. M. MADHUKAR: Minister of Home Affairs.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN:.... giving a certificate to one of the most rabid, antinational and fascist elements in the country. Unless—I may be pardoned if I use this word—there is some horse-trading and unless it is the banner of opportunism which the Minister is trying to raise, I do not think there is any reason for keeping a watch......

MR. SPEAKER: The hon. Member should avoid insinuations.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I am not. The Prime Minister herself joined the laughter in the House. That is the kind of answer that the Minister has given.

I would like to know from the hon. Minister. Apart from this which I have sited, what exactly is the reason which gives Shiv Sena a lease of life? I would like to know. Watching means for what? Watching can be for promotion.

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: I mentioned only a fact, namely. .that it has come to our notice. ..

SHRI C K. CHANDRAPPAN It was doubted by the Chief Minister of Maharashtra.

SHRI K BRAHMANANDA REDDY: .that Mr. Bal Thakeray has welcomed the emergency and the 20-point programme. I have not gone into whether that statement of his was sincere or insincere The only point (*Interruptions*)

SHRI C. K. CHANDRAPPAN. Today Bal Thakerary will hold a meeting in Bombay to say that this Home Minister has given him a certificate.

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY. Even the Chief Minister of Maharashtra has said that he will have to look into how far his support to the 20-point programme is sincere. This is what he mentioned.

SHRI VASANT SATHE: Tomorrow if the Anand Marg and RSS say, 'We give support to the 20-point programme,', will you accept it?

MR. SPEAKER: Mr. Sathe, please do not ask any question.

SHRI VASANT SATHE: How is it—I would like to know.

MR. SPEAKER: Let him complete his answer.

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: I want to tell the hon. Members that the mere fact that a party or organization mentions support to emergency or the 20-point programme does not entitle it not to be banned. The point is: what activities are they indulging in at the moment, are they serious enough, have they come to the adverse notice of other organizations and like that. We have to consider that. I am not giving a clean chit to Shiv Sena. I am not saying that Shiv Sena is not parochial.

SHRI C K. CHANDRAPPAN: The Prime Minister wants to say something

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF PLANNING, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I think we have gone off at a tangent. It is not relevant whether the Shiv Sena is sincere or not with regard to the 20-point Programme. What is relevant is their activity in Maharashtra. We know the organisation is a parochial one. But it is limited to a particular area In the past it has acted against the interests not only of the minorities but of all people from other parts of India, whether Kerala, other parts of the South or North Indians. But the question now is whether they are continuing with that policy. This has to be watched.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Without any action.

SHRI SARJOO PANEDY *rose*

MR. SPEAKER: Now let us go to the next question. . .

(Interruptions)

Mr. Ram Gopal Reddy.

Items for Small Units

*673. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether list of items for small units has recently been expanded; and

(b) if so, the names thereof?

Perhaps the Minister has not found the answer. I have got it here. Shall I read it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A P. SHARMA): (a) No, Sir

(b) Does not arise.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: On previous occasions also he said the same thing to me. But I now want to know from his senior colleague as to what are the criteria for giving concessions and facilities to the small scale industries.

THE MINISTER OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI T. A. PAI): We have reserved nearly 147 plus 30-about 177 industries exclusively for the small-scale sector. Now, there is a continuous study as to which other items may to included. The consideration and selection will depend on the technical and economic suitability of the items for production in the small-scale sector and the potential of small-scale units to contribute to production in terms of both quantity and quality. Even now there are certain items under consideration of the Government and we shall include them in the list and the list will continue to expand depending upon the possibility if these industries would be taken up increasingly by the small-scale sector

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Some items were banned previously for the small scale sector like AC conductors, PVC footwear, manufacture of stainless steel products, etc.

I want to know whether they will be allowed to work now and necessary raw materials supplied to them.

SHRI T. A. PAI: It is the policy of the Government to see that the small-scale sector is continuously expanded. We are happy that we have nearly half a million of them operating all over the country and we feel that they are going to be a very important and major instrument for the industrialisation of the country and whatever be their problems, either finance or raw material, they will be continuously looked into. If any specific instances are brought to our notice, we shall certainly take action immediately.

श्री नाथू राम अहिरवार : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह बात सही नहीं है कि जहां जहां पर शहरों में बड़े उद्योग लगे हैं वहीं पर छोटे उद्योग लगाये जा रहे हैं और जो पिछड़े इलाके हैं, देहाती क्षेत्र हैं वहां पर उद्योग नहीं लगाये जा रहे हैं ? इस दिशा में क्या सरकार ऐसा प्रतिबन्ध लगायेगी कि जो लोग आगे लाइसेंस लेने वाले हैं उनको कम्पेल किया जायेगा कि वे पिछड़े क्षेत्रों और देहाती क्षेत्रों में ही उद्योग धंधे लगायें तभी उनको लाइसेन्स दिया जायेगा ?

SHRI T. A. PAI: The small-scale industries are not licensed. The field is open to self-employed people and technocrats. In the recent census we found this. Instead of going to rural areas and backward areas, near about 60 per cent of them are around the four metropolitan cities and 3 big towns. We are trying to evolve this strategy whereby the conglomeration of small scale industries will be set up in the backward areas. There are certain incentives and facilities which are offered here and we hope that these things would be of advantage in helping the smallscale industries to set up their units in the backward areas.

श्री सरजू पांडे : अध्यक्ष जी, आम तौर से पिछले सालों का जो तजुर्बा है वह यह है कि छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना भी उन्हीं जगहों पर ही होती है जहां पर बड़े बड़े उद्योग लगाये गए हैं। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि छोटे उद्योगों को उन इलाकों में रखा जाये जो पिछड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं देश के जो सब से पिछड़े इलाके खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्से हैं वहां के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई खास तरह की योजना विचाराधीन है और उस पर अमल किया जायेगा ?

SHRI T. A. PAI: We shall certainly like as many people of the locality to take to new entrepreneurship as possible and I hope that hon. Members would encourage them also, because it is the local enterprise that has to come forward.

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI: May I know what protection has been given to the small-scale industries in regard to supply of the raw materials which are mostly controlled by big houses like tallow for soaps and filament for electric bulbs? Even though the small scale industries are entitled to start production as per the DGSD's orders, raw materials from big houses are not made available and they had to purchase them at black market. So, I want to know as to what specific assurance can be given to them.

SHRI T. A. PAI: Tallow is a raw material and it is mixed with other ingredients. Such cases as have been quoted do arise where small scale industries do depend upon big industries for supply of components and they have to purchase in the blackmarket etc. Such instances whenever brought to notice are being looked into. We shall certainly ensure that no blackmarket in these things are indulged in, and that regular supply to small-scale industries is ensured.

SHRI RANABAHADUR SINGH: In the evolution of this policy your effort

is to draw the small-scale industries to the backward areas. May I know from the hon. Minister whether he is intending or contemplating to set up all necessary infrastructure along with the incentives that are being given for the setting up of industries in backward regions?

SHRI T. A. PAI: That is what we are contemplating. A combination of these things would be necessary and this is what we are doing.

CBI investigations asked for by States

*674. SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there has been rise in States' demand for C.B.I. investigations of cases relating to crimes involving violence during 1975-76; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL, AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): (a) Yes, Sir.

(b) In 1975, the C.B.I. took over investigation of 13 (Thirteen) criminal cases involving violence. In 1976 so far, they have taken over two cases. The corresponding figures for 1973 and 1974 are 5 and 4 respectively.

SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA: So far CBI has enquired in the cases of bribery, corruption and the conduct involving on the part of the Government officials etc. Now States are referring cases for enquiry by them. May I know from the Minister how many cases have been referred to them for investigation last year?

SHRI OM MEHTA: In 1976 two cases were referred to them one case is from the Gujarat State, and the other case is from the U.P. State. The Gujarat case relates to the seizure of explosives from Baroda in March last while the U.P. case relates to the murder of a girl in Lucknow in January last.

SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA: What are the details of the Baroda explosives case which he has referred in the statement and I would also like to know which are the political parties which are behind the explosives case?

SHRI OM MEHTA: We do not have the information about all the political parties. But, upto this time, whatever information is with us I would like to give it to you. Those explosives were detected on 8/9-3-1976 by local police who seized the seven Crates, weighing 114 k.gs in all, of nitro-glycerine sticks (800 numbers) and fuses from the godown of a transport company.

Upto this time, 11 persons have been arrested. The details have been given in reply to an unstarred question. Some of them have affiliations with the socialist party and one of them with the Congress Organisation. It was found on investigation that there was an organised conspiracy to commit various acts of sabotage in different parts of the country with these stocks of explosives with the intention to over-awe the Government and to create a feeling of insecurity and terror in the country.

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, हिंसा की वारदातें बड़े लार्ज पमाने पर हो रही हैं— खास तौर से हमारे बिहार में। प्रधान मंत्री जी अभी वहां गई थी तो छोटी मीटिंग में और पटना की विशाल मिटिंग में भी उन्होंने इसका जिक्र किया। अब कहां तक सही है, कहां तक गलत है, मैं नहीं कह सकता लेकिन लोगों ने मुझ से कहा कि प्रधान मंत्री ने वहां चीफ सेक्रेटरी और आई जी, पुलिस से कहा कि यदि हिंसा की वारदातों को आपने नहीं

दबाया तो सेन्टर का इन्टरवेन्शन जरूरी है। कहां तक सही है या कहां तक गलत है, लेकिन पटना में यह रयूमर थी कि प्रधान मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी और आई० जी०, पुलिस से ऐसी बात कही है कि अगर आप हिंसा को नहीं दबाते हैं तो सेन्टर को लगाना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस हिंसा को दबाने के लिए क्या कोशिश कर रही है? इस में सामाजिक, असामाजिक, राजनीतिक व गैर-राजनीतिक—सारी वारदाते शामिल है जिनको दबाना केन्द्र की ताकत में है जब कि हो सकता है कुछ राज्यों में, जैसे बिहार राज्य में—आप तो उसी राज्य से आते हैं और आप जानते हैं—आये दिन लोगों को गोली मारी जाती है, जो हमारे कार्य कर्ता भाई थे राम दयाल नगर के पास उन को रेलगाड़ी में तमंचा छुरा दिखाकर दूसरे पसेंजर्स के साथ लूट लिया गया, घड़ी छीन ली गई और 18000 रुपया उन से वसूला गया तो मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): पहले मैं तो माननीय सदस्य से कहूंगी कि वे अफवाह बाजी में विश्वास न करें। जो कुछ बात बन्द मीटिंग में होती है उसकी सूचना बाहर हमेशा सच नहीं निकलती है। लेकिन यह सच है कि कहीं कहीं हिंसा बढ़ी है और हमारा पूरा ध्यान उस तरफ है। कार्यवाही तो राज्य सरकार को ही करनी है लेकिन जो उचित सहायता उन को चाहिए वह केन्द्र हमेशा देने को तैयार है।

SHRI PRABODH CHANDRA. May I know from Government if they have got any information that some of these dynamites were meant to be sent to Varanasi in anticipation of the Prime Minister's visit to that place?

SHRI OM MEHTA: The evidence has come to us that they were being despatched to Varanasi. We have no information. The Prime Minister was to visit that area We do not know the details about it.

श्री लालजी भाई : इसी सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं जब राज्य इस तरह की मांग कर रहे हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो विभिन्न मामलों की जांच करे तो क्या राज्यों का अपनी पुलिस पर विश्वास घट गया है और वह समझती हैं कि पुलिस निजी फ़ायदा उठाती है, गोली चलाती है, लूट-पाट कराती है और इस प्रकार की घटनाओं में पुलिस का हाथ रहता है। इस प्रकार का विश्वास कितनी राज्य सरकारों का है जो कि केन्द्रीय सरकार के सामने मांग रख रही हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामलों की जांच करे?

श्री ओम मेहता: इस साल दो केसेज आये हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों का अपनी पुलिस से विश्वास उठ गया है, बल्कि जो इन्टर-स्टेट रमिफ़िकेशन्स के केसेज हों वह यहां पर रेफर जिन में कोई स्टेट खुद इंक्वायरी न कर सके या जो ग्रेवियस नेचर के केसेज हों वह यहां पर रेफर किए जाते हैं। जब हम देखते हैं वह ऐसे केसेज हैं जिन में स्टेट गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती तभी उन को लिया जाता है।

श्री मुहम्मद शमीमुर्रहमान: मोहतरिम स्पीकर साहब, मैं आप के जरिये मोहतरिम वजीर साहब से जानना चाहता हूं—उन्होंने अभी बड़ौदा वाले केस में कुछ पोलिटीकल पार्टियों का जिक्र किया था, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, जिन का नाम इन्वेस्टीगेशन के दौरान इन पोलिटीकल पार्टीज में आया है?

श्री ओम मेहता : नाम पहले दिये जा चुके हैं, मगर आप चाहें तो मैं फिर से उन नामों को पढ़ सकता हूं। जो लोग अरेस्टेड हैं :-

जसवंत सिंह चौहान :

—सोशलिस्ट पार्टी

कीरित भट्ट :

—प्रो० सोशलिस्ट पार्टी

के० विक्रम राव :

—प्रो० सोशलिस्ट पार्टी

राधे श्याम सिंह :

—प्रो० सोशलिस्ट पार्टी

मोतीलाल बाबूलाल कानोजिया :

—सोशलिस्ट पार्टी

गोविन्द भाई सोलंकी :

—सोशलिस्ट पार्टी

प्रभुदास पटवारी :

—कांग्रेस आर्गेनाईजेशन के हैं।

Issue of Letters of Intent for setting up industries in Gujarat

+

*876 SHRI ARVIND M. PATEL:
SHRI VEKARIA:

Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the number of letters of intent issued in Gujarat State for setting up industries during the Fifth Plan period; and

(b) the names of industries with their locations?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI T. A. PAI): (a) 117 letters of intent were issued during the calendar years 1974 and 1975, for setting up of new industrial undertakings in Gujarat.

(b) The details of letters of intent including names of the industries and location etc. are being published in "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", "Indian Trade Journal", "Journal of Industry and Trade" and "Monthly List of Letters of Intent and Industrial Licences". Copies of these publications are available in the Parliament Library.

श्री अरविंद एम० पटेल : आप ने जो 117 आशय पत्र जारी किये हैं उसके सम्बन्ध में कितनी एप्लीकेशन्ज आप के पास आई थीं तथा जिन को रिजेक्ट किया गया है, उन के रिजेक्ट करने की वजह क्या है?

दूसरा प्रश्न – सरकार ने जो 117 आशय पत्र जारी किये हैं, उन में से कितनों का इण्डस्ट्री लगाने का काम शुरू हो गया है?

SHRI T. A. PAI: Sir, the total number of applications received for the whole country were 3280, 4372, 1882 and 219 for the years 1973, 1974 1975 and the first quarter of 1976 respectively. the last two years exclude COB, Fertilizer and KFTZ cases The applications received from State of Gujarat for the years 1973, 1974, 1975 and the first quarter of 1976 were 294, 370. 252 and 14 respectively. the last two years exclude COB, Fertilizer and KFTZ cases Out of the applications received from the State of Gujarat the total number of letters issued were 96, 125 and 107 for the years 1973, 1974 and 1975 respectively. The total number of licences issued excluding Sugar, Textiles. Flour Milling Vegetable oil and coal from 1952 to 1971 is 603 Out of this the units in production and implementation are 412; effective steps taken 22; not implemented 41; rejected surrendered and closed 37 and information not available in regard to 47.

SHRI B. V. NAIK: The other day the hon'ble Minister for Industry had the opportunity of addressing the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry where he stated that in these cases where there is delay in the implementation of a licence, the same will be cancelled or rejected. May I know whether a time-limit is going to be included in the Letter of Intent or the Licence that in case it is not implemented within a specific period and the date to be noted therein the licence will automatically get cancelled?

MR. SPEAKER: This was about Gujarat, not a general question.

SHRI B. V. NAIK: It is pertaining to licences.

MR. SPEAKER: Next question.

SHRI B. V. NAIK: The hon Minister is willing to answer. I think it would be very unfair to shut it out. It is a policy statement he has made.

MR. SPEAKER: You said it would be about Gujarat, and asked a general question.

SHRI B. V. NAIK: Let it be confined to Gujarat.

MR. SPEAKER: Next question.

Trade Marks of Coca Cola Export Corporation

*677. SHRI H. N. MUKERJEE:
DR. RANEN SEN:

Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken by Government not to continue the trade marks of Coca Cola Export Corporation beyond 31st December, 1976; and

(b) if so, whether the Government have communicated the same to the Coca Cola Export Corporation of U.S.A.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): (a) The applications made by the Coca Cola Export Corporation for permission to use the trade marks are under consideration of the Government.

(b) The question does not arise.

SHRI H. N. MUKERJEE: This is a very tiresome subject. We were given to understand a few months earlier that 31 December, 1976 would be the target date. Here is a 100 per cent foreign company, no question of dilution of equity to 40 per cent. It does not export very much these days. The Minister said the other day that its exports are falling. So no question of 100 per cent export. Why this mollycoddling of this organisation for ever and ever? What can be the conceivable reason for treating this kind of company with the indulgence which is being shown by Government?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI T. A. PAI): There is no question of any indulgence at all. Their application under FERA has been received; it is under consideration. But the whole problem is this that as long as we have decided not to ask them to quit completely, if they are willing to subject themselves to any regulations we might impose on them, they will still have a chance to be considered, provided it is in the interest of the country and the export performance is there. But it is true that the exports made are falling and this will also be taken into consideration and a decision arrived at quickly.

SHRI H N. MUKERJEE: In view of the statement before the House by the Finance Minister himself that the sooner we get rid of the Coca Cola Corporation, the better for this country, in view of so many other statements made by Ministers repeatedly, may I know how long, in the name of implementing FERA, a legislation nearly four years old, are we going

to continue to indulge this kind of company and not resuscitate our own Indian concerns largely operating on a small scale basis, from which in the pre-Coca Cola days we used to get the type of cold drinks we required? It is not that Coca Cola is giving us something so essential that we are treating them in this mollycoddling fashion. How long do we have to wait for the resuscitation of our own cold drinks industry, particularly in this part of the country about which we all have personal experience for many years?

SHRI T. A. PAI: Not very long.

SHRI H. N. MUKERJEE: Is that all?

SHRI T. A. PAI: I can only say that the country is not interested in losing valuable foreign exchange for getting soft drinks introduced into the country. But the facts of life are there. For the last 15 years this industry has been there. Nearly 22 bottling plants have been set up employing about 20,000 workers and involving an investment of Rs. 6 crores in these bottles. But it is not for the sake of the bottlers and not even for the sake of the consumers that a decision will be taken, but because there have been various demands and pressures brought up as to what will happen to the bottles Something will have to be done for that. What the Finance Minister said is right. We will certainly take into consideration what is in the best interest of the country.

DR. RANEN SEN: The hon Minister said that this is under consideration and soon a decision will be taken. For your information, I will quote what the Finance Minister said in reply to a question by Shri Shashi Bhushan on 2nd November 1974. Even then it was said by Shri C Subramaniam, who was probably the Finance Minister then, that the sooner we get rid of the Coca Cola Corporation, the better for the country, which was quoted by Shri H. N. Mukerjee here just now. In view of the fact that this is pending for the last 1½ years and more, is the delay due to the fact that there is a strong lobby for Coca Cola working inside the Government so that Government refuse even to pressurise this company to dilute its capital under section 28(1) of FERA? If so, when is the government going to get rid of such a lobby inside its own administration?

SHRI T. A. PAI: There is no need to get rid of the lobby because it does not exist except in the imagination of the hon. Member. Nor is any one of us addicted to Coca-Cola and therefore to say that we are being pressurised to take a decision or delay the decision is not correct. We have been often told that if any harsh decision is taken 20,000 persons will be thrown out of employment unless a substitute is provided. We have asked the CFTRI to evolve a substitute and they have evolved it But I do not know whether those who drink Coca-Cola would prefer it, nor should we care about it We have a right to ask for the dilution of the capital. Their application under FERA has come up and a decision is being taken.

SHRI R S. PANDEY: May I know whether the government is contemplating to ask the Coca-Cola company in regard to the foreign exchange that they earn over here, to invest that over here instead of squandering away the foreign exchange or sending it to America?

SHRI T. A PAI: They have accumulated assets to the extent of Rs. 6 crores; whether we should utilise it or not, in what industries and to what benefit to the country—we will have to think seriously about those questions

SHRI K. S. CHAVDA: In reply to a question of Shri Shashi Bhushan in 1974, the hon. Minister has stated that no royalty was being charged from the bottlers by the Coca-Cola company of the United States which is the proprietor of this trade mark but the bottlers have to purchase the raw

material, namely Coca-Cola concentrate from the Coca-Cola export-corporation, a subsidiary of the Coca-Cola company of the United States which amounts to indirect payment of royalty. May I know whether the government is going to do costing of Coca-Cola concentrate and fix the selling price of it, if so, when? If not, why the government is not going to do that?

SHRI T. A. PAI: The question would arise only when it is decided to allow Coca-Cola to continue. If the decision is otherwise, costing has no relevance.

Loan to J & K State for Power Lines

*679. SHRI JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Jammu and Kashmir State has been provided a loan of Rs. 11.5 million for power lines; and

(b) if so, the terms and conditions thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) A loan of Rs. 115.53 lakhs was sanctioned during 1975-76 to the Government of Jammu and Kashmir for the construction of the Pathankot-Udhampur-Chenani 220 KV inter-State transmission line.

(b) The loan is repayable in 25 (Twentyfive) equal annual instalments with interest at the rate of 5½ per cent per annum.

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत कौन कौन से प्रान्त आते हैं और कर्ज की जो पूरी राशि दी गई है क्या उसका हिस्सा या उसका पूर्ण दायित्व जम्मू-कश्मीर का ही रहेगा या और प्रान्त जो हिस्सेदार हैं वह भी इस में हाथ बटायेंगे ? और क्या इस योजना में हाथ लग चुका है ? अगर हां तो कब तक सम्पन्न करने का विचार है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : योजना के अन्तर्गत काम हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि इस साल के अन्त तक काम पूरा हो जायगा। जहां तक इस योजना के अन्तर्गत अन्य राज्यों को ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिये कर्ज देने का प्रश्न है, अन्य राज्यों को भी कर्ज दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कौन कौन राज्य हैं ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : काफ़ी लम्बी सूची है, कई राज्यों को दिया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : जिस शर्त पर कर्ज इन्होंने जम्मू-कश्मीर को योजना के कार्यान्वियन के लिये दिया है क्या उसी शर्त पर और प्रान्त भी कर्ज ले कर ऐसी योजनायें अपने यहां चलाने को प्रस्तुत हैं ? अगर हां, तो उन के नाम क्या हैं ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : इन्टर-स्टेट लाईन के लिये कर्ज दिया जाता है जैसा मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया है। और जिन राज्यों ने इस योजना के अन्तर्गत कर्ज लिया है वह हैं, आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु वेस्ट बंगाल, और डी० वी० सी० जो बिहार को कवर करती है।

इस के साथ ही माननीय सदस्य ने पूछा कि किस शर्त पर यह कर्ज दिया जाता है। इस में साढ़े पांच प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज लिया जाता है और 25 वर्ष में इस ऋण को चुकाना होता है।

खादी तथा ग्रामोद्योगों को सुविधायें

+

*680. **श्री कमला मिश्र 'मधुकर'**

श्री चिरंजीव झा :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार का हथकरघा उद्योग को दी गई सुविधाओं की भांति खादी और ग्राम उद्योगों को भी सुविधायें देने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A P. SHARMA): (a) and (b) The Khadi sector has traditionally enjoyed a special status with Government giving special attention to its development. The Khadi and Handloom sectors enjoy several concessions which are common to both, such as reservation of certain varieties of cloth for manufacture in these sectors, cash assistance for the export of fabrics and garments and concessional finance under the Differential Rate of Interest Scheme. In addition to this Government also extends special preference to the Khadi sector with respect to purchases required for Government use. In order to encourage sales of Khadi products, Government has also made available a rebate on retail sales.

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' : अध्यक्ष जी, खादी उद्योग देश के लाखों लोगों को काम देता है और खादी के जो कपड़े बन रहे हैं उसने बाजार में अपना काफी स्थान बना लिया है, खासकर के ऊन और रेशम के कपड़ों में। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिस के जरिये खादी उद्योग को वह तमाम सहूलियतें मिल सकें जो आप हथकर्घा उद्योगों को देते हैं जिन के जरिये खादी उद्योग के लिये आप ने जो लक्ष्य रखा हो वह पूरा हो सके और खादी ने जो बाजार में अपना स्थान बना लिया है उसका और विकास किया जाय ?

श्री ए० पी० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, खादी को, जो हथकर्घा में कपड़े बनते हैं उस से बहुत सारी अधिक सुविधायें दी जाती हैं। इसलिये दोनों के बीच में कोई तुलना का प्रश्न नहीं है। और जो माननीय सदस्य ने कहा है जो एक स्पेशल स्कीम खादी के काम को बढ़ाने के लिए है उस में प्लान के अन्दर ही 180 करोड़ रु० ग्रान्ट के रुप में है।

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' : लेकिन खादी ग्रामोद्योग, बिहार में बहुत गोलमाल, भी हुआ है और इस के अध्यक्ष थे जय प्रकाश नारायण। तो मैं जानना चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग संघ में बिहार में वहां के मजदूरों का 90 लाख रु० प्रोविडेंट फ़ंड का बकाया है और पटना हाई कोर्ट का जजमेंट भी हो चुका है, लेकिन अभी भी बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। क्या इस उद्योग को विकसित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ऐसी कोई कार्यवाही करने जा रही है जिस से वह बकाया भुगतान हो सके और उस के जरिए मजदूर लोग उत्साह से खादी ग्रामोद्योग के विकास में काम कर सकें।

श्री ए० पी० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस की सूचना कि 90 लाख रु० बकाया है, अभी खादी कमीशन के पास नहीं है।

जैसे ही इस की सूचना मिलेगी, या जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है, इसके संबंध में हम कार्यवाही करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उन का बकाया है उस को दे दिया जाय।

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI: The Khadi and Village Industries are employment oriented. As the Hon'ble Minister knows that a large percentage of the Central assistance given to the Khadi and Village Industries Commission fritters away because of the huge expenditure that is incurred on overheads and other establishment may I know from the Hon'ble Minister how he is going to stop the Khadi Commission spending more and more on the employment oriented scheme and whether he is going to decentralise the Khadi and Village Industries Commission?

SHRI A. P. SHARMA: The work of the Khadi and Village Industries is carried on by two agencies, one is by the Village and Khadi Industries Boards in the States and the other is directly by the Khadi Commission It is not a fact that most of the amount allocated for the Khadi Commission and Village Industries is spent on the establishment charges

Shortfall in Industrial Explosives

*681. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there is likelihood of shortfall in industrial explosives;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps taken to the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLES (SHRI B. P. MAURYA): (a) There is no likelihood of shortfall in industrial explosives in the near future.

(b) and (c). To meet the anticipated increase in demand for industrial explosives in the next few years, Government have approved the setting up of adequate additional capacity for this item.

SHRI VASANT SATHE: There was a reply given long ago by Dr. Triguna Sen that a public sector undertaking for manufacturing industrial explosive will be set up. I would like to know how far this project has come up and when it is going to be commissioned, in view of the tremendous and growing need for industrial explosives in this country.

SHRI B. P. MAURYA: There is a proposal which is being cleared It may take some time. By 1978 it may be commissioned.

MR. SPEAKER: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Indo-West German Seminar on Atomic Energy to be held in Zurich

*668 SHRI RAJDEO SINGH: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether a joint Indo-West German Seminar on atomic energy is expected to be held in Zulich by the end of June this year;

(b) whether the atomic energy scientists of India will exchange views with the atomic scientists of West Germany on problems connected with the construction and maintenance of atomic reactors only; and

(c) other items on the agenda?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF PLANNING, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) A joint Indo-Fedtral Republic of Germany Seminar on "Nuclear Power Plant

Operation" is being held at Julich, in the Federal Republic of Germany from June 29 to July 2, 1976.

(b) and (c). Indian Scientists from the Department of Atomic Energy and Scientists from the Federal Republic of Germany will present papers on the operation and maintenance of power reactors and will have discussions on these matters.

Slowing down of production due to steep fall in offtake of Coal

*675. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether in view of the steep fall in offtake of coal, Government are thinking of slowing down production;

(b) whether any plans have been made for rational utilization of manpower employed; and

(c) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT): (a) No, Sir. There has been no general fall in the off take of coal except in the case of slack coal for the power houses and cement and soft coke where the demand of coal has been below the anticipated level. The demand in some other sectors like steel and miscellaneous industries, has been higher than the anticipated level.

(b) and (c). Rationalisation of manpower is a continuous process. The companies are reployeding regularly the manpower with a view to regulate production as per market demand. For re-deployment of manpower and change of mining technology, it is necessary to impart training to unskilled workmen to take up semi-skilled and skilled works for higher productivity.

Formula for Manufacture of Substitute of Coca Cola

*676. SHRI D. K. PANDA: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether a formula for manufacture of substitute of Coca Cola has been evolved by Central Food Technological Research Institute;

(b) if so, the steps Government propose to take to withdraw permission given to Coca Cola Export Corporation; and

(c) how long Government will take for complete Indianisation of bottling industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA):

(a) The Central Food Technological Research Institute, Mysore is reported to have evolved a formulation which might prove to be a substitute for the Coca Cola beverage.

(b) No such proposal is under consideration.

(c) The Coca Cola bottlers are already Indian companies

International Criminals

*682. SHRI SHASHI BHUSHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of international criminals brought to book in India since the proclamation of Emergency;

(b) the number of such criminals, country-wise and type of offences committed by them; and

(c) the links of foreign criminals in India?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY): (a) to (c). Information readily available indicates that 106 international criminals, including Indians and foreigners hailing from various countries as detailed below, have been booked under specific penal Acts

and also under the preventive Acts since the proclamation of Emergency:—

Nationality	Number
U. K.	27
Iran	17
India	17
France	7
U.S.A.	7
Switzerland	4
Canada	3
Australia	3
Sri Lanka	3
Afghanistan	2
Egypt	2
Yugoslavia	2
Italy, Malaysia, Singapore, Phillipines, Spain, Austria, Netherlands, Denmark, Ireland, Nepal, Brazil, West Germany	1 each

They have been involved in cases of smuggling, foregery, cheating, contravention of Foreign exchange regulations, smuggling and possession of contraband/Narcotics. It would not be in public interest to disclose information of links with Foreign criminals.

Accident in Akashkinari Colliery of Bharat Coking Coal Limited

*683. SHRIMATI ROZA DESHPANDE:

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether two miners died when a boiler burst at Akashkinari Colliery of the Bharat Coking Coal Limited;

(b) whether this was the second incident of boiler burst in Jharia Coal-field of Bharat Coking Coal Limited within two months;

(c) if so, reasons thereof; and

(d) steps Government propose to take to check such explosions in future?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The accident occurred due to failure of the inner shell of the old repaired boiler which had thinned out.

(d) Inspections are conducted according to law, by the Inspectorates of Boilers of the State Govts. The Coal Companies are also being instructed to take more stringent measures in this regard.

Resurgence of Extremists and Reactionary Forces

*684. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some incidents have been reported from different States proving the resurgence of extremists and reactionary forces in the country;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the concrete measures being taken against such subversive activities?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: (a) Some incidents of extremist violence and reactionary activities have been reported from certain States in the recent months but they have been contained by stringent measures taken by State Governments.

(b) It will not be in public interest to disclose at this stage the details of these incidents.

(c) The measures include the strengthening of police set up in the affected area, organising appropriate intelligence arrangements and a relentless drive for the apprehension of the absconding extremists and militant elements.

National Integration Council

*685. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to revive and reconstitute the National Integration Council; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY): (a) and (b). Government has initiated action to get issues relevant to national integration considered in depth. The question of reactivising the National Integration Council and its other bodies will be considered in due course.

Meeting of Coal Sub-Committee of National Apex Body

*686. SHRI N. K. SANGHI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Coal Sub-Committee of the National Apex Body recently met at Calcutta and considered proposals for welfare of miners;

(b) whether the meeting recommended amalgamation of coalmines provident fund organisation and coalmines welfare organisation in the national sector; and

(c) what other suggestions in addition to the above were made and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT): (a) There is no coal sub-committe of the National Apex Body. There is, however, a Joint Bipartite Committee for Coal Industry, which met on the 20th March, 1976 in Calcutta and discussed among other things, matters relating to the welfare of mine workers.

(b) The matter of taking over of the Coal Mines Provident Fund Organisation and the Coal Mines Labour Welfare Organisation by the Coal Industry was raised in the meeting. On earlier occasions the Joint Bipartite Committee recommended integration of coal-mines Provident Fund Organisation and the Coalmines Labour Welfare Organisation with the public sector coal companies.

(c) The Joint Bipartite Committee in their meeting held on 20th March, 1976 laid emphasis on the implementation of the unanimous recommendations of the safety conferences, increased activity in construction of houses and provision of water supply and other amenities to the workers and implementation of the scheme of Workers' participation at different levels. The public sector coal companies are trying to implement these suggestions to the extent possible.

Exemption from Licensing for Industrial Units sponsoring Research

*687. SHRI R. S. PANDEY: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government propose to exempt such industrial units from licences which sponsor research in approved laboratories; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI T. A. PAI): (a) and (b). Government desires to encourage commercialisation of technology developed by national laboratories in the country so that technological self-reliance can be successfully pursued. It has accordingly been decided that henceforth industrial undertakings other than those falling within the purview of the Monopolies and Restricted Trade Practices Act and Foreign Exchange Regulation Act, which take up the manufacture of any item based on the technology developed by any of the laboratories established by the Council of Scientific and Industrial Research and laboratories approved by

the Department of Science & Technology will be exempted from the licensing provisions of the Industries (Development & Regulation) Act. This facility will also be available in respect of sponsored research undertaken by such laboratories on behalf of industrial undertakings. This facility is subject to the condition that the item of manufacture is not one reserved for development in public sector or small scale sector or governed by special regulations.

Financial aid to Universities for Rural Development Research

*688. SHRI P. GANGA REDDY: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether C.S.I.R. has drawn up a scheme to provide cent percent financial aid to Universities for rural development research by scientists; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SHANKAR GHOSE): (a) and (b). The Council of Scientific and Industrial Research has no scheme to give cent percent financial aid to Universities for rural development work.

A proposal is, however, under consideration to give more emphasis to rural development work by awarding Fellowships to increasing number of deserving candidates in this area in Universities/IITs. The selected Fellows are expected to take up R & D problems in fields more directly linked to development work in rural areas.

Horse Racing in Tamil Nadu

3306. SHRI MURASOLI MARAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government of Tamil Nadu are considering to re-introduce horse-racing at Ooty; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) and (b). In view of the stay order passed by the Supreme Court in appeal against the judgment of the Madras High Court and stay of operation of the Tamil Nadu Horse Races (Abolition of Wagering of Batting) Act, 1974 read with Madras City Police and Gaming (Amendment) Act, 1949 the Madras Race Club has resumed horse racing at Ooty with effect from 28-4-1976. However, there is no change in the policy of the State Government.

Construction of Roads by China along Borders

3307. SHRI RAM PRAKASH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Chinese have built roads of vital military importance in Tibet leading to India's frontiers touching Ladakh and Tsepla along the borders of Sikkim and Bhutan; and

(b) if so, the reaction of Indian Government thereon?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI BANSI LAL): (a) Government are aware of road construction by the Chinese across our borders in Tibet.

(b) These and related developments bearing on our security are taken into account in our defence planning.

Guidelines to States regarding Expenditure to be incurred in Backward Districts and Tribal Areas

3308. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have issued any guidelines to the States

to spend sizeable amount in the backward districts and tribal areas to eradicate the regional imbalance within their States;

(b) if so, reaction of the States in this regard; and

(c) the total amount proposed to be spent in the tribal and backward districts of Orissa in 1976-77 under minimum needs programmes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SHANKAR GHOSE): (a) In the guidelines issued in connection with the formulation of the Draft Fifth Five Year Plan and the Tribal Sub-Plans, the State Governments were asked to allocate suitable outlays to their backward and tribal areas.

(b) The State Governments are paying special attention to their backward and tribal areas while determining allocations of Plan outlays for them.

(c) The information has been called from the Government of Orissa and will be made available as soon as the same is received.

Employment of Local People in Regional Research Laboratory, Jorhat, Assam

3309. SHRI NOORUL HUDA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state what percentage of local people (i.e. permanent residents of the State) has been employed in the Regional Research Laboratory, Jorhat, Assam?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE): Local people employed in the Regional Research Laboratory, Jorhat constitute about 66 per cent.

Collection for violation of Foreign Exchange Regulations by Foreign Exchange Enforcement Directorate during 1975-76

3310. SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the total amount collected by the Foreign Exchange Enforcement Directorate for violation of Foreign Exchange Regulations during 1975-76?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA):

The reference presumably is to the realisation of the amount of penalties imposed in the course of adjudication proceedings by the officers of the Enforcement Directorate for violation of Foreign Exchange Regulations. During 1975-76 the Enforcement Directorate realised penalties amounting to Rs. 65.58 lakhs.

Allotment of Services on Reorganisation of Punjab

3311. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some cases of final allotment of services consequent upon the reorganisation of Punjab in 1966, are still pending with Government, including the settlement of appeals against the initial allotment; and

(b) the likely date by which all these cases would be settled by the Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): (a) and (b). Though the work relating to final allotment of service

personnel under the Punjab Reorganisation Act, 1966 has been virtually completed, there are a few isolated cases, where provisional allotments are to be finalised. These few cases and some appeals are pending with the successor States Efforts are being made to get these cases finalised as early as possible.

हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन

3312. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या हिन्दी भाषा-भाषी जनसंख्या के अनुपात में हिन्दी दैनिक समाचारपत्रों की संख्या और सर्क्यूलेशन की संख्या निराशापूर्ण है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हिन्दी दैनिक समाचारपत्रों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठायें गये है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। 31 दिसम्बर 1974 को प्रकाशित होने वाले 822 दैनिकों में से, सब से बड़ी संख्या, अर्थात 254, हिन्दी में प्रकाशित होने वाले दैनिकों की थी। जहां तक परिचालन संख्या का संबंध है, हिन्दी दैनिकों का नम्बर दूसरे स्थान पर था। इनकी परिचालन संख्या 17,23,000 थी।

(ख) सभी भाषायी समाचारपत्रों के बारे में सरकार की नीति एकसी है।

Distribution of Colour Films

3313. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have introduced any scheme for distribution of colour films;

(b) if so, the broad outlines thereof and procedure in allotting the colour films; and

(c) the steps taken for the availability of the colour films to the South Indian films?

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA):

(a) The present policy for the distribution of cine raw film, including colour stock, is contained in the Import Trade Control Policy as notified by the Government for the year 1976-77

(b) It broadly provides for (i) the unrestricted release of colour cine raw stock imported from the Rupee Currency Area, and (ii) the release of colour stock from General Currency Area, in different phases, against an export obligation of 200 per cent which is required to be supported by bonds and bank guarantees The import and distribution are canalised through the Film Finance Corporation.

(c) There is no discrimination in the matter of distribution of cine raw film on regional basis However, in view of the difficulties for finding adequate market abroad for regional films the question is being examined whether the export obligation in respect of release of colour raw stock from General Currency Area for producing regional films can be reduced to some extent.

Setting up of a statue of Netaji at Port Blair

3314. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a sum was allocated for setting up of a statue of Netaji at Port Blair; and

(b) if so, when it is expected to be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) Yes, Sir.

(b) The artist has been requested to go ahead with the casting of the statue so that it could be installed by the end of 1976.

किसानों को सप्लाई की गई बिजली की प्रतिशतता

3315. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) देश के कुल बिजली उत्पादन में से कितने प्रतिशत बिजली किसानों को नलकूप चलाने के लिए और उठाऊ सिंचाई क पम्पों के लिए सप्लाई की जा रही है और विभिन्न राज्यों में इसकी प्रति यूनिट दर क्या है ; और

(ख) क्या देश के कुल बिजली उत्पादन में से केवल अल्प अंश ही किसानों को उद्योगों की अपेक्षा काफी ऊंची दर लेकर सप्लाई किया जाता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नलकूपों तथा सिंचाई पम्पसेटों को चलाने के लिए कृषकों को 1974-75 के दौरान बेची गई बिजली देश की कुल बिजली की बिक्री का लगभग 14.3 प्रतिशत थी । 1-3-1976 को कृषकों देश की विद्युत सप्लाई की जो औसत दर थी वह नीचे दी गई है :—

राज्य	10% भार अनुपात पर 5 अश्व शक्ति के लिए औसत दर (ड्यूटी/कर सहित) प्रति यूनिट
	(पसे प्रति यूनिट)
आंध्र प्रदेश	21.51
असम	14.00
बिहार	21.23
गुजरात	22 83
हरियाणा	21 76
हिमाचल प्रदेश	10 00
जम्मू व कश्मीर	11.50
कर्नाटक	19.68
केरल	9.90
मध्य प्रदेश	16 00
महाराष्ट्र	20 00
नागालैंड	12.00
उडीसा	17.50
पंजाब	21.80
राजस्थान	21 00
तमिलनाडु	16.00
त्रिपुरा	22.00
उत्तर प्रदेश	27.57
पश्चिम बंगाल	38.00

(ख) सिंचाई पम्पसेटों इत्यादि के लिए कृषि के क्षेत्र में जितनी बिजली का उपयोग हुआ उसका स्थान उपयोग में इस्तेमाल हुई बिजली की मात्रा के बाद है अर्थात् दूसरा है । सब मिलाकर, राज्यों में कृषि के लिए बिजली की दरें तुल्य भारों वाले

लघु उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली बिजली दरों की अपेक्षा कम है।

मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र

3316. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन पत्रों के बारे में 9 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5611 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए 16 आवेदन पत्रों को निपटाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : 9 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5611 (लोक सभा) के उत्तर में उल्लिखित सभी 16 आवेदनपत्र निपटा दिए गए हैं।

Sick Units in Private Sector

3317. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the Union Finance Minister told in Calcutta that managements' inefficiency was the main reason for units going sick in the private sector; and

(b) if so, the names of the factories that went sick due to the inefficiency of the managements?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Equipping Capacitors to Pumpset Motors

3318. SHRI P. NARASIMHA REDDY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the different State Electricity Boards propose to make or have already made it obligatory for the agricultural electricity consumers to equip capacitors to their pumpset motors;

(b) whether *Government* are aware of the wide-spread criticism that this step is being taken more in the interest of the capacitor manufacturers; and

(c) the correct position in regard to the need and cost of equipping capacitors to pumpset motors?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD): (a) Yes, Sir. The State Electricity Boards of Haryana, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Assam and Rajasthan have already amended the conditions of the supply of electric energy making it compulsory for the inductive power consumers including agricultural consumers to instal capacitors The other State Electricity Boards have also initiated action regarding amendments to the conditions of supply of electric energy

(b) Government is not aware of such criticism

(c) A number of steps have been taken to reduce the heavy losses being incurred in transmission and distribution system in the country Effective reduction of losses is achieved by installing capacitors at the locations where reactive power is required. Induction motors which drive electric pumpsets draw considerable reactive power. The installation of capacitors

on these pumpsets is, therefore, considered justified. It also improves the supply of energy at the consumers' end.

The installation of a capacitor at motor terminals costs the agricultural consumer between Rs. 400 and Rs. 500.

Nicobar Aborigines Hostile to Indian Settlers

3319. SHRI R. P. DAS: Will the Miniser of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a few groups of the Nicobaris are becoming unfriendly every day with the Indian settlers;

(b) the role being played by foreign Missionaries who have been allowed to work among the aborgines of the Nicobar Islands in this matter; and

(c) the reasons why individuals and Indian Missionaries are not encouraged to work among the aborigines of the Andamans and the Nicobar Island?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) There is no evidence of any section of Nicobarese becoming unfriendly to settlers from other areas.

(b) Does not arise as no foreign Missionaries have been allowed to work among the tribals of the Nicobar group of Islands.

(c) So far no such persons have come forward to work among the tribals in the Nicobar group of Islands. Some Workers of Bharatiya Adim Jati Sevak Sangh are working among the tribals in the Andaman group of Islands.

Indian citizenship to Tibetans

3320. SHRI B. V. NAIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Tibetan children born in India will automatically be treated as Indian citizens under the Constitution;

(b) whether those Tibetans who have been residing for more than five years in India will acquire citizenship rights;

(c) whether any requests in this behalf have been received; and

(d) if so, the reaction of Government thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) Every person born in India on or after the 26th January 1950, becomes a citizen of India by birth under sub-section (1) of section 3 of the Citizenship Act, 1955, subject to the exceptions under sub-section (2) thereof.

(b) Tibetans who came to India and have been residing in India for more than five years will acquire citizenship rights only if they are granted certificates of naturalisation by the Central Government under section 6 of the the Citizenship Act, 1955.

(c) and (d) A few applications have been received by the Government from Tibetans for grant of Indian citizenship by naturalisation and these will be dealt with as per rules and regulations on the subject.

Extension of Credit Guarantee Scheme to cover Small Scale Ancillary Units

3321. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to extend the Credit Guarantee Scheme to cover small-scale ancillary units; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. P. SHARMA): (a) Yes, Sir.

(b) Hitherto the Credit Guarantee Scheme for Small scale industries covered only such industrial undertakings in which the investment in plant and machinery was not in excess of Rs. 7.5 lakhs in line with the general definition of "small scale industries". The general definition of "small scale industries" and "ancillary industries" was revised in May, 1975, by raising the ceiling on investment in plant and machinery to Rs. 10 lakhs and Rs. 15 lakhs in the case of "small scale industries" and "ancillary industries" respectively. The facility of Credit Guarantee Scheme was, however, extended in August 1975 to all undertakings having investment in plant and machinery not exceeding Rs. 10 lakhs, irrespective of the fact whether the unit is 'small scale industry' or 'ancillary industry'. On further consideration the facility of Credit Guarantee Scheme has been extended to cover 'ancillary units' with investment in plant and machinery beyond Rs. 10 lakhs but not exceeding Rs. 15 lakhs in line with the general definition of 'ancillary industries'!

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पुर्नानियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत्त अधिकारी

3322. श्री मूल चन्द डागा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने सेवा निवृत्त अधिकारी पुर्नानियुक्त किये गये और वे भिन्न-भिन्न पदों पर पुर्नानियुक्त किये गये ; और

(ख) उन्हें उनके वेतन के रूप में कितनी धनराशि अदा की गई तथा वे कितने समय से पुर्नानियुक्त हैं और उन्हें रखने की क्या आवश्यकता है ?

गृह मंत्रालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Orissa's Irrigation Plan

3323. SHRI RAM BHAGAT PASWAN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have accorded approval to Orissa's irrigation plan; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE): (a) and (b): The Annual Plan 1976-77 of Orissa has been approved by the Planning Commission at Rs. 124.67 crores. This outlay includes Rs. 25.90 crores for Irrigation, the details of which are indicated below:

A. Major and Medium Irrigation Projects

(a) Continuing Schemes

		(Rs. crores)
I. Major Schemes		
1. Mahanadi delta	5·00	
2. Salandi	0·51	
3. Anandpur	0·25	5·76
II. Medium Schemes (18 Nos.)	7·82	7·82
TOTAL :		13·58

		(Rs. crores)
(b) New Schemes		
I. Major Schemes		
1. Rengali Multipurpose Scheme	1·90	
2. Upper Kolab	1·00	2·90
II. Medium Schemes	2·46	2·46
TOTAL (*b*) :		5·36
(c) Survey & Investigation	0·40	
(d) Flood restoration works	0·56	
TOTAL (*a*), (*b*), (*c*) & (*d*):		19·90
B. Minor Irrigation		6·00
		25·90
Potential likely to be created during 1976-77		(000 Hectares)
Major and Medium Irrigation		40·00
Minor Irrigation		83·00

Television Centre in Kerala

3324. SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Kerala State Government have made a representation for setting up of a television centre in Kerala; and

(b) if so, Government's decision thereon?

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir. In September 1975, the State Government had suggested extension of SITE programmes to Kerala and also the setting up of a studio and 3 Transmitting Stations during the Fifth Plan in the vicinity of Trivandrum, Cochin and Calicut.

(b) The feasibility of extending the SITE programmes to Kerala was examined. It was, however, found that it would not be possible to do so for technical reasons such as the strength of the signal, limited capacity of programme production facilities in additional languages and other aspects of the Instructional TV Experiment. As regards the second part of the State Government's suggestion, it was not found possible to set up any TV Centre during Fifth Plan in Kerala State due to constraints in resources.

Television Centres in Maharashtra

3325. SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE. Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is a proposal for setting up additional television centres in Maharashtra;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) the time by which they are likely to start functioning?

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

Raid on the Headquarters of Meivazhi Sabha in Tamil Nadu

3326. SHRI S. A. MURUGANANTHAM:

SHRI M. KATHAMUTHU:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some dangerous weapons were seized from the residence of a person connected with the Meivazhi Sabha in Tamil Nadu;

(b) whether any investigation has been conducted into the activities of this Sabha;

(c) whether any arrest has been made in this regard; and

(d) if so, the facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the House on receipt.

IAS/IFS/IPS Candidates from Orissa

3327. SHRI ARJUN SETHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of candidates belonging to Orissa who have joined Indian Administrative Service/Indian Foreign Service and Indian Police Service during the last three years, year-wise; and

(b) the number of candidates amongst them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): (a) and (b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

Number of candidates belonging to Orissa who joined I.A.S./I.F.S./I.P.S. on the basis of the I. A. S. etc. Examinations held in 1972, 1973 and 1974.

Sl. No. Service	1972 Examination Gen.	S.C.	S.T.	Total	1973 Examination Gen.	S.C.	S.T.	Total	1974 Examination Gen.	S.C.	S.T.	Total
1. Indian Administrative Service	10	1	2	13	2	1	..	3	4	.	..	4
2. Indian Foreign Service	.	..	..	..	1	..	..	1	1	.	..	1
3. Indian Police Service	2	..	..	2	3	..	..	3	6	1	.	7

Orders for Machine Tools from U.K.

3328. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether UK has placed orders for machine tools with our country recently; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): (a) Yes, Sir.

(b) Hindustan Machine Tools has received orders for 15 Nos. A24 NC

Machines valued at Rs. 29.30 lakhs from U.K. during 1975-76. In addition five other Indian Companies have procured orders from U.K. for Rs. 161.91 lakhs.

Press trip to Development Projects organised by P.I.B. in Eastern and North Eastern States

3329. SHRI S. N. SINGH DEO: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether P.I.B. organised a Press trip to various development projects in the country for the small newspapers' editors of Eastern and North Eastern States;

(b) if so, the names of the editors who were selected in this trip and the impact of the visit on them; and

(c) the attitude of P.I.B. regarding these small newspapers' editors?

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir.

(b) A statement of 9 journalists comprising of 7 Editors, one sub-editor and one correspondent is enclosed. They visited projects in West Bengal, Tamil Nadu, Delhi, Bombay and Karnataka. The participants expressed the view that the tour was very useful.

(c) The policy of Press Information Bureau has always been to assist medium and small newspapers. P.I.B. offers facilities such as specially written developmental stories, articles of topical interest, photo service, ebonoid blocks, 'Charba' service for the Urdu press, liberal accreditation facilities etc. to small land medium papers and also organises tours for their benefit.

Statement

1. Shri Neitu Angami, Editor, Citizen's Voice, Kohima.

2. Shri J. N. Chatterjee, Sub-Editor, Nagaland Times, Dimapur.

3. Shri L. Harrison, Editor, Ka Pyrta U Reiwlum, Shillong.

4. Shri B. F. Syiem, Editor, Ka Lyngwiardpei, Shillong.

5. Shri B. Shallam, News Editor, U Naphang, Jowai.

6. Shri H. P. Lytam, Editor, U Para Ri, Jowai.

7. Shri K. R. Eangdiar, Correspondent, The Implanter, Shillong.

8. Shri Purna A. Sangma, M.A. LL.B., Editor, Chadambeni Kurang, Tura, Meghalaya.

9. Shri Ranjit Naug, Editor, Shillong Herald, Shillong.

Criteria for grant of Cash Subsidy

3330. SHRI TUNA ORAON: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the criteria of including districts for grant of Cash Subsidy; and

(b) the steps taken by Government to develop industries in Purulia and Bankura of West Bengal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. P. SHARMA): (a) The Planning Commission have fixed the following criteria for inclusion of districts in the scheme for grant of cash subsidy:—

(1) It must be economically and industrially backward district which possess the minimum infra-structure facilities essential for industrial development.

(2) In order to identify these districts falling under the aforesaid

category the following guidelines have been suggested:

(i) Per capita foodgrains/commercial crops production depending on whether the district is predominantly a producer of foodgrains/cash crops. (For inter-district comparisons conversion rates between foodgrains and commercial crops may be determined by the State Government on a pre-determined basis where necessary).

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) Per capita industrial output (gross).

(iv) Number of factory employees per lakh of population or alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population.

(v) Per capita consumption of electricity.

(vi) Length of surfaced roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

Only those districts with indices well below the State average may be selected for suitable incentives for financial institutions.

(3) After selection of the backward districts on the aforesaid criteria, the State Governments were requested to name 6 districts in backward States and 3 districts in other States for consideration of outright grant of subsidy by Central Government.

The Central Government selected the districts on the basis of the aforesaid recommendation of the State Governments.

(b) The Central Government under the Centrally sponsored scheme of Rural Industries Project Programme selected Bankura in the first series and Purulia in the second series for location of Rural Industries Projects.

The physical progress in terms of number of industrial units assisted, invested, gross value of production and employment in respect of Bankura and Purulia rural industries projects upto March 1975 is given below:

Indications	(Upto March, 1975) Bankura	Purulia
1. No. of industrial units assisted to come up (cumulative)	2600	100
2. No. of persons provided employment opportunities (cumulative)	21881	324
3. Investment (cumulative)	(Rs. in lakhs)	
(i) Fixed	239·38	4·26
(ii) Working	340·19	2·98
(iii) Total	579·57	7·24
4. Gross value of production during the year 1974-75 (Rs. in lakhs)	601·20	27·70

Both the Districts are Backward District for concessional finance as well as eligible for capital subsidy.

Employment to Urdu Post-Graduates from J & K in A.I.R. and Television

3331. SHRI SYED AHMED AGA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Jammu and Kashmir Government had recommended to Central Government that post-graduates in Urdu from the State be considered for Central services, more particularly in Radio and Television;

(b) the action taken by Central Government in the matter; and

(c) the number of such persons already employed in Radio or Television?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): (a) and (b). The Central Government have not received any such recommendation from the Jammu and Kashmir Government. However, Degrees/Diplomas awarded by Universities in India which are incorporated by an Act of the Central or State Legislature are recognised for the purpose of employment under the Central Government

(c) The number of post-graduates in Urdu from the State of J & K, working in Television in that State is two. Four staff artists who have passed M. A. (Urdu), are working in the radio stations in J & K State in various capacities.

Closure of Auto Ancillary Units

3332. SHRI B. S. BHAURA: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether many of the auto ancillary units in the country have been closed down;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the total number of workers being retrenched as a result of these closures; and

(d) measures being taken to avert the crisis in this industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): (a) At present three automobile ancillary units in the organised sector are closed.

(b) One unit has been closed down due to low off-take of its products, second due to some management problems and third on account of State Government's directive to shift the unit from residential area to Industrial area.

(c) 294 workers have been affected as a result of these closures.

(d) There is no crisis in the industry as such.

राजस्थान में गांवों का विद्युतीकरण

3333. **श्री लालजी भाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में कितने गांवों में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है और कितने गावों में यह चालू किया जाने वाला है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने अब तक राजस्थान की 94 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों में 5186 नए गांवों के विद्युतीकरण की योजना है। इनमें से 31-12-1975 तक 1816 गांव विद्युतीकृत किए गए । शेष गांवों में विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है ।

राजस्थान में और अधिक गांवों के विद्युतीकरण हेतु स्कीमों की स्वीकृति, राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित की गई और निगम द्वारा अपने निर्धारित मानदण्डों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनुमोदित की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की संख्या पर निर्भर होगा ।

Reorganisation of Marketing operation of Coal India Limited

3334. SHRI PRABODH CHANDRA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to reorganise and rationalise the marketing operation of Coal India Ltd.; and

(b) if so, the facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) Yes, Sir.

(b) With a view to giving a thrust to sales and marketing activities, Coal India Limited have decided to reorganise their sales organisation by dividing the entire country into five zones, each allotted to a subsidiary company, as per details given below:—

S. No.	State/Plants	Regional Office & No.	Branch Office
ZONE A: RESPONSIBILITY:		WESTERN COALFIELDS LIMITED NAGPUR	
1.	Madhya Pradesh	Bhopal	Bilaspur
2.	Rajasthan	Bhopal	Jaipur
3.	Gujarat	Bombay	Ahmedabad
4.	Maharashtra	Bombay	—
5.	Andhra Pradesh	Madras	—
6.	Karnataka	Madras	Bangalore
7.	Tamil Nadu	Madras	—
8.	Kerala	Madras	—
ZONE B: RESPONSIBILITY:		CENTRAL COALFIELDS LIMITED RANCHI	
9.	Orissa	Lucknow	—
10.	Bihar	Lucknow	Patna
11.	Uttar Pradesh	Lucknow	Varanasi & Kanpur
2.	Nepal	Lucknow	Patna
ZONE C: RESPONSIBILITY:		EASTERN COALFIELDS LIMITED SANCTORIA	
13.	West Bengal	Calcutta	—
14.	Sikkim	Calcutta	—
15.	Bhutan	Calcutta	—
16.	Assam	Margharita	—
17.	Arunachal	Margharita	—
18.	Bangla Desh	Calcutta	Dacca
19.	Burma	Calcutta	—

S. No.	Plants/State	Regional Office & No.	Branch Office
ZONE D : RESPONSIBILITY:		BHARAT COKING COAL LTD. DHANBAD	
20.	Jammu & Kashmir	Chandigarh	Jammu
21.	Himachal Pradesh	Chandigarh	—
22.	Punjab	Chandigarh	Jullundur
23.	Haryana	Chandigarh	Delhi
24.	Delhi	Chandigarh	Delhi
ZONE : RESPONSIBILITY :		BHARAT COKING COAL LTD. DHANBAD	
25.	Steel Plants and Representative at each Steel Plant. Durgapur Coke Oven Plant		

Each subsidiary company in-charge of a particular zone will act as the lead company for that zone and service the consumers of coal in the zone on behalf of the different subsidiary companies supply coal according to established linkages etc.

Maintenance of G.P.F., Indian Ordnance Factory Workers' Provident Fund Accounts

3335. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there are large number of discrepancies in the maintenance of General Provident Fund and Indian Ordnance Factory Workers' Provident Fund Accounts in respect of the employees working in the office of Assistant Garrison Engineer, Ramgarh Cantt. and Garrison Engineer, Ranchi;

(b) whether Account slips have not been distributed to a large number of employees since 1973;

(c) whether the recovered amount on account of General Provident Fund and Indian Ordnance Factory Provident Fund in respect of employees are being adjusted against their names; and

(d) if not, the action Government propose to take in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

पाकिस्तान तथा बंगलादेश द्वारा सीमा का उल्लंघन

3336. श्री भगीरथ भंवर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश तथा पाकिस्तान ने सीमा के निकट अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं;

(ख) क्या दोनों देशों के सैनिकों द्वारा हाल में अनेक बार सीमा का उल्लंघन किया गया है और यदि हां, तो ऐसी घटनायें कितनी बार घटी और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या दोनों देशों के सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आये थे और हानि पहुंचाई ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सीमा के पार की गतिविधियों के बारे में सरकार उनको सूचित करती रहती है। तथापि, ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

(ख) बंगलादेश के बारे में अप्रैल मास के दौरान (28 अप्रैल तक) सीमा के पार गोली चलाये जाने की चार घटनाएं हुईं जिनमें से दो घटनाएं गम्भीर रूप की थीं। जिनके परिणामस्वरूप व्यक्ति हताहत हुए। इन दो घटनाओं के विषय में भारत सरकार ने बंगलादेश की सरकार को कड़ा विरोध प्रकट किया है।

पाकिस्तान के बारे में उसी मास के दौरान (28 अप्रैल तक); सीमा के पार से गोली चलाई जाने की एक तथा पाकिस्तानी विमानों द्वारा हमारी अन्तरिक्ष सीमा के उल्लंघन की तीन घटनाएं हुईं। भूमि सीमा उल्लंघन के प्रश्न पर हमारे स्थानीय कमांडर द्वारा वहां के कमांडर के साथ विचार किया जायेगा। वायु सीमा उल्लंघन के संबंध में स्विटज़रलैंड दूतावास के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार को विरोध प्रकट किया गया है।

(ग) पाकिस्तानी अथवा बंगलादेश के सैन्य बल द्वारा भारतीय क्षेत्र में हाल ही में घुस आने की कोई सूचना नहीं है।

Funds for development of Road Communication in N.E. Region

3337. SHRI NOORUL HUDA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether as per recommendations of the North Eastern Council, Government have agreed to allot adequate funds for development of road communications in North Eastern Region; and

(b) if so, the amount so far allotted?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) Out of a total outlay of Rs. 100 crores for the Fifth Five Year Plan of North Eastern Council, Rs. 27.00 crores have been earmarked for road communications.

(b) Annual allocations on road communications made so far are as follows:—

	Rs. lakhs
1974-75	300·00
1975-76 and	481·00
1976-77	480·16

Thus, the total allocations made so far amount to Rs. 1261.16 lakhs.

Development Assistance to States

3338. SHRI R. N. BARMAN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating to change the present pattern of giving development assistance to States,

(b) if so, the main difficulties experienced by the States under the present system, and

(c) the new pattern envisaged?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE): (a) to (c). The matter is under examination. Some change is however, being contemplated for providing an incentive to the States to step up the effort in the area of family planning.

Agreement between India and USSR

3339. SHRIMATI ROZA DESHPANDE:
SHRI C. K. CHANDRAPPAN:
SHRI BHOGENDRA JHA:

Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there is a new form of co-operation envisaged in the Indo-U.S.S.R. Protocol which was signed in Moscow recently;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) how far this would improve our economic development?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): (a) and (b). The Protocol of the third meeting of the Inter-Governmental Soviet-Indian Commission on Economic, Scientific and Technical Cooperation signed in Moscow on 5th April, 1976, seeks to give concrete shape to the concept of production cooperation on compensation basis and complementarity of production, between the two countries; this matter had been under discussion between India and USSR for the last 2 or 3 years. These include such proposals as setting up of alumina plant with Soviet investment support to be paid for by export of alumina to USSR 'supply of additional cotton by USSR and counter purchase in India of cotton textiles and cotton yarn of equipment value, production cooperation in the field of certain agricultural produce in India for long term supply to USSR and the supply of heavy engineering equipment to third countries for Soviet assisted projects. The possibility of undertaking jointly civil construction and erection work for turn key projects in third countries was also explored and agreed to

(c) The present composition of our trade with Soviet Union is tilted strongly in favour of traditional commodities. The new form of cooperation will not only introduce much greater diversification in our trade relationship but would be of great mutual advantage considering that we enjoy an advantage in terms of our wide and highly developed industrial base and considering that we have the third largest skilled scientific and technical power in the world. As against this, concentration in the Soviet Union on highly capital intensive technologies for the development of natural resources makes it uneconomical for the Soviet Union to produce same categories of industrial products. The first concrete result of this understanding was an order for electrolysers used in aluminium industry, valued at Rs. 4.2 crores, placed on the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, for supply to a Soviet assisted aluminium plant in Yugoslavia during the deliberations of the Indo-Soviet Joint Commission.

राज्य चिह्न का प्रयोग

3340. श्री चिरंजीव झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ग्राम पंचायतों को लेटर हैड पैड तथा कार्यालय मोहर में राज्य चिह्न (अशोक स्तम्भ) प्रयोग करने का अधिकार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ग्राम पचायतों के निर्वाचित पदाधिकारी भी अपने व्यक्तिगत लेटर हैड पैड पर इस चिह्न का प्रयोग कर सकते है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

Key positions in Newspapers

3341. SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are considering to restrain family members of newspaper owners from holding key positions in the newspapers;

(b) whether profits of the newspapers have been restricted from being used in other business; and

(c) the state of affairs in "Basumati" newspaper after its take-over by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) The Question is concerned with the general issue of the delinking of newspapers from the business houses.

(b) No, Sir.

(c) According to the information given by the Government of West Bengal, the state of affairs in Basumati newspaper has improved considerably after its take-over by the State Government. Its circulation is reported to have gone up from 3500 to about 20,000 copies.

Massive Transfer of Coal Mines

3342 SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there is massive transfer of coal miners;

(b) if so, reaction of Government; and

(c) steps taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD): (a) and (b). There has been no massive transfer of coal miners. Some transfers of under-utilized mine workers for the purpose of rationalising the deployment of labour have been going on as this process is a continuous one and necessary for the optimum efficiency and utilization of labour in an expanding industry in which a large number of new mines are being opened and existing mines developed further, in different parts of the country.

(c) Does not arise.

Employment of Educated Youth in Sixth Plan

3343. SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether there is any target for employment of educated youths in Sixth Plan period; and

(b) what is the present position of unemployment among rural youths, as today?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE): (a) No quantitative target for employment of educated youths in the Sixth Plan period has yet been worked out.

(b) Precise estimates of the extent of unemployment among educated rural youths are not available. However, according to a survey of the registered job seekers conducted by the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour, approximately 16 lakh persons belonging to rural areas who had educational qualifications of matric and above, were registered with employment exchanges as on 30-6-1973. The survey also revealed that bulk of these job seekers were below 30 years of age.

District Correspondents for Radio Stations

3344. PROF NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it has been decided to appoint District Correspondents for Radio Stations in the various States to give wide publicity to the progress and implementation of the 20-point Economic Programme;

(b) if so, the number of Districts in the country which are still without District Correspondents at present and the names of such districts in Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan; and

(c) the likely date by which the appointments would be made in all such districts as have no correspondents at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) It has been decided in principle to have a part-time Correspondent of AIR in each District. The decision will be implemented in phases, subject to availability of funds.

(b) 264 districts are at present without District Correspondents. A statement showing the names of such Districts in the States of Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan is enclosed.

(c) It is proposed to appoint part-time Correspondents in 142 districts shortly. It is not possible to indicate the date by which part-time Correspondent will be appointed in all the Districts.

Statement

DISTRICTS OF HIMACHAL PRADESH, J & K, PUNJAB, RAJASTHAN, UTTAR PRADESH AND HARYANA WHERE AIR HAS NO PART-TIME CORRESPONDENTS

Himachal Pradesh

1. Bilaspur 2. Chamba 3. Kinnaur 4. Lahaul and Spiti 5. Mahasu 6. Sirmaur.

Jammu and Kashmir

1. Anantnag 2. Baramula 3. Doda 4. Kathua 5. Ladakh 6. Poonch 7. Rajauri 8. Udhampur.

Punjab

1. Bhatinda 2. Firozpur 3. Gurdaspur 4. Hoshiarpur 5. Kapurthala 6. Patiala 7. Ropar 8. Sangrur.

Rajasthan

1. Alwar 2. Bangwara 3. Barmer 4. Bharatpur 5. Bhilwara 6. Bundi 7 Chithaurgarh 8. Churu 9. Dungarpur 10. Ganganagar 11. Jaisalmer 12. Jalor 13. Jhalaur 14. Jhunjhunu 15. Kota 16 Nagaur 17. Pali 18. Sawaimadhopur 19. Sikar 20. Sirohi 21. Tonk.

Uttar Pradesh

1. Aligarh 2. Almora 3. Azamgarh 4. Bahraich 5. Ballia 6. Banda 7. Bara Banki 8. Bareilly 9. Basti 10. Bijnor 11. Budaun 12. Bulandshahr 13. Chamoli 14. Deoria 15. Etah 16. Etawah 17. Faizabad 18. Fatehpur 19. Ghazipur 20. Gonda 21. Gorakhpur 22. Hamirpur 23. Hardoi 24. Jalaun 25. Kheri 26. Jaunpur 27. Mainpuri 28. Mathura 29. Meerut 30. Mirzapur 31. Moradabad 32. Muzaffarnagar 33. Pilibhit 34. Pithoragarh 35. Pratapgarh 36. Rae Bareli 37. Rampur 38. Saharanpur 39. Shahjahanpur 40. Sitapur 41. Sultanpur 42. Tehri-Garhwal 43. Unnao 44. Uttarkashi.

Haryana

1. Ambala 2. Gurgaon 3. Hissar 4. Jind 5. Karnal 6. Mahendragarh 7. Rohtak.

Cement Factories in Kangra and Chamba District of Himachal Pradesh

3345. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the rich deposits of lime-stone in Kangra and Chamba districts of Himachal Pradesh;

(b) whether any cement factories are proposed to be located in these two districts; and

(c) if so, the likely date by which the factories would be sanctioned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) Yes, Sir. The State Government have reported that limestone deposits estimated at 18 million tonnes and 300 million tonnes respectively are available in Kangra and Chamba districts of Himachal Pradesh.

(b) A licence was given to the Himachal Pradesh Mineral and Industrial Development Corporation—a State

Government Undertaking—to set up a cement plant for a capacity of 2.00 lakh tonnes at Samloti, district Kangra. The State Government are engaged in detailed investigations of raw material deposits in the area.

(c) No proposal for setting up a plant in either of these districts is pending sanction of the Government of India now.

Loktak Hydel Project

3346 SHRI NOORUL HUDA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state the total estimated cost of Loktak Hydel Project and the amount spent so far?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) The estimated cost of oktak Hydro-electric Project is Rs 50 80 crores for the Stage I and Rs 5 65 crores for the Stage II The amount spent upto the end of March, 1976 was about Rs. 30 00 crores for the Stage I and Rs. 1 02 crores for the Stage II.

पूणे स्थित "नेशनल फिल्म आरकाईव "आफ इंडिया' को सहायता

3347. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पूणे स्थित नेशनल फिल्म आरकाईव आफ इंडिया को दी जा रही वार्षिक राशि घटा कर पांच लाख रुपये कर दी गई है जबकि उसकी वार्षिक आवश्यकता 20 लाख रुपये से भी अधिक है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है,

(ख) आरकाईव में इस समय कितने फिल्म प्रिन्ट हैं; और

(ग) फिल्म प्रिन्टों को एकत्रित करने में क्या-क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पांच वर्ष के लिए 35 लाख रुपये के कुल योजनागत आबटन में से वर्ष 1976-77 के लिए फिल्म सामग्री प्राप्त करने की योजनागत स्कीम के लिए राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का स्वीकृत योजनागत बजट अनुदान 5 लाख रुपये है। योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में 20 लाख रुपये संग्रहालय को पहले ही दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1976-77 के लिए 2 लाख 2 हजार रुपये की गैर योजना मजूरी है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के लिए वर्ष 1976-77 के लिए 7 लाख 2 हजार रुपये की कुल मजूरी पर्याप्त समझी जाती है। अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकताओं का प्रत्येक वर्ष संशोधन प्राक्कलनों के समय पुनर्विलोकन किया जाता है और यदि वृद्धि का औचित्य होता है तो संशोधनों की उपलब्धि पर अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध कर दी जाती है।

(ख) 31 जनवरी, 1976 के दिन की स्थिति के अनुसार; 878 भारतीय फिल्में (726 फीचर और 152 लघु) और 493 विदेशी फिल्मे (332 फीचर और 161 लघु) संग्रहालय द्वारा प्राप्त की जा चुकी थी।

(ग) फिल्मो की प्रिंटें प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली मुख्य कठिनाइयां संसाधनों की कमी और उन फिल्मों, जिनकी मिल्कियत विवादास्पद होती है या जिनके मालिकों का पता नहीं होता, के बारे में कापीराइट संबंधी पेचीदगियां रही हैं।

मध्य प्रदेश से विचाराधीन पड़े आशय-पत्र

3348. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से औद्योगिक पूंजी निवेश के कितने आशय-पत्र विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख). कैलेन्डर वर्ष 1974 और 1975 की अवधि में उद्योगों के मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने के लिए 94 आशय पत्र जारी किये गये थे। जारी किये गये आशय पत्र की प्रारम्भिक वैधता अवधि एक वर्ष होती है तथा पर्याप्त औचित्य दिखाये जाने पर प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा यह अवधि और भी 6 से 12 महीनों तक बढ़ायी जा सकती है। वैधता की अवधि में आशय पत्र धारी से यह आशा की जाती है कि वह सरकार के विचारार्थ तथा स्वीकृति के लिए आशय पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार अपेक्षित विदेशी सहयोग, पूंजीगत माल के आयात आदि के लिए अपने प्रस्ताव पेश करेगा। आशय पत्र धारी द्वारा आशयपत्र में अपेक्षित सभी आवश्यक अनुमतियां मिल जाने के बाद आशय पत्र को एक औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया जाता है। सामान्यतया लाइसेंस धारी को 2 वर्षों की अवधि दी जाती है कि वह लाइसेंस शुदा क्षमता स्थापित कर लेगा और उत्पादन प्रारम्भ कर देगा। उचित मामलों में जहां लाइसेंस धारियों को औद्योगिक क्षमताएं स्थापित करने में व्यावहारिक कठिनाइयां का अनुभव होता है उनमें प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा और भी एक से दो वर्षों की अवधि बढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है। अपवाद स्वरूप प्रकरणों में 4 वर्षों से अधिक की अवधि के अनुरोध पर भी विचार किया जाता है। उन प्रकरणों में जिनमें आशय पत्र धारी आशय-पत्र की शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तथा औद्योगिक लाइसेंसधारी वैधता की अवधि में क्षमता स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने में असफल होता है, तो आशय पत्र व्यपगत हो जाता है अथवा वह रद्द कर दिया जाता है तथा औद्योगिक लाइसेंस रद्द अथवा प्रतिसंहृत कर दिया जाता है।

Activities of Swiss Aid Abroad Organisation

3350. SHRI SHASHI BHUSHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that certain persons of Gujarat were paid money in lakhs by the Swiss Aid Abroad for School building and that money was utilised by them for political gains;

(b) if so, (i) since when Swiss Aid Abroad has been functioning in Gujarat; (ii) names of the persons to whom the money was paid; (iii) how much and when Swiss Aid Abroad paid the money to Gujarat Vidyapith; and

(c) whether Swiss Aid Abroad is a voluntary organisation or a Government organisation and the reaction of Government towards the activities of this organisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) (a) According to information received from the Government of Gujarat, Rs 2,50,000 were paid in 1968 by the Swiss Aid Abroad to Shri Lalbhai D. Naik of Navsari for the construction of an Ashram building at village Ambheti, taluka Dharampur,

district Valsad. During 1972-73, Rs. 9,80,000 were paid by Swiss Aid Abroad to Shri Babubhai J. Patel, the President of Bhartiya Uttar Buniadi Trust at village Agashi, district Bulsar, for the construction of Bhartiya Uttar Vidyalaya and its hostel.

(b) (i) No branch of Swiss Aid Abroad is functioning in Gujarat.

(ii) The same as (a) above.

(iii) In the year 1969-70 and 1972-73 Ambheti Gram Sewa Kendra received an amount of Rs. 2,84,000 from Swiss Aid Abroad for the development of Buniadi Vikas. Gujarat Vidyapith is looking after this Kendra besides other Gram Sewa Kendras in Gujarat.

(c) According to the information available, Swiss Aid Abroad is a voluntary organisation.

Non-payment of Dividend by Sugar Factories in Maharashtra to Government

3351. SHRI SHANKERRAO SAVANT: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether several cooperative sugar factories in Maharashtra have not paid dividend to Government for the share capital contributed by it;

(b) if so, which are those factories and the amount of dividend due from them during the last three years; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to recover these amounts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES. (SHR A. C. GEORGE): (a) to (c). The cooperative sugar factories in Maharashtra Government on the share capital contributed by it at rates varying from 3 per cent to 6 per cent as prescribed in June, 1966, by the High Level Ministerial Committee presided over by the Chief Minister. The cooperative factories were declaring dividend on Government's shares till 1969-70. The cooperatives which were in arrears in payment of dividend on Government's share capital from 1965-66 till 1969-70 paid the arrears during 1970-71 to 1974-75. When the purchase tax on cane was increased from 1st October, 1971, the State Government decided not to insist on payment of dividend on Government share capital. The purchase tax was increased from Rs. 5 to Rs 7.50 per tonne of cane with effect from 1st October, 1971 and again to Rs. 16 60 with effect from 4-11-74. In view of this position, none of the cooperative sugar factories in Maharashtra declared dividend during the last 3 years namely 1972-73, 1973-74 and 1974-75

Use of Indian made liquors at receptions/dinners hosted by heads of various departments of Central Government

3352 SHRI RAM PRAKASH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to serve Indian made liquors at receptions/dinners hosted by heads of various Departments of Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): No, Sir. It is the normal practice, except on special occasions when foreign delegations are the guests, not to serve any liquor at receptions or dinners hosted on behalf of Government Departments.

Use of imported raw material

3353. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government have created a separate unit for keeping a watch on how imported raw materials are used; and

(b) if so, the faits thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) No, Sir. There is no decision to create a separate unit for keeping a watch on how imported raw materials are used.

(b) Does not arise.

Capital Punishment

3354. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether Government propose to discontinue capital punishment in the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): There is no proposal to discontinue capital punishment altogether. The attention of of the Hon'ble Member is invited to the provisions of the Indian Penal Code (Amdt.) Bill 1972 as reported by the Joint Committee.

Survey of Jodhpur and other districts in Rajasthan

3355. SHRI RAJDEO SINGH: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether a joint survey was recently conducted of Jodhpur district in Rajasthan by the Reserve Bank of India and the Industrial Development Bank which revealed big industrial Development prospects; and

(b) whether other districts in Rajasthan and other States were also surveyed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHR B. P. MAURYA): (a) A joint survey of Jodhpur district in Rajasthan was conducted by Study Team comprising officials of Reserve Bank of India and Industrial Development Bank of India in April, 1972, with a view to making an intensive study of the potential for small-scale industries and indentifying specific projects for development in the small sector. The survey indentified 29 industrial projects for development.

(b) District surveys are also conducted by the Small Industries Development Organisation (Government of India), State Government, State-level financial agencies as also the lead banks under the Lead Bank Scheme. District surveys have been completed of 22 districts in Rajasthan by various agencies.

Solar-powered Electric commuter car designed by Australia

3356. SHRI RAJDEO SINGH: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that two Australian inventors have designed successfully a solar-powered electric commuter car powered by four individual printed armature servo motors fitted into the hub of each wheel according to the Australian Information Service Press release;

(b) if so, the other facts thereof; and

(c) whether our Solar scientists too are experimenting on these lines?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): (a) Government have come across a Press Report to this effect.

(b) No other details excepting those appearing in the Press are available with Government.

(c) No, Sir.

(c) No, Sir.

हिन्दी फिल्मों के पूर्व विवरण का हिन्दी में होना

3357. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी फिल्मों के विवरण जो चलचित्र के पहले दिखाये जाते हैं अक्सर अंग्रेजी में होते हैं, और

(ख) क्या सरकार ऐसा निर्देश देगी कि उनके पूर्व विवरण भी हिन्दी में हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इस प्रकार का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। तथापि, सरकार का यह मत है कि मुख्य नामोल्लेख अवश्य ही उस भाषा और लिपि में दिखाए जाने चाहिए जो फिल्म की भाषा हो। इस मामले में फिल्म उद्योग के साथ बातचीत की जायेगी।

Utilisation of Paper Machinery Producing Plants

3358 SHRI N. E HORO: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the names of industrial houses which own large scale paper machinery producing plants and the number of plants owned by each house;

(b) the production capacity and their actual utilization of these plants; and

(c) the number of small scale paper industries being set up during the current financial year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): (a) Larsen & Toubro Ltd. and Utkal Machinery Ltd., both registered under the MRTP Act, own undertakings for the manufacture of large scale paper machinery.

(b) The production capacities for the two are Rs. 250 lakhs and Rs. 500 lakhs per annum respectively at current prices. Their actual production during 1975 has been Rs. 45 lakhs and Rs 3251 lakhs. In the year 1976, their production is expected to be Rs 100 lakhs and Rs 350 lakhs respectively The capacity utilization has, therefore, been of the order of 50-60 per cent.

(c) As the cost of even the smallest plant will be more than Rs. 10 lakhs, it is not possible to organize these units in the small scale sector

Rural Electrification in Bihar

3359 SHRI N E HORO. Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the percentage of rural population in Bihar which is covered by the rural electrification schemes sanctioned by the Rural Electrification Corporation,

(b) whether any preference has ben given to any set of population particularly Scheduled Castes/Scheduled Tribes; and

(c) steps being taken under the 20-Point Programme to boost up rural electrification in that State?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD): (a) About 11.6 per cent of the rural population will receive the benefit of electricity on completion of the rural electrification schemes sanctioned by the Rural Electrification Corporation Ltd.

(b) The Corporation has been giving special consideration to rural electrification projects pertaining to relatively backward areas including areas inhabited by tribal population. Loan assistance is being sanctioned for the projects relating to these areas on comparatively softer terms and conditions.

While sanctioning rural electrification projects for financial assistance, the Corporation ensures that wherever the main villages are included for the purpose of providing street lights, the adjoining Harijan Bastis are also invariably covered for this purpose.

(c) Bihar is one of the backward States in the matter of rural electrification. A number of steps have been taken to accelerate the rural electrification programme in the State.

With a view to reducing the regional imbalances, the rural electrification has been taken up as a part of the Minimum Needs Programme (MNP) in the Fifth Plan. Besides Rs. 15 crores under the normal development programme of State, Rs. 45 crores have been provided for rural electrification works in the State under the MNP The terms, conditions and viability criteria for loan assistance under this programme have been specially liberalised. On the implementation of this programme, it is expected that about 40 per cent of the rural population in the State will be covered by electricity.

The Corporation has opened a regional office in Patna to have a closer association with the State Electricity Board and render necessary assistance and guidance to it in the formulation of rural electrification programme. This will enable the State Electricity Board to formulate more viable rural electrification projects expeditiously for consideration by the Corporation and will also help in the accelerated implementation of the sanctioned schemes.

Public Sector Projects in Maharashtra

3360. SHRI SHANKARRAO SAVANT: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) which public sector projects are under construction in Maharashtra;

(b) the estimated cost and the production potential of each of them; and

(c) the progress of each of them and the time by which they are expected to be commissioned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Government Decision on Application of Coca Cola Export Corporation under Foreign Exchange Regulation Act

3361. SHRI C. K CHANDRAPPAN:
SHRI H. N. MUKERJEE:

Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government could not communicate their decision on the application of the Coca Cola Export Corporation under the Foreign Exchange Regulation Act although it had applied in June 1974; and

(b) if so, the reason that had prevented Government from communicating their decision on the application of the party and facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): (a) and (b). The application of the Coca Cola Export Corporation under the Foreign Exchange Regulation Act is under consideration of the Reserve Bank of India.

Alleged fraud to Accounts of Khadi and Gramodyog Board, Kanpur

3362. SHRI C K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is allegation of fraud against Khadi Board;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action taken against those who are responsible for Rs. 70 lakh fraud in the accounts of Khadi and Gramodyog Board, Kanpur in June 1974?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. P. SHARMA): (a) to (c). According to information furnished by the Khadi and Village Industries Commission, the statutory audit report revealed an embazzlement in the Khadi Board, Kanpur. The amount involved is reported to be around Rs. fifty-six thousand. It has been indicated that police investigation and departmental enquiry are under progress and the Board is taking appropriate action against the concerned persons.

Visit of Scientists from West Germany for setting up a Solar Energy Project in India

3363. SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA:
SHRI K. MALLANNA:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether any team of leading scientists from West Germany visited India in April, 1978 to establish a solar energy project in India; and

(b) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE) : (a) and (b). A two-member team visited the National Physical Laboratory, Delhi; Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar; and Birla Institute of Technology and Science, Pilani. The presence of the team was utilised for formulating projects on solar energy devices to be taken up on a bilateral basis between Indian and German institutions.

Survey of Coal Mines to identify Economically Unsound and Unsafe Mines

3364. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether surveys have been conducted to identify such of the coal mines which have become economically unsound and/or unsafe for further operations;

(b) if so, the full facts thereof; and

(c) action proposed to be taken in regard to such mines?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Closure of Small Units

3365 SHRI VEKARIA:
SHRI ARVIND M PATEL:

Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the number of small scale industrial units which closed down since 1974 onwards, State-wise;

(b) the reasons for their closure; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to restart them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. P. SHARMA): (a) The national census of small scale industries conducted in 1973-74 showed that the cumulative figure of industries closed up to 1972 was 66,161. The state-wise figures are given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-10785/76].

(b) and (c). With a view to taking remedial action to assist closed and sick units in the small scale sector, a sample survey in a few selected industrial areas was taken up recently. These sample surveys indicated that the percentage of closed units in the small scale sector was less than one. The main reasons for their closure were lack of demand and defective financial management. In consultation with the banks, remedial action has been taken in respect of closed units and sick units. The State Governments have been advised to set up review committees with representatives of the banks so that advance remedial action is taken. The position will be reviewed by the Small Industries Development Organisation after the periodical reviews of the State Level Committees.

Pricing of the Products of Defence Public Undertakings

3366. SHRI B. V. NAIK: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the basis on which the aircraft, helicopters and other accessories produced in the defence public sector undertakings, where the production is monopolised, are priced when they are sold to the army or the navy or the air force; and

(b) whether the sale price is determined by international prices or the cost of production or on an 'ad hoc' basis?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI VITHAL GADGIL): (a) and (b). The prices for aircraft, helicopters and other equipment manufactured by defence public sector undertakings for the armed forces are determined in most cases on the basis of the estimated cost of production which are closely scrutinised by Government. In cases where estimates of cost are difficult to determine in advance the prices are based on actual cost of production. A reasonable profit margin is allowed on the manufacturing cost to enable the undertakings to generate internal resources for re-equipment, growth and research and development activities.

Power Supply to Calcutta Electric Supply Corporation

3367. DR. RANEN SEN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether public sector agencies in West Bengal are continuing to increase their supplies to Calcutta Electric Supply Corporation;

(b) if so, the facts thereof for the last three years and the rates at which it is given to CESC;

(c) whether Government have a proposal to nationalise the CESC; and

(b) if so, the facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD): (a) and (b). The West Bengal State Electricity Board and the Damodar Valley Corporation are supplying power to the Calcutta Electric Supply Corpora-

tion. The West Bengal State Electricity Board supplied power to the Calcutta Electric Supply Corporation as follows:

Year	Energy supplied	Tariff
1973-74 . . .	1026 MU	Rs. 15/- per KVA per month plus 4·2 paise per unit of energy plus fuel surcharge of 2·733 paise per unit.
1974-75 . . .	824 MU	Rs. 15/- per KVA per month plus 4·2 paise per unit of energy plus fuel surcharge of 4·706 paise per unit.
1975-76 . . .	888 MU	Rs. 19/- per KVA per month plus 5·3 paise per unit of energy plus fuel surcharge of 5·75 paise per unit.

The DVC supplied power to Calcutta Electric Supply Corporation as under :

Year	Energy supplied	Tariff
1973-74 . . .	478·63 MU	paise 8·477 per kwh.
1974-75 . . .	631·74 MU	paise 12·075 per kwh.
1975-76 .	figures are not readily available.	paise 15·715 per kwh.

(c) and (d) The Calcutta Electric Supply Corporation holds a licence under the Indian Electricity Act, 1910 for generation and supply of electric power in Calcutta and surrounding areas. The State Governments have the power to make alterations and amendments in the terms and conditions of the licence and recently they have extended the licence upto 2000 AD.

आगामी तीन वर्षों में भारतीय उपग्रह को पृथ्वी-कक्षा में स्थापित करना

3368. श्री चिरंजीब झा :

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों में भारतीय उपग्रह स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी कक्ष में एक भू-प्रेक्षण संबंधी उपग्रह स्थापित करने की योजना बनाई है, जो कि अधिक जटिल नीतभार, दत्त प्रबंध और नियंत्रण प्रणाली सहित, वस्तुत आर्यभट्ट का रूपान्तरण है। इस उपग्रह का भार 400 किलोग्राम से कुछ अधिक होगा और यह दो दूरदर्शन कैमरे और माइक्रोवेव रेडियोमीटर संबंधी नीतभार ले आयेगा। इससे कुल लक्षणों का फोटोचित्रण और सुदूर संवेदन संभव होना चाहिये, जो कि वानिकी, जीवभारों के अध्ययन, जल-विज्ञानीय लक्षणों इत्यादि पर लागू होगा। इस उपग्रह के 1978 में किसी समय छोड़ जाने की संभावना है।

विकासाधीन अन्य उपग्रह रोहिणी उपग्रह है, जिसका भार 40 किलोग्राम के लगभग होगा। यह उपग्रह मद्रास के निकट श्रीहरिकोट

से भारत में निर्मित एस०एल०वी०-3 नामक उपग्रह प्रक्षेपक राकेट की सहायता से छोड़ा जायेगा। यह उपग्रह वस्तुतः प्रक्षेपक राकेट के कार्य-निष्पादन की जांच के लिये प्रौद्योगिकीय नीतभार ले जायेगा। इसके 1978 के अन्त तक छोड़ जाने की संभावना है।

दूरदर्शन और दूर-संचार के लिये भारतीय उपग्रह के बारे में सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

नेपाल के साथ पन-बिजली परियोजनाओं के लिए बातचीत

3369. श्री चिरंजीव झा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के साथ अनेक पन-बिजली परियोजनाओं के लिये और भारत-नेपाल सीमा के क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई के बारे में बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). इस समय नेपाल के साथ निम्नलिखित जल-विद्युत् परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया जा रहा है :

(1) करनाली जल-विद्युत् परियोजना : इस परियोजना पर आगे अनुसंधान करने के कार्य में भारत को भी शामिल किया गया है। इस परियोजना से 1800 मेगावाट बिजली पैदा होने की संभावना है। इस बात पर भी समझौता हो गया है कि नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा स्थापित करनाली कार्यपालिका बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व होगा।

(2) पंचेश्वर जल-विद्युत् परियोजना : इस परियोजना संबंधी अनुसंधानों का निर्देशन करने के लिए विशेषज्ञों का एक संयुक्त दल बनाने के बारे में सहमति हो गई है।

(3) देवीघाट जल-विद्युत् परियोजना : इस परियोजना से नेपाल को 14 मेगावाट बिजली मिलेगी।

(4) राप्ती पर एक बहुउद्देश्यीय परियोजना की संभावना पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों के एक संयुक्त दल की बैठक होगी।

(5) भारत-नेपाल सीमा पर बिजली की सप्लाई के बारे में, विनिमय की वर्तमान मात्रा को 5000 किलोवाट से 25000 किलोवाट के स्तर तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बिहार के सहरसा जिले के गांवों में बिजली की सुविधा

3370. श्री चिरंजीव झा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 तक बिहार के सहरसा जिले में कितने गांवों मे बिजली लगाई गयी; और

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान कितने गावों में बिजली लगाये जाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मार्च, 1976 तक सहरसा जिले मे 267 गांव विद्युतीकृत किये गये थे।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 1976-77 के दौरान सहरसा जिले के 172 गावो को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

Reappraisal of Concept of Backward Areas

3371 SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Planning Commission is considering a proposal to have a close look and a realistic and factual reappraisal of the prevailing concept of backward areas, and

(b) if so, the change in the concept envisaged?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE): (a) and (b). Various issues relevant to the development of Backward Areas are being examined by a Committee. The report of this committee is awaited.

Demand for better conditions of Service by Members of U P S C.

3372. SHRI VASANT SATHE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether members of the Union Public Service Commission have demanded better conditions of service;

(b) if so, nature of demands made; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): (a) Yes, Sir.

(b) The demands relate to enhancement of salaries, retirement benefits and other conditions of service, like rent free accommodation, conveyance allowance etc.

(c) The demands are being examined.

Task Force to use rated capacity of Wagon Units

3373 SHRI SAKTI KUMAR SARKAR:

SHRI VASANT SATHE:

Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether his Ministry has formed any task force to use the rated capacity of the wagon units;

(b) whether the units are not utilising its rated capacity;

(c) if so, the capacity and the production of these units during the last three years, year-wise and unit-wise; and

(d) action taken so far to utilise these units fully?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): (a) The Ministry has constantly been engaged in the task of optimising utilisation of capacity.

(b) There is yet sizeable underutilisation of capacity.

(c) The installed capacity and the actual production of these units during the last three years, is given below:

Name of Unit	Capacity in terms of 4-wheelers	Production in terms of 4-wheelers		
		1973-74	1974-75	1975-76
Arthur Butler & Co. Ltd.	1000	..	8	112·0
Bridge & Roof Co. Ltd.	785	421·3	363	300·0
Britannia Engg. Works	1500	..	122·5	207·5
Braithwaite & Co. (I) Ltd.	3000	1761·5	1365	1856·0
Burn & Co. Ltd.	4500	22·5	345	1007·5
Cimmco Ltd.	2000	2867·9	2064	2392·5
Hindustan General Industries	1000	442·3	291	266·0
Indian Standard Wagon Co. Ltd.	3911	82·5	30	700·0
Jessop & Co. Ltd.	3279	680	504	295·0
K. T. Steel Industries (P) Ltd.	240	..	..	..
Modern Industries	2000	447·5	548·5	528·5
Southern Structurals Ltd.	1000	353	217·5	47·5
Texmaco	3600	3200·8	3428	3264·00
	27815	10279·3	9286·5	10976·5

(d) The following steps have been taken to ensure progressive step-up in capacity utilization:—

(i) Orders have been placed for 15,555 wagons in terms of four wheelers.

(ii) Efforts are being made to achieve inter-complementarity and cost rationalization through phased manufacture of components in wagon manufacturing units.

(iii) Serious efforts have been mounted for export of wagons.

(iv) Product-mix of the wagon units is being diversified with encouraging success. A study to prepare a blueprint for a market-oriented product diversification in units in the Eastern region has been commissioned.

Issue of Licences for Manufacture of Electronic Equipment

3374. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state the total number of applications received for licences for manufacture of electronic equipment and the total number of licences issued during the last three years?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF PLANNING, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI): 129 applications for the manufacture of electronic equipment were received over the last three calendar years (1973, 1974 and 1975). Out of these, 55 letters of intent have been issued (including 13 which have been converted into Industrial Licences); 70 applications have been rejected

and 4 cases are pending on account of Monopolies Restrictive Trade Practices clearance.

मध्य प्रदेश के इंदौर डिवीजन में ग्रामीण विद्युतीकरण

3375. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर डिवीजन में प्रत्येक जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) मध्य प्रदेश के इन्दौर डिवीजन मे ग्राम विद्युतीकरण के लिए निगम ने 1729 908 लाख रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकारहै —

क्रम स०	जिले का नाम	स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रुपया में)	वितरित किए गए ऋण की राशि (लाख रुपया मे)
1	इन्दौर	127 940	84 355
2	देवास	110 780	55 765
3	धार	154.960	75.606
4	झबुआ	108 546	56 343
5.	खडवा	374 530	72 660
6	खरगोन	232 093	147 870
7	मन्दसौर	283 590	132 490
8.	रतलाम	79 989	49.629
9.	उज्जैन	257.480	201 090
		1729.908	875 808

मध्य प्रदेश में बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में हानि

3376. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1974-75 से अब तक बिजली की कमी के कारण उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में औद्योगिक उत्पादन कितना कम हुआ है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) केवल बिजली ही की कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है क्योंकि हानियां सामान्यतया अनेक बाधाओं यथा, आयतित और देशी कच्चे माल की कमी, पर्याप्त मात्रा में फरनेस आयल का न मिलना, वित्त की कमी, मदी माग, श्रमिक विवाद आदि के कारण हुई है।

Services of Army Engineers for constructing a Bridge over River Beas

3377 SHRI N. K SANGHI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the services of army engineers were requested for constructing a bridge on river Beas; and

(b) if so, to what extent the work of constructing the bridge has been completed and the expenditure involved therein?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI BANSI LAL): (a) Yes, Sir.

(b) The bridge was completed and opened for traffic on the 5th January, 1976. This is only a temporary bridge which has been loaned by the Army and the cost of its erection is negligible.

Discrimination between Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Reservation of Services

3378. SHRI N. K. SANGHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a member of Scheduled Caste in one part of India gets the same benefits of reservation of service as another in other parts of the country;

(b) whether the same principle does not apply to Scheduled Tribes and the persons of the same origin may be declared a tribal in one State but not so in another;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether during the last 25 years with Government's assistance, members of Scheduled Caste have progressed much more than Scheduled Tribes; and if so, what steps are being taken to remove this anomaly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): (a) to (c). The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, made by the President in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 341 and clause (1) of Article 342 of the Constitution of India, specify the castes, races tribes, communities etc. which are to be deemed as Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, with reference to the various States and Union Territories of India. Any person declared to be a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in accordance with the provisions of those Orders enjoys the same benefits throughout the country, insofar as reservations to Central Government posts or services, or concessions in the matter of appointment to such posts or services, are concerned.

(d) In regard to the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services and posts under the Central Government, over the decade from 1965 to 1975, for which relevant data is available, the proportionate increase during the above ten year period, in terms of number of employees of Scheduled Tribes has been higher than in the case of Scheduled Castes.

Use of Special Ammunition to Control Violent Mobs

3379. SHRI R. S. PANDEY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether State Governments have been asked to favour use of special riot guns, launchers and rubber bullets to control violent mobs;

(b) if so, the reaction of State Governments thereto; and

(c) whether Centre has to provide these items to the States?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) No Sir Only field trials by a few select Police Forces have been authorised.

(b) Does not arise.

(c) The supply of these items is being arranged by the Centre.

National Seminar on Energy

3380. SHRI P. GANGA REDDY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether a national seminar on energy was recently held in Hyderabad; and

(b) if so, the conclusions of the seminar?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT): (a) The Administrative Staff College of India and the Institute of Asian Studies had organised a 'National Seminar on Energy' in Hyderabad from 5th to 7th March, 1976.

(b) The main recommendations of the Seminar are summarised in the attached statement.

1. Government should adopt a national energy policy based on the objectives of:

(a) increasing the energy production and consumption to ensure economic growth and improvement in living standards.

(b) supplying energy on a priority basis to the lowest economic strata of the population to improve living standards.

(c) rational and equitable distribution of energy in different parts of the country and for use by different sections of society.

(d) conservation of energy

2. The Government should organise nation-wide surveys of energy production and consumption patterns and a proper information and monitoring system.

3. Hydro-Electric potential in the country should be developed rapidly through both major and micro hydel schemes.

4. Use of oil for heating purposes in industry should be avoided as far as possible. Substitution in favour of coal, specifically the low grade variety, should be encouraged wherever technically and economically feasible.

5. The forest area in the country should be increased to 30 per cent by planning quick-growing trees

6. The transportation system in the country should be reoriented with emphasis on mass transportation system, particularly in the rural areas, and accelerated development of river and coastal transportation.

7. Installation of gobar gas plants should be accelerated.

8. G&D activities in the fields of coal gasification and application of solar energy and development of tidal, wind and geothermal power should be stepped up with special emphasis on development of solar energy.

9. Activities relating to oil exploration should be stepped up. As we may have to depend on outside sources for oil supplies, the international trade should bt oriented to building a mutuality of interest with countries that supply us oil.

10. Environmental impact of energy consumption and production should receive adequate attention

11 Proper institutional arrangements should be made to enable formulation of energy policy and its guidance on desired lines.

Use of Trade Mark of Coca Cola Company, U.S.A.

3381. DR. RANEN SEN: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state

(a) whether there is a condition in the franchise agreement between Coca Cola Export Corporation and the Bottlers in India that the Coca Cola Company, U.S.A. allow the use of trade mark to the company only when they buy material from the nominee of the Coca Cola Company, U.S.A.; and

(b) if so, whether this direct or indirect consideration is for use of trade mark?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): (a) and (b). Yes, Sir.

Production and Supply of Coal

3382. DR. RANEN SEN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether a committee has been set up by the Government to make comprehensive examination of the problems connected with the production and supply of coal of the required quality to consumers;

(b) if so, facts thereof;

(c) whether Government have received any complaint from Railways regarding the quality of coal supplied to them; and

(d) if so, the facts thereof and Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI SIDIHESHWAR PRASAD): (a) and (b). Yes, Sir. In pursuance of the recommendation made by the Public Accounts Committee in their 154th Report (1974-75) a ten-member-committee has been set up to examine comprehensively the problems connected with production and supply of coal of the required quality to the various consumers including the Railways. The committee has been asked to submit its report to the Government by the 31st August, 1976.

(c) and (d). Some complaints have been received for time to time from the Railways regarding supply of inferior quality of coal. For ensuring supply of coal of appropriate quality the programme for supply to the Railways is drawn up every month by the Chief Mining Adviser, Railway Board, Dhanbad, in consultation with Coal India Limitd. Apart from the normal precautions taken by the supplying collieries at the time of loading, the Railway Board have an inspection wing for ensuring proper loading. Frequent checks aee made by the quality control Department of the Coal India Limited to ensure that the loading of coal is of appropriate quality. Several coal handling and beneficistion plants are being put up by Coal India Limited at pit-heads to ensure supply of coal of appropriate size and quality to consumers, including the Railways.

Press Trips by P.I.B. to Development Projects

3383. SHRI TUNA ORAON:

SHRI SAKTI KUMAR SARKAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether P.I.B. in consultation with the various Ministries organised Press trips to various development projects in the country;

(b) whether in most of the press trips correspondents of the metropolitan English news papers were always taken; and

(c) the action being taken by P.I.B. to encourage the out station language dailies' correspondents to write on various development projects in the country to contribute to national integrity and curb parachialism?

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir

(b) Correspondents of metropolitan English papers as well as correspondents of out-station language dailies were included in the press tripes organised by Press Information Bureau.

(c) In addition to participation in press trips organised by Press Information Bureau, arrangements are made by Press Information Bureau to facilitate trips of representatives of out station language papers to individulal projects on their request. Press materials, special features and photographs on various development projects are also supplied by Press Information Bureau to these papers.

Assistance to Small and Medium Newspapers by Newspaper Finance Corporation

3384. SHRI TUNA ORAON: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Newspaper Finance Corporation is giving financial help to small and medium newspapers; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA). (a) There is no such corporation

(b) Does not arise

Short Supply of Electricity to Steel Plants

3385 SARDAR SWARN SINGH SOKHI Will the Minister of ENERGY be pleased to state

(a) whether the Public and Private sector Steel Plants, including mini Steel Plants have made complaints recently about shortage of the electric power; and

(b) if so, steps Government propose to take to solve their problems in national interest?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDESHWAR PRASAD): (a) and (b) In so far the integrated steel plants in the public and private sectors are concerned, no shortage of power has been reported in the recent past except in the case of the Durgapur Steel Plant and the Alloy Steels Plant, Durgapur There was shortage of power supply to these units in April 1976, following forced outages of certain generating units in the DVC system. Remedial steps have been taken resulting in a marked improvement in the position of power supply which is expected to be entirely normal very soon.

No complaints have been received recently from mini steel plants in regard to shortage of power.

Dynamite Sticks unearthed in Orissa

3386 . SARDAR SWARN SINGH SOKHI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether one hundred or more dynamite sticks were unearthed in Orissa, recently;

(b) whether any of the Government officials was involved in stealing, or supplying the same to unauthorised persons;

(c) the circumstances under which the licence, if any, was issued;

(d) whether there was hand of any political party with ulterior motive; and

(e) if so, the steps Government propose to take to check such recurrences in future?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H MOHSIN): (a) to (e). The information from the State Government is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt

दानापुर छावनी में पेय जल का अभाव

3387. श्री रामावतार शास्त्री क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी के निवासियों में पेय जल के अभाव के कारण भारी असन्तोष है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) और (ख) दानापुर छावनी में सभी क्षेत्रों को पेय जल मिल रहा है परन्तु जल की सप्लाई 9 1/2 घंटे प्रति दिन तक सीमित है। जल सप्लाई सुधार करने के लिए 2.55 लाख रुपए का विशेष सहायता अनुदान हाल में स्वीकृत किया गया है।

सेवा संबंधी मामलों के लिये प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना

3388. श्री के० एम० "मधुकर": क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासकीय न्यायाधिकरण की स्थापना करके सेवा संबंधी मामलों को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक, सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख): मामला विचाराधीन है, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Court Martial of Officers in Defence Services

3389. SHRI BIRENDER SINGH RAO: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of cases involving officers of the rank of Colonel and above in the Army and equivalent ranks in the Navy and Air Force in which Court Martial has been held in each of the three services during the last three years; and

(b) the number of officers convicted and acquitted, separately, in the Army, Navy and Air-Force in the above cases?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI BANSI LAL):

(a) Army		5
Navy		2
Air Force		1
(b)	*Acquitted*	*Convicted*
Army	1	2
Navy	..	2
Air Force	1	..

2 cases relating to the Army are pending confirmation by the Chief of the Army Staff.

Charges of Corruption against Chief Minister of Karnataka

3390. SHRI MURASOLI MARAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the memorandum alleging corruption and other charges signed by the Congress and other Opposition members against the Chief Minister of Karnataka is still under the consideration of Government; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): (a) and (b). Some memoranda containing allegations of corruption, misuse of power, etc., against the Chief Minister and other Ministers of Karnataka were submitted by some MLAs of the State to the Prime Minister in 1973. These memoranda contained 99 allegations, 16 of which concerned the Chief Minister and the remaining concerned the other Ministers of the State Government.

In accordance with the settled procedure, comments of the Chief Minister were invited on these allegations. Clarifications were also obtained on some points arising out of the comments received. After examination of the matter, the allegations against the Chief Minister were found to lack substance.

Certain other allegations against the Chief Minister made by a few Members of Parliament were also received. These are being examined in accordance with the settled procedure.

12 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

REVIEWED AND ANNUAL REPORT OF MINING AND ALLIED MACHINERY CORPORATION LTD., DURGAPUR FOR 1974-75 WITH AUDIT REPORT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Review by the Government on the working of the Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur, for the year 1974-75.

(ii) Annual Report of the Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur, for the year 1974-75 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library*. *See* No. LT-10779/76]

NOTIFICATION RE. GOVERNMENT CONTROL OVER MANAGEMENT OF M/S. BRAITHWAITE AND CO. (INDIA) LTD., CALCUTTA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 170(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 5th March, 1976 regarding the continuance of control over the management of Messers Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta, under sub-section (2) of section 18A to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. [*Placed in Library*. *See* No. LT-10780/76]

TAMIL NADU GENERAL CLAUSES (AMENDMENT) ACT, 1976

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. V. A SEYID MUHAMMAD): I beg to lay on the Table a copy of the Tamil Nadu General Clauses (Amendment) Act, 1976 (Hindi and English versions) (President's Act No 12 of 1976) published in Gazette of India dated the 17th April, 1976, under sub-section (3) of section 3 of the Tamil Nadu State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1976. [*Placed in Library*. *See* No. LT-10781/76]

REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1973-74

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1973-74, under article 338(2) of the Constitution. [*Placed in Library*. *See* No. LT-10782/76]

BUDGET ESTIMATES OF DAMODAR VALLEY CORPORATION FOR 1976-77 AND INDIAN ELECTRICITY (AMENDMENT) RULES, 1975

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दानोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दानोदर घाटी निगम के वर्ष 1976-77 के बजट प्राक्कलन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[*Placed in Library. See* No. LT-10783/76].

(2) भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय विद्युत् (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 527 में प्रकाशित हुए थे ।

[*Placed in Library. See* No. LT-10784/76].

ELECTION TO COMMITTEE

COIR BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. P. SHARMA): I beg to move:

"That in pursuance of sub-rule (1) (e) of rule 4 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of Coir Board for a term to be specified by the Central Government."

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-rule (1) (e) of rule 4 of the Coir Industry Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct two members from among themselves to serve as members of the Coir Board for a term specified by the Central Government."

The motion was adopted.

12.03 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS 1976-77—*Contd.*

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture and Irrigation. The time allotted is 16 hours of which 9 hours 10 minutes have been taken. The balance time left is 6 hours 50 minutes.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur). That means, the Ministry of Industry and Civil Supplies will be taken up *tomorrow*?

MR. SPEAKER: Yes. This will continue for the whole of today and the minister will reply tomorrow. Shri Sarkar.

SHRI SAKTI KUMAR SARKAR (Joynagar): Sir. I rise to support the Demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation. While doing so, I want to highlight some of the problems facing my State of West Bengal. We are facing floods every year as a result of

*Moved with the recommendation of the President.

[Shri Sakti Kumar Sarkar]

which the miseries of the people are increasing year by year. To remove the miseries and control the floods, the DVC came into the picture for taking flood-control measures. But the DVC is not giving full protection from floods. It was previously envisaged that 8 dams would be constructed, but ultimately 3 dams were not taken into consideration. For protecting the State of West Bengal, particularly the Damodar basin from floods, we have to give due consideration to the proposals which were previously recommended by the expert committee. In the interest of control of floods in West Bengal, particularly in the Damodar region, I request the Agriculture and Irrigation Minister to take up those schemes immediately under which two extra dams can be constructed. Moreover, about the lower Damodar basin, this is a very serious matter A new scheme called Lower Damodar Basin Scheme has been taken into consideration for controlling the heavy discharge of water and a heavy amount has been allotted for controlling the flood waters by that scheme. In order to control floods, this new scheme which is called lower Damodar basin Scheme has been taken into consideration and crores of rupees have been sanctioned for that scheme. If the scheme is implemented, sixty to seventy thousand people of that area will be badly affected. For this reason people came in a deputation to Babu Jagjivan Ram three weeks ago to explain their plight. The scheme is a gigantic one. If the scheme is implemented, not only hundreds of families will be uprooted but hundreds of primary and high schools will also be affected. Some Members of Parliament both from this House as well as from the other House, including myself visited this place and we came to the conclusion that there was certainly a need for some scheme to came up there but the present scheme would not be of much help to the people there because the old menace of floods had already been controlled by DVC. What is now required is restructuring of the scheme. The old Damodar channel has been discarded and no flood water is discharged from this channel. To save the people there, we, the Members of Parliament who have visited this area, feel that a portion of this water should be diverted to this channel and the huge embankment cost should be minimised. Rather, there is at present no necessity of any embankments even. There is another danger also. If all the discharges of Durgapur barrage would go to Roopnarain River directly, that will create another havoc for the people of Midnapore District. This aspect cannot be ignored at all. At present, the flood water is not creating any havoc there. If we really want to control the floods for ever, we request the Minister to take into consideration the recommendations of the Expert Committee which recommended firmly that three more dams should be constructed in Bihar. I request the Minister to take up the matter with the Bihar Government so that two or three dams could be constructed there without any delay.

I also request the Central Ministry to take up the responsibility of fighting or controlling floods. This matter should not be left with the States. I agree with Mr. Nathu Ram Mirdha's point that the subject of flood control should be taken up by the Government of India particularly when the river is flowing through different States. This is a very important matter and I request the Minister as well as the House to take into consideration this aspect.

As regards irrigation to the places where there is no river or where there is no sub-soil water, some measures should be taken so that these lands can be utilised for second cropping or another cropping. In my town constituency, viz., the Sunderbans region, the land is so rich that it has no parallel anywhere in India. You will not find a single stone in the soil there,

throughout the length and breadth of the 1200 sq. miles area. This is such a good land; but there is no possibility of irrigation water. Water is there, but it is tidal saline water, and its water area, is 731 miles in length. All the waters are flowing through into the rivers, channels and creeks. It is being protected by 2200 miles of embankments. As regards the potentiality for irrigation water, there is no source of any water, from which water can be given to second cropping. Where there is no possibility of giving irrigation water, some sort of dry land farming should be developed. I request the hon. Minister to give serious thought to this and to ask the ICAR to develop some projects here, so that the residual moisture of the land can be kept in view and some crop pattern be evolved accordingly and which will also be applicable for the Sunderbans area. I also request that operational research projects should be taken up for all these regions. This is the only project which can be done for places where irrigation water cannot be supplied.

I want to highlight one point now, viz., about fisheries. In West Bengal, there is an immense possibility for developing fisheries. But it is being neglected, because it is a State subject. But the Centre cannot shift its responsibility, because ultimately it is the Centre which is allocating the money and giving approval to the schemes of the State Government. The Centre is actually giving loans and providing money both from outside and also from within. You will be astonished to hear that the daily requirement of fish for the people of Calcutta is 353 tonnes, whereas the supply is only 41 tonnes. There is a big gap. If we want really to feed the people, we should take some concrete steps in this regard. Fish is the only protein food for the Bengali-speaking people. Some sort of a control should be taken up. Of course, the Minister, in his reply can easily spare a few minutes to touch upon this point.

Now, kindly give me two minutes.

MR. SPEAKER: Kindly conclude. You have already taken 10 minutes.

SHRI SAKTI KUMAR SARKAR: I am just finishing. I request the Minister to give consideration to my request. He can easily give one example, viz., that of the composite culture. It has been evolved by the ICAR. Though apparently it seems to be a good scheme, I would like to put it seriously here that there is nobody to make such huge and heavy capital investment for developing the composite culture. I request that steps be taken to develop some sort of fish culture in saline areas particularly in Brackish water. This brackish pisci-culture is neglected. I request the Minister concerned to give serious thought to this brackish water culture It can be developed easily in West Bengal, where the coastline consists of hundreds of creeks and canals i.e., in Sunderbans. This area can be developed for fisheries. Now only one point more.

MR. SPEAKER: No. You have already taken more than ten minutes.

SHRI SAKTI KUMAR SARKAR: Just one minute please, or at least half-a-minute.

MR. SPEAKER: No, please Now Mr. Chandrika Prasad.

श्री चंद्रिका प्रसाद (बलिया) : कृषि मन्त्रालय की अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई है कि 1976 में भारत में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। किसानों के साहस और कृषि वैज्ञानिकों की दूरदर्शिता के कारण ही मैं समझता हूं कि हमको दुर्भिक्ष का सामना नहीं करना पड़ा और मन्त्री महोदय की अक्लमन्दी और कार्य कुशलता से हमारा उत्पादन भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन हम को इतने से ही सब्र नहीं कर लेना चाहिये। हमको इतना उत्पादन कर दिखाना चाहिये कि विश्व

[श्री चंद्रिका प्रसाद]

हमारी मार्किट बन जाए । हम खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्म निर्भर बनें बल्कि विश्व भी हमारी मार्किट बने यह हम को प्रयत्न करना चाहिये । इससे हमारी आजादी पर कोई आंच आने का खतरा नहीं रह जाएगा । अमरीका की तरफ से कभी कभी इस तरह का आभास मिलता है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी को भोजन देकर वह हमारे देश पर कब्जा कर लेगा । इससे उसके इस विचार को भी धक्का लगेगा और जो उसके मनसूबे हैं उनमें उसको असफलता का ही सामना करना पडेगा । मैं समझता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों को इधर भी सोचना चाहिये और आगे बढ़ना चाहिये ।

प्रधान मन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम में दो तीन बातें बहुत महत्वपूण हैं । उन्होने खेतीहर मजदूरों तथा बन्धक मजदूरा के बारे मे जो बातें कही हैं वे देश की अस्सी प्रतिशत जनता के दिल को छूने वाली बाते हैं । इससे उन में खुशी की लहर दौड गई थी । आपने श्री भोगेन्द्र झा की बात को सुना और उन्होने आपको बताया बिहार में क्या हो रहा है । बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलो और सारे देश का यही हाल है । लोगों को भूमि के स्वामित्व के कागज तो मिल गए हैं लेकिन कब्जा उनको नही मिल पा रहा है । हमारे प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में उनको पूर्ण विश्वास है और वे समझते हैं कि वही देश को आगे ले जा सकती हैं और उनको आशा है कि उनको कब्जा जमीन का भी मिल जाएगा । वे हमारे साथ हैं इस में कोई दो राहें नहीं हैं । लेकिन उनके धैर्य की सीमा भी कुछ है और इस सीमा को उनका धैर्य लांघ जाए इससे पहले ही हम को यह प्रयत्न करना चाहिये कि उनको भूमि का कब्जा हम दिला दे । इस वक्त तो कागज ही उनको दिया गया है । अगर उनको वास्तविक कब्जा नहीं दिलाया गया तो उनको धक्का लगेगा और उनकी परेशानी बढ़ेगी और हमारी—पार्टी से वे नाराज होंगे । मुझे लगता है कि हमारी जो मशीनरी है, जो अधिकारी हैं वे हमारी नीतियों में विश्वास नहीं रखते हैं । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि हमारी सरकारी नान आफिशल एजेंसीज बनाए तो वे इसको देख सकें कि हमारी जो नीतियां हैं उनका ठीक से इम्प्लेमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है । ये कमेटियां जिला से ब्लाक लेवेल तक आपको बनानी चाहियें । ये देखेंगे कि काम तेजी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इम्प्लेमेंटेशन कितना हो रहा है । जो बाते मैं सुन रहा हूं संसद् मे और बाहर उससे मझे लग रहा है कि जब तक सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं कर दिया जाएगा और जमीन उनको नहीं दे दी जाएगी जा खेती करना चाहते हैं हमारी—समस्यायें हल नहीं होंगी । प्रशासन के ढांचे को भी बदला जाना चाहिये । ऐसा आपने किया तभी जाकर पूरी तरह से इम्प्लेमेंटेशन आपकी नीतियां का हो पाएगा । फिलहाल मैं चाहता हू कि आप रूरल वैलफेयर बोर्ड बनाएं जिला के लेबेल पर और ब्लाक के लेवेल पर । ये बोर्ड भूमि सुधार के कार्यक्रमों को, बन्धक मजदूरों की स्थिति को देखेंगे । आप कहते हैं कि बन्धक मजदूर अब नहीं रहे, यह समस्या हल हो गई है । लेकिन अभी यह खत्म नही हुई है । मेरी कंन्टिट्यएन्सी के साथ आपकी भी अध्यक्ष महोदय कन्स्टिट्यएन्सी लगती है । आपको पता ही होगा कि आज भी गरीब हरिजन अगर दूसरे की खेती न करे तो कल को उसको खेत में पेशाब तक करने नहीं दिया जाता है और आसानी से वह खेत में से निकल भी नहीं सकता है । इस वास्ते इस मामले मैं आपको ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा । कानून को बदल कर बीस सूत्री प्रोग्राम को इम्प्लेमेंट करने के लिए आपको इस तरह की कमेटियां बनानी होंगी ।

आई० एन० टी० यू० सी० ने अभी तक तो कारखानों आदि के मजदूरो को संगठित करने का काम किया है । अब उसने खेतीहर मजदूरों को संगठित करने का काम हाथ में

लिया है । यह बहुत ही कठिन काम है क्योंकि ये लोग गांव गांव में फैले हुए हैं । रूरल लेबर फैडरेशन के नाम से उसने एक संस्था बनाई है । मैं चाहता हूं कि रूरल वैलफेयर बोर्ड में इनके लोगों को रखा जाए । ये बोर्ड सरकारी मशीनरी के साथ तालमेल बिठा कर सब चीजों को देखें ।

अस्सी प्रतिशत हमारी देश की आबादी गांवों में रहती है । वहां पर खेतीहर मजदूरां तथा किसानों की हालत बहुत ही खराब है । मैं बलिया के तथा पूर्वी जिलों के बारे में कहता हूं कि हमारे यहां जो होल्डिंग है सत्तर प्रतिशत के पास एक एकड़ से पांच एकड़ तक की है और पांच से लेकर बीस एकड़ तक तीस प्रतिशत के पास है और जिन के पास पचास एकड़ से ऊपर है वे मुश्किल से दस प्रतिशत हैं । हर जगह मैं समझता हूं यही प्राब्लम हैं । अंग्रेजों के जमाने में यहां जो नहरी पानी, बिजली मिली वही मिली हुई है अब भी उनमें कोई प्रगति नहीं हुई है । हमारे यहां के किसानों की जो समस्या है, छोटे छोटे किसानों की जो समस्या है, खाद, बिजली पानी आदि की वह अभी भी हल नहीं हुई है । ये चीजें उनको देखने को नहीं मिलती हैं । हमारी मुश्किल यह भी है कि हम बिजली नहीं भी लेते हैं तब भी उसका चार्ज हमको देना पड़ता है । नहरी पानी का रेट बढ़ गया है, ट्यूबवेल के पानी का रेट बढ़ गया है । खाद कुछ इधर आपने सस्ती की । अब किसान जन चीजों को खरीदना चाहता है वे उनको महंगी खरीदनी पड़ती हैं । किसान की जो चीज है वह तो सस्ती बिकती है लेकिन उसको जो खरीदना पड़ती है वह उसको महंगी खरीदनी पड़ती है । जो वह खरीदता है वह भी आपको सही रेट पर और सस्ती उसको दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये तथा किसानों को घाटा न लगे इसके सम्बन्ध में किसानों को सबसिडी देना चाहिये ।

हमारा क्षेत्र बाढ़ और सूखे का है । आपका ध्यान भी, माननीय सभापति जी, तथा हुआ है । आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहां गंगा, घाघरा, पुनपुन और सोन नदियां बाढ़ से तबाही कर देती हैं । हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर में है और देश में जो दूसरे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हैं, वह अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल पाये हैं । बाढ़ के दिनों में बहुत पानी बर्बाद जाता है । बाढ़ का पानी निकलने के बाद जो खेती करना चाहते हैं वह सूखे के कारण खेती खत्म हो जाती है । इसका कोई रास्ता नहीं निकला है ।

मेरा एक सुझाव है कि वहां पर पानी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे बाढ़ आने के पहले हमको पानी मिल जाये, उन्नत बीज मिल जाये ताकि बाढ़ आने से पहले ही हम खेती तयार कर लें और उसे काट लें । फिर जब बाढ़ आये तो छोड़ दें । बाढ़ का जो पानी होता है, उसका कोई बैरज बनाकर या कोई और रास्ता निकाल कर इस्तेमाल किया जाना चाहिये । बिहार और यू० पी० की सरहद या और जो बैकवर्ड पाकेटस हैं दोनों सूबों को मिला कर कोई एक बैरेज बनाया जाये ताकि बाढ़ के पानी का स्टोरेज हो सके और उससे सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये ।

हमारे यहां शारदा सहायक पूरे ईस्टर्न यू० पी० की सरहद को फीड नहीं करती है । उसका कोई उपाय करना चाहिये । दोहरी कनाल से उसको जोड़ दें । गंडक की हमारी योजना है, मई-जून का सरप्लस पानी बेकार जाता है । यू० पी० और बिहार के जो गंगा और घाघरा के दियारे हैं, जहां कि अभी तक सिंचाई का बन्दोबस्त नहीं है, वहां हमारे पूर्व सिंचाई मन्त्री डा० के० एल० राव गये थे, उन्होंने कहा था कि यहां मिनी ट्यूबवेल लगाये जायें, उससे हरियाली हो जायेगी और पास की जो बैकवर्ड पाकेटस हैं, जहां कि घनी आबादी है वहां लोगों को उससे लाभ होगा । वहां के लोग गरीबी के कारण मजदूर बन कर आसाम और बंगाल में चले गये और देश के सभी

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

भागों में गये । 30, 40 हजार हमारे पूर्वी जिलों के मजदूर आसाम में खेती करते हैं, लेकिन आज वे हटाये जा रहे हैं । 15, 20 बरस की आजादी के बाद भी आज उनको सिटीजन नहीं माना जाता है । उन्होंने जंगल को काटकर वहां खेती की है और फसलों के उत्पादन को कई गुना बढ़ाया है, लेकिन अभी तक उनकी वेजेज तय नहीं हुई हैं । मजदूरों के जो वेजेज तय किये गये हैं, वह उनको मिलने चाहिये ।

हमारी सरकार, कृषि वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों को किसानों के लिये उन्नत बीज, पानी और खाद की व्यवस्था करने के बारे में सोचना चाहिये । इसके अतिरिक्त किसानों को इंसेंटिव भी मिलना चाहिये, जिससे उनका खर्चा पूरा हो । खेतिहरों को उचित मजदूरी दिलाने के लिये मशीनरी की स्थापना करनी चाहिये । अभी तक वह उनको नहीं मिल रही है ।

हमारे यहां विश्व बैंक से कर्ज देकर प्राइवेट ट्यूबवेल बनाये जा रहे हैं । उस कर्ज का 11, 12 परसेंट सूद लिया जाता है । एक, दो एकड़ का किसान 11, 12 परसेंट सूद कैसे दे सकता है । इसमें 50 परसेंट की छूट या अनुदान मिलना चाहिये और सूद घटा कर 3, 4 परसेंट कर देना चाहिये । या पब्लिक सैक्टर में ट्यूबवैल लगाये जा सकते हैं जिससे हमारे यहां प्राब्लम का हल हो सके ।

इस बात की बराबर मांग की जाती रही है कि पुरानी शुगर फ़ैक्टरीज का राष्ट्रीयकरण किया जाये, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है । हम चाहते हैं कि शुगर मालिकों, किसानों और मजदूरों को मिला कर तथा उनको हिस्सेदार बना कर फ़ैक्टरीज खोली जायें और सहकारी मिल बना दी जायें पूर्वी जिलों में कई सहकारी चीनी मिल खोली गईं, उनके ध्यान में यह कमजोरी है कि वहां 8 करोड़ का एक सोल्वैन्ट तो लगा दिया गया है लेकिन गन्ने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । इसका परिणाम यह होगा कि 4, 5 बरस में करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जायेगा । इस बात की आवश्यकता है कि गन्ना पैदा करने वाले किसानों को इंसेंटिव दिया जाये और इसके लिये 3, 4 करोड़ की और व्यवस्था होनी चाहिये । कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इन लोगों को अच्छे बीज, सिंचाई की व्यवस्था और टैक्निकल सलाह देने की व्यवस्था की जाये ।

सारे देश में हमारा यह बैकवर्ड एरिया है, विशेषकर ईस्टर्न यू० पी० में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है । हमारा सूखा और बाढ़ का क्षेत्र है, गंगा और घाघरा नदी के पानी और बालू का क्षेत्र है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर विकास टैक्स लगाया है । 27 वर्षों से यह इलाका ऐसे ही चला आ रहा है । इस पर विकास टैक्स नहीं लगना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का प्रबल समर्थन करता हूं ।

श्री शिव शंकर प्रसाद यादव (खगरिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि और सिंचाई के सम्बन्ध में बोलने की इजाजत दी है, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, मैं ही क्यों इस सदन में बैठे हुए और अनेक सदस्य भी उस क्षेत्र से आते हैं, जिसका नाम है इंडोगैंगेटिक प्लान अर्थात गंगा और सिंध की समतल भूमि । उस क्षेत्र में नदियों की भरमार है । यदि उसका कुछ उचित उपयोग हम कर सके होते तो हमारा क्षेत्र अन्न का भंडार होता । वहां की जमीन उपजाऊ है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उस क्षेत्र में इन नदियों से लाभ के बदले किसानों को प्रतिवर्ष बाढ़ और कटाव के कारण सर्वनाश ही देखना पड़ता है ।

हमारे इलाके मे राष्ट्रीय राजपथ मन्सी हो कर जाता है। वह गगा के किनारे किनारे बहुत दूर तक गया है। मन्सी के लिए बहुत दिन तक खतरा बना रहा। उस को बचाने के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये गये। आठ दस बरस के प्रयत्न के बाद अब मन्सी का बचाव नजर आ रहा है। मन्सी से खगरिया तक तो स्थिति कुछ अनुकूल हुई है और उस क्षेत्र का बचाव नजर आ रहा है, लेकिन खगरिया से लेकर मुगेर घाट तक कटाव की स्थिति काफी भयकर है, जहा इंजीनियरो की रिपोर्ट के मुताबिक 500 गज जमीन गत वर्ष कट गई और उस मे कितने ही गाव गगा के गर्भ मे चले गये। एक ओर उपजाऊ जमीन घटती जा रही है और दूसरी ओर बालू फैलती जा रही है, जिस से अन्न की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड रहा है।

हाल की बात है कि गगा फ्लड कट्रोल कमीशन के डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई, जिन को पटना में भेजा गया है। मैंने उन से अनुरोध किया कि वह चल कर उस क्षेत्र को देखें और वहा की स्थिति का अध्ययन करें। मैं ने उन के लिये बहुत व्यवस्था की और उन को गगा के किनारे किनारे घुमाया। उन्होंने मेरे सुझाव का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि चडीस्थान से हो कर गगा की धारा को पूर्व की ओर मोडना जरा कठिन है, लेकिन स्पर इत्यादि दे कर गगा की धारा को दूसरी ओर मोडने की व्यवस्था की जायेगी।

खगरिया से जो नैशनल हाईवे आता है, उस पर एक पुल है। उस पुल से उमेशनगर स्टेशन तक एक बांध है, जो बूढी गंडक के दक्षिणी किनारे पर है। वह बहुत कमजोर बांध है। उस से लगा हुआ एक कटरमाला बांध है, जो उमेशनगर तक आया है, जिस से रेलवे लाइन के पश्चिमी क्षेत्र का तो बचाव हो जाता है, लेकिन रेलवे लाइन के पूर्व के हिस्से में गंडक का पानी उस कमजोर बांध मे टपक कर आ जाता है, जिस से लाखो एकड जमीन जलमग्न हो जाती है और पैदावार पर बहुत बुरा असर पडता है? प्रत्येक वर्ष यही होता है। मैं ने अनुरोध किया कि उस बांध को मजबूत कर के कटरमाला बाध से सम्बद्ध कर दिया जाये और नैशनल हाइवे पर बने हुए पुल तक पहुचाया जाये। डायरेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया कि ऐसी व्यवस्था की जायेगी।

नैशनल हाईवे से एक सडक हेराटोल से बाईफर्केट हो कर मुगेर घाट तक जाती है। उस सडक को कुछ ऊचा तो किया गया है, लेकिन कभी कभी भयंकर बाढ आने पर पानी उस पर से हो कर बहता है जिस से बीच मे पडे हुए गाव जलमग्न हो जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। 1971 की बाढ मे नैशनल हाईवे साहबपुर कमाल स्टेशन के पास कट गया था और वह रेलवे लाइन भी कट गई थी। उस के बाद यह आशा हुई कि इस सम्बन्ध मे सरकार की ओर से कुछ तीव्र कदम उठाया जायगा, लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ है, सतोषप्रद नही कहा जा सकता है।

एक सडक मुगेर घाट से चल कर लखमनिया मे उस नैशनल हाईवे से मिल जाती है। उस सडक का नाम तिरहुड रोड है। उस रोड पर समस्तीपुर गाव से लखमनिया तक पी डबलयू० डी० के अधीन है और समस्तीपुर से मुगेर घाट तक आर० ई० ओ० के अधीन है। उन के अधिकारियो से मिलने पर उन्होने कहा कि यह हमारे अधिकार में नही है कि इस के स्तर को ऊचा किया जाय। मैंने डायरेक्टर साहब से भी अनुरोध किया था कि वे कोशिश करें कि

इस को भी पी डब्लू डी के अन्दर कर दिया जाय और उस के द्वारा इस को उचा किया जाय। अभी नेशनल हाई-वे के पूर्वी किनारे पर जो बांध बनाया गया है उस मे भी मालूम हुआ कि एक करोड से ज्यादा रुपया खर्च हो गया है लेकिन उस की जरूरत नही होती अगर तिरहुत रोड को मुगेर घाट से और नेशनल हाई-वे से मिला दिया जाता। अभी कसल्टेटिव कमेटी की बैठक मे भी इस ओर हम ने ध्यान दिलाया था तो मंत्री महोदय ने कहा था कि उस सडक को ऊचा करने की कोशिश की जायगी बशर्ते कि फड अवेलेबल हों। लेकिन यह विषय इतना महत्वपूर्ण है और उस क्षेत्र में बसे हुए कम से कम पचासों घनी आबादी के गांव हैं, करीब पचास साठ हजार एकड जमीन है, तो उन के बचाव के लिए पी डब्लू डी या केन्द्रीय सरकार इस को ले ले और इस को ऊचा कर दिया जाय तो फिर उस की उपयोगिता कुछ नही रह जाती।

अभी नेशनल हाई-वे पर जो बांध बना है वह बांध केवल नेशनल हाई-वे और रेलवे का बचाव करता है लेकिन उससे दक्षिण जो जमीन है करीब पचास साठ हजार एकड जमीन, उस जमीन के लिए वह बिलकुल लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मुगेर घाट वाली सडक के बारे में जो सुझाव मैंने दिया है उसको कार्यान्वित किया जाय, उसको भी ऊंचा किया जाय और तिरहुत रोड को भी ऊचा करने के लिए पी०डब्लू०डी० के अधिकारियों को उसे दिया जाय। इस संबंध मे केन्द्रीय सरकार कुछ तत्परता से काम करे क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। केवल दो ढाई महीने बाकी हैं जब कि फिर बाढ़ शुरू हो जायगी और इस बीच मे थोड़े ही दिन में गंगा का पानी बढ़ने लगेगा जिससे कटाव शुरू हो जायगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में बिहार सरकार को आदेश देने की जरूरत हो तो मंत्री महोदय उसके ऊपर ध्यान दें जिससे यह काम जल्दी हो सके।

यह संतोष की बात है कि अन्न की उपज ज्यादा हुई है और लोग उन्नत खेती की ओर उन्मुख हुए हैं। लेकिन उन के लिए जो सुविधाए चाहिएं वह उचित मात्रा मे नही मिल रही है। कई ब्लाकों मे हम ने ऐसा देखा है कि किसान जाता है पम्पिंग सेट वगैरह के लिए तो उसको पम्पिंग सेट का आर्डर तो मिलता है लेकिन उस के ऊपर दबाव डाला जाता है कि अमुक फर्म से ही पम्पिंग सेट लिया जाय जिससे शायद उनको कमीशन मिलता है जिसका नतीजा होता है कि अच्छी क्वालिटी का पम्पिंग सेट नही प्राप्त होता है।

मैंने प्रखण्ड विकास समिति की बैठक मे एक इस बात की ओर ध्यान दिलाया था— हमारे यहां गत वर्ष कुछ लोगों को जिनके पास एक बीघा भी जमीन नही थी उनको 110 रुपये की दर पर खाद दी गई और उन्होंने उसको 70 रुपये के भाव मे बेचा, यह सुन करके आपको आश्चर्य होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लाक के कर्मचारियो से मिल कर गलत नाम और पते दे कर खाद ले ली और उसके बाद उसके वसूले जाने की उम्मीद तो थी ही नहीं क्योंकि फर्जी नाम और पते दिए थे और फिर उन्होंने उसको

70 रुपये में बेचा जो 70 रुपये उन को मुफ्त ही मिल रहे थे। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि के लिये जो कुछ हो रहा है उस में मेरा अनुरोध है कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमारे इलाके में जो जो कठिनाईयां है उन को दूर करने के ऊपर ध्यान दें और सड़क के संबंध में जो सुझाव मैं ने दिये हैं उन पर ध्यान दे।

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : अध्यक्ष जी, यह इतना बड़ा विषय है कि दस मिनट तो इसकी भूमिका में ही समाप्त हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप भूमिका छोड़ दीजिए।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं चाहता हूं केवल भूमिका देकर ही बैठ जाऊं। सिंचाई खाद्य, कृषि अनुसंधान—बहुत सारे विषय इसमें हैं। मैं केवल चार-पांच मोटी मोटी बातें ही कहना चाहता हूं। मैं प्रयास करूंगा कि जो बातें कही जा चुकी हैं उनसे अलग रहूं ताकि मन्त्री महोदय को उन पर ध्यान देने में कुछ अधिक सुविधा हो।

इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए, जैसा कि कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा है, मैं भी इस बात के लिए अनुरोध करता हूं भारत सरकार से कि कृषि और सिंचाई का केन्द्रीय विषय होना चाहिए। जब तक यह विषय केन्द्र के जिम्मे नहीं होगा भारत के किसानों का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बड़े ही आदर के साथ यह अनुरोध करता हूं। सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि किसान या खेती में लगे हुए जो मजदूर हैं उन का केवल जीवन-स्तर ही ऊंचा न हो बल्कि सामाजिक रूप से उन को प्रतिष्ठा भी मिले। अभी देश की कुल जनसंख्या के अस्सी प्रतिशत लोग जो देहातों में रहते हैं उन्हें वह सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिली है जो कि शहर में रहने वाले एक क्लर्क को मिलती है। कारण यह है कि उन के पैर कीचड़ और धूल में सने रहते हैं और वे घुटनों तक धोती पहनते हैं। उन की आमदनी कितनी ही बढ़ जाय लेकिन अगर वे किसी कार्यालय में पहुंच गए तो प्रखण्ड विकास अधिकारी, एस डी ओ या कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठने की उन की हिम्मत नहीं होती और अफसर यह नहीं कह सकते हैं कि आप कुर्सी पर बैठें। इसलिए मैं कहता हूं आवश्यकता इस बात की है कि भारत के किसान और किसानों के साथ लगे हुए जो खेतिहर मजदूर हैं उन को सामाजिक प्रतिष्ठा मिले और महत्व मिले। इस लिये कृषि विभाग को और भारत सरकार को कुछ करना है चाहे वह योजनाओं से हो या व्यावहारिक रूप से कदम उठा कर हो।

यहां पर ट्रैक्टर के संबंध में बड़ी बातें कही गई हैं। उस के मूल्य के संबंध में और उस के उत्पादन के संबंध में कहा गया है। लेकिन जब सीमांत किसान खेतिहर मजदूर या भूमिहीन लोगों की बातें हम करते हैं तो उस के लिए ट्रैक्टर एक स्वपन है। मैं कहता हूं बैलों के लिए कोई योजना बनानी चाहिए ताकि किसान को सस्ते बैल मिल सकें। इस बात के लिए यहां पर कोई नहीं कहता जबकि ट्रैक्टरों की कम कीमत के लिए सभी कहते हैं। आज स्थिति यह है कि दो हजार से कम में एक जोड़ी बैल नहीं मिलते हैं। जबसे हमने बैलो को छोड़कर गाय-बछड़े को अपनाया है तभी से बैलों की कीमत बढ़ गई है और बछड़ा बेचारा अभी उतना बड़ा हुआ नहीं है। इसलिए ट्रैक्टरो की बात को तो आप वही छोड़ दीजिए। 1974–75 में भारत में ट्रैक्टर्स की उत्पादन क्षमता 31,088 थी जबकि लाइसेन्स के अनुसार 1 लाख 49 हजार बनने थे। आप जो ट्रैक्टर बनाते है जिसकी अभी 50 हजार

[श्री शंकर दयाल सिंह]

पए तक कीमत है उसके दाम कम से कम 50 प्रतिशत नीचे होने चाहिए तभी शायद इस देश के हर गांव में एक एक ट्रैक्टर हो सकेगा नहीं तो खेती के लिए बैलों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा ।

इसी सम्बन्ध में एक बात और मैं कहना चाहता हूं । जब सामाजिक प्रतिष्ठा की बात हमने कही तो पूंजी लगाने की एक दूसरी व्यवस्था कृषि के लिए होनी चाहिए । अभी तक हमारे देश का एक संस्कार रहा है या प्राचीन परम्परा रही है कि वही धनी, दानी या पुण्यात्मा माना जाता है जो मंदिर बनवा दे, धर्मशाला बनवा दे या स्कूल बनवा दे । हमको प्रोत्साहन देना चाहिए कि धनी, दानी या पुण्यात्मा वही माना जायेगा जो एक नहर खुदवा दे, बांध बंधवा दे जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो सके । आज देश को इस ओर ले जाने की आवश्यकता है ।

इस के लिये पहल करनी पड़ेगी—कृषि मंत्रालय को । इस लिये कि अब धर्मशालाओं से, मन्दिरों से, पाठशालाओं से अधिक अवश्यकता है—बांध और नहरों की । अगर भारत के किसान को पानी मिल जाय, बीज मिल जाय, खाद मिल जाय और यह तरीका मालूम हो जाय कि कैसे पैदा करना है, तो वह दुनिया के किसी भी किसान के मुकाबले ज्यादा पैदा कर के दिखला सकता है । इस का सब से बड़ा उदाहरण इस बार किसानों ने पेश कर दिया है—जब आप ने दो बार फर्टिलाइजर के दाम कुछ ही कम किये तो आप ने देखा कि पैदावार कितनी अधिक आगे बढ़ गई है । इस लिये जैसे-जैसे आप उन को सुविधायें देंगे, वैसे वैसे वे आगे बढ़ेंगे और अपना काम करते रहेंगे ।

अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा—भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने बहुत ही प्रशंसनीय और सारहनीय काम किया है, उस का फल किसानों ने स्वयं देखा है । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं—आई०सी० ए०आर के जो अनुसन्धान हैं, उन को छोटे किसानों तक, छोटे गांवो तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये । आज तक आप के जितने भी वैज्ञानिक अनुसन्धान हुए हैं, जब तक वे छोटी खेती तक नहीं पहुंचेंगे, उन का कोई लाभ नहीं होगा । आज होना यह चाहिये—रीजनल लैंग्वेज में आई०सी० ए० आर० के अनुसन्धानों को छपवा कर, जनता में पहुंचाया जाय, ऐसा न हो कि वे मोटी-मोटी जिल्दों में ही बन्द रह जायें । इन के अनुसन्धानों से बहुत लाभ हुआ है—इन्होंने कई तरह के गेहूं, बाजरा, मक्का और धान की किस्में बनाई हैं । जितना पहले पैदा होता था, आज उस से चौगुना और पंचगुना पैदा हो रहा है । आप ने जो अनुसंधान किये हैं, उस के लिये भारतीय वैज्ञानिक बहुत धन्यवाद के पात्र हैं । अभी दो-तीन दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा—कटक में जो चावल का अनुसन्धान केन्द्र है उस ने चावल की ऐसी किस्में पैदा की है जिस से दस गुना चावल अधिक पैदा होगा और 100 से भी कम दिनों के अन्दर, 70 दिन के अन्तर्गत धान की फसल किसान को मिल सकती है । इस तरह के अनुसन्धानों को बढ़ावा देना चाहिये, इस के बीज किसानो को उपलब्ध कराने चाहिये, बल्कि मुफ्त बांटे जाने चाहिये । पहले चाय कम्पनियां लोगों को मुफ्त चाय पिलाती थीं लेकिन अब सुबह जब उठते हैं तो चाय न मिले तो बितस्र में से उठना मुश्किल हो जाता है । इस लिये मेरा अनुरोध है कि इन उन्नत बीजों का लाभ हमारे छोटे किसानों को मिलना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं—आज सब से पहले जिन्होंने इस बहस की शुरुआत की थी, सरकार साहब

ने, उन्होंने अपने भाषण में दामोदर वैली कारपोरेशन की बहुत चर्चा की । दामोदर वैली कारपोरेशन बंगाल में बना है, लेकिन उस से यदि सब से अधिक किसी को नुकसान पहुंच रहा है—तो वह बिहार है । मैं कोई अन्तर्राज्य-विवाद की बात नहीं कर रहा हूं—माननीय उप मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने इसी सदन में 29 मार्च, 1976 को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था—

"इस समय पश्चिम बंगाल में लगभग 3.88 लाख हैक्टेअर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को दिया जा रहा है । बिहार में दामोदर घाटी निगम परियोजनाओं से इस समय कोई सिंचाई नहीं हो रही है ।" जब कि उन को दो-तीन स्कीमें इन के पास हैं, बहुत दिनों से विचाराधीन हैं । जब से यहां चुन कर आया हूं, तब से प्रश्न पूछता हूं और यही जवाब मिलता रहता है, यही टका-सा जवाब लेकर जनता के पास चला जाता हूं । जनता कहती है—हमें पानी चाहिये, जवाब नहीं चाहिये । यहां का किसान दिखला चुका है कि वह हरित-क्रान्ति कर सकता है, लेकिन उस को सुविधायें चाहिये । अगर आप उस को पूरी सुविधायें दे दें, तो वह परिणाम दिखला सकता है । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई की जो भी योजनायें आप के पास हैं, कृपा कर उन को कार्यान्वित करें । अगर कोई अन्तर्राज्यीय विवाद है, तो जिस तरह से आप ने अभी कुछ विवाद सुल्टाये हैं, उसी तरह से उन को भी सुल्टाया जा सकता है ।

यहां जब मैं सिंचाई की बात कर रहा हूं—तो एक बात जरूर कहना चाहता हूं—पिछले दिनों आप ने कई योजनाओं के बारे में, जो विचाराधीन थीं, स्वीकृति दी है, उन में एक पंजाब और हरियाणा की भी योजना थी, जिस के लिये आप ने अन्तिम फ़ैसला दिया था । लेकिन हम को यह बात मालूम हुई है कि उस सम्बन्ध में कोई प्रगति अभी योजना के सम्बन्ध में नहीं हुई है । तो केन्द्र जो कुछ फ़ैसला करे उस पर फैसला होना चाहिये और राज्यों को कोई हीला हवाला नहीं करना चाहिये ।

अब मैं चन्द सुझाव रख रहा हूं । पहला यह कि पढ़े लिखे लोग भी खेती में लग सकें इस के लिये उन को अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिये आई० सी० ए० आर० के द्वारा और उन को सामाजिक रूप से यह बताया जाना चाहिये कि कोई अगर बी० ए० और एम० ए० करता है तो वह क्लर्की न करे बल्कि खेती में लगे जिस में लाभ भी है और प्रतिष्ठा भी है । दूसरा सुझाव यह है कि किसान के उपयोग की चीजों के मूल्य में कमी होनी चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि उस के उत्पादन का मूल्य कम दिया जाय लेकिन जब वह खरीदने जाय तो ज्यादा पैसा लगे, और इस के लिये सब से पहले हल और बैल की कीमत में कमी होनी चाहिये । या सरकार की ओर से उन को इस के लिये सुविधा मिलनी चाहिये । मैं ट्रैक्टर की बात नहीं करता हूं ।

तीसरा यह कि जैसा मैंने कृषि अनुसन्धान परिषद के बारे में कहा उस के कामों का विस्तार होना चाहिये । उस का फ़ल भी मिला है, और बहुत खुशी की बात है कि पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने श्री चन्द्र शेखर लोहमी को, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, 15,000 रु० का पुरस्कार दिया इसलिये कि बड़े बड़े वैज्ञानिक जिस काम को नहीं कर सकते थे उस को एक साधारण किसान ने कर के दिखा दिया । इसलिये उस के कामों का विस्तार होना चाहिये ।

अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री ने जब 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की थी उन्होंने ग्रामीण विकास और खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट

[श्री शंकर दयाल सिंह]

किया था। उन का भाषण मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि खेतिहर मजदूर हमारे समाज का वह अंग है जिस का बुरी तरह से शोषण किया जाता है। खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन सम्बन्धी कानून की भी समीक्षा की जायगी और जहां आवश्यक होगा न्यूनतम वेतन को उचित रूप से बढ़ाने की कार्यवाही की जायेगी।"

अध्यक्ष जी, अलग अलग प्रान्तों में उन की मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं। कहीं 3 रु० है, मेरी जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में 3 रु०, उडीसा में 4 रु० मध्य प्रदेश में 4 रु०, बिहरा में साढे चार और 5 ० दे रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में आप को सभी श्रम मंत्रियों और कृषि मन्त्रियों को बुला कर एक नीति निर्धारित करनी चाहिये। और जैसा कि 20 सूत्री कार्यक्रम में यह कहा गया है कि 50 लाख हैक्टर भूमिमें और सिचाई की व्यवस्था की जायगी तो इस के लिये हर प्रान्त में दो, चार योजनाये ऐसी तैयार होनी चाहिये, जो कम समय में बन जाये।

अन्त में केवल इतना कहना चाहता हू कि भूमि सुधारों के नाम पर इस देश में भाषण बहुत हुए हैं, कानून बहुत बने हैं, लेकिन उन का कार्यान्वियन अभी तक नही हुआ है। मैंने स्वयं पद यात्रा के दौरान देखा है कि 1955 में भूदान यज्ञ के द्वारा जो जमीन दी गई उस का भी अधिकार अब तक भूमिहीनों और गरीब किसानों को नहीं मिला है। पिछले दिनों भी बहुत से लोगों को जो पर्चा मिला, मैंने खुद अपने क्षेत्र चतरा में देखा है कि जिन लोगों को पर्चा मिला, जमीन का हक उन्हें नहीं मिला। और पर्चे के बाद मुकदमे बढ गये इसलिये कि कर्मचारी ने पर्चा उस को दे दिया लेकिन प्लाट नम्बर और खाता नम्बर दूसरा लिख दिया। तो इस के लिये बहुत बड़ी कार्यवाही होनी चाहिये, बहुत कड़ाई से काम होना चाहिए। और केन्द्रीय सरकार जब तक इस काम के निरीक्षण का जिम्मा अपने हाथ में नही ले लेगी तब तक यह काम नही हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ कृषि में जो क्रान्तिकारी कार्य हुआ है जिस के चलते देश अपने पांव पर खड़ा हुआ है, इस के लिये कृषि मंत्रालय को बधाई देता हू। और जो सुझाव दिये हैं मैं चाहता हूं कि अगर उन में से दो, चार पर भी ध्यान दिया गया तो मेरा यहां बोलना सार्थक हो जाय।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Mr Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants which have been brought before the House for approval, by the hon Minister for Food and Agriculture and Irrigation

Sir, I had the occasion to read the most illuminating speech which has been made by Dr K L Rao, with regard to certain steps being undertaken with regard to irrigation in this country

First of all, I want to congratulate the hon Minister for Irrigation for having resolved many of the river water disputes that have been pending for decades Of course, this context I have also to congratulate my Chief Minister who has taken the initiative to take out the Godavari Water Dispute from out of the purview of the Tribunal and now the concerned States have come to an agreement I congratulate both the Irrigation Ministry and the Ministers concerned in this connection.

In the last ten to fifteen years, these river water disputes have been pending for settlement because every State has been taking a very rigid

stand. They were under the impression that by more geographical accident, if a State happens to be by the side of the river, that river belongs to them. That has affected much of our agricultural production. In this connection, I would only suggest that the Ministry, in consultation with the State Governments should evolve a national water policy by treating water as a national asset. The sooner it is done the better it is. Rs. 3,000 crores have been invested in the irrigation sector but, there has not been a resultant benefit from out of the investment of Rs. 3,000 crores.

I would, in this connection, also thank the Prime Minister for her being able to persuade the three States to give water to Madras State 15 TMC of water is being taken from Krishna to feed the population of Madras who are suffering from acute drinking water scarcity. I would plead with the Prime Minister as also the Minister for Irrigation that same generous attitude which has been shown to the population of Madras must also be shown to such of those areas which are subjected to famine and brought and where there is no possibility of getting water from the major rivers.

Rayalaseema is one such area which has often been subjected to famine and drought due to adverse seasonal conditions. That area being in the rain-shadow region; it is suffering from acute water scarcity. While taking water from the Krishna I suggest that the *en route* area of Rayalaseema must also be given the benefit of Krishna water. Then only the famine will vanish from that unfortunate part of the country. I hope that the concerned Governments and the Prime Minister, by using her good offices, will persuade the States to divert water to these areas.

Coming to the utilisation of water potential that has been created for the last three to four Plans, out of the total cultivated area of 164 million hectares in this country, only 25 per cent has been brought under irrigation. I feel that intensive effort has to be made to have the maximum utilisation of water potential in this country.

Here I would suggest that the major river projects in the country which remain to be completed for decades like the Nagarjunasagar and Rajasthan Canal and some important projects in Bihar and Karnataka have to be completed soon. I am glad to know that some gulf countries like Saudi Arabia and others have come forward to give soft loans through World Bank for the early construction of these projects. I thank the Central Government for having taken the initiative. Speedy steps may be taken for immediate completion of the projects.

The Minister referred to the record output in our agricultural production in this country. Fortunately, we had a favourable monsoon and, as a result, we had a record output of 118 million tonnes of grains in this country. But, my feeling is this. Perhaps, it may be temporary because 75 per cent of our cultivated lands is exposed to the vagaries of monsoon. So, we should soon take steps in protecting these areas and also keeping up the record production which we have been doing all these years. It is for that reason that many schemes have been implemented by the Government, and the most important of it is with regard to water management. Water management is highly essential in this country in order to increase the acreage under irrigation. More steps have to be taken by the Government to have a proper water management.

Coming to rice production, it has been said that out of 164 million hectares of cultivation area, 38 5 million hectares *come under paddy production*. But, Sir, the per hectare yield in this country has been the highest

[Shri P. Venkatasubbaiah]

only in Punjab and Haryana. The per hectare yield in Punjab and Haryana is 2,500 kg. per hectare whereas in Tamil Nadu and Andhra Pradesh—which are considered to be the rice belt areas—the per hectare yield is only 1800 to 2000 kg. This poor yield is due to lack of proper water management and also lack of proper direction to the farmers to utilise the maximum water that is available Unfortunately, States like West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh and Assam and U P are very much lagging behind in per hectare yield of rice. I would like to say that if the Government wants to realise the target of 51 million tonnes of rice fixed for this year, these States ought to be given proper direction.

Sir, I do not agree with my friend, Shri Shankar Dayal Singh when he suggested that agriculture should be taken up as a Central subject. It is not possible, sitting in Krishi Bhavan and directing operations to take place in the States. It is the State Governments that have to be given proper encouragement and also the 'kishans' should be given adequate inputs to increase the per hectare yield in that area. Agriculture has to be lifted from the present subsistence economy. It can be done only when the farmers are looked after properly.

Now, the cost of production has gone up. The water rates have gone up. The rates of fertilisers have gone up. In order to escape from going to other countries with a begging bowl, I will suggest to the Agriculture Ministry that, if necessary, they should subsidise the purchase of chemical fertilisers and protect the interests of the farmer. After all it is he who has to toil hard and feed the 600 million people of our country. They should plead administrative difficulties If necessary, they should come to the rescue of the farmer and the farmer is there to produce as much as possible.

The various schemes like the marginal farmers' scheme and the small farmers' scheme have to be implemented on a large scale. They are now being executed on a pilot basis. The marginal farmers' schemes and small farmers' schemes are doing good to the farmers. They have to be done on a large scale. Also the Drought Prone Areas development schemes have to be implemented and executed wherever it is possible.

12 hrs.

Another important factor is that if you want to develop agriculture in this country, the scheme of consolidation of land holdings must be given top priority. Of course, administratively there have been difficulties. There has been some harassment in some places But ultimately, in order to rescue this country from further fragmentation of land, it is necessary that there should be consolidation of land holdings which should go hand in hand with land reforms.

Then there is a most important point in connection with the twenty-point economic programme. We are now engaged in the task of distribution of *banjar* and surplus land to the landless poor But unless credit is made available, distribution of land will not have the desired effect. Survey of rural credit necessary is to be made. Simultaneously with distribution of land, credit also must be made available to the landless poor Unless that is done, our schemes will only remain on paper.

Then about sugarcane prices. At one time, sugarcane price was linked to recovery. Unfortunately, that has been given up. The result is that the States which are showing higher recovery are the sufferers. There is a premium on inefficiency and laziness This should go. We cannot have spoonfeeding of people who do not grow cane with good recovery. So the old scheme has to be revived and

the price of cane linked to recovery. Unless that is done, sugarcane production will not go up in this country. Specially, States in the south suffer from this handicap, because they are efficient and the cane they grow has a better recovery, then in the other States. So the old formula should be restored.

I congratulate the Agriculture Ministry on giving certain concessions as per the Sampath Committee recommendations for new sugar factories going into production. In this connection, I must also say that the central financial institutions must come in in a big way to give proper encouragement and necessary finance to sugarcane factories to come up so that they may take advantage of the Sampath Committee recommendations so that sugar production may increase in this country by which we can have more export earning in foreign exchange. With these words, I support, the Demands of the Ministry.

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia): Day before yesterday, Shri B. N. Reddy spoke on these Demands on behalf of our Party.

12.22 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

A superficial study of our agricultural development shows that we are progressing. Some progress in our production and in our technology is undeniable, but if we study deeper the whole agricultural system of our country we find that the situation is not so simple. Our Finance Minister was saying that India lives in villages. It may be better said that the heart of India is in the villages. If the village goes well, if land and labour in the rural area are fully utilised with the help of technology, then production will rise and industry can also be provided with the raw materials for development so that our national cycle can be growing and developing in a healthy way. But the situation is totally different from what it should be or expected to be. Our poverty is growing. In the rural areas, the unemployment problem as also in the urban areas, is developing to an impossible situation. In this country this is a problem which cannot be solved so quickly; everybody must think over that problem and see how it could be solved. I shall read out to you a passage from a newspaper report published in Newsletter on International Women's Year; it is a reproduction of the report of the Times of India dated 5-10-1975, entitled: Flourishing trade in women. In the last para of that report, it says:

> "Of all the women in this area in Delhi brothels who had been interviewed by the study team, the last interviewed Janaki was the most candid. An old woman who had been sold into prostitution in Lahore before the advent of the second World War, Janaki brushed aside all attempts to end prostitution as feeble. Nothing was going to help according to her, not the police raids nor the check posts at Purolai borders . . ."

MR. DEPUTY-SPEAKER: What has it to do with the demands of the Agriculture Ministry?

SHRI S. P. BHATTACHARYYA: Please keep patient; I will tell you. It goes on:

> ". . . nor Nari Niketans or pension for widows. Buy freedom for our men; give them land and only land. It is this land, the greenfields which will contain their girls and nothing else can."

This is the suffering of the women of our country. It is their cry for solution. It is the extreme nature of poverty that leads to that evil. How

[Shri S. P. Bhattacharyya]

poverty is growing from 1901 can be seen from the figures of the growth of the landless people in our country, published every census year. In 1901 it was 18.81 million; in 1921 it was 20.51; in 1951 it was 27.51; in 1961 it was 31.48 and in 1971 it was 47.49 million. That is the growth of landless peasantry in our country. Even after our freedom and independence, things have not been attended to, this has not been arrested in the rural area; the number is growing more and more. A recent publication about our agricultural census states only 15 per cent of the rural families are controlling 60 per cent of cultivable land and they are all owners of more than four hectares of land Our All India Kisan Sabha study report says that owners above four hectares in general, are not themselves cultivators That is how land is being controlled by those who are not themselves cultivators Real cultivators are exploited and thrown out of land and cheated. That is how they are made to suffer Now, I will give you the figures In the booklet 'The Changing Scene' published by the Indian Oxygen, a review on the Indian economy has been made for the benefit of our industrial and agricultural development I quote here the relevant extract of the booklet

> "Another basic problem highlighted by the recently released data of the first agricultural census is that a huge area—over three crore acres in aggregate—of cultivable land lies waste in India. Half of this land is in large holdings of 25 acres and above each While it is imaginable that lack of resources constrain the small and marginal farmers to leave their holdings fallow, what prevents the top brackets of the farming community from a fuller utilisation of this scarce and valuable resource, that is land, has to be gone into in depth Differentiated approaches should be evolved to induce and enable the cultivators at both ends of the rural spectrum to put an end to this scandalous situation".

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken your time.

SHRI S P. BHATTACHARYYA: But I have got my party's time.

MR DEPUTY-SPEAKER: The first speaker of your party has practically taken all your party's time. This is additional time given to you

SHRI S. P BHATTACHARYYA: My party leader has told me that we have half-an-hour time. But please give me five minutes more.

MR DEPUTY-SPEAKER: I do not know what your leader has said But I would tell you that your first speaker has taken all the time Please understand that Now, you can take five minutes more

SHRI S P BHATTACHARYYA: Now, what about the land reform policies so far adopted by our Government? In early Fifties, the Mahalanobis Commission found that after fixing the ceiling of 20 standard acres, there would be a surplus of 63 million acres in the country In 1970-71, the Dandekar-Raj Committee estimated that the surplus would be about 42 million acres In 1972 the Agriculture Minister had said in Lok Sabha that there would be a surplus of 40 million acres, In 1975, the estimate of the Government came down to 37 lakh acres Here you will notice that the figures were quoted in millions previously and now in 1975 they are quoted in lakhs. Recently in reply to a question put by an Hon'ble Member in the Rajya Sabha, it was stated that the surplus would be about 9 lakh acres, out of which 4.1 lakh acres have been taken possession of and from this 1.2 lakh acres have been distributed so far. Truly speaking we have failed to make any land reform.

Now, I would like to refer you to a report received by me. I think the Minister would confirm it. The Collector of East Godavari District, Andhra Pradesh, Mr. Govindarajan, has stated that out of 38,000 acres of surplus land in Andhra Pradesh, in East Godavari District alone there are 15,000 acres of land as surplus. The crime of Mr. Govindarajan was that he had launched a case against big land-owners for misappropriating government lands. For this, he has been transferred as Deputy Secretary for Planning. Are you going to save the interests of the big landlords or give land to the tiller? That is the moot question you must answer clearly. It is in our national interest that owners having above 4 hectares of land, who are not themselves tillers must not have any land. All land must be distributed by the people by their own committees with the government's cooperation in a massive way. No present ceiling policy will be able to achieve this. No administrative committees can do it because the officers would be compelled by the landowners to defeat the purpose. So, land must be distributed by the people's committees elected by the people. That is the only way to make real land distribution. Then only technology can help. The reports of the study teams on small farmers submitted by R.B.I. in 1967—69 and also in 1972-73 have pointed out that without land reforms, technology, government help, loan etc. will not go down to the marginal farmers. Without radical land reforms and radical land distribution to the real tiller, the problem cannot be solved. Our unemployment problem also cannot be solved. Our industries cannot be developed. The question is whether this government will fulfil this task of national development or not. It is for the government to answer it. The land system which you are still carrying on is the heritage of the British colonialists. They developed the ownership of land, taking away the ownership of land from the tillers to the government and to the zamindars. Our Constitution has given property rights to the land owners but not to the real tiller. This must be ended if you are to end poverty and unemployment. Not only the heritage of colonialism must be ended, but also the heritage of past oppression from the prehistoric age which was going on against the real tillers of the soil must be ended. Our effort should be in that direction. That is the only way for the emancipation of the country. If the government fails in this you must know that the starving people and the unemployed young men will be bound to have their own way. It will be a glory for the government if they fulfil this task, but if they fail, the people will have their way and they will not die endlessly in this way. They cannot die. The time is ripe for this. This must be understood by the government.

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA (Balasore). Mr. Deputy-Speaker, Sir, food and agriculture form the lifeline of India's economy and the success of this Ministry will bring eventual 'success to' the 20-Point Economic Programme. India's population is growing up at a galloping speed. By 1st January, 1976, we have reached more than 600 million. But I have no doubt that with the hand of Midas who was very famous for touching all and turning them into gold, our elder statesman, Babuji who is ably aided by his two Ministers, will give a new dimension to the Food and Agriculture Ministry.

Last year, the kharif production had reached an all time record of 70 million tonnes. If the calculations of the economists go right, by the end of the rabi cultivation year, we will have reached 40 million tonnes in rabi production. It is a very spectacular performance of the Agriculture Ministry as far as kharif production is concerned.

Even before the Emergency was started our Agriculture Minister,

[Shri Shyam Sunder Mohapatra]

Babu Jagjivan Ram had thought that there should be social and economic transformation simultaneously with the change in society and in an address to the Chief Ministers he had said: "Despite the rich natural resources the country possessed, the socio-economic development had not kept space with the size and nature of the problem of majority of vast mass of rural population" If we want to change the rural population, it is only the programmes, plans, schemes and social transformation of the Agriculture Ministry which can change them. India's population lives in villages and not in urban cities like Delhi, Bombay, Calcutta or Bangalore. If we want to change the face of the rural area, we have to embark on a crash programme to give employment to the rural people. The teeming millions, the youth in millions, today, are unemployed in rural areas. Once we were concerned about the educated youth, but today we are concerned about the rural youth. Three years before, under the leadership of our great Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, we embarked on a crash programme through the community development projects. But probably it ended in a fiasco. Hardly, we could allot a lakh of rupees for each block and hardly we could employ one thousand youth and that again barring the rainy season, i.e for seven months in a year. This fact should be noted and given top priority. If the Agriculture Ministry wants to give employment to the rural youth, they must embark on a crash programme to give employment at least to 70 per cent of the youth.

In West Bengal, the Calcutta and Haldia Ports are in danger because of some controversy between India and Bangladesh. When Babuji was in Dacca at the time of Mujibur Rehman, he made is successful conclusion of the problem of Farrakka Barrage particularly the water running through the feeder canal. I understood from a very reliable diplomatic source, being the President of Indo-Bangladesh Association, that late Mujibur Rehman broke even protocol to give honour of our elder statesman Babuji. Those days are gone now. Now that Government does not see eye to eye with us. But I have every hope and confidence in Babuji's dynamic leadership that he will do something after two of our Secretaries, Shri C. C. Patel and Shri Azwani come back, so that we get the required amount of water for the the Calcutta and Haldia Ports.

Land distribution is a big hurdle. Although we have given lands to the Harijans and the tribal population, I have come to know from some reliable source that the Harijans and tribals are not able to give the best attention to the land that has been given to them because they have no money. The Land Mortgage Banks are not forthcoming to give them loans to buy fertilisers, etc. Although they have been given an acre or half-an-acre of land they are probably giving it to some others and they are almost in bondage. What is the reason for that? The Government should see that the lands which have been given to them should be made good use of. I have to bring to the kind notice of Babuji that although the Government has fixed the procurement price, I know that in Orissa and in other States, rice and paddy are selling at a very cheap rate, at a price cheaper than those fixed by the Government as procurement price. Government is not vigilant enough to check it, nor is the Government in a position to purchase paddy and rice from the cultivators, so that they get an incentive, and do not work under frustration. If the procurement price remains high, but the selling price in the market is lower then naturally the incentive goes. To-day, the people have started thinking "Why go in for paddy

and rice cultivation; why not switch over to something else?" So, incentive is going away. (*Interruptions*) The thinking in their minds is, "Why not switch over to some other cash crop?" Although the Agricultural Prices Commission has fixed Rs. 105/- for the purchase of one quintal of wheat there is now clamour in many quarters for increasing it. We had increased the price of wheat from Rs. 67/- to Rs. 105/-. But I must agree on one point, which the economists are now putting forward, viz. that it is the price structure of rice and paddy which determines the price structure of other commodities. If the prices of wheat and rice go up, go up and up, naturally the prices of other commodities will also go up.

I will now come to the problem of irrigation. I come from North Orissa which has seen the vagaries of floods and droughts. Between 1967 and now, we have had probably 7 floods. Even in the months of October and November we had floods. The districts of Balasore, Mayurbhanj and Cuttack districts were washed away by floods in varying degrees during the last 8 years. The Government of Orissa has put forward so many plans for the consideration of the Government of India; but I know that the Subernarekha river project, which is an inter-State river valley project passing through West Bengal, Bihar and Orissa—and on which there has been an agreement between the Chief Ministers of Orissa and Bihar, has not reached its concluding stage. Under Babuji's leadership, so many inter-State river valley problems have been solved. I have every belief that this problem will also soon be solved, and that the West Bengal Government which has not yet signed the agreement, will also come forward to sign it. The Budabalanga river is passing through Mayurbhanj and Balasore districts; and a few years ago, the Government had decided to have a reservoir at the upper reaches of the river, at a place called Kuliana. But we do not know what has transpired during the last few years. It has been rejected. Government is in a mood to find out another place. My contention is: how is it that a place was selected—and probably many engineers must have put their heads together to find out a proper place and schemes were put through— and suddenly the place has been rejected in favour of another place. Has this been done only to consume time, so that the people will be fed on hopes year after year? Due thought should be given to this reservoir on the upper reaches of Budabalanga river. In regard to the Salandi river in Balasore, once upon a time it was thought that the waters of that river will come even to the town of Balasore. Those were the days, i.e. 15 or 20 years back, when the chief minister used to say this in public meetings. The waters of the Salandi river can be connected with the Baitarani, from where we will take more, water so that larger areas can be irrigated.

Mr. Deputy Speaker, Sir, agriculture and irrigation need the maximum consideration from the Government. These are the two items which can change the very face of India's economy. If we give top priority to agriculture and food and provide a vast network of irrigation, there is no doubt that, as the Agriculture Commission has said, by 2016 A.D. India will have almost doubled the area under cultivation.

With these words, I conclude; I hope, Sir, that under the able guidance of Babuji and his able Ministers, due thought will be given to the underdeveloped, poor and backward Stats like Orissa.

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, जो खाद्य और सिंचाई मंत्रालय की ग्रान्ट सदन के सामने पेश है, मैं उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

मान्यवर, आज सारे देश का दो-तिहाई हिस्सा किसानों के ऊपर निर्भर करता है और लाखों लाग खेती का काम करते हैं। यह हमारे देश का सब से बड़ा उद्योग-धंधा है और इस को हमें उसी रूप में देखना चाहिए और इस के बारे में जो भी उन्नति के साधन हों, जो भी रिसर्च के इंस्टीटयूशन्स इस काम के लिए बनाए गये हों, उन्हे उसी रूप में काम करना चाहिए।

श्रीमन्, खेती की उपज बढ़ाई जा सकती है अगर कुछ बेसिक फैक्टर्स, जो उस के साथ में है, इस्तेमाल किये जाए। सब से बड़ा फैक्टर पानी का है। इस के बाद खाद का फैक्टर है, जुताई का फैक्टर है और फिर अच्छे बीजों को देने का फैक्टर है, ऐसा मैं मानता हूं।

मान्यवर, पिछले सालों में जब से बाबू जी ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, हमारे एग्रीकल्चर के हर विभाग में काफी उन्नति हुई है। रिसर्च के काम में उन्नति हुई है, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने में उन्नति हुई है, खाद देने में उन्नति हुई है और इस तरह से हर प्रकार से उन्नति हुई है लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है वह यह है कि हम बाढ को कैसे रोकें। सारे देश में बाढ से दो करोड जन मानस को परेशानी होती है और उस के जीवन की रक्षा हम कैसे करें, आज यह प्रश्न हमारे सामने है। श्रीमन् आप जानते हैं कि मोहनजोदारो और हडप्पा की जो खुदाई हुई है, उस से पता चला है कि आर्य सभ्यता बाढ़ में ही विलीन हो गई थी। इस चीज को हमारे अन्वेषणकर्ता मानते हैं। इस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि सभ्यता का जो विकास हुआ था उस का विनाश इस बाढ के कारण ही हुआ था। श्रीमन् मैं ने जो हिसाब लगाया है, उस में ऐसा पाया है कि हर वर्ष वर्षा से 40 करोड घन मीटर पानी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सागर को समर्पित हुआ है और कुल मिला कर 168 घन मीटर पानी तीन महीने के अन्दर बरसता है और अगर इस पानी का उपयोग किया जा सके, तो उस से करीब ढाई करोड एकड हैक्टयर जमीन में सिंचाई कर सकते हैं और देश के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इतना ही नही बाढ़ से 13 हजार किलोमीटर जो हमारा तटबन्ध है, हर साल कही न कही से टूटता है और गावों की बर्बादी होती है। 1971 तक के जो आंकडे बर्बादी के हमारे सामने आए हैं उन से ऐसा पता लगा है कि 24 अरब रुपये की बर्बादी हुई है और 25 हजार व्यक्ति बाढ में डूब गये हैं और दो करोड लोग प्रति वर्ष प्रभावित होते हैं जैसा कि मैं ने पहले निवेदन किया है। तो इस विभीषिका को अच्छी तरह से हमे ध्यान में रखना चाहिए। आज इस बाढ से हमारे देश का बहुत सा भूभाग एक नारकीय भूभाग बन जाता है। एक तरफ तो बाढ के पानी की हमारे सामने समस्या है और दूसरी तरफ हमारे देश के 98 जिले ऐसे हैं जो हर साल सूखे से पीडित होते हैं। इसलिए जो एक कमीशन बनाया गया था उस ने एक सुझाव दिया था कि गंगा और कावेरी नदियों को मिलाया जाए और यह श्री के० पी० रामास्वामी अय्यर की एक बड़ी पुरानी कल्पना थी। अगर इन को मिलाया जाएगा तो हमारे देश में पानी बरसता है, एक-तिहाई ब्रह्मपुत्र, एक-तिहाई गंगा और एक तिहाई देश की दूसरी नदियों में से और जो छोटे छोटे जलाशय हैं, उन में आता है, तो उस का भरपूर इस्तेमाल हो सकेगा और उन से हम खेती के काम में काफी तरक्की कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि तत्काल आप कावेरी और गंगा के प्रोजेक्ट को इम्पलीमैंट करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठावें।

दूसरी बात मझे यह कहनी है कि बाढ़ के लिए एक बाढ़ आयोग का निर्माण किया

जाए और वह इन्डिपेंटली सेन्टर के चार्ज में होना चाहिए। हर साल हम प्रान्तीय सरकारों को बाढ़ को रोकने के लिए पैसा देते हैं लेकिन वे उस का खर्च नहीं कर पाती हैं और उस के लिए कोई स्कीम नहीं बना सकतीं। आपने पांचवी प्लान में इस के लिए साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया रखा है लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई स्कीम केन्द्रीय सरकार के सामने या प्लानिंग कमीशन के सामने किलयेरेन्स के लिए भेजी है। इस के बारे में मुझे पता नहीं है। इस तरह से हजारों करोड़ रुपया प्रान्तीय सरकारों को जो हम देते हैं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, वह उनमें लगता नहीं है बल्कि लैप्स हो जाता है, खर्च नहीं होता है। मैं समझता हूं कि बाढ़ नियंत्रण को हमें केन्द्रीय विषय बना कर पूरा सर्वे करवा करके नदियों में आने वाली बाढ़ों को रोकने का प्रबन्ध करना चाहिए।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है हमारे यहां भिन्न-भिन्न प्रकार की जमीनें हैं और उन जमीनों में भिन्न-भिन्न प्रकार के उन्नतिशील एवं अन्वेषणप्राप्त बीज अगर बोये जायें तभी उपज बढ़ सकती है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि हम भूमि सुधारों को प्राथमिकता दें, उस पर बल दें। लेकिन भूमि सुधारों की हालत क्या है। जमींदारी एबालिशन हुआ। उसके बाद जो जमीन मिली ग्राम समाजों में उसका अधिकांश भाग ग्राम सभापतियों ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम करवा लिया। थोड़ी बहुत बची इस तरह से भूमि हमारे पास मिली। उसके बाद सीलिंग एक्ट आया। उसमें हजारों हजार एकड़ भूमि हम को मिली। लेकिन मैं अपने जिले की बात बताता हूं। इसके हजारों मुकदमे आज कई सालों से हाई कोर्ट में तथा दूसरी कोर्ट्स में चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनके जो आंकड़े हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए और कुछ आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। जमींदारों ने भी सीलिंग से बचने के लिए ट्रस्ट बना दिये, सोसाइटीज़ बना दीं और नाना प्रकार के फर्जी नक्शे तैयार करवा करके फर्जी लोगों के नाम कर दीं। इस तरह से उन्होंने अपनी सुरक्षा कर ली है। उनके पास ट्रैक्टर हैं, सब चीज़ें हैं। हम सही तरीके से लैंडलैस लेबर को ज़मीन देना चाहते हैं तो हमें ज़मीन को सीलिंग एक्ट के तहत बाहर निकालना चाहिए और संविधान में या कानून में ऐसा परिवर्तन करना चाहिए ताकि जो जमीन निकले उसको कोई हथिया न सके, कानून का लाभ, उसमें लूपहोल का लाभ कोई उठा न सके और उस ज़मीन का राष्ट्रीय हित में और आज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में हम उपयोग कर सकें।

जब फैमिलीज का बटवारा हमारे देश में होता है तो जमीन का बटवारा भी होता है और वह होता चला जा रहा है। सीलिंग एक्ट में जो सीमा थी इसकी वजह से वह भी घटती जा रही है। सीलिंग एक्ट अब अठारह एकड़ तक आ गया है। यह फ्रैगमेंटेशन अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारी उपज पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। मैं यह भी चाहता हूं कि गांव में खेतीहरों की कोआप्रेटिव्ज बनाई जायें। सीलिंग एक्ट के नीचे मिली ज़मीन को सरकार लेकर भूमिहीनों की कोआप्रेटिव्ज़ बना करके सही तरीके से उनको बीज उपलब्ध करे, खाद दे, कम्युनिटी ट्रैक्टर का उसके लिए इंतजाम करे। साथ ही लैंडलैस लेबरर्ज़ के बच्चों को पढ़ाने का उसको इंतज़ाम करना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो एक एकड़ और आधा एकड़ जिस किसान के पास जमीन है उसके परिवार के बटवारे के बाद जो उसका फ्रैग-मैंटेशन होगा उसका बहुत बुरा असर उत्पादन पर पड़ेगा। आपको लैंड-लैस की कोआप्रेटिव्ज़ बनानी चाहिए, जो ज़मीन आपको मिले उस जमीन का इस्तेमाल कोआप्रेटिव्ज़ बना करके सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, जैसे कृषि विभाग है, एक्सटेंशन विभाग है इनकी जो

(श्री नरसिंह नारायण पांडे)

योजनाएं हैं उनको वहां लागू किया जाये। ऐसा आपने किया तो हमारा जो उत्पादन है वह बहुत आसानी से बढ़ सकता है।

अब मैं चीनी नीति के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले सदन में मैंने कहा था कि गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। शिन्दे साहब ने भी कहा था कि चार साढ़े चार परसेंट इस बार गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ गया है। मैंने बार-बार यहां कहा है कि चीनी मिल मालिक ऐसा कुछ अपना तरीका अपना रहे है ताकि वे सरकार पर प्रभाव डाल सके और क्रेडिट स्क्वीज की जो पालिसी है उसमें ढील देने पर सरकार को मजबूर होना पड़े और उनको कर्ज आसानी से मिल सकें। वे कोशिश कर रहे हैं कि चीनी मिलों को वे देर से चलाएं ताकि जो उनके चलने का ड्यूरेशन है वह कम हो, उनकी कास्ट बढ़े और जब कास्ट बढ़ेगी तो वे गवर्नमेंट से बारगेन कर सकेंगे और कह सकेंगे कि वे न गन्ने का दाम नहीं दे सकते हैं और न मजदूरों की मजदूरी दे सकते हैं जब तक नाना प्रकार की सहूलियतें न मिल जावें।

मैंने इसी सदन में कहा था कि इस साल 60 करोड रुपया किसानों का बकाया होने जा रहा है। मेरे पास आंकड़े है, मैं उनको पेश करना चाहता हूं। सन् 1975-76 में 31 मार्च तक के आंकड़े मेरे पास हैं, उसमें टोटल केन-एरियर करीब-करीब 56 करोड़ रुपये है जो कि गन्ना किसानों का सारे देश में बकाया पड़ा हुआ है। 20 करोड रुपया केवल यू०पी० में एरियर है, इसी तरह 11 करोड रुपया पहले का बकाया है। अगर इस सब को लें तो 67 करोड रुपये से अधिक गन्ना किसानों का बकाया है।

मेरे क्षेत्र में मुगली चीनी मिल की हालत ऐसी है कि उसके पास करीब 44 लाख 15 हजार रुपया किसानों और मजदूरों का बाकी है। तीन महीने से मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली है, 16 लाख रुपया किसानों का बकाया है। 44 लाख रुपया मिल मालिक आज बैंकों से ले चुके हैं। कुल मिलाकर 80, 85 लाख रुपया का कर्जा उनके पास सरकारी और बैंकों का है। उसके बाद किसान, मजदूर का प्राविडेंट रिटेनिंग, सब का ब्रेक-अप मेरे पास है। उसकी यह स्थिति चल रही है।

इसी सदन में माननीय श्री शाहनवाज खां ने कहा था कि इस सीजन में गन्ना किसान का एक पैसा भी बकाया नहीं रह गया है। मुझे मालूम नहीं कि यह कैसे उन्होंने बताया। यहां पर मंत्री जी बैठे हुए हैं, अगर मेरे आंकड़े गलत हैं, वह बतावें कि मेरे आंकड़े गलत हैं।

इस घुघुली चीनी मिल मालिका ने अपना बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बदल लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कम्पनीज एक्ट में उसको कैसे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बदलने की परमीशन दी गई जब कि 80 85 लाख रुपया उनके पास बकाया है। रिकवरी सर्टिफिकेट अभी तक इनके विरुद्ध इश्यू क्यों नहीं हुआ तथा इनको जेल क्यों नहीं भेजा गया। किसान को तो 5 रुपये के लिये जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी तरफ 85 लाख रुपया बाकी है, तो क्यों नहीं यू०पी० गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन लेती? केन्द्रीय सरकार क्यों नहीं कहती कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाये? इनको जेलों में डाला जाये।

स्थिति इतनी ही नहीं है, मैं माननीय मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि 5 लाख रुपये में ये एक बायलर बेचने जा रहे हैं। मुझे आज ही वहां की चीनी मिल मजदूर यूनियन का पत्र प्राप्त हुआ है, कि मजदूर भूखे मर रहे हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब है, जो मेहतर हैं, अन्य जाति के लोग हैं, उन्हें तीन-तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। यह मेरा क्षेत्र है, ऐसी स्थिति में मैं वहां का

नहीं पा रहा हूं, मैं सोचता हूं कि क्या व्यवस्था करूं।

मैं माननीय मंत्री जी से बाग्रदब कहना चाहता हूं कि अगर देश में एमरजेंसी है तो वह जिस तरह से गरीब के लिये है, वैसे ही आज इस मिल-मालिक के लिये भी है, क्यों नहीं इस मिल के मालिको को कैद किया जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है कि 14 दिन के अन्दर गन्ना किसान का पैसा दिया जाये? आज तक 64, 65 करोड़ रुपया बकाया है, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है?

भार्गव कमीशन की रिपोर्ट आपके पास है, मेरा कहना यह है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। हमारी सरकार और खाद्य मंत्री जी का प्रस्ताव है। न केवल उनका प्रस्ताव ही है, मैंने इनके प्रस्ताव का समर्थन किया है और इसके बाद सारी कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया है। यह समर्थन इसलिये किया गया कि जिन मिल-मालिकों से हमारे उत्तरप्रदेश और बिहार के किसानों को परेशानी हो रही है, अगर आप उन किसानों की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, तो उनको इन मिल-मालिकों से त्राण दिलावें।

अब आप सोच रहे हैं कि करोड़ो रुपया इनको माडर्नाइजेशन के लिये दें। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आप एक पैसा भी इनको न दें। आप एक शुगर अथॉरिटी क्रिएट करें जो कि इस तरह के जर्जरित तथा बीमार मिलों को लेकर चलावे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मजदूर, किसान आपका साथ देंगे, हम आपको पैसा देने के लिये तैयार हैं, लेकिन आप इनको एक पैसा भी न दें और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करें। आप शुगर अथारिटी बनाकर चीनी मिलों का कब्जा अपने हाथ में लें।

बापूजी भविष्य के प्रकाश हैं, मुझे विश्वास है कि बापूजी, जिन्हें हमारे देश में धरती-पुत्र कहा जाता है, इन किसानो की करुणगाथा को सुनकर ऐक्शन लेंगे, क्योंकि उन्हीं के हाथों से इस देश को चलना है, उन्हीं पर किसानों, मजदूरों और इस देश के सर्वहारा वर्ग को खिलाने की जिम्मेदारी है। इन शब्दों के साथ मैं मांगो का समर्थन करता हूं।

SHRI RANABAHADUR SINGH (Sidhi): Sir, I believe that no other Ministry in this country carris a greater burden on itself, as far as the national future is concerned, than the Ministry of Agriculture; and this burden has been further increased by the rapid strides that our population is making and, at the same time, the increasing possibility of providing solutions has also come into the hands of this Ministry by virtue of the increase of our scientific knowledge. While agriculture is showing greater production every year, it is also an observable fact that there are things which are happening on the agricultural front which require urgent action. For example, it has been noticed that on a large scale in our region, that there has been a consistent fall in productivity, especially in the production of wheat, in spite of the fact that the farmers are given good seeds and they are given the fertilizers required and they are also irrigating. Now, here is a very, very disturbing factor which should find a place on a most priority basis among the Ministry's thinking, and research should be directed towards this problem.

Research in this country, to my mind, in spite of having a hoary history behind it, still has a time-lag between the recognition of a problem and solution of it. This, of course, should find a remedial measure and I am sure that at Bapuji's hands, this could possibly be solved before it takes on a more disturbing aspect. I believe there should now be a re-orientation of research. Any research of a far-flung nature which has no direct bearing on the requirements of the small farmer becomes redundant because the findings do not help the

[Shri Ranabahadur Singh]

farmer immediately to solve his problems. So, a symbiotic research which would take cognisance of the farmer's needs today and present solutions within a week or within a month is what our country requires on the agricultural front. And, for this, I believe that there might be a possibility of providing regional Committees for the ICAR....

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI JAGJIVAN RAM): This has been done

SHRI RANABAHADUR SINGH: Thank you. If this has been done, I should again congratulate Bapuji because he has taken the words out of my mouth and he has already done it. But I hope this would be carried down to the level where a direct communication link with the farmers at the village level finds a place in our ICAR Board meetings here in New Delhi.

It has been a matter of great satisfaction to read this new booklet by Shri C Subramaniam "Strategy for integrated Rural Development" On p 3, in para 2.4 he lays down a parameter for research and I think this is what would really have a meaningful impact on our agricultural production. It is a long paragraph and I won't burden the House by reading it; but I would mention that this should be read by every person who goes in for agricultural research before he sets out on the task. But, in my very next sentence, I have to give vent to a feeling of disappointment that, on reading the ICAR's Report and on reading the annual reports of the Ministry, I find that one factor which I have been consistently bringing up before the Ministry has again received very slight mention. This factor is research in hybridization of minor millet. Adivasis can never grow wheat; they can never grow rice. They will have to exist on this millet because they have been relegated to a type of land where neither of these sophisticated crops will ever grow, whether you link the Ganga to the Cauvery or whether you tame the God of Varuna. This particular land is suited only for these minor millets and so, the agricultural green revolution will never get to the doors of the huts of these Adivasis unless science takes into its hand to produce improved seeds of minor minor millets like *kodav* and *kutki* through hybridization and give them the capacity to become high-yielding.

It is also noticeable that this ICAR report on page 78 gives the places where research for minor millets is being carried out. This may be read with what is mentioned on page 10 of the same report, here only one instance is mentioned and that too in Tamil Nadu Agricultural University where a new short-duration variety, suited to rain-fed conditions and called *Samai* CO2, has been evolved. Minor millet research will have to be taken to the land where it is grown, and I think it is time that, urgent action is taken and this research is taken to those areas where it is grown.

Another factor that is troubling our farmers is the question of not being able to have a concise and comprehensive report or booklet which would (?)ides that are suited to the different pests that are troubling us in the farm field, that would list all the fertilisers with their trade names, with their composition and their use and, more importantly, that would give the veterinary medicines that are required by a farmer in his day-to-day living. Nothing like this exists today and the farmer has to run around finding the people who know about these. It is a waste of time. If the ICAR can put all this information togther in a booklet, which could be printed in regional languages and

distributed, the farmer would take care of most of the pests and diseases and the diseases of his animals on his own and become knowledgeable as to what remedy lies in his hands.

In the same context, there is a very concerning matter regarding the functioning of some of our Agricultural Universities. These Universities were formed with the express intention of helping the farmers, and the management of these Universities is now done by a Management Board. In the Universities that I know of, invariably are these Management Boards there are some representatives of the agricultural graduates. These agricultural graduates' representatives come to the Board by virtue of the support they receive from the agricultural graduates most of whom have become employees of the University. This creates a terrible vitiation of the whole orientation of the University-working. Instead of giving priority to the agricultural needs, most of the time of these Boards is spent on giving better service facilities to the agricultural graduates who are employed in the University and who have sent in these representatives. I would plead that a new look at the constitution of these Management Boards of these Universities might be undertaken.

I now come to the point of forests. Every one has become aware of the fact that we are losing our forests too fast for our good. In the last Central Board of Forestry meeting, it was the consensus that forests are one of our most-treasured assets and their dwindling is going to be a very dangeourous thing for us as a nation. In answer to my question I was told by the hon. Minister that he also is quite aware of this disturbing factor and that he is trying his best to do what is possible for re-forestation. I pointedly asked him as to how, he thinks he can involve the people into this most crucial aspect of national reconstruction, and on that score I felt that, in spite of the fact that he conceded that that was an important aspect of the problem, the thinking was still in the process of crystallizing.

In this respect, I would like to mention an experiment that has been carried out in my district. A barren piece of a hill which had lost all its vegetation was parcelled out amongst some of the farmers surrounding it and they were supposed to look after the trees standing on it. In about five years time that barren hill has 20 ft. high trees standing on it. The farmers use the forest for their fuel wood and in spite of their using it, the trees are there and they are looked after by these people. I mention this only in the context of the point that involvement of the people is under the active consideration of the Ministry and it may be helpful.

It is a matter of great satisfaction and pride that the State Ministry has given us a sanctuary in Sidhi district. It has recently been sanctioned. I plead with Babuji that some help from the Centre should be given to the sanctuary so that it might come up and the last remnants of the wild life may find protection at the hands of the Government.

In closing, I have to say that we as a people have before us a glorious future. The next decade might find this nation not only self-sufficient in food; but given the irrigation potentialities of the Ganga Canal; Rajasthan Canal and the Jaisalmer Sub-terranean Water Resources; it might be possible for us to become one of the major exporters of food for African and the Gulf countries. In this context of future; I would like to draw the attention of the Ministry to page 5 of Strategy for Integrated Rural Development, wherein para 3.1(d), a mention is made about how this Ministry could in conjunction with the people bring about this glorious future. I would think that this paragraph would find a major place in the thinking of the Ministry.

[Shri Ramabahadur Singh]

With these words, I support the Demands for Grant for the Ministry of Agriculture and Irrigation.

SHRI KRISHNARAO PATIL (Jalgaon): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands of Grant for the Ministry of Agriculture and Irrigation. While going through the report and the performance budget of the Departments very carefully, I am convinced that this Ministry deserves congratulations for its better performance during the previous year. At the same time, I would like to offer my compliments to the research scholars, scientists and experts working in the field of agriculture because they have done a wonderful job.

14 hrs.

Though this Ministry has done well, yet there are a number of programmes where there is some scope for giving suggestions for improvement. I would like to say something about the present atmosphere prevailing in the country among the peasants The situation in the various States may be different As far as the peasantry in my State is concerned, I would like to say this on the basis of my experience. The peasantry, the agricultural class is such that they feel insulated nowadays when we talk loosely something about the surplus land, vested interests and clash of interests They feel insulted when I say that right from 1939 the State Governments have passed tenancy laws, the first ceiling law, the second ceiling law and so no. So I would request the government to be very effective in implementing the ceiling laws and try to bring out the surplus land to be distributed. Let there not be an atmosphere of uncertainty because a guarantee of some stability in every walk of life is very essential. That is the incentive for marching ahead and this sort of an uncertain atmosphere which we create affects the psychology of the general masses also. I would request the very seasoned and dynamic leader, Babuji, to remove this uncertain atmosphere. Let there be stability. Let there be a certain atmosphere that there is now a stable thing, there is now an economic and valuable unit of land decided once for all and that we are going ahead with this. This is my first request.

Giving some suggestions, the first suggestion would be regarding the programme of high-yielding varieties. I must say that during the course of the last 8—10 years, of the total area under crop, particularly, of foodgrains, I think, the high-yielding area coverage so far is only about 30—35 per cent on an all-India basis. When I visited some States, I found that there are vast disparities In some States, the high-yielding variety coverage is only 10—20 per cent There is a lot of scope and the high-yielding varieties will definitely give better results. So far as my State is concerned, there is not even 20 per cent coverage. In some States it is only 10 per cent. This sort of disparity in implementation is not going to give good results. So my suggestion would be that so far as this high-yielding programme is concerned. I think, the department should be given a proper understanding right from the top to the bottom and it should be seen that the acreage under high-yielding varieties increases and better production achieved

The second point I would like to make out is that there is a huge land in this country which can give two crops, short-duration crops, even under the normal rainfall, but this opportunity is not fully being utilised. In some areas we are accustomed to grow two crops. For the last 20 years in our areas we are growing two crops under the normal rainfall. In some States there are huge areas which can easily grow two crops even under the normal rainfall. Of course, sometimes, nature changes its course, but the rainfall is not below 30—40

inches. During the course of the three monsoon months it will be better to go in for a short-duration crop like moong, groundnut and Bajra etc. After that we can grow the Rabi jowar or wheat. Thus the land can be utilised in a better way. This is my second suggestion.

My third suggestion would be regarding the long-term crop also. I am a bit doubtful whether this Department has taken into account the basic aspects in the development of land. Is there any co-relation between short-term credit and long-term credit policy? There is no such policy. There must be a long-term credit policy for agricultural development so that the land can be properly developed. There is no such policy and the Department has not got any assessment of the actual land to be developed. What has been happening for the last 25 years is this. We have been advancing loans to griculturists without proper planning. So far as land development is concerned, this should be done. There should be proper planning for long-term credit also.

My last point is this. I am making points only and not elaborating. So far as pricing policy is concerned, during my *padyatra*, people have been asking me the question: Is there any overall pricing policy in this country? They asked me such questions. They asked me why there is lot of disparity between agricultral and finished produce. I cannot give any justifiable reasons for this. I could not satisfy those people. Therefore, Sir, what I feel is, a stage has come in the economic life of the country that the Planning Commission and this Department should insist on parity in regard to pricing policy so that the people would not feel that their produce is not being given the proper price.

Before concluding, I wish to refer to cooperatives and panchayat raj. Regarding panchayat raj, the Centrally sponsored, the States and other schemes are all being implemented by these panchayat raj institutions. Panditji expressed his hope during the Nagpur session that panchayat raj institutions are going to do lot of good. After this decentralisation of 10 or 15 years, I find that the staff working at the district and panchayat level are not being properly utilised. There should be effective implementation even at the taluka level so that the agriculturists could get the benefit from these schemes. Effective implementation of the programmes for the benefit of the agricultural classes is necessary. Thank you.

श्री जगदीश नारायण मंडल (गोड्डा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाज कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बाबू जी, आपके मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं अन्न के मामले में आपको सफलता मिली। इस साल देश में 11 करोड 40 लाख टन अनाज पैदा होने की उम्मीद है जिसका श्रेय आपके मंत्रालय के प्रयत्नों को जाता है। आपके मंत्रालय ने देश में किसानों को उन्नत बीज का वितरण कराया, रसायन खाद किसानों को दिलाया और जो कमी रही उसकी पूर्ति के लिये विदेशों से भी खाद मगायी। रसायन खाद की कीमत आप ने काफी बढा दी है, फिर भी 200 करोड का आज घाटा है। एक साल के अन्दर आप ने चार बार खाद की कीमत में कमी की है। आप ने इरादा किया है कि एक साल के बाद हम इस देश मे खाद की सारी समस्याये हल कर लेंगे। सिंचाई की व्यवस्था मे भी काफ़ी तेजी आयी है। जो जमीन बेकार पड़ी थी उसको उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया। रिसर्च के द्वारा बीजों के अनुसंधान मे इस देश को दुनिया मे दूसरा स्थान मिला। गेहू, धान, अरहर, चना, बाजरा के अलावा बाबू जी का यह विचार है कि कोदों और मडुआ और कुरथी आदि का भी रिसर्च करायेंगे। जो बिहार राज्य

[श्री जगदीश नारायण मंडल]

संथाल परगणा और छोटे नागपुर की मुख्य फसल हैं। आपातकालीन स्थिति से आपके मंत्रालय के द्वारा चोर बाजारी और मुनाफ़ाखोरी पर रोक लगी है और हजारों लाखों मन गल्ली जो पहले लोग छिपा कर रखते थे, वह आज बन्द हो गया है। आज तो स्थिति यह हो गई है कि अनाज के सम्बन्ध में जो दरें सरकार ने निश्चित की है उससे भी नीचे दाम गिर रहे हैं। आप को बफ़र स्टाक बनाने के लिए जल्द से जल्द अनाज रखने के लिए गोदाम बनाने की जरूरत है। आज जहां भी हम गये हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में हम ने देखा है कि लाखों मन अनाज गोदामों के बाहर पड़ा हुआ है।

बाबू जी, आप ने एक बार सलाहकार समिति की बैठक में यह कहा था कि आज गंगा दशहरे का दिन है और सारे देश में रात में वर्षा हुई है। इसलिए इस साल पूरी फ़सल होगी, और अच्छी वर्षा देश में होगी। इस देश का खाद्य मंत्रालय भगवान पर विश्वास करता है और जो अन्तरात्मा से सोचता है, भगवान अवश्य उसको पूरा करते हैं। यह जो आपका विचार है कि देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, यह स्वप्न भी आपका पूरा होगा।

चीनी के सम्बन्ध में काफ़ी माननीय सदस्यों ने आपको बताया है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज किसानों का काफ़ी रुपया मिल-मालिकों पर बाकी है। यह शुभ लक्षण नहीं है। आपके प्रयत्न से इस साल काफ़ी रुपया वसूल किया गया है लेकिन अभी भी काफ़ी रकम बाकी है। करोड़ों रुपया उनका मिल मालिकों के पास पड़ा है। यह रुपया जल्द से जल्द वसूल हो जाये, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए।

आज आपके मंत्रालय के द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध काफी किया गया है लेकिन सिंचाई के मामले में जितना आगे बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं हो सका है। आज आप का लक्ष्य है कि हम बहुत जल्दी सारे देश की नदियों के पानी को कन्ट्रोल करेंगे और सभी नदियों से सिंचाई का प्रबन्ध करेंगे लेकिन एक बात आप को यह भी सोचनी है कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं या पिछड़े हुए इलाके हैं और जिनका सिंचाई प्रतिशत बहुत कम है, उनमें ज्यादा सिंचाई उपलब्ध करने के लिए आपको चिन्तन करना चाहिए। आज बिहार की स्थिति यह है कि वहां पर बाढ़ और सुखाड बराबर लगा ही रहता है और उससे करोड़ों रुपये की क्षति होती है। इस पर आप को चिन्तन करना चाहिए। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सुखाड की हालत यह है कि वहां पर पानी का साधन रहते हुए भी आज सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है। मैं आपको अपने ज़िले की संथाल परगना की बात बताता हूं, सिंचाई के साधन होते हुए भी 2 प्रतिशत इर्रीगेशन है। जबकि हमारे यहां मही राक्षी तथा दामोदर योजना है उससे पश्चिम बंगाल के लोग अपनी जमीनों की लाखों एकड़ की सिंचाई करते हैं हमारे यहां 2 प्रतिशत ही इर्रीगेशन है।

आज हम यह देखते है कि जिस सिंचाई योजना का सर्वे होता है, उस पर कुछ अमल नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि सुग्गाथान में एक ऐसी स्कीम है जिसका सर्वे 20 वर्ष से हो रहा है लेकिन आज तक वह स्कीम पूरी नहीं हो सकी है। हमारे ज़िले में इस तरह की कई नदियां हैं जैसे बांसलोई, गुमानी, और अजय, जिन को अगर कन्ट्रोल किया जाए तो काफी सिंचाई हो सकती है। योजना को जल्द बनाया जाये लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है।

हमारे यहां पहाड़ियों की समस्या है। संथाल परगना ज़िले के पहाड़ में रहते हैं और उनकी जनसंख्या पहले 3 लाख के करीब थी लेकिन अब वह घट कर डेढ़ लाख रह गई है उनकी सारी जीविका नष्ट हो गई है। उन

और आर्थिक साधन थे वे सब नष्ट कर दिए गए हैं। पहले जो आस पास आठ लाख मन होता थी आज घट कर आठ दस हजार मन ही होती है। पहाड़ के ऊपर ये लोग कुरथा की खेती करते थे कुरथा भी सब नष्ट कर दिए गए हैं और उनको सिर्फ जंगल में डाल दिया है, फलदार वृक्ष जैसे महुआ, आम, कटहल, बांस यह भी सब नष्ट हो गया है। अब उनके पास खाने लायक कोई चीज नहीं रह गई है। साढ़े तीन लाख से उनकी जनसंख्या डेढ़ लाख रह गई है। उनकी जनसंख्या निरन्तर कम होती जा रही है। अगर यही स्थिति चलती रही तो एक दिन वे समाप्त ही हो जाएंगे। इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी तरफ़ भी आर्थिक मामले में आपका ध्यान जाए।

SHRI P. NARASIMHA REDDY (Chittoor): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while supporting wholeheartedly the demands for the Ministry of Agriculture and Irrigation, I would at the outset express my surprise at the statement made by our distinguished colleague, Shri B. N. Reddy while initiating the discussion. He ascribed the entire credit for the bumper harvest to the monsoons and nothing to the policies of the Government and the Ministry. It is surprising that such a view is given expression to by some both inside as well as outside the House. It is an accepted fact that science and technology or any other technological means have yet to be evolved which would bring or make the rain bring paddy or wheat etc. straight from the heavens.

Sir, it is on account of the steady and thoughtful policies of this Government and the consistent decades of planning that has gone in the right direction that the necessary infrastructure has been built up in this country so as to take advantage of such monsoons and translate them into concrete terms of foodgrains. This aspect should not be lost sight of. In this connection I join Mr. Ramabahadur Singh in hailing the new strategy for integrated rural development that had been propounded at the time of the budget speech by the hon'ble Finance Minister. That has given us in essence and in brief, the guidelines for the future development of our agriculture and irrigation in this country. I would say not only irrigation and agriculture but the total development of the entire resources of the country for which we have been pledged ever since Independence.

Sir, while applauding the efforts made and the results so far achieved, I would share my misgivings in one respect, namely, that this country too long dependent on imports and ridden with shortages has not yet equipped itself to cope up with the problems of surplus. Sir, it became evident when the unusual good harvest last year had almost taken the Government by surprise. The price support was not at all in evidence anywhere. The institutions on which we had relied for procurement and price support policy unfortunately failed miserably. Apart from some selected centres, in many parts of the country and particularly in several districts of Andhra Pradesh the small and marginal growers had to sell their produce at ridiculously low prices.

Apart from this failure on our part to ensure adequate procurement and support pricing policy, the food control machinery also began to fumble and further accentuated this serious crisis in the agriculture price field. For example, the foodgrains movement control which had been brought into existence in scarcity-situation, to prevent and control movement of foodgrains with a view to insulate the prices against such undesirable movements, left us in the lurch and did not at all vary or alter to suit the new situation of surplus. The result is that when there were bumper harvests, on account of the State Governments' continued adherence to the same control of foodgrain movements, pockets and areas of

[Shri P. Narasimha Reddy]

scarcity and high prices were sedulously maintained. Even after bumper harvests right till now the same situation continues with pockets of scarcity all along the borders of each State. Each State is supposed to be a separate zone and foodgrain movements control would prevent movement of foodgrains from out of the State as well as within the State; this continues to be in force with the same rigour and, in my opinion, thoughtlessness. Many representations were made to the State Governments and the Central Government to relax the foodgrain movements control which has been causing hardship to the people and creating scarcity in the face of the surplus we are having in this country. This deserves to be looked into at once. We must have a flexible foodgrain movement control and machinery which will cope up with scarcity as well as surplus and ensure that such hardships are not caused to the people.

Again, the problem of surplus has highlighted our weaknesses in the management of food economy Due to want of storage capacity and adequate nagement of food economy. Due to that even today stocks of valuable grains procured are stored in the open inadequately protected, risking heavy loss and deterioration in quality. We must equip ourselves with sufficient storage capacity and distribution machinery to handle right up to 20 million tonnes, which would be the expected quantity which would be handled by the public distribution system by the end of the century.

In addition to this, it cannot be denied that our agriculture is still largely a gamble in the monsoon. The inevitability of uncertain weather must always be kept in our calculations (*Interruptions*). The advantage you take of this weather, favourable or unfavourable, depends on the expertise you have developed, the infrastructure you have built up and the planning that has gone into this aspect of the matter. It is to this that I draw the attention of this august House.

It is true, as hon. members have pointed out, that after independence we have doubled the area under irrigation, we have built up a vast infrastructure of science and techonology and various industrial inputs to prop up our agriculture so that even in times of adversity when there is no good monsoon we are able to insulate the country against acute scarcity. Last year I distinctly remember the hon. Minister, Shri Shinde, while interveing in the discussion, was able to highlight this fact that even in case of adversity, even when the monsoon failed, overall agricultural production had been raised to such a height that the hardships caused to the people had been very much minimised and the country safeguarded against the regours of adverse weather conditions. It is a fact that the vagaries of the weather will be long with us and cannot be ruled out; they must be reckoned with. In this connection, I would urge upon the Ministry of Agriculture to apply its mind to strengthening its efforts to intensify the drought eradication programmes in the country. Shri Venkatasubbaiah had pointed out the case of Rayalaseema which has been a chronic drought area which has a history of centuries of suffering and deprivation. The drought prone areas programme now implemented by the Government to tackle this drought condition has no doubt extended a considerable amount of protection to these areas, but much more remains to be done. Major steps have got to be thought of if drought conditions are to be eradicated permanently.

In this connection, I welcome the suggestion made by many honourable speakers before me. Thanks to the wise intervention and statesmanship of our central leadership, the riparian States have agreed to spare water to

the people of Madras to meet their drinking water needs. The proposal of taking water from the Krishna river to Madras city is a historic one and the scope of that project could be expanded and the Krishna water could be conveyed through the drought affected area to mitigate the drought conditions in the Rayalaseema.

I shall conclude with one main problem; I want to draw the attention of the hon. Minister to this problem. In connection with International Development Association (IDA) assisted tractor loan programme of this country, 22,000 tractors are being imported and distributed to the states through the agro industries corporations. When this programme was initiated the price quoted for an IMT 355 tractor was about 54,000 rupees and it is on that basis applications were taken and advances were collected and banks, also arranged credit. Subsequently one came to know that the price was about Rs. 60,000. To my question tabled in this House a reply was given that a commission of 20 per cent was given to the importing agent on the whole tractor and a commission of 44 per cent was allowed on the import of spares. It is astonishing that this much is allowed as commission on the import to an importer; it is an unconscionable burden on the poor, miserable agriculturist. It is unthinkable that an import agent who merely imports tractors from Yugoslavia, from a state-owned plant on rupee account is given such a high percentage of commission.... *(Interruptions)*. In regard to sugar policy, you have said that the sugar factories will be given only 12.5 per cent return on the capital outlay. You have meticulously worked out every pie that goes into the capital and the cost of production and so on But for merely importing a tractor and distributing it to the agiculturist, a twenty per cent commission on the whole tractor and 44 per cent commission on spares is allowed and the prices have been raised. The Ministry should intervene and reduce the prices.

श्री भगत राम मनहर (अंजगीर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और सिंचाई मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मन्त्रालय ने जनहित में काफ़ी उत्साहवर्द्धक काम किया है जिससे खाद्यान्न की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके लिए इस मन्त्रालय के मन्त्रिगण, इसमें कार्यरत अधिकारीगण तथा खास कर कृषि वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। कृषि का क्षेत्र यों तो काफ़ी व्यापक है, फ़िर भी इस मन्त्रालय ने कुछ अनुकूल काम इस दिशा में किया है।

कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान गेहूं, ज्वार, मक्का, कपास, धान आदि फ़सलों की ओर तो गया है, इन के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी खोज की है। लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है जंगलों में रहने वाले आदिवासी हरिजन और पिछडे तबके के लोग हैं उनका खास भोजन कोदों, कुटकी और लेसर मिलेट हैं, उसके उत्पादन को बढ़ाने की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया है। इस मन्त्रालय से मेरा निवेदन है कि इस दिशा में वे विशेष ध्यान देंगे।

हमारी कृषि नीति में कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं जिससे आप लोगों में काफ़ी असन्तोष है। अभी जितने नियम बन रहे हैं और उनमें परिवर्तन हो रहे हैं उससे कृषक अनिश्चय के वातावरण में है कि वह अपनी खेती का किस तरह विकास करे। अगर विकास करता है तो सीलिंग में वह जमीन कहीं निकल तो नहीं जायगी और अगर रह जाती है तो उसकी क्या स्थिति होगा यह सारी स्थिति उसको अभी अस्पष्ट है। इसलिए मंत्रालय से मेरा निवेदन है कि इस दिशा में कुछ सोच कर के पन्द्रह बीस साल के लिए कम से कम किसानों को कुछ आश्वासन दे ताकि किसान आश्वस्त हो जाय और उसके उत्पादन की प्राइस भी रेक्योर्ड हो, इसके लिए भी मन्त्रालय कुछ प्रबन्ध करे।

[श्री भरत राम अहूर]

दूसरी चीज यह है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, समाजवादी देशों की हम नकल कर रहे हैं, समाजवादी देशों में खाद्यान्न की स्थिति यह है कि यूगोस्लाविया को छोड़ कर बाकी जितने भी समाजवादी देश हैं वे रूस के सब खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं हैं। सब के सब बाहर से खाद्यान्न मंगवाते हैं। सोवियत रूस भी मंगवाता है। उसका कारण यह हैं कि वहां पर कुछ ऐसी नीति अपनाई गई है कि जो मजदूर खेती में काम करते हैं वे काम करने के बाद फ़िल्म और टेलीविजन देखते रहते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा उनका खेती में कोई लगाव नहीं रहता है। दूसरी ओर हमारे देश में दूसरी नीति है। किसान अपने खेत को अपने हृदय से भी अधिक चाहता है। यदि रात को भी जरूरत पड़े तो रात में भी काम करने के लिए खेत पर जाता है और अपनी खेती की पूरी देखभाल करता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं समाजवादी देशों की नकल न करके जो हमारे देश की स्थिति है जो बात हमारे देश के अनुरूप हो उसी को यहां पर लागू किया जाये और उसी के अनुसार कृषि नीति निर्धारित होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं कृषकों की पैदावार के बारे में कहना चाहता हूं। जिस समय किसान अपना गल्ला बेचता है उस समय गल्ले का भाव सस्ता रहता है लेकिन जब किसान का गल्ला किसान के पास से व्यापारियों के गोडाउन में पहुंच जाता है तो सरकार समय समय पर नीति को परिवर्तित करती है जिससे किसानों को कोई फ़ायदा होने के बजाये व्यापारियों के हाथ में मुनाफ़ा आता है। इस बात की ओर भी शासन को ध्यान देना चाहिए।

अब मैं प्रशासनिक दृष्टि से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी जिले और ग्रामीण स्तर पर आपके जितने अधिकारीगण काम करते हैं हैं उनके पास कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है। नतीजा यह होता है कि जब किसानों को बीज, खाद और दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो ये चीजें उनको पास नहीं पहुंचती हैं। फसल में बीमारी लग जाने के समय किसान दवाई ढूंढते हैं लेकिन वह मिलती नहीं। यही स्थिति है कि जब आग लग जाये तब कुआं खोदने की बात सोची जाये। ऐसी स्थिति में जब तक आप उनको पूर्ण रूप से सक्षम नहीं बनायेंगे, कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं अपनायेंगे तब तक मैं नहीं समझता आप खेती में कोई विशेष प्रगति कर पायेंगे। खेती की पैदावार इसलिए कम हुई कि इंटीरियर में जितने सेन्टर्स हैं वहां पर खाद नहीं थी? जिस समय किसानों को खाद चाहिए उस समय कहा जाता है स्टाक में खाद नहीं है। आवागमन के साधनों की इतनी तकलीफ़ है कि सेन्टर से ले जाते समय अगर रास्ते में बारिश हो गई तो खाद घुल जाती है और सारा लाना ले जाना बेकार हो जाता है। इसलिए सरकार को खाद की एडवांस स्टाकिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चर की जो सर्विस है उसको आई ए एस और आई पी एस की तरह आल इंडिया एग्रीकल्चरल सर्विस बनाना चाहिए। दूसरे जो कृषि विभाग हैं वह अभी भी टेक्निकल विभाग घोषित नहीं हैं रिकार्ड के ऊपर हालांकि बाहर जाकर आफ़ दि रिकार्ड उसको टेक्निकल सर्विस कहते हैं। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से सहकारिता में अभी भी बड़े लोगों की मानोपली चली आ रही है। हरिजन आदिवासी और पिछड़े लोगों को वहां पर किसी भी समिति में उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है जिसके कारण जब उनको ऋण लेने की जरूरत होती है तो उनको समय पर ऋण उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार से जो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं उनके द्वारा किसान, हरिजन, आदिवासी और पिछड़े लोगों को भले ही आपके रिकार्ड में और बोल चाल में ऋण दिए जाते हों लेकिन वास्तविक स्थिति

बिल्कुल इसके विपरीत है । आज भी यह लोग साहूकारों के चुंगल में फंसे हुए हैं । अब स्थिति यह है कि न तो बैंक ही उनको ऋण देते हैं और न साहूकार ही उनको ऋण दे रहे हैं । ऐसी स्थिति में केवल प्रचार न करते हुए जो असलियत है उसको ध्यान में रख कर इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

जब सिंचाई की बात आती है तो हम कहते हैं बहुत से जल विवाद हैं लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है । अगर पैसा नहीं है तो जल विवाद हल होने से भी क्या फायदा होगा ? अगर पैसा है तो बहुत सी ऐसी छोटी मोटी योजनायें हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है उनको आप क्यों नहीं लेते है ? दो तरह की बात सरकार कहती है—एक तरफ कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ यह कहती है कि बहुत सी योजनाय जल-विवाद में पड़ी हैं । इस ओर आप को ध्यान देना चाहिये ।

फ़ारेस्ट डेवलपमेन्ट के बारे में मुझे यह कहना है कि बस्तर ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत बड़ा फ़ारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है । अभी वर्ल्ड बैंक ने वहां के डेवलपमेन्ट के लिये 6 करोड़ रुपया दिया है, 2 करोड़ रुपया केन्द्रीय शासन से और दो करोड़ प्रदेश शासन से मिलेगा—अब देखना यह है कि वहां पर किसी तरह का एक्सप्लायटेशन न हो वहां के आदिवासियों को सैमिस्किल्ड कामों पर रखा जाना चाहिये, इस के लिये उनको ट्रेनिंग दिये जाने की व्यवस्था कीजिये ।

डेयरी विकास तथा ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिये बस्तर बहुत उपयुक्त सेन्टर है । जहां जमीन है, घास है, पानी है और मजदूर है—इतना सब कुछ है, अब केवल केन्द्रीय सरकार की मंशा की जरूरत है, यदि सरकार यह निश्चय कर ले तो इस के काम के लिये वहां से उपयुक्त स्थान दूसरी जगह नहीं हो सकता और इससे उस इलाके का पिछड़ापन भी दूर होगा ।

"एस० एफ० डी० ए० तथा सीमान्त कृषक विकास अभिकरण के तहत पशु पालन एवं डेयरी उद्योग के लिये छोटे किसान उत्पादन यूनिट के पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत और सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक 33.33 प्रतिशत राज-सहायता पाने के पात्र हैं" ऐसा आप की रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन यह सिर्फ़ कागज पर है, ग्रामीणों को इस का कोई लाभ नहीं मिल रहा है । मैं चाहता हूं कि इस की तरफ़ आप का ध्यान आना चाहिये ।

अन्त में अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा—बिलासपुर सम्भाग में इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है । लेकिन दूसरी तरफ़ कर्ज की वसूली का काम बहुत जोरों से शुरू हो गया है, किसानों ने जो पहले कर्जा ले रखा था तथा बाद में जो लिया था, सब की वसूली एक साथ हो रही है और बहुत सख्ती के साथ उन से रुपया वसूल किया गया है, जिस का नतीजा यह हुआ है कि किसानों के पास खाने को भी नहीं बचा है । ऐसी स्थिति में वहां पर राहत कार्य की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां लोगों के भूखा मरने की स्थिति हो गई है । मेरा मंत्रालय से निवेदन है कि वहां पर राहत कार्य खोलने की शीघ्र व्यवस्था की जाय ।

SHRI K. PRADHANI (Nowrangpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands of the Agriculture Ministry.

Our country which has 15 per cent of the world's population, has only 2.4 per cent of the available land. With such a high density of population and with day to day increase in population, the food question in India always remains as a national problem. During

[Shri K. Pradhani]

the last three years, we imported 3.6, 4.8 and 7.4 million tonnes of foodgrains from outside to meet the deficiency of our country. Severe drought had resulted in the steep rise in prices in 1975. But the prices have been brought down by the enforcement of anti-inflationary measures, proclamation of emergency and due to the good harvest in 1975-76. Now, as per the present situation, the consumers are very happy but the producers are not so happy. The reason is that the prices of the inputs, like bullocks, tractors, etc. have not come down but they have to sell their foodgrains comparatively at a cheaper price. Secondly, the cultivators cannot sell their produce according to the support price fixed by the Government, because most of the procurement centres are overladen with stocks that they have already purchased, and some of them have stopped procurement of foodgrains due to want of accommodation My suggestion is that in order to give an incentive to the cultivators, we should impose some restrictions on the price of bullocks and arrange to clear the stocks already available with the procurement centres

Now about buffer stocks. We have produced 114 million tonnes of foodgrains during 1975-76 and we already have about 9.7 million tonnes of foodgrains in our buffer stock. We cannot be complacent with this reserve, because from our experience in the past we have seen that in each and every alternate year we get natural calamities; and our production is affected So, I humbly suggest that the buffer stock should be as big as to feed at least all the 'needy' or deficit retail centres in our country for two consecutive years. Only then we can say that we can meet any eventuality in future.

I now come to the classification of paddy, adopted by the FCI. This does not tally with the local classification off paddy. For example, 'Basmati' rice is one of the standard varieties of paddy adopted and accepted by the FCI. There are finer varieties of rice than Basmati, in size, shape and smell; but they are not accepted as super-fine varieties of rice, because they do not tally with the formula adopted by the FCI. They have got a measuring instrument; they say that the length divided by thickness should give 2.8 to 3. If it is less, even though the variety is finer and smaller in size, it would not be accepted as superfine. Thereby, the producer suffers. The finer the rice, the lesser is the quantity of production. Thereby, the cultivator will be losing both ways. If the length ratio is accepted by the local people and they regard the variety as superfine, why should it not be accepted as such by the Government, even though it is shorter in length—if it is superior in other respects?

Now about agriculture and cooperative societies Ours is a country where about 80 per cent of the people live on agriculture; some as owner-cum-cultivators and others as landless labourers In States like Orissa where 65 per cent of the people live below the poverty line, land is not a problem; but the problem is one of inputs. The basic factors of agriculture are land, water and inputs In a large number of holdings, there is lesser production, only due to inadequacy of inputs We have got a number of cooperative societies in our State, and in our country as well In Karnataka, it seems that 86 per cent of the mofussil people are covered by these societies. The percentages are something like 79 in Himachal Pradesh and 77 in Punjab; but in the case of Orissa, only 37 per cent are covered by these societies As a result, more than 50 per cent of the holdings give lesser production. I would urge upon the hon. Minister to expand these cooperative societies, particularly in such States, so as to cover the weaker sections of the society to the maximum, in furtherance of the 20-point programme.

I now come to irrigation. I come from a district where irrigation facilities are provided to less than 1 per

of the area. I think that this is the lowest figure and that place is the worst and most backward one in our country. The Department of Rehabilitation of the Government of India has taken up Poteree project since 1972-73 and it has provided Rs. 101 lakhs, as against Rs. 108 lakhs provided by the State Government. During the year 1975-76 they have released less amount. It is the feeling of the State Government that it is only due to the tardy release of funds by the Government of India that the progress of the project has been delayed. I bring it to the notice of the Agriculture Ministry that they should remind the concerned department to release adequate funds for this project as early as possible.

Secondly, the Kolab multi-purpose project is taken up by the State Government of Orissa out of the State Plan. This project consists of two parts, the hydel project and the irrigation project. The hydel project costs Rs. 58.97 crores. The State Government financed Rs. 5 crores during the Fifth Plan period. At this rate, it will take 50 more years to complete the hydel project and another 50 years to complete the irrigation portion. So, it is not even the second generation but the third generation that can see the completion of this project. I am not saying this to expose the State Government but simply to show the constraints on the resources of the State Government.

During this year, the Government of India have taken over and financed many projects under irrigation, taken up by the States out of their Plans, where they found there is some constraint on resources, in order to co-operate with them in the implementation of the 20-Point Economic Programme to help the weaker sections of the society. This particular area is a Scheduled Area, predominently inhabited by tribals and Scheduled Castes. It is more or less under the direct control of the Government of India. So, I would urge on the Agriculture Ministry to intervene in this case and take up this project immediately as a Central project and complete it to help the weaker sections of the society.

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज): मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप का शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे मौका इनायत किया है। मैं अर्ज करूंगा कि मुल्क की मजबूती की जांच व परख इस तरह की जाती है कि उस मुल्क की बागडोर किस शख्सियत के हाथ में है। तो इस मामले में हमारा मुल्क भारत बड़ा खुशकिस्मत है कि इस देश की बागडोर ऐसी लीडरशिप के हाथ में है, जिस ने बेरूनी और अन्दरूनी खतरों का बाहिम्मत और बुलन्द हिम्मत से मुकाबला किया है और यह उन की सियासी सूझबूझ थी कि उन्होंने मुल्क के बढते हुए कदमों को पीछे हटने नही दिया यद्यपि इसकी साजिश की गई, बल्कि और आगे बढ़ाया चाहे जितनी बात हुई हैं, चाहे बेन उल अक्वामी फ़ील्ड में हों, या फ़ौजी मैदान में हों या एग्रीकल्चर के मैदान में हों या प्रोडक्शन के मैदान में हों।

इस वक्त जेर-ए-बहस खेती है, इसलिए मैं अपनी बहस को उसी तक महदूद रखूंगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह महकमा अब बाबू जी के हाथ में है जिन को सलाहियत के बहुत से नमूने हैं। उन में से एक बंगला देश भी एक नमूना है। वह मैदान मारने के बाद अब वे इस महकमे में तशरीफ़ लाए हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि उन के इस महकमे में रहने के बाद इस में काफ़ी तरक्की होगी और वे निहायत कामयाब रहेंगे। जब से यह महकमा उन के हाथ में आया है, बहुत अच्छी खासी तब्दीली इस महकमे में आई है। आप मुलाहजा फ़रमाइए कि इमरजेन्सी लागू होने से पहले लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, कीमतें आसमान को छू रही थी और गरीबों की

[श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान]

माली हड्डियां करीब करीब टूट गई थीं। नौकरी पेशावाले परेशान थे, मजदूर परेशान थे गर्जेकि हर जगह मुर्दनी छाई हुई थी। मुल्क की पैदावार में रुकावटें डाली गई और हर तरह की कोशिश की गई थी कि मुल्क की पैदावार आगे न बढे। गर्ज कि हर वे काम किये गये जिससे मुल्क की माली हालत कमजोर से कमजोर हो जाए और ये सारे काम बेरूनी मुल्कों के इशारे पर हुए। लेकिन इस मुल्क की रहनुमा ने देश को बचा लिया और जो वायदे हम ने लोगों से किये थे उन को पूरा कर रहे हैं। आप मुलहाजा फ़रमाए कि इमर्जेन्सी लागू होने के बाद से मुल्क में हर तरह का अमन है और हर फील्ड में प्रोडक्शन बढ़ा है। इस में कोई दो राय नही हैं। मुल्क खाने में खुद कफील हुआ है और खेती की पैदावार बढी है, इस में दो राये नही है। लेकिन इसको भी आपको मानना होगा कि मुल्क की आबादी का अस्सी परसेंट हिस्सा खेती के काम में लगा हुआ है, गावों में रहता है आपको देखना चाहिये कि उनको किन किन चीजो की जरूरत पडती है खेती को आगे बढ़ाने में। जरूरत पडती है पानी की, बिजली की, खाद की, बीज की और दवाई की। जहा तक पानी का ताल्लुक है पानी हमारे मुल्क में काफ़ी है लेकिन उसका इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है यह देखने वाली चीज है। आस्मानी बारिश से हम लोग खेती करते हैं। वह बारिश काफ़ी नहीं है। हम लोग नहरी पानी या पम्पिंग सैट लगा कर लोगों को पानी देकर इरिगेशन की फ़ैसिलिटीज को बढ़ा कर खेती की पैदावार बढा सकते हैं। अभी 45 मिलियन हैक्टर जमीन को नहरों से पानी दिया जा रहा है। इसको बढ़ा कर 160—165 मिलियन हैक्टर किया जा सकता है। इसका आपको इंतजाम करना चाहिये और नहरें खुदवानी चाहियें।

जहां तक बिहार का ताल्लुक है मैं कुछ बातें खास तौर पर कहना चाहता हूं। कोसी प्राजेक्ट जिस मकसद को सामने रखते हुये बनाई गई थी वह मकसद ही फौत हो चुका है। आज भी हम देखते हैं कि जितना पानी आना चाहिये वह आता नहीं है। हालांकि मेरे गांव में जो नहर है उसके टेल एण्ड तक में पानी नही आता है लेकिन बीच बीच में इतना कम पानी आता है कि एक किसान और दूसरे किसान में झगड़ा हो जाता है। यह आये दिन की बात है। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये।

जहा तक कोसी के सैण्ड सिल्ट का ताल्लुक है अगर आप दो चार बरस के बाद मेरे इलाके में आयेंगे तो आप पायेंगे कि वह छोटा मोटा रेगिस्तान बन गया है। इसको रोकने का भी आपको प्रयत्न करना चाहियें। एड़ी चोटी का आपको इसको रोकने के लिये जोर लगाना चाहिये।

जहा तक बाढ़ों का मामला है नार्थ बिहार एक ऐसा इलाका है जो हमेशा मौत के मुंह पर खडा रहता है। छोटे बडे सब किसान इसके शिकार होते हैं। इनकी रोकथाम के लिये आपको पूरा ध्यान देना चाहिये। मेरी कंस्टिट्युएंसी किशनगंज है। वहा पर पाच छ बहुत ही भयानक नदिया बहती हैं। उनमे महानन्दा है, कनकई है, मेछी है, बकरा है परमार है। पिछले साल भी बहस के वक्त मैंने कहा था कि आप एक डैम बनायें ताकि बाढ़ से उस इलाके की रोकथाम हो और उससे बिजली भी पैदा हो। आपने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। बिजली पैदा होगी तो वह किसानों को मिलेगी और वे छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा सकेंगे। साथ ही वह उस बिजली को खेती मे ला सकेंगे। यह अभी तक नहीं हो पाया है। इस तरफ आप ध्यान दें।

पम्पिंग सैट्स से जो पानी पटाया जाता है उनकी लागत सिर्फ 2100 या 2200 से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन उनको स्माल और मार्जिनल फार्म्स को 5500 रुपये में दिया जाता है। अब आप देखिये कि इस पर कितना उनको सूद देना पड़ता है और कुल कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस तरफ भी आपकी तवज्जह जानी चाहिये।

खाद की कीमत कम नहीं है, बीज की कम नहीं है, बिजली का चार्ज कम नहीं है, पानी का भी चार्ज कम नहीं है। दवाओं के बारे में तो कहना ही बेकार है इस वास्ते कि दवाएं छिड़कने के बाद कीड़ों की तादाद जो घटनी चाहिये या जिनको खत्म हो जाना चाहिये, मर जाना चाहिये, वह बढ़ती ही जा रही है।

हमारी पैदावार भी कम होती है। लोगों की इकोनोमिक कंडिशन बिगड़ी हुई है। आबादी हमारी बढ़ती जा रही है। हमको उसी हिसाब से पैदावार में भी इजाफा करने की तरफ ध्यान देना होगा।

ट्रैक्टर की बात को आप लें। उसकी कीमत साठ हजार रुपये है। कहां से स्माल और मार्जिनल फार्म इनको ले सकता है। कौन इस कीमत पर इसको खरीदेगा। क्यों नहीं आप जनता ट्रैक्टर बनाते हैं। इनके दाम चाहे आप सबसिडी दे कर या किसी और तरीके से कम करें। अगर आप जनता ट्रेंज चला सकते हैं, जनता भोजन दे सकते हैं तो क्या जनता ट्रैक्टर नहीं बना सकते हैं अपने मुल्क में। लोहे की पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई है। मिनिस्टर साहब को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

जहां तक लैण्ड रिफार्मज का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि गरीबों को खेती के लिये और बसो-बास (होमस्टेड) की जमीन दी गई है। सरप्लस जमीन भी बांटी गई है। लेकिन इस सिलसिले में उतना काम नहीं हो पाया है, जितना कि होना चाहिये था। मेरी जाती राय है कि कुछ वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स इसमें रुकावट डाल रहे हैं। उनमें कुछ एक्सीक्यूटिव आफिसर्स भी शामिल हैं। वे लोग ऐसे तरीके अख्तियार कर रहे हैं, जिससे अवाम में हमारी बदनामी हो। हमें उन लोगों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये। सीलिंग एक्ट को सख्ती और मजबूती के साथ लागू करना चाहिये और उसमें कोई ढील नहीं होनी चहिये।

जमीन का बंटवारा गरीब क्लास में होता है। गरीब बजाते-खुद एक क्लास है और गुरबत मुल्क के लिये एक लानत है। गरीब क्लास में कोई हिन्दू, मुसलमान, सिख या ईसाई नहीं होता है—वे सब गरीब हैं। चूंकि गरीबों का एक तबका है, इसलिये फाजिल जमीन का बंटवारा करते हुये जात या मजहब की बिना पर कोई इम्तियाज नहीं करना चाहिये, और कोई हिन्दू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, या आदिवासी और हरिजन हो, अगर वह गरीब तबके से ताल्लुक रखता है, तो उसको जमीन मिलनी चाहिये।

बिहार स्टेट माइनारिटीज कान्वेन्शन में, जो 24–25 अप्रैल, 1976, को हुई थी, एक रेज्यूल्यूशन पास किया गया था। मैं उस रेज्यूल्यूशन के दो पायंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं :

एक पायंट यह है :

"This convention feels that the true implementation of the declared Economic Policy places a secred obligation on the National Leadership to solve the problems of economically backward minorities and the Muslim Community in particular—

[श्री मुहम्मद असीलुर्रहमान]

"The 20-point economic programme of the Prime Minister must be applied to the Muslim including them in the "Weaker Section" as mentioned in the programme, for their economic uplift, and the same concessions be accorded to them as provided for the weaker sections known as backward and depressed classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

मैं आपकी इजाजत से दूसरा पायंट भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इस तरह है :

"High Power Committees representing the interest of the economically backward sections and minorities may be vested with powers to supervise and control the implementation of the scheme with direction to report from time to time about the progress made and to make further suggestion for better results"

मेरी दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में काम किया जाना चाहिये ।

20—प्वायंट इकानामिक-प्रोग्राम के मातहत रूरल इनडेटिडनेस खत्म हुई है, बांडेड लेबर खत्म हुई है और महाजनों की महाजनी खत्म हुई है। लेकिन अब हमें यह देखना चाहिये कि हम उन गरीब लोगों को क्या सहूलियतें दे सकते हैं। अगर हम उन लोगों को पूरी सहूलियतें न दे पाये, तो बड़ी परेशानी होगी । इसलिये 20 पायंट इकानामिक प्रोग्राम को लागू करने के लिये हम लोगों को मजबूती के साथ काम करना चाहिये ।

जहां तक मार्केटिंग फैसिलीटिज मुहैया करने का सवाल है, गांवों की छोटी सड़कों को मेन रोड के साथ मिलाना चाहिये, ताकि किसान जो पैदा करते हैं, उनको बाजार लाकर उसकी सही कीमत मिले । यह भी जरूरी है कि किसानों की पैदावार की चीजों की कीमत मुकर्रर करके पहले से उसका ऐलान कर दिया जाये, ताकि उनको इत्मीनान हो और वे अपनी पैदावार को बढ़ा सकें । उनको इस बात की गारंटी मिलनी चाहिये कि उनकी पैदावार की कीमत कम नहीं होगी और उनकी पैदावार सही तरीके से बेची जा सकेगी ।

पंचायती राज के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायतों के पास इतने फंड्स होने चाहिये कि वे पीने के पानी का इन्तजाम गरीबों की फौरी इमदाद, कर्ज देने और छोटी-मोटी सड़क बनाने के लिये काम को वक्त पर कर सकें । इस वक्त इस बारे में प्रासीजर काफी लम्बा है, और इसे कम होना चाहिये ।

एफ० सी० आई०, सीड्स कारपोरेशन और माडर्न बेकरीज ने अच्छा काम किया है। इस बारे में मुझे एक ही शिकायत है। इन कारपोरेशन्ज में बहालियों का मसला निहायत संगीन है। हमारे कांस्टीट्यूशन के मुताबिक इन सब कारपोरेशन्स में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को एक खास परसेंटेज के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। माइनारिटीज कम्यूनिटी के लोग भी उसमें आते हैं। इन कारपोरेशन्स में उनकी तादाद की निल के बराबर है ।

आखिर में मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी से ताल्लुक रखने वाले एक मसले के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे भाई, केदार साहब, की मिनिस्ट्री जूट की पैदावार और बीज और पानी देने के लिये जिम्मेदार है। लेकिन उसको बेचने का काम श्री चट्टोपाध्याय करते हैं। इन दोनों में ताल-मेल का कोई सवाल ही नहीं। नतीजा यह है कि किसान लोग तबाह हो रहे हैं। अगर उनको जिन्दा रखना है, तो जूट को मुकर्रर रख कर उनको राहत देनी चाहिये ।

आखीरी बात जिसकी तरफ स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, अर्ज करना चाहता हूं। झालर के बाढ़ के पानी ने अजमेर शरीफ के दरगाह शरीफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पिछले साल भारत सरकार ने ढाई करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को दिया उसकी मरम्मत के लिये। वह दरगाह शरीफ आप जानते हैं कितना मशहूर है। तो उसकी मरम्मत होनी चाहिये थी। लेकिन अभी भी उसका कोई काम नहीं हो पाया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी फरमा कर हम लोगों के दिलों के जज़बात सरकार तक पहुंचायें और राजस्थान सरकार से कहा जाये कि इस दरगाह शरीफ में जो नुकसान हुआ है जो वहां टूट-फूट हुई है उसकी मरम्मत कराये। इसकी तरफ सरकार तवज्जह दे।

इन अल्फाज़ के साथ मैं इस मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करता हूं।

[شری محمد جمیل الرحمٰن (کشن گنج)]: محترم ڈپٹی سپیکر صاحب- میں آپ کا شکر گزار ہوں - کہ آپ نے مجھے موقعہ عنایت کیا ہے -

میں عرض کروں گا کہ ملک کی مضبوطی کی جانچ و پرکھ اس طرح کی جاتی ہے کہ اس ملک کی باگ ڈور کس شخصیت کے ہاتھ میں ہے- تو اس معاملے میں ہمارا ملک بھارت بڑا خوش قسمت ہے - کہ اس دیش کی باگ ڈور ایسی لیڈر شپ کے ہاتھ میں ہے- جس نے بیرونی اور اندرونی خطروں کا با ہمت اور بلند ہمت سے مقابلہ کیا ہے - اور یہ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ تھی - کہ انہوں نے ملک کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا - گرچہ اس کی سازش کی گئی - بلکہ اور آگے بڑھایا - چاہے جنگ جیتنی ہوئی ہوں چاہے بین الاقوامی فیلڈ میں ہوں یا فوجی میدان میں ہوں یا ایگریکلچر کے میدان میں ہوں - یا پروڈکشن کے میدان میں ہوں -

اس وقت زیر بحث 'ہوتی ہے- اس لئے میں اپنی بحث کو اس تک محدود رکھوں گا - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ محکمہ بابو جی کے ہاتھ میں ہے ، جن کی صلاحیت کے بہت سے نمونے ہیں - ان میں سے بنگلہ دیش بھی ایک نمونہ ہے - وہ میدان مارنے کے بعد اب وہ اس محکمے میں تشریف لائے ہیں - میرا ایسا خیال ہے کہ ان کے اس محکمے میں رہنے کے بعد اس میں کافی ترقی ہو گی - اور وہ نہایت کامیاب رہیں گے - جب سے یہ محکمہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے - بہت اچھی خاص تبدیلی اس محکمے میں آئی ہیں - آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایمرجنسی لاگو ہونے سے پہلے لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا - قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں - اور غریبوں کی معاشی ہڈیاں قریب قریب ٹوٹ گئیں تھیں - نوکری پیشہ والے پریشان تھے - مزدور پریشان تھے-

[شری محمد جمیل الرحمان]

غرض کہ ہر جگہ مرکزی حکومت کی ہوئی تھی - ملک کی پیداوار میں رکاوٹیں ڈالی گئیں - اور ہر طرح کی کوشش کی گئی تھی کہ ملک کی پیداوار آگے نہ بڑھے - غرض کہ ہر وہ کام کیا گیا کہ جس سے ملک کی معاشی حالت کمزور سے کمزور ہو جائے - اور یہ سارے کام بیرونی طاقتوں کے اشارے پر ہوئے - لیکن اس ملک کی رہنما نے دیش کو بچا لیا - اور جو وعدے ہم نے لوگوں سے کئے تھے ان کو پورا کر رہے ہیں - آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایمرجینسی لاگو ہونے کے بعد سے ملک میں ہر طرح کا امن ہے اور ہر فیلڈ میں پروڈکشن بڑھا ہے - اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں - ملک کھانے میں خود کفیل ہوا ہے - اور کھیتی کی پیداوار بڑی ہے - اس میں دو رائے نہیں ہیں - لیکن اس کو بھی آپ کو ماننا ہوگا - کہ ملک کی آبادی کا اسی پرسینٹ حصہ کھیتی کے کام میں لگا ہوا ہے - گاؤں میں رہتا ہے - آپ کو دیکھنا چاہئیے کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے - کھیتی کو آگے بڑھانے میں - ضرورت پڑتی ہے پانی کی - بجلی کی کھاد کی - جہاں تک پانی کا تعلق ہے - پانی ہندوستان ملک میں کافی ہے - لیکن اس کا استعمال کسی حد تک ہو رہا ہے - یہ دیکھنے والی چیز ہے -

آسمانی بارش سے ہم لوگ کھیتی کرتے ہیں - وہ بارش کافی نہیں ہے - ہم لوگ نہریں پانی یا پمپنگ سیٹ لگا کر لوگوں کو پانی دے کر ایریگیشن کی فیسیلیٹی کو بڑھا کر کھیتی کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں - ابھی ۴۵ ملین ہیکٹر زمین کو نہروں سے پانی دیا جا رہا ہے - اس کو بڑھا کر ۱۶۰-۱۶۵ ملین ہیکٹر کیا جا سکتا ہے - اس کا آپ کو انتظام کرنا چاہئیے - اور نہریں کھدوانی چاہئیں -

جہاں تک بہار کا تعلق ہے میں کچھ باتیں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں - کوسی پروجیکٹ جس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی وہ مقصد ہی فوت ہو چکا ہے - آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا پانی آنا چاہئیے - وہ آتا نہیں - حالانکہ میرے گاؤں میں جو نہر ہے اس کے ٹیل اینڈ تک میں پانی نہیں آتا ہے - لیکن بیچ بیچ میں اتنا کم پانی آتا ہے کہ ایک کسان اور دوسرے کسان میں جھگڑا ہو جاتا ہے - یہ آئے دن کی بات ہے - اس طرف بھی آپ کو دھیان دینا چاہئیے -

جہاں تک کوسی کے سیکنڈ سلائس کا تعلق ہے اگر آپ دو چار سالوں کے بعد میرے ضلع میں جائیں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ [illegible] ہو گیا ہے [illegible]

آپ کو پربندھ کرنا چاہئے - اس کو روکنے کے لئے اپنی چوٹی کا زور لگانا چاہئے -

جہاں تک باڑوں کا معاملہ ہے - نارتھ بہار ایک ایسا علاقہ ہے - جو ہمیشہ موت کے منہہ پر کھڑا رہا ہے - چھوٹے بڑے سب کسان اس کے شکار ہوتے ہیں - ان کی روک تھام کے لئے آپ کو پورا دھیان دینا چاہئیے میری کانسٹیٹیوئنسی کشن گنج ہے - وہاں پر پانچ چھ بہت ہی بھیانک ندیاں بہتی ہیں - ان میں مہانندہ ہے - کنکئی ہے - میچی ہے - بکرا ہے - پنار ہے - پچھلے سال بھی دھوت کے وقت میں نے کہا تھا - کہ آپ ایک ٹیم بنوائیں تاکہ باڑھ سے اس علاقے کی روک تھام ہو سکے - اور بجلی بھی پیدا ہو - آپ نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا ہے - بجلی پیدا ہوگی تو وہ کسانوں کو ملیگی - اور وہ چھوٹی موٹی انڈسٹری لگائینگے - اور ساتھ ہی وہ اس بجلی کو کھیتی کے کام میں لا سکینگے - یہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے - اس طرف آپ دھیان دیں -

پمپنگ سوٹ سے جو پانی پٹایا جاتا ہے - اس کی لاگت صرف ۲۱ سو یا ۲۲ سو سے زیادہ نہیں ہوتی ہے - لیکن ان کو سمال اور مارجنل فارمرز کو ۵۵ سو روپئے میں دیا جاتا ہے - اب آپ دیکھیں کہ اس پر کتنا ان کو سود دینا پڑتا ہے - اور کل کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے - اس طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہئے -

کھاد کی قیمت کم نہیں ہے - بیج کی کم نہیں ہے - بجلی کا چارج کم نہیں - پانی کا بھی چارج کم نہیں ہے - دواؤں کے بارے میں تو کہنا ہی بیکار ہے - اس واسطے کہ دوا چھڑکنے کے بعد کیڑوں کی تعداد جو گھٹنی چاہئے - یا جن کو ختم ہو جانا چاہئے - مر جانا چاہئے - وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے -

ہماری پیداوار بھی کم ہوتی ہے - لوگوں کی اکانامک کنڈیشن بگڑی ہوئی ہے - آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے - ہم کو اسی حساب سے پیداوار میں بھی اضافہ کرنا چاہئے - سرکار کو اس کی طرف دھیان دینا ہوگا -

ٹریکٹر کی بات کو آپ لیں - اس کی قیمت ساٹھ ہزار روپئے ہے - کہاں سے سمال اور مارجنل فارمر ان کو لے سکتا ہے - کون اس قیمت پر اس کو خریدے گا - کیوں نہیں آپ چلتا ٹریکٹر بناتے ہیں - ان کے دام چاہے آپ سب سڈی دے کر یا کسی اور طریقے سے کم کریں - اگر آپ چلتا ترین چلا سکتے ہیں - چلتا بھوجن دے سکتے ہیں - تو کیا چلتا ٹریکٹر نہیں بنا سکتے ہیں - ابھی

[شری محمد جمیل الرحمان]

ملک میں لوہے کی پیداوار کی بڑھوتری ہوئی ہے - منسٹر صاحب کو اس طرف دھیان دینا چاہئے -

جہاں تک لینڈ ریفارمز کا تعلق ہے - اس میں کوئی شک نہیں ہے - کہ غریبوں کو کھیتی کے لئے اور بسانے کے لئے زمین دی گئی ہے - سرپلس زمین بھی بانٹی گئی ہے - لیکن اس سلسلے میں اتنا کام نہیں ہو پایا ہے - جتنا کہ ہونا چاہئے تھا - میری ذاتی رائے ہے - کہ کچھ ویسٹڈ انٹریسٹ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں - اس میں کچھ ایگزیکٹیو آفیسرز بھی شامل ہیں - وہ لوگ ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں - جس سے عوام میں ہماری بدنامی ہو - ہمیں ان لوگوں پر کڑی نگرانی رکھنی چاہئے - سیلنگ ایکٹ کو سختی اور مضبوطی کے ساتھ لاگو کرنا چاہیے - اور اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہئے -

زمین کا بٹوارہ غریب کلاس میں ہوتا ہے - غریب بذات خود ایک کلاس ہے - اور غریب ملک کے لئے ایک لعنت ہے - غریب کلاس میں کوئی ہندو - مسلمان - سکھ - عیسائی نہیں ہوتا ہے - وہ سب غریب ہیں - چونکہ غریبوں کا ایک طبقہ ہے اس لئے فاضل زمین کا بٹوارہ کرتے ہوئے ذات یا مذہب کی بنا پر کوئی امتیاز نہیں کرنا چاہئے - اور کوئی ہندو ہو - یا مسلمان - کرسچین سکھ - یا آدی باسی - اور ہریجن ہو - اگر وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے - تو اس کو زمین ملنی چاہئے -

بہار سٹیٹ مائنارٹیز کنونشن میں - جو ۲۳-۲۵ اپریل ۱۹۷۶ کو ہوئی تھی - ایک ریزولیوشن پاس کیا گیا ہے - میں اس ریزولیوشن کے دو پائینٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں - ایک پائینٹ یہ ہے -

"This Convention feels that the true implementation of the declared Economic Policy places a sacred obligation on the National Leadership to solve the problems of the economically backward minorities and the Muslim Community in particular The 20-Point economic programme of the Prime Minister must be applied to the Muslim including them in the "Weaker Section" as mentioned in the programme, for their economic uplift, and the same concessions be accorded to them as provided for the weaker sections known as backward and depressed classes and Scheduled Castes and Tribes"

میں آپ کی اجازت سے دوسرا پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس طرح ہے -

'High Power Committees representing the interest of the economically backward sections and minorities may be vested with powers to supervise and control the implementation of the scheme with direction to report from time to time about the progress made and to make further suggestion for better results."

میری درخواست ہے کہ اس سلسلے میں کام کیا جانا چاہئے -

۲۰ پوائنٹ ایکنومک پروگرام کے ماتحت رورل اینڈیبٹڈنیس ختم ہوئی ہے - باونڈڈ لیبر ختم ہوئی ہے - لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہم ان غریب لوگوں کو کیا سہولتیں دے سکتے ہیں - اگر ہم ان لوگوں کو پوری سہولتیں نہ دے پائیں تو بڑی پریشانی ہوگی - اس لئے ۲۰ پوائنٹ اکانامک پروگرام کو لاگو کرنے کے لئے ہم لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ کام کرنا چاہئے -

جہاں تک مارکیٹنگ فیسلیٹیز مہیا کرنے کا سوال ہے - [illegible] کی چھوٹی سڑکوں کو مین روڈ کے ساتھ ملایا جانا چاہئے ، تاکہ کسان جو پیدا کرتے ہیں ان کو بازار لا کر اس کی صحیح قیمت ملے - یہ بھی ضروری ہے - کہ کسانوں کی پیداوار کی چیزوں کی قیمت مقرر کرکے پہلے سے اس کا اعلان کر دیا جائے - تاکہ ان کو اطمینان ہو اور وہ اپنی پیداوار کو بڑھا سکیں - ان کو اس بات کی گارنٹی ملنی چاہئے کہ ان کی پیداوار کی قیمت کم نہیں ہوگی - اور ان کی پیداوار صحیح طریقے سے بیچی جا سکیگی -

پنچایتی راج کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنچایتوں کے پاس اتنے فنڈز ہونے چاہئیں کہ وہ پینے کے پانی کا انتظام - غریبوں کی فوری امداد - قرض دینے اور چھوٹی موٹی سڑک بنوانے کے کام کو وقت پر کر سکیں - اس وقت اس بارے میں پروسیجر کافی لمبا ہے - اسے کم ہونا چاہئے -

ایف - سی - آئی - و سیڈز کارپوریشن اور مارکٹنگ بورڈز نے اچھا کام کیا ہے - اس بارے میں مجھے ایک ہی شکایت ہے- ان کارپوریشنز میں یہ بھالیوں کا مسئلہ نہایت سنگین ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے کے مطابق ان سب کارپوریشنز میں شیڈولڈ کاسٹس اور شیڈولڈ ٹرائبز کو ایک خاص پرسینٹیج کے حساب سے نوکری ملنی چاہئے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے - مائنورٹی کمیونٹی کے لوگ بھی اس میں آئے ہیں - ان کارپوریشنز میں ان کی تعداد نل کے برابر ہے -

آخر میں میں اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے تعلق رکھنے والے ایک مسئلے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کیدار صاحب کی منسٹری جوٹ کی پیداوار اور بیج اور پانی دینے کے لئے ذمے دار ہے - لیکن اس کو بیچنے کا کام شری چٹوپادھیائے کرتے ہیں - ان دونوں میں تال میل کا کوئی

[شری محمد جمیل الرحمان]

سوال نہیں ہے - نتیجہ یہ ہے کہ کسان لوگ تباہ ہو رہے ہیں - اگر ان کو زندہ رکھنا ہے تو جہرت کو مقررہ در پر خرید کر ان کو راحت دینی چاہئے -

آخری بات جس کی طرف سپشل اٹینشن دینے کی ضرورت ہے - عرض کرنا چاہتا ہوں - جہالر کے بارھہ کے پانی نے اجمیر شریف کے درگاہ شریف کو بہت نقصان پہنچایا ہے - پچھلے سال بھارت سرکار نے ڈھائی کروڑ روپیہ راجستھان سرکار کو دیا - اس کی مرمت کے لئے - وہ درگاہ شریف آپ جانتے ہیں - کتنا مشہور ہے - تو اس کی مرمت ہونی چاہئے تھی لیکن ابھی تک اس کا کوئی کام نہیں ہوا پایا ہے میں آپ سے گزارش کرونگا کہ آپ مہربانی فرما کر ہم لوگوں کے دلوں کے جذبات سرکار تک پہنچائیں اور راجستھان سرکار سے کہا جائے کہ اس درگاہ شریف میں جو نقصان ہوا ہے جو ترت پورت ہونی ہے - اس کو فوراً مرمت کرائیں - اس طرف سرکار توجہ دے - ان الفاظ کے ساتھ میں اس منسٹری کی مانگوں کا سمرتھن کرتا ہوں -]

15.00 hrs.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): Mr. Deputy-Speaker, thank you very much for your kindness in permitting me to intervene in this debate. I am thankful to the very large number of hon. Members who have participated, and also those who will participate, in this discussion on the Demands for Grants in respect of this Ministry. This shows how great interest is being shown by this House and also by the hon. Members in one of the most vital sectors of our economy—agriculture and the related sectors. I am thankful to the hon. Members who have made very important suggestions in their debate. Some criticism has also been voiced. There is nothing wrong in constructive criticism because that helps us to understand the problem. As far as the debate is concerned, my senior colleague will give the final reply to the various points raised by the hon. Members. Even then, I would dwell on some of the important aspects and important points which have been raised by the hon Members in this debate

I have been attending this debate for the last 14 or 15 years, and I have never seen food being so "neglected" as in this debate, and the reasons are quite obvious (*Interruptions*) I say 'neglected' in this sense that it did not attract much of a criticism, only some suggestions have been made here and there. The food situation is so easy today All of us are proud and happy that the food situation is easy, the prices are ruling very satisfactorily, the consumers have received a relief; there is an all-round satisfaction in the country. This has been reflected in the various observations made by the hon. Members. But then there are prophets of gloom and prophets of doom also if I may be permitted to say that without hurting the feelings of anybody. Hon. Member, Shri B. N. Reddy, who opened this debate—he is not here now—made a statement which is not at all supported by any data or statistics I think, he has political differences with us. But my senior colleague and myself have been always saying that agriculture should not be made a controversial subject It should

be above politics, because we want the cooperation of everybody as far as these matters are concerned....

AN HON. MEMBER: Mr. B. N. Reddy has come now.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Mr. B. N. Reddy has said, while speaking on this subject, that the increase in agricultural production is very marginal, very small, and that this has been accidental because nature has been good and that the policy-makers or the government's policies or the Ministry's policies have not contributed to this. I will quote what he has said. He has said:

"The small increase in agricultural production is being shown as the main factor for the improvement. No doubt there is a small increase in agricultural production, but it does not reflect a steady growth of our agriculture, it is also not a new development at all. The increase in production is only due to favourable monsoon and not due mainly to any policy or plan of the government."

I take very strong objection to these observations of the hon. Member, and I am supported in what I say by very well-documented data. I am not making this statement in order to score a debating point over Mr. Reddy.

15.05 hrs.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

As an individual I have great respect for him, but I think there is a need to make an appropriate assessment of the situation to-day, of the food and agricultural situation to-day and nothing should be said which will sap the confidence of the country when, in particular, it is not supported by data.

For instance, I would like to say what has happened during the last 10-15 years as far as agriculture is concerned. I think any country in the world—I have studied the agricultural economy of many countries in the world—can be proud of what has happened in this country. In order to elucidate my point I would like to mention some of the very outstanding achievements in the agricultural front. Take the case of the most important sector of agriculture, *viz.*, foodgrains production. Now, in the first Plan our average production of foodgrains was 66 million tonnes and in the Fourth Plan our average ropduction was 103 million tonnes. We are now in the Fifth Plan but even in the Fourth Plan the production was going much higher. That means compared to the First Plan the tempo has been so great and as compared to even the population growth—I am not justifying the population growth because it has many other implications and the country is well aware of the situation—the foodgrains production has even outstripped the population growth. Would all this have happened without deliberate policy decisions and planning on the part of the government, without the support of the government, and without a number of experts and administrators contributing in this? Then take the growth rate. In the first 14 years, 1952-53 and 1964-65, the rate of growth is 2.5 while during the period 1960-61 and 1970-71 it has been 2.7. There has been an increasing trend. Even in the growth rate— I would like to elucidate an important point to support my argument—one important point is that the percentage of fluctuation between the highest production and the lowest production in the First Plan used to be 30%. Now this fluctuation has come down to 11%. This reflects the deliberate policy contribution and effort made by the Government in raising agricultural production.

If we go to individual crops, take the case of rice. In the First Plan, our average production was 28.7 million tonnes. Now, in the Fourth Plan our average production has been 41.8 million tonnes. Then take wheat which I am going to elucidate more because some other hon. Members raised some other points. In the First Plan the average production was 8

[Shri Annasaheb P. Shinde]

million tonnes. Now it is 23.4 million tonnes. Oil seeds—the average production in the First Plan was 52 lakhs tonnes. Fourth Plan average production was 83 lakhs tonnes. Potato—the First Plan average production was 2.7 million tonnes. Now, it is 6 million tonnes. The growth rate of potato is quite impressive. It is almost 5.5. This reflects how agricultural production in this country is growing at a very satisfactory rate. I am not suggesting that there is no scope for improvement. To rectify the situation is the main responsibility of my Ministry But we are mortals.

The Communist (Marxist) Party may be infallible but we are fallible, we are mortals. But the point is....

SHRI B. N. REDDY (Niryalguda): The point I raised was that it was not a steady growth.... (*Interruptions*).

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Mr. Reddy, I did not interrupt you. Why do you interrupt me?

Therefore, I always take the position that we welcome suggestions from any quarter, not only from our Party but even from Members on the other side, to improve our production. I am not suggesting but I can tell you. There has been better co-ordination in the Government and my Ministry received tremendous support from all other Ministries, including/Finance, the Chemicals and Fertiliser Ministries. Particularly, I would be failing in my duty if I do not mention that it was because of our Prime Minister's very strong support to Agriculture that it has been possible for us to make this progress. Unless we work as a team and supported by our team leader it is not possible. I can take the House into confidence. I can tell the hon. members that there has been considerable good expertise in my Ministry whether it is irrigation, rural development, agriculture, or food. It is not that everybody is perfect, but I must say the way in which the experts and scientists, etc. have been making contribution, it is the sum total of all, particularly the farmers of this country as also the social and political workers of this country. It is all because of the co-operation of all, that it has been possible in the country. There is nothing to be ashamed of, rather we are and should be proud of it. No doubt, weather also plays a very important role in agricultural production. No country in the world has escaped it. Take for instance, the Soviet Union. They have been trying for half a century to raise agricultural production. The Soviet Union is a great and strong or powerful country. They have the capacity to purchase large quantities of foodgrains. Despite the fact that they have reached the moon, the food problem continues to worry them.

The other point made by Shri B. N. Reddy was that India continues to import from the imperialist countries. I do not know to whom does he owe allegiance—China or the USA? Even China purchased foodgrains from the United States and other countries when they wanted it. There is nothing wrong in it. If the Government of India imports, there is nothing wrong. But their party's main intention is to criticise our party and to say that nothing good is happening in the country and to shake the confidence and morale of the people. I, therefore, reject outright the arguments advanced by the hon. member Shri Reddy, in regard to agricultural production.

MR. CHAIRMAN: On foodgrains, I believe, there is no tag attached.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Anybody—even the communists or the Chinese—consumes any food.... (*Interrutions*).

Some of my partymen made some observations. I would like to put the records straight. For example, Shri Ranabahadur Singh made a statement—the productivity of wheat is going down. Shri Ranabahadur Singh made a very constructive speech. I was very

much impressed by it: But as far as the productivity part is concerned, it is not correct and that will also give a wrong impression. In fact I would not like to take much of the time of the House as far as the details are concerned, but I would like to tell Shri Ranabahadur Singh, amongst the various crops, the highest growth rate has been that of wheat. Everybody knows as to what has happened during the last three years. There has been a setback because of drought, inadequate power, high price of fertilisers, etc. Even assuming all this and taking all these factors into consideration, the growth rate of wheat has been the highest 4.3 amongst the various crops and it would be totally wrong..

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer): It is not for argument's sake, but I want to know for the sake of information whether this increase is because of more land being brought under production or because of the yield per acre.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: The additional land that has come is 3.6 but the productivity is 4.3. As compared to the land, the productivity is higher. You rightly raised this issue.

MR. CHAIRMAN: He was probably having in mind certain varieties like sonar. Because of genetic reasons, these have certain standards.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I would like to submit, in the earlier period some of the varieties like Kalyan, Sona were released, Kalyan Sona had a very rich potential. It was very high yielding. But this variety become susceptible to rust and so on. As you know, our scientists are evolving new varieties and a number of them are being developed. And in fact, so far as wheat productivity is concerned, among the various crops, this productivity in respect of wheat is really very high. But the point which I would like to make here is only this. There are very large areas in this country where during the last 3 or 4 years you may say that what production has not been so satisfactory and, of course, there was some slight downward trend in production. That is to say, the production was a little less. This year the picture is different. Even in Mr. Goswami's area, that is, Assam, wheat is grown. This is not a traditional wheat growing area. But this thing has happened now. This happened in respect of West Bengal for the first time. In the history of West Bengal this has not so far happened. Government had to step in to give market support. Unconventional areas like these are coming up. Previously these were confined to mostly Punjab, Haryana, Western UP and also some areas of Rajasthan and Madhya Pradesh. There are now such areas as Bihar, Eastern UP, Orissa, Assam and Bengal. Even in Maharashtra a very interesting development took place. This year under the able leadership of the Chief Minister and the Agriculture Minister a massive programme was launched for wheat production. They took about 55 to 60 thousand acres as a pilot project and the agriculturists have been told that they could produce 10 quintals per acre which is the average yield of Punjab. The number of blocs were 80 by 90. They were told that they would be compensated by the Government if the yield would be less than that. But there are certain conditions. The farmers will have to sow at the time and date fixed by the Government; the seed also will not be what they like but what has been suggested by the experts and water will be given at a particular time and if it fails he will be compensated. Input supply was ensured. So, these thing were very helpful to the farmers and they have been able to increase production. Everybody could get 10 quintals or more. So all these things show that we need not take a pessimistic view at all. This country has tremendous potentialities. I request that I should not be charged with being too nationalistic or chauvinistic when I say this that this country has got more potentialities than the USA to produce more

[Shri Annasaheb P. Shinde]

grains and therefore we need not take a pessimistic view of things at all.

Mr. D. D. Desai made a basic statement that a platu has been reached so far as productivity is concerned. He made a very constructive speech. But so far as productivity is concerned of foodgrains, I think his is really not a statement supported by facts I will give certain figures. Ludhiana produced 29 to 33 quintals per hectare of wheat. Punjab average is 22 to 24 quintals per hectare. All India average is 11 to 13 quintals per hectare. I just now mentioned about Maharashtra and what tremendous scope we have got in our country There are various difficulties faced by the farmers, because of their poverty, because of lack of credit resources, because of weak banking system and so on but these are being remedied. Therefore, the potentialities are great and there are tremendous possibilities and the statement of Mr. D. D Desai is not borne out by facts and is not correct. It was very far from truth

Then, Sir, another important aspect which my ministry deals with is regarding land reform. Land reform is again one of the very vital subjects which has a lot to do with the rural economy as also it has an important role to play in our agricultural production. Even from the point of view of social justice and egalitarian society we believe that land reforms have to be implemented with all sincerity.

However, criticisms have been made that implementation of it has not been satisfactory. I am prepared to share some of the feelings of the hon. Members and I would like to tell them that never before in the history of this country, even in the post-Independent period, when landlordism was abolished in the country, at that time even, there was not so much of awareness as there is today about the land reforms. In fact, all Chief Ministers are now taking keen interest in that and nobody can charge them excepting the C.P.M. perhaps that there is no political will etc. Of course, there has been some difficulty such as lack of proper records and difficulties of certain administrative machinery etc., etc. I have been keeping a close watch on the situation and I can submit, for the information, of this House and also yourself that in every State, we see a lot of conscious activity going on in favour of land reforms. In fact for 12 lakhs, returns have been filed Despite that, there is a gap of information on how much of surplus land has been declared and how much of it has been taken over. The information with me is this—it is a month old information but, even that indicates that almost 11 lakh acres of land have been declared as surplus of which six lakhs acres of land have been taken over by the State Governments and about 2.20 lakhs have actually been distributed In a number of States, for instance, I find that they were in a position to see that within the next two months—May and June—a considerable progress would be made in the field of implementation of land reforms. *(Interruptions)* Unfortunately, despite the fact that the laws have been included in the Ninth Schedule of our Constitution West Bengal is notorious for that—I do not know whether I am using a proper word for that—where in the high courts and judicial tribunals, thousands of cases are still pending. What we have now done is this We have tried to see that necessary constitutional protection is given to the laws I think that only in four States like Tamil Nadu, Maharashtra, J & K and Manipur constitutional protection still remains to be done but, in Maharashtra, the law is being implemented very expeditiously and the Chief Minister says that he will be in a position to complete that process before 30th June. There is no so much judicial intervention though here and there, there may be some applications filed, like West Bengal.

My senior colleague has requested the Chief Ministers to see that the

land reform measures, particularly, land ceiling laws are implemented vigorously so that we are in a position to keep to the time schedule unless of course there is judicial intervention or some other difficulty which is beyond the control of the State Governments. (*Interruptions*)

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): Yesterday, Shri Bhogendra Jha mentioned about the Ordinance issued by Bihar Government.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Shri Jha, one of our colleagues, made a statement. Also Shri Kathamuthu, DMK Member raised some issues about the tenancy. That gives a good opportunity to us to explain the position. In regard to this Shri Bhogendra Jha said that Bihar Government wanted to enact the law. In fact he personally spoke to me about the issue of an Ordinance in regard to resumption of lands held by tenants. And if there is a tenant, then the landowners would be in a position to resume that land by evicting the tenant.

I think that was the substance of his statement. As far as my ministry is concerned, it is not justified at all by facts. Bihar Government has not approached at all with this proposition.

As far as we are concerned, even if such a proposition is made for resumption of the land, if it has not the support, then no law would be effective without the assent of the President. Government of India is very clear on this and its national policy is known to all State Governments. I am quite sure that Bihar Government is in a position to take a very responsible view in regard to all these matters. In regard to the tenancy, in the first and Second Plans, we allowed resumptions of lands to certain extent. Now, we have taken the position that a tenant must get a permanent right for cultivation. Tenancy must be made permanent and hereditary. Not only that. The tenant must also get the ownership right of land. We would not like to disturb that position so far as tenants in this country as concerned.

So far as our ministry is concerned, we are more concerned with their rights and we would like to protect their interests. Shri Kathamuthu said that some tenants were being evicted in Tamil Nadu. I am sorry he is not here. But, I would like to tell him he is a DMK Member—that it is now under President's Rule and after the President's taking over the State's Administration, President has been pleased to enact a law to protect the interests of the tenants, and, therefore, to charge that the tenants are being evicted because of the Presidential Rule is not fair on his part. We had been even earlier pressing the DMK Government to see to it that adequate protection was given to the tenants.

Sir, he raised another point about the land owned by the religious trusts. In this regard our position is very clear. Though as far as lands owned by public charitable trusts and religious trusts are concerned we allow them to own the land if they are cultivated by the tenants we will not allow any religious trust to evict the tenants. We would like to submit through you to the hon. tenants and would not like to make any departure from this policy.

Now, I will say a word about the input prices because in agriculture the input prices play a very important role. By and large I am in sympathy with the hon. Members when they express that the prices of fertilisers have been very high. Sir, I would like to submit through you to the hon Members to appreciate the difficulties of the Government of India.

Sir, the energy crisis had affected our agriculture badly and this energy crisis was due to the external factors beyond the control of the Government of India. What happened was, immediately after the energy crisis the fertiliser prices in the world market shot up.

[Shri Annasaheb P. Shinde]

We were purchasing urea at a price of Rs. 500 to Rs 600 per tonne, at one time the prices of urea went up to Rs. 3,700/- to Rs. 3,800/- per tonne. In spite of this we were selling urea to our farmers at Rs. 2,000/- per tonne I know, the price of Rs. 2,000/- per tonne is a very high price for the Indian farmer.

Sir, in this connection I would like to mention some figures with regard to the losses which the Central pool incurred and the subsidy which the Government of India had to provide during the last two-three years. Sir, in 1974-75 the Central pool suffered a loss of Rs. 340 crores because we sold fertilisers to Indian farmers at a price less than our purchase price in the international market. In 1975-76 the loss was Rs. 303 crores and even this year we anticipate a loss of Rs. 139 crores. Sir, the hon. Members have to appreciate this because already our economy is functioning under stress and strain and deficit financing is causing a lot of concern to the policy makers....

MR. CHAIRMAN: The point raised again and again by various hon. Members is that they are not blaming you for the prices. All that they were saying was that there has to be some parity between the prices of inputs and the prices of agricultural commodities. What have you to say about it?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Even in regard to that I stand fairly on strong position—at least technically.

श्रीमती सहोदरा बाई राय : (सागर): हमारे जो भूमिहीन किसान हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं उन्हें सही तरीके से जमीन क्यों नहीं मिलती हैं, उन्हें तरह तरह से क्यों तंग किया जाता है ? इस तरह से तो वे आगे बढ़ नहीं सकेंगे ।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: इसके बारे मे बाबू जी कल आपको बताएंगे ।

Sir, my time is very limited. Though the sudden fall in agriculture prices has caused some concern and some hon. Members and farmers are worried but what has to be appreciated is that between 1972—74 the increase in agricultural prices—particularly foodgrains —was to the tune of Rs. 74 per cent. The fell has been now 24 per cent ...

MR. CHAIRMAN: You mean to say open market prices?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: The overall level of prices include controlled prices as well as....

MR. CHAIRMAN: We were talking of support price.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Support price has nothing to do with this. There is an effective combination between procurement price and open market price. Economists work out the figures at what ratio, by what percentage with public distribution etc. They take into consideration all these factors and arrive at this conclusion. I have got all the statistics here. I will not have the time to give them because I have to deal with some other points also But I would broadly state the position. There was an increase to the tune of 80 per cent between the two years of inflationary periods. Our whole economy was in doldrums. Poor people with low purchasing power suffered in this country. There was need for the prices to be brought down. The prices have come down 24 per cent; whether we take the 1952 base or the 1962 base, still the prices are in favour of agricultural commodities as compared to manufactures. I have all the statistics with me. I have given them in the Rajya Sabha. If any hon. member is interested, I am prepared to share them with him. But as regards a sudden fall in agricultural commodity prices, input prices etc., that is a matter which requires very close attention from policy makers and from all of us. It requires sympathetic attention from all of us. I would leave it at this point.

SHRI AMRIT NAHATA: May I seek a clarification? As regards the 80 per cent increase and the 24 per cent fall, does it mean that today the prices are still higher by 62 per cent from the base?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I have got all the statistics here.

MR. CHAIRMAN: By what ratio have the prices of inputs gone up and have they fallen by that percentage?

SHRI AMRIT NAHATA: Is the 24 per cent fall from the base year or from the peak?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: From the peak, not from the base year. I am prepared to show all the statistics. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: By what percentage from the base year did the prices of inputs go up and by what percentage have they fallen?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: That makes it further complicated because input prices have recently gone up. The Agricultural Prices Commission takes all these factors into consideration.

I would not like to go into details because of the very happy food situation. This debate has some important features. For the first time, I think forests, animal husbandry and dairy development have received wide attention from a very large number of hon. members. This is a very good augury for our country. I shall first deal with forests. Forests occupy a very important place in our economy, particularly ecology. In fact, in this country over the last 100 years, if anything has happened which has affected the ecological balance, it is that large denudation of forests has taken place. There are large areas, even good rainfall areas, which are without vegetation or tree cover. I am glad now there is a good debate going on in the country. There is greater awareness in leaders political workers and our colleagues are drawing our attention to this very important aspect of forestry. Therefore, Government are also trying to respond to the aspirations of the people.

I would just like to show how forestry is getting more and more attention at our hands. I would quote some figures. For instance, in the First Plan, we provided only Rs. 8.5 crores in the country for forestry development. In the Second Plan, the figure was 21.2 crores; in the Third, it jumped to Rs. 45.9 crores; in the Fourth Plan, we provided Rs. 89.2 crores and now the Fifth Plan provides almost Rs. 215.8 crores for forestry. This can go up. It is our experience that these are not paper figures. In some areas, the expenditure may go up a little more than what is provided. But I would like to make a point here. . Without the willing co-operation and conscious awareness of the population, the forestry development programme will never succeed. I was in some European countries. There I found that even in small, small areas they have planted forests. Nobody would touch a tree; in some countries, there is a feeling that if somebody cuts a branch of a tree, it is a sin like cutting the hand of a child. In our Puranas and in the time of our forefathers, they had attached great importance to this aspect. One of our valued colleagues has drawn our attention to the fact that the Great Budha had attached importance to forestry.

Now two things are important here: popular awareness and popular involvement. If these come about, if the gram panchayats, educational institutions, social and political workers forgetting all political differences, try to do that, it should be possible to protest our forests and bring about a proper ecological balance.

In regard to dairies, I should like to highlight one or two points briefly. For the past twenty years the picture was discouraging but milk production has come up at a satisfactory rate in

[Shri Annasaheb P. Shinde]

recent times. What has happened for the first time last year indicated the rich potential, like foodgrains production, this country has a very rich potential for producing good quantities of milk. Some areas have started actually producing more milk than the government dairies could collect. In Maharashtra State there have been angry demonstrations by farmers against Government for not accepting all that was produced. In Bombay milk is available in abundance, as also milk available in abundance, as also milk Punjab and Haryana, the same thing We have been importing skimmed milk powder to the extent of Rs 11, 20 or 30 crores annually; for the first time now we took a decision· no imports will be allowed unless whatever is locally produced is consumed We can manage the dairies in the country by using our milk powder. It has shown the rich potential that is there. Cities like Delhi still have some problems· I am aware of that. But the present trend augurs well for the dairy industry. Some hon. members have termed it as white revolution; whether it is the proper word or not

MR. CHAIRMAN: Operation Flood

SHRI ANNASAHEB P SHINDE There are various terminologies and I would not accept a foreign terminology. As far as this is concerned, this country is in for a very good development.

MR. CHAIRMAN: Are you thinking of exporting milk powder?

SHRI ANNASAHEB P SHINDE· Not immediately. But if Australia and New Zealand can do it, why cannot India do it? If EEC countries which had four months of snow covered lands can do it, why cannot we? The potential is there. This development has thrown upnew possibilities. Mr Painuli was referring to cross-breeding and he said that in the Himalayns cattle development could be improved. You also referred to this.

MR. CHAIRMAN: I was thinking of millions of underfed children.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Even for children milk was not available. Now that milk production is coming up, the problem of nutrition of children will get solved. I see all those possibilities. We started with a provision of Rs. 15 crores in the first plan in the fifth plan the provision is Rs. 539 crores We have modern dairy plants all over the country, more than 168. We propose to have more and more dairy plants wherever milk production and marketing arrangements have to be made We have approached the World Bank for loan for very big projects in some places.

Shri Chandrappan asked about the coconut board, he was a participant at the conference of parliament members which my ministry organised and I am glad that the conference made very valuable contribution to an understanding and assessment of the problems of coconut industry We as a ministry think that there was a strong case for the formation of a coconut board We have not taken a final decision, we are awaiting the comments of the governments in the coconut growing states. We are well aware that the Kerala government is very much in favour of that; the Karnataka government have also said that they want the coconut board to be set up We are awaiting the comments of the other state governments The conference has succeeded in opening up this issue and my ministry's approach is to find out ways and means so that the coconut economy could be supported as coconut plays an important role in the farmers economy and also in oil and agricultural economy in coastal areas.

Some hon. members referred to the implementation of the recommendations of the National Commission on Agriculture. Shri Nathu Ram Mirdha was the chairman. First of all I want to thank Mr. R. N. Mirdha and all his colleagues in the commission and the vice-chairman Shri Sivaraman, who is

deputy chairman of the planning commission. They have produced a very valuable document for the guidance of the government of India. After the 1929 Royal Commission on Agriculture, for the first time such a valuable report has come which will help us in formulating our policies. I thank the Commission and others who worked on it. My ministry has taken the recommendations very seriously and would like to implement them as expeditiously as possible. But as he himself said, some of them are of far-reaching importance and cannot be implemented in a year. In some recommendations the State Governments are involved and some have financial implications. All these will have to be gone into. We have set up an implementation cell in the ministry and I am sure these recommendations will provide a very strong basis for formulation of future policies. Some of the recommendations in the interim report have been incorporated in the fifth plan regarding marginal farmers, small farmers, dairy programme, piggery and poultry programmes for weaker sections, etc.

Food procurement this year has been going on very well The good food situation is getting reflected in the procurement. As far as kharif procurement is concerned, we have crossed 56 lakh tonnes. I am confident we will reach 6 million tonnes. Our stock position is very comfortable We are almost approaching 11 million tonne mark in the stock position in the central pool and with State Governments. Our original estimate was that by 31st July we will have a stock of 13 million tonnes, but I am afraid our stock position may exceed even 15 million tonnes.

MR. CHAIRMAN: You do not have enough storage capacity.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: You are aware of it. We require the sympathies of the hon. members and yourself. I am glad to mention that despite the good food situation, we are not relaxing procurement because the public distribution system plays . very important role in our economy Mr. Bhogendra Jha said that prices should not be allowed to rise in the loan period. With such a large stock with us, I do not think we should be afraid of it. We shall be able to release large quantities through the public distribution system and see that the interests of the vulnerable sections are well protected.

MR. CHAIRMAN: You must requisition private godowns

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: That we are doing. Wherever storage capacity is available, we will use it.

SHRI NATHU RAM AHIRWAR (Tikamgarh): The prices of inputs should not be allowed to go up

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Our effort is to bring down their prices. Shri D. D. Desai always makes suggestions with good intentions. He said that 15 per cent of the production should be kept in silos. I would point out that the cost of construction of silos as against ordinary storage is very high. If for ordinary storage we have to invest Rs. 250 per tonne, for silos it would be Rs. 700 to 800. We are not against silo construction. In the long run for maintaining buffer stocks over long periods, we do require silos But when we are struggling with the problems of inadequacy of resources and when time is of the essence and we have to construct storage capacity very fast, silos will have to wait for their turn and come in gradually.

Shri Hari Singh said, there are some malpractices taking place in Bulandshahr and for quality reasons wheat is being rejected and not purchased by the FCI or State Government agents Immediately we got in touch with the FCI and they have deputed an officer to Bulandshahr area. We have asked him not to leave that place till all the problems have been tackled. In this respect the cooperation of the State

[Shri Annasaheb P. Shinde]

Government is necessary. They will have to be very vigilant. A similar situation was there in the past and we want popular committees to be set up, which will cooperate with the local administration.

श्री नाथूराम अहिरवार : आपका जो अफसर है वर वहां के लोकल अफसरों को कुछ नहीं समझता है, वह कहता है हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अफसर हैं ।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: We want to know from the U.P. Government what type of arrangement they consider desirable.

Sir, agriculture is playing a very important role as far as exports are concerned. Hon. Commerce Minister, Shri Chattopadhyaya knows about it. This year, we have almost succeeded in exporting agricultural commodities worth Rs. 1000 crores.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): This includes sugar also.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Yes, of course.

Regarding the point of Shri Painuli, we are thinking of setting up a fruit and vegetable corporation so that the interest of the farmers in the hill regions is safeguarded.

I do not want to take much time of the House. I thank all the hon. Members for taking keen interest in the subject and showing courtesy towards us because without their courtesy it would have been difficult for me as well as for my senior colleague to function effectively.

I would like to end by saying that this country has a great future as far as agriculture is concerned. We must try to see that this country becomes the first rate agricultural power in the world.

श्री सी० डी० गौतम (बालाघाट) : सभापति महोदय, 1972—73 और 1973-74 ये दोनों साल भयंकर अकाल के थे । अब हमें प्रकृति पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा । सिंचाई की जितनी भी योजनायें हैं — उन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ....

सभापति महोदय : आप की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, आप थोड़ा आगे आ कर बैठ जायें ।

श्री सी० डी० गौतम : तो मैं यह कह रहा था कि दो अकालों से 1973—74 और 1974—75 हम को सबक लेना है और सिंचाई के साधन जितने भी बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ाना जरूरी है । बड़ी योजनायें तो केन्द्रीय सरकार करने वाली है, और करेंगी भी, छोटी योजनाओं को राज्य सरकार करती है । इन के अलावा और भी छोटी तथा अन्य योजनायें हैं जो अमल में ला सकते हैं, जैसे पुराने तालाब हैं जिन से प्रति तालाब 1,000, 500 एकड़ की सिंचाई होती थी । आज उन तलाबों की हालत बहुत खराब है, उन में पानी नहीं भरता है । पहले छोटी नदी, नाले रोकते थे, उन के भी रोकने का काम आज बन्द हो गया है । इस का कारण यह है कि ग्राम पंचायतें परवाह नहीं करती हैं । वैसे ही जंगलों और पहाड़ो से जो पानी आता था उस को भी रोकते थे और सिंचाई के काम में लाते थे जिस से फसल अच्छी होती थी । जो वर्षा का बस्तियो में से बहता पानी होता था वह भी बड़ा रसायनिक तत्वों से भरपूर होता है और उस को को भी रोकते थे । परन्तु आज उस को भी कोई नहीं रोकता तो आज हजारों मन की फसल हम गंवा रहे हैं जो कि मामूली उपाय से उपलब्ध हो सकती है । ग्राम पंचायत और राज्य सरकार उस को उपलब्ध कर सकती हैं अगर थोड़ा सा ख्याल करें । इस के लिये केन्द्रीय सरकार को राज्यों को सुझाव देना चाहिये कि वह इन की व्यवस्था करें ।

दूसरे हम देखते हैं, मैं अपनी जगह की बताता हूं कि हमारे जिले में भिसोर नाम क

बहुत बढ़िया चावल होता है जो बासमती से महक में ऊंचा होता है, परन्तु ग्राज कल रसायनिक खाद का उपयोग होने लग गया है इसलिये उस का दाना जरा मोटा हो गया है ग्रौर उस में महक भी वह ग्रब नहीं है। बासमती का भी शायद वही हाल हुग्रा होगा। इसलिये इस ग्रोर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये, ग्रौर इस के लिये उपाय सोचना चाहिये कि जैसी पहली हालत थी उस हालत में उस चावल को रखने के लिये क्या उपाय किये जायें।

सभापति महोदय ग्रसली गुलाब ग्रौर नकली गुलाब वाला मामला है।

श्री सी० डी० गौतमः : बिल्कुल सही ग्राप ने कहा। कुछ मुर्झाया सा फूल हो गया है। तो यह ग्रनुसंधान की बात है।

हम ने देखा कि हमारी सरकार उत्पादन बढ़ा रही है। 11 करोड़ 40 लाख टन तक बढ़ गया है, ग्रच्छी बात है। ग्राप ने पढ़ा होगा कि केन्द्रीय चावल ग्रनुसधान केन्द्र एक हैक्टर में 50 क्विंटल धान पैदा कर रहा है। अब ग्रगर वह कहते हैं तो यह बात सही होगी ग्रौर हमें इस को मानना चाहिये। इस तर ह से ग्रगर हम बढ़े तो एक ग्रादमी 10 एकड़ जमीन में बहुत पैदा कर सकता है। परन्तु इस में हम कितने सफलीभूत होते हैं यह देखना है।

ठीक है कहीं कही दो फसल लेते हैं। परन्तु ऐसा क्षेत्र कितना है? मैं ग्रपने गाव का बताता हूं कि मेरे गाव में दो फसल नहीं होती, सिर्फ एक होती है क्यो कि पानी ग्रौर बिजली का साधन नहीं है। बालाघाट जिले मे जो मेरी कांस्टीट्एंसी है, ग्राप देखेंगे तो दो फसल बहुत कम ली जाती हैं। छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है। ऐसा इसलिए है क्यों कि पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पानी का प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय ग्राप के यहां से तो नदी जाती है।

श्री सी० डी० गौतम : ग्राप ने ठीक फरमाया। वेनगगा जाती है जोकि 70 हजार एकड़ में सिंचाई करती है लेकिन पूरे जिले मे 3 लाख एकड जमीन है। बाकी जो जमीन रह जाती है, उस मे सिंचाई नहीं हो पाती है। बलाघाट जिले मे बहयर का जो इलाका है, वह बिल्कुल जंगली इलाका है ग्रौर वहा पर ग्रादिवासी ग्रौर हरिजन रहते हैं लेकिन उन के लिए वहां पर पानी की सुविधा नहीं है। ग्रगर उन को ग्राप पानी की सुविधा नहीं देंगे तो वे ग्रपनी प्रगति करेंगे। इस के बारे में कितनी बार जिले के ग्रधिकारियों को कहा है, नहरों के ग्रधिकारियों को कहा है लेकिन उन्होने इस पर कोई ध्यान नही दिया है। मैं चाहता हू कि सरकार इस ग्रोर ध्यान दे।

मलाज खड मे एक कापर की माइन है ग्रौर वहा पर कापर निकल रहा है। वह एक बड़ी भारी वस्ती होने वाली है ग्रगर वहा पर इस काम को बढ़ाया गया। जब वह एक टाउनशिप बन जाएगी, तो वहा पर लोगों को ग्रन्न की जरूरत पड़ेगी। ग्राज तो वहा पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि सिंचाई की व्यवस्था वहा पर होनी चाहिए ग्रौर इस के लिए ग्राप कोई बड़ी योजना तैयार करे।

ग्रब मैं ग्रनाज के भावों पर ग्राता हू। हमारे यहां धान का भाव 90 रुपये है। बालाघाट मेरा जिला है ग्रौर वहा से भंडरा जिले में, जोकि महाराष्ट्र मे है ग्रौर वहा से बहुत दूर नही है, भाव बहुत ज्यादा है। जब फसल चालू हुई थी, उस वक्त हमारे यहा 80,90 पैसे किलों का भाव था जबकि भंडारा में डेढ़ रुपया था। इसलिए हमारे यहा से माल स्मगलिंग हो कर वहां जाता था ग्रौर बिकता था। जब वहां पर दाम ज्यादा होंगे तो लोगों को स्मगलिंग का

[श्री सी० डी० गौतम]

लोषन होगा। लेकिन अब इस बीस सूत्री कार्यक्रम मे स्मर्गलिंग का काम बन्द हो गया है और थोडा बहुत है भी तो उस से बहुत फर्क पडने वाला नही है। मेरा एक सुझाव मंत्री महोदय को और भी है। जो हमारे यहा किसान मजदूर है, उन को सिर्फ 5,6 महीने ही किसानी करने मे लगते हैं और बाकी समय वे बेकार रहते हैं। जहा दो तीन फसले होती है वहा तो ठीक है कि उन को काम मिल जाता है लेकिन मेरे जिले मे एक ही फसल होती है। क्योंकि वहा पर पानी की व्यवस्था नही है। इधर दो साल से 30, 35 हजार एकड में दो फसले होने लगी है लेकिन बाकी रकबे में एक ही फसल होती है। इसलिए वहा पर कोई इस तरह की व्यवस्था हो कि जिन दिनों वे खाली रहते है उन को काम मिल जाए। सिचाई की सुविधा बढाने पर वहा पर और रकबे में भी दो फसले हो सकती है।

एक बात यह कहना चाहता हू कि इस साल फसल बढिया हुई है। इसलिए कुछ लोगों का यह कहना है और उन्होंने हमारे पास कहलवाया है कि यह जो प्रान्तबदी है, इस को तोड़ दिया जाए। इस के बारे मे मंत्री जी ख्याल करें या कम से कम यह कर दे कि 10 किलो से 20 किलो तक, जोकि एक आदमी अपने सिर पर ले जा सकता है, उस को दूसरी जगह ले जाने की इजाजत दी जाए जिस से कि वह दो तीन रुपये रोज कमा सके क्योंकि हमारे यहा 8,90 पैसे प्रति किलो का जब भाव है, तो पास ही भंडारा जिले मे 1 रु० 25 और 1 रु० 30 पैसे का भाव है। कुछ तो बेचारे अपने खाने पीने के लिए कमा सके। इतना तो आप करही सकते हैं इस में कोई स्मर्गलिंग का सवाल नहीं आएगा जितना स्मगल होना था हो चुका है, जितना किसानो ने बेचना था बेच चुके हैं। मजदूरों के लिये थोडा बहुत हो सकता है अब भी हो जाए मई का महीना इन बेचारे मजदूरो के लिए बहुत भयंकर है। पहले वे पहाड़ो पर, जंगलों में जाते थे, महुआ खाते थे, अचार खाते थे तेंदु के फल खाते थे। अब तो तेंदु के पत्तो का भी राष्ट्रीयकरण हो गया है। अब वे कंद मूल भी नहीं ला सकते हैं। यह भयंकर समस्या किसानी मजदूरों के सामने है। इस वास्ते अगर आप इतना कर दें तो आप उनको बहुत कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं।

16 hrs.

SHRI BANAMALI PATNAIK (Puri) At the outset I must congratulate the Ministry of Agriculture and Shri Jagjivan Ram on resolving the water disputes among the various States and also the Chief Ministers for agreeing readily to resolve these river disputes so that many problems can be solved In this Orissa is also one of the States like your State of Maharashtra and Andhra Pradesh I hope that the projects which have been pending for a long time will now go ahead

I have listened very keenly to the speech of Mr Shinde It is really gratifying that food production is going ahead and that in the near future we will no longer have to face the humiliating prospect of going to foreign countries with a begging bowel The day is certainly coming when India will be not only self-sufficient in food, but will also be in a position to export

We have to depend mostly on our science and technology and the socialistic idea which has developed various methods suggested to the agricultural universities For this purpose also, agricultural education is important We have established a large number of agricultural universities and the ICAR is financing them, but what is the result? After all, who is the farmer? No agricultural graduate is a farmer We have to think of the people who are working in the field. So, there must be some kind of change in our thinking of agricultural education.

Some years ago there was a suggestion made by the Government of Orissa to which the Government of India agreed. A committee was appointed under the chairmanship of Shri B. D. Nag Chowdhury, the then Member of the Planning Commission, for the introduction of agriculture in higher secondary schools. A syllabus was drawn up and curriculum was prepared. A circular was issued to the different States. Some provision was made by the Planning Commission. The proposal was to set up at least 50 such schools in each State so that agricultural education could be imparted because today, though science and technology have advanced, the agriculturists cannot understand what is input, what is agricultural management, what is water management, what is command area development etc. So, something should be taught at the school level so that those who go to the fields may understand these things, and not merely the graduates who only become supervisors at the district or block level. But that has not been developed. That file is moving between the Agriculture Ministry and the Ministry of Education. The Agriculture Ministry is very keen on it, but aparently the Ministry of Education is not. Agricultural schools should be set up so that the boys who go to the field have some basic knowledge and they can utilise science and technology on the farm. It is stated sometimes that the illiterate farmers do not know anything. So we want everyone to be literate. They must be at least of Matriculation standard: they may be given education at least up to Higher Secondary standard. Their education is very important and this is linked with the Agricultural Universities, the Agriculture Ministry and the Education Ministry. So they should take it up and at least some Higher Secondary Schools should be started in different States in this Plan period and these have to be connected with the Krishi Vidya Kendras of the ICAR at different places. There is a lot of information available with the Krishi Vidya Kendras but who knows it? It is only the Block Development Officer who goes there and then tells them something, but they cannot understand if it is something mechanical. Of course they are intelligent and they have been traditionally doing something, but that tradition has to be changed and it has to be done in a scientific manner. So, agricultural education is very necessary and plays an important role in achieving our target in the agricultural field—because bout 50 per cent of the population are engaged in agriculture. And if agriculture does not improve, industry will suffer because agriculture produces raw materials for the industry, agriculture produces materials for export and agriculture produces various other things. The Agriculture Ministry is the biggest Ministry with which all the States are concerned because it deals with Forests, it deals with Animal Husbandry, it deals with Co-operation, it deals with Community Development, with Irrigation, Agriculture, Land Reforms and many other things. So, this Ministry with which all the States are concerned, should see how these are to be integrated.

In our Universities, Forestry is not a subject they never introduced it. They are now trying to introduce Fisheries as a subject. Of course. Fisheries has a very important role in our development because fish is part of our protein food. But how are you going to do it? There has been very little research in Fisheries development. From the report I find that there is some research in fresh water fish. But in regard to Chilka brackish water lake which has an area of 80 kilometres, no research has been done. We have been pressing and the Orissa Government has also been pressing that this should be a Central subject. With World Bank assistance, this should be developed for the purpose of exports. Last year we exported marine products worth Rs. 10 crores, but it can be further developed, not only for the purpose of fisheries but for other development also because it has been tested and found that desilted Chilka soil can also be utilised as

[Shri Banamali Patnaik]

chemical fertilizers. But how should it be desilted? This should be taken up for consideration, as to how to improve the position in regard to the Chilka Lake.

Now, something has been said about Forests and I don't want to repeat the same thing But our forest products also help certain industries. A large number of paper mills are set up in this country. We have given licences to some paper mills and they are cutting bamboo at random, they don't care for the forests. Each paper mill should be made responsible for the growth of forests which they are utilising. One acre of bamboo growth can give only 20 tons of pulp, but one acre of eucalyptus can give 80 tons of paper pulp. So, it has to be calculated as to what should be grown, if you are thinking of expanding the paper industry. Because there is shortage of paper we want the paper industry to grow, but without forest resources, the paper industry cannot grow. So, the paper industry must have a say in the expansion of forest resources They must work on some rationale or some method to develop forests in areas in which licences have been granted to paper mills Whether it is Orissa, Madhya Pradesh, Bengal or Assam, the forests have to be developed if we want to develop our industries in the manner we want.

MR. CHAIRMAN Please co-operate with me, there are 40 persons on the list down below

SHRI BANAMALI PATNAIK: Just one minute more.

Now, in regard to Community Development, we are not really giving adequate finance to the Community Development Blocks though we wanted to decentralise power. Let the Minimum Needs Programme be given to them, let there be more activity there. But there is no money with the Community Development Blocks even for certain programmes which the Agriculture Ministry gives them. This Minimum Needs Programme is also looked after by the Agriculture Ministry. So let the Ministry allot this programme also to the Committee Development Blocks so that they get more incentive and more work and will know the work.

SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA (Amritsar): Mr. Chairman, Sir, I must congratulate the Government for turning this country from the position of a deficit State to that of a surplus State in respect of food. It has been possible only on account of the policies which this Government has been pursuing in the past. It is the direct result of these policies that we have now a very big surplus this year. We have 70 million tonnes of grains in the kharif crop and we are likely to have 45 million tonnes of foodgrains in the rabi crop, thus totalling 115 million tonnes ...

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Kharif will be slightly more.

SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA: It is good if it is more than 70 million tonnes. My estimate was that it was about 70 million tonnes.

With this sizable quantity of grains in our hand, there are certain problems to which I want to draw the attention of the Ministry.

The first problem that comes to my mind is that of storage. We do not have good storage facilities, and with the sizable quantity of grains that we are going to have with us plus the carry-over of 11 million tonnes plus the imports of four to five million tonnes—we have already agreed to import and those imports are also coming to this country—with this large amount of foodgrains, we will find it difficult to manage. I know, the Food Corporation of India, which is handling the storage, procurement and distribution on behalf of the Government, is being manned by a very experienced officer,

and I have no doubt also that the officers in the Food Ministry who are very well trained will be able to rise to the occasion to meet this challenge. Still I feel—I have got a fear in my mnd—that we will not be able to manage this much quantity. It is not a question of only storage. Whatever storage facilities you may be able to get or procure, whether in the schools or in the private godowns of the country still our foodgrains will be much more than what you can possibly arrange for, more so because the foodgrains of the rabi crop will come within two months. When there is a shortage, arrivals in the market are not much, but when there is a surplus, the farmer tries to unload his grains in the market because he knows that the prices are not going to rise. Therefore, I would like that, apart from storage space, you may also think of revising your policies by which so much of storage may not take place.

My first suggestion is that, instead of having a single zone, you may have three zones in this country, so that the wheat or other grains may flow on private level also, so that there may not be much pressure on the FCI, which is a single agency handling this affair in the country.

The second suggestion that I want to make is that you must change your psychology, your policy. When we were deficit, you were having certain policies, certain rules which were quite right when we were deficit. But since we are surplus now, I would like to ask you as to what is the necessity of having controls or restrictions on the movement of wheat products. Wheat products should be allowed to move all over India. That will certainly relieve the pressure on the FCI. The 250 units of floor-mills in India are working to a capacity of 20 or 30 per cent. If the mill products are permitted to move all over India, surely, the mills will get more work and they will consume more wheat. That will reduce the pressure on storage.

The second point I would like to raise is with regard to the prices of the foodgrains. Every year you have an Agricultural Prices Commission which advises you on prices of foodgrains. But the farmers are not happy because the prices fixed by you are not in consonance with the prices which they have to pay on the inputs etc. For instance, you have seen, all the States have raised the water rates and the electricity rates. The prices of tractors are prohibitive. You have raised the prices of fertilisers. If you see their economy, you will find that the farmer is not happy because while he is producing more for the nation, he is not getting the same remuneration as he was required to have or at least what he used to have in the past. You have commissions for fixing prices of other commodities but why do you not have commissions which will go into the prices of inputs and the cost of the grain which he produces. There in order to have a long-term policy, you must go into this aspect and also wherever you can reduce the prices, whether it be of fertilisers or tractor or other inputs, you must do that.

The third point I would like to mention is with regard to irrigation. The Indus Water Treaty of 1960 gave unrestricted use of water to India after 1970 March. We have spnt Rs. 100 crores in foreign exchange which was paid to Pakistan as compensation, to get the use of the waters of the Ravi, the Beas and the Sutlej. But we have not been able to tame and utilise the waters of the Sutlej. So far as the Ravi and the Beas are concerned, after 1970 we could have utilised those waters. But after payment of Rs. 100 crores, still Pakistan is taking advantage of that water which is flowing to Pakistan. We have not been able to make use of that water. May I ask from the Ministry why is it so? Why have we not been able to utilise the water? Firstly you said that there are inter-State disputes. But those disputes are not there. Punjab and Kashmir have settled. You have unilaterally decided to give water to a large extent

[Shri Raghunandan Lal Bhatia]

to Haryana. That is all right. That is your decision. That is all right. But why are you not going ahead with the Thein Dam scheme when you know it that this scheme is pending for the last 7-8 years? No clearance is given to it. May I know why it is so? Because sometimes it is said that it is an energy scheme and it has very little irrigation potential...(*Interruptions*) Whatever it is, this is a problem which you have to tackle but you are running away from it. We have got certain misunderstandings about this scheme, whether the centre is at all interested to carry out this scheme. You have said about Punjab. But Punjab is giving you 90 per cent of the rice procurement to the Central Pool and it is giving 60 per cent of the total wheat to your national pool. Even many States put together cannot give 60 per cent. Punjab alone with 12 small districts is giving you 60 per cent of the national pool. When there is a war—1965 and then 1971—it is the Punjabis who have borne the brunt of it But what are you doing for Punjab? This is one scheme which we are requesting you again and again for the last 7-8 years, but you are silent about it. I would request the Minister to categorically let us know whether you are interested to carry on this scheme or not, whether it has irrigation potential or not and whether it is an energy scheme or not, or whatever it is. We are very sentimental about it and we want a clear-cut answer from the Centre, for even if you clear the scheme to-day, it will take 6-8 years for completion and you are unnecessarily wasting a national water which is going to Pakistan If we utilise that water we will be able to bring more than a million acres under cultivation and we will be able to save all the money that we are spending now on import of foodgrains. . . .

MR. CHAIRMAN: Which is that scheme?

SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA: Thein Dam.

You can well afford to spend millions and millions of rupees on import of foodgrains but you cannot afford to spend Rs. 200 crores on this scheme. I would, therefore, strongly request the Minister to make a categorical statement on this Thein Dam.

श्री दलीप सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति जी, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कई वर्षों के अकाल के बाद इस वर्ष हमारी माननीया प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर जो बीस सूत्री कार्यक्रम चला— उस का परिणाम है कि हमारे किसानों ने बहुत अच्छी पैदावार कर के दिखलाई है। आप जानते हैं कि गेहूं और दूसरी चीजें जैसे चना, जो, आदि इस वर्ष देश के अन्दर इतनी मौजूद हैं कि हमारा देश आज धन-धान्य से भरपूर है। लेकिन, सभापति जी, देखने में यह आया है कि किसान जितनी ज्यादा पैदावार को बढाता है, उतना ही उस की पैदावार का रेट गिर जाता है। आप को याद होगा, पिछली दफा उत्तर प्रदेश में किसानो ने बहुत ज्यादा आलू पैदा किया। एक रुपए का ढाई किलो आलू तो दिल्ली में बिका और उत्तर प्रदेश मे एक रुपये का चार किलो आलू बिका—इतना ज्यादा भाव आलू का गिर गया। लेकिन जब वह माल किसान के घर से चला गया तो आज आलू का भाव क्या है —आप देख लीजिये, दुगना, तिगुना भाव हो गया है। किसान का उत्साह इन बातों से टूट जाता है।

गेहूं का भाव प्राइस कमीशन ने 105 रुपया मुकर्रर किया है, लेकिन आज आप किसी भी मार्किट में जाये, कोई भी ग्राहक इस बात के लिए तैयार नही है कि 105 रुपये में खरीद ले। फूड कार्पोरेशन के इन्स्पैक्टर मार्केट में आते हैं, किसान की ढेरियों को छोड़ कर चले जाते हैं, नहीं खरीदते हैं, नतीजा यह होता है कि किसान को उस ढेरी को सस्ते दामों पर बेच कर अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है। जब सरकार ने 105 रुपए का भाव मुकर्रर किया है तो फिर उस भाव पर उस

के माल को क्यों खरीदा नहीं जाता ? किसान इस बात से बहुत परेशान है। हालांकि 105 रुपए का भाव बहुत कम है। प्राइस कमीशन ने पता नही किस तरह से हिसाब लगा कर यह भाव मुकर्रिर किया। एग्रीकल्चर कमीशन की सिफारिशें ज्यादा भाव के लिए थीं, लेकिन उन की बात को नही माना गया।

मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूं—इस प्राइस कमीशन में किसानों का नुमाइंदा जरूर होना चाहिए ताकि किसान को तसल्ली हो सके, कि प्राइस कमीशन में उस का नुमाइन्दा है जो बैठ कर भाव को मुकर्रर करेगा। किसान इस से निश्चित हो जाएगा, वह यह समझ लेगा कि वहां पर उस का नुमाइन्दा जा रहा है, वह ठीक कर रहा है।

सभापति जी, आप जानते हैं कि बिजली के रेट बढ गए हैं। जैसा अभी भाटिया साहब बतला रहे थे—डीजल के रेट भी बढ गए है, कैमिकल खाद जो पिछले साल से पिछले साल 50 रुपए बोरी में मिलती थी, इस दफा 105 रुपए में मिल रही है। जब हर चीज का भाव तना बढ जाय और किसान को पैदावार का भाव न बढ़े, तो इस का किसान के मन पर क्या असर पडेगा आप खुद अन्दाजा लगा सकते है। मैं चाहता हू कि इस तरफ आप अपनी तवज्जह लगायें—आखिर किसान किस लिए पैदावार को बढायें, वह नेशन की खिदमत के लिए तैयार है, पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाव की कमी को वह बहुत ज्यादा महसूस करता है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर सारे हिन्दुस्तान के अन्दर लैंड-लैस लोगों को, जो बगैर-जमीन के लोग हैं, उन को जमीनें बाटी जा रही हैं। किसी को एक एकड मिलती है, किसी को दो एकड़ मिलती है। आप सोचिये एक एकड़ या दो एकड़ जमीन में किसान कैसे गुजारा कर सकता है। वह बैल खरीदें या ट्यूब-वैल बनायें—उस के पास साधन नही है, पैसा नही है। इस सिलसिले में मैं एक सजेश्चन देना चाहता हूं—आप एक्सपैरिमेंट के तौर पर एक ऐसा यूनिट कायम कीजिए, जहा 100 किसान मिल जाए, उन्हें जोतने के लिए एक या दो ट्रैक्टर दीजिए, जैसी वहा पर जरूरत हो उसके लिहाज से दीजिए और उनसे जुताई के पैसे चार्ज किये जाय। इसी तरह से वहा पर ट्यूबवैल या नहर का इन्तजाम कीजिए और जब वे पानी लें तो उन से पानी का पैसा ले लीजिए। अगर हम छोटे किसानों को इस तरह की सहूलियत दे तो इस से उस का काम चल सकेगा, वरना उन को बहुत परेशानी होगी।

सभापति जी, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा है—हमारे देश में सिंचाई की बहुत दिक्कत है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पानी नही पहुचता और पानी के न पहुचने से किसान कोई भी चीज वहा पर पैदा नही कर सकता। अभी थीयन स्कीम की बात भाटिया जी ने उठाई थी। हम ने भी वहां जा कर देखा है, तलवाडा तक हम देख कर आये है, वह स्कीम अभी तक पूरी नही हो सकी है। पजाब और हरियाणा की नदियों के पानी का मसाल बहुत दिनों से का हुआ था, मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देता हू, उन्होंने उस का फैसला कर दिया है। और उम्मीद करता हू कि वह फैसला ज्यों का त्यो अटल रखा जाएगा और रद्दोबदल नही होगा ताकि और जगहों के फैसले भी इसी तरह से हो जाएं।

सभापति महोदय एक बात मैं कई साल से कहता रहा हू और हमारे माननीय शिन्दे साहब हमारे सामने हैं दिल्ली के किसानों की जिन की जमीनें ऐकवायर हो गई हैं, 115 गावों की, उन्होंने अपने पडोस हरियाणा में कुछ जमीने खरीद ली हैं। लेकिन वह अपना पैदा किया हुआ अनाज वहा से दिल्ली नही ला सकते हैं। किसान के तौर पर मैं बताता हू कि नरेला गांव मेरे चुनाव क्षेत्र में है, उस गाव के लोगों की जमीन हरियाणा में मौजूद है

[श्री दलीप सिंह]

जो बिलकुल मिली हुई है। वह उन खेतों पर से गेहू उठा कर नही ला सकते है, मजबूरन उन को गेहू हरियाणा में बेचना पड़ता है। तो मतलब यह हुआ है कि जो किसान गेहू पैदा करता है, वह किसान अपना गेहू खाता है। चाहे वह किसान मद्रास का हो, पंजाब का हो या हरियाणा का हो, उन को सहूलियत है कि अपना पैदा किया हुआ गेहू या चावल खाये। लेकिन दिल्ली के लोग अपना पैदा किया हुआ गेहू नही खा सकते। तीन साल से इस बात पर पाबन्दी है। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जिन की अपनी जमीन है उन को राशन के हिसाब से जो दिल्ली मे मिलना है, एक दफा उस हिसाब से अपना पैदा किया हुआ अनाज लाने की इजाजत दे दी जाय ताकि वह अपने गेहू को दिल्ली मे ला सके और अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सके।

सभापति महोदय अब तो यह पोमिशन हो जाएगा।

श्री दलीप सिह आप किसी मंडी मे जाइये अनाज के ऊपर से जानवर और गाडिया घूम रही है। लेकिन दिल्ली वाले अपना पैदा किया हुआ अनाज यहा नही ला सकते हैं। अगर आप उन को लाने की इजाजत दे दें तो 115 गावो के लोग आप के बहुत आभारी होगे।

MR CHAIRMAN: Kindly make a note of this request, it is reasonable

श्री दलीप सिह दिल्ली के देहात शहर की गिरफ्त मे आ गये है। दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है और दिल्ली के किसानो को बढ़िया जमीनें बस्तिया बनाने के लिए ली जा रही है। अभी झुग्गी झोपडी वालों को निकाला जा रहा है और उन को दूर बसाया जा रहा है। हम ने कई बार कहा कि इस काम के लिए जो बजर जमीन हो उसे लिया जाय। लेकिन जो फर्टाइल जमीन है, जिस जमीन के अन्दर 50,60 मन एकड मे पैदा होती है, ऐसी हमारी जमीन छीनी जा रही है। इसलिए मेरा कहना है कि दिल्ली के किसानों की उपजाऊ जमीन न लें जिस से वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। आज उस जमीन पर झुग्गी झोपडिया डाली जा रही है। जिस जमीन मे 10 मन बीघा का गेहू पैदा होता है क्या वही झुग्गी झोपडी डाली जाय? और बहुत ही बजर जमीन है वहा पर क्यों नहीं झुग्गी झोपड़ियों को डाला जाता है? मेहरबानी कर के इतना आप कर दे कि जो दिल्ली की फर्टाइल लैंड है उस को पीछे रखा जाए और जब कही भी आप को जमीन न मिले तभी उपजाउ जमीन को लिया जाए। उस को प्रायरेटी न दी जाए।

इन शब्दो के साथ मे आप का बहुत मशकूर हू कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

प्रो० एम० एल० सक्सेना (महाराजगंज) सभापति महोदय, शिन्दे साहब ने एक विरोधी सदस्य के कुछ शब्द यहा पढे थे। मुझे सुन कर दुख हुआ। आज वह जमाना नही है कि विरोध के लिये ही विरोध किया जाय। जहा तारीफ की बात हो वहा तारीफ भी करनी चाहिए। और सारे सदन ने कृषि मंत्रालय की तारीफ की है। इसलिये मै शिन्दे बाबूजी को और उन के सहयोगियो को बधाई देता हू। बहुत अच्छी तरह से माननीय जगजीवन राम जी ने इस मंत्रालय को सम्भाला है। पहले जब वह कृषि मंत्री थे तो ग्रीन रिवोल्यूशन लाये, जब सुरक्षा मंत्री थे तो देश को सफलता मिली और अब की 114 मिलियन टन गल्ला पैदा किया जिस के लिये वह बधाई के पात्र हैं।

मैं ने अखबार में पढ़ा था पिछले हफ्ता कि अमेरिका से 4 मिलियन टन अनाज, एक मिलियन टन राइस और

3 मिलियन टन गेहूं, हम पर जबरदस्ती लादा जा रहा है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब हमारे यहां इतना ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ है, तो इस को क्यों लिया जा रहा है। एक मुकदमा भी अमेरिका में चल रहा है जिस में हम ने खराब गल्ले देने के कारण मुआवजे की मांग की है। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि इतना अनाज क्यों अमेरिका से खरीदा जा रहा है ?

अब एक और शिकायत मंत्रालय से है और वह यह है कि इस साल इतनी ज्यादा पैदावार हुई है कि किसान उस से परेशान हो गया है और गल्ले के दाम बहुत ज्यादा गिर गये हैं। आम बाजार में 85 90 क्वींटल गेहू बिक रहा है और जो सपोर्ट प्राईस गवर्नमेंट ने फिक्स की है, वह भी किसान को नहीं मिल रही है। दूसरी बात यह है कि अधिकारियों से बनियों ने साठगांठ कर ली है और कम दामों पर किसानों का गेहू बिक रहा है और जो मुनाफा होता है उस को वे आपस में बांट लेते हैं। सब से जरूरी बात आज यह है कि किसान को कम से कम सपोर्ट प्राइस अपने गल्ले की मिले वैसे वह प्राइस 125 रुपये क्वींटल होनी चाहिए थी।

अब मैं फोरेस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज कल जो देहरादून में फोरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट के चेयरमैन श्री जगदीश प्रसाद हैं, मैं खुश हूं कि उन का अभिनन्दन किया गया है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वे 22 साल तक अन्दमान में रहे हैं और 6 साल से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। बहुत विरोध के बावजूद वे अच्छा काम कर रहे हैं और यह खुशी की बात है कि इस बात को समझा गया है और उन को सम्मानित किया गया है लेकिन मैं चाहूंगा कि जल्दी से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उन के बारे में फैसला करे। आज फोरेस्ट का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और वे बहुत काबिल आदमी हैं।

इस के बाद मैं जमीन के बटवारे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज लोगों को जमीन बांटी जा रही है, यह बहुत खुशी की बात है लेकिन मैं आप को बताऊं कि हमारे यहां भुतनी में एक तीन एकड का टुकडा 22 आदमियों में बांटा गया। इस का मतलब यह हुआ कि एक एक आदमी के हिस्से में करीब 1/7 एकड जमीन का टुकडा हिस्से में आया। अब इतना छोटा सा टुकडा एक आदमी के लिए बेकार है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप अगर किसी को जमीन देते हैं तो कम से कम एक एकोनामिक यूनिट तो दीजिए वर्ना जमीन बाटने का कोई फायदा नहीं हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं वे सीलिंग लाज से बच जाते हैं और खराब जमीनें ही लोगों को दे देते हैं। इसलिए मैं बहुत जोर लगा कर कहूंगा कि आप लोगों को ऐसी जमीनें दीजिए जिनमें वे खेती कर सकें।

अब मैं फर्टिलाइजर्स पर आता हूं। आज उन की कीमत इतनी ज्यादा बढ गई है कि उन का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। मैं चाहता हूं कि सन् 1972 में जो फर्टिलाइजर्स की कीमतें थीं, वही कीमतें होनी चाहिए जिस से लोग उन को खरीद सकें।

फ्लड्स के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी बांध हैं उन को वार फुटिंग पर पूरा करना चाहिए। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से नेपाल की जल-कुंडी योजना बहुत महत्व की है। 22 साल पहले श्री गुलजारी लाल नन्दा

[प्रो॰ एस॰ एल॰ सक्सैना]

जी ने इस के बारे में कहा था लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि नेपाल सरकार से सलाह कर के इन को पूरा किया जाए जिस से पूरे गोरखपुर डिविजन को बाढ़ से बचाया जा सके। आज वहां पर इस के कारण बहुत बाढ़ आ जाती है। यह खुशी की बात है कि आप ने रीवर डिस्प्यूट्स को हल कर दिया है लेकिन इस को भी आप को देखना चाहिए।

यह भी खुशी की बात है कि आप ने कानून से कर्जों की माफी गावों में कर दी है लेकिन देहातों में अब कर्ज मिलता नहीं है। आप वहां पर बैंक वगैरह की कोई ऐसी व्यवस्था करें जिस से उन को कर्ज मिल जाए नहीं तो उन के सामने आज बड़ी मुश्किलें आ रही हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि गेहूं और चावल की प्राइस डिटरमिन करने के लिए साइंटीफिकली काम होना चाहिए। जो किसान का खर्च हो, उस को ध्यान में रख कर प्राइस उस को मिलना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि आज जो प्राइस किसान को मिल रही है, वह काफ़ी कम है। खाद के दाम अधिक हैं, पानी के अधिक हैं। लगान बहुत ज्यादा है और इनके साथ साथ जितनी भी इनपुट्स हैं उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं। इस वास्ते आप पता लगाएं। साइंटीफ़िकली कि उसका क्या कास्ट आफ प्रोडक्शन आता है व्हीट, राइस, गन्ने, जूट, काटन आदि का ताकि उनको सपोर्ट प्राइस और रिम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके।

शुगर इंडस्ट्री के नैशनलाइजेशन का प्रस्ताव आपने बम्बई अधिवेशन में पास किया था। इसको सात साल हो गए हैं। लेकिन आपने इसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। या तो आप कह दें कि नहीं करना है और करना है तो वैसा आप साफ़ साफ़ कह दें। यह जो अनिश्चितता की स्थिति है यह तो खत्म होनी चाहिये। अब क्या हो रहा है। वे लोग मशीनरी की रिपेयर तक नहीं करवा रहे हैं। प्रोडक्शन इस वजह से घट रहा है, रिकवरी गिर रही है। राष्ट्रीयकरण आप कर दें तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं करना है है तो कम से कम आप कह द इस बात को ताकि वे लोग रुपया लगा सकें और काम ठीक हो सके।

शुगर केन एरियर्ज भी पचास करोड़ से ज्यादा के हैं। ये बचारे गरीब किसानों के बकाया पड़े हुए हैं। उन को इन एरियर्ज को दिलाने के लिए आप कोई सख्त कार्रवाई करें। जिस फैक्ट्री के जिम्मे बीस लाख से ज्यादा के एरीयर्ज हों उसको आप प्रोकमन कर दें और इनके एरियर्ज इनको दिलाएं। कोई और सख्त कार्रवाई आप कर सकते हैं तो वसी कार्रवाई कर के आप कम से कम इस बात की व्यवस्था तो कर कि उनका पैसा उनको मिल जाए। यह बहुत बेजा बात है। वे तो मौज कर और किसान मरे, यह ठीक बात नहीं है।

शुगर केन का डिवलेपमेंट नहीं हो रहा है। उसकी भी बहुत खराब हालत है। जहां 1940 और 1942 में रिकवरी दस परसेंट होती थी वहां आज आठ परसेंट ही हो रही है। इसकी तरफ़ आपने ध्यान नहीं दिया है। वाटर लागिंग और सीपेज आदि की जो समस्याएं हैं उनको आपने हल नहीं किया है। गंडक योजना से जब नहरें निकाली गईं तब कहा गया था कि ड्रेनेज पर चौदह

करोड़ रुपया खर्च आप करेंगे ताकि वाटर लागिंग न हो और सीपेज न हो लेकिन उसको भी आपने नहीं किया। उस तरफ़ भी आपका ध्यान जाना चाहिये और इस समस्या को आपको हल करना चाहिये।

खंडसारी पर आपने पिछले साल ड्यूटी बढ़ाई थी। हमने विरोध किया था। इसको इस साल भी वापिस नहीं लिया गया है। इसे आप वापिस लें। यह एक नैशनल इंडस्ट्री है, काटेज इंडस्ट्री है।

प्राविडेंट फंड का लोगों का रुपया ये खा जाते हैं जमा नहीं करते हैं। जो ऐसा करते है उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। घघली चीनी मिल, गोरखपुर, से मेरे पास एक पत्र आया है जिसमें यह कहा गया है कि पिछले तीन महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। उसमें यह लिखा हुआ है :

इधर आपने पिछले तीन महीनों का वेतन श्रमिकों में नहीं बांटा है। फलस्वरूप श्रमिकों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। हमें डर है कि निकट भविष्य में अनाज के अभाव में कोई पत्र उन्होने मिल के मनेजर को लिखा है।

मौत न हो जाए। यदि कोई मौत हुई तो इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी।

अब एक मजदूर की तनख्वाह तीन सौ रुपये होती है। उसके नौ सौ रुपये बकाया हो गए।

श्री जगजीवन राम : कौन सी फ़ैक्ट्री है।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : घुघली चीनी मिल, घुघली, गोरखपुर।

उनके यहां रिकवरी आठ रह गई है। यह सब वाटर लागिंग और सीपेज की वजह से हुआ है। उन्होंने सैंट्रल बैंक के चेयरमन श्री पट्टा को लोन के लिए प्रार्थनापत्र दिया। लेकिन उनको लोन नहीं मिल रहा है। आज फ़ैक्टरी की हालत खराब है तो उनको लोन नहीं दिया जा रहा है। इधर भी आपका ध्यान जाना चहिये ताकि वे श्रमिकों को वेतन आदि दे सकें। उनको लोन दिलाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

मैं बहुत से सोशलिस्ट देशों में गया हूं। वहां पर मैंने देखा है कि अगर वे कैटल, पिगरी और पोल्टरी नहीं रखते हैं तो उनको मुनाफा नहीं होता है। अकेले गल्ला पैदा करके किसान मुनाफ़ा नहीं उठा सकता है। पिगरी, पोलटरी आदि की तरफ़ भी इस वास्ते आपको ध्यान देना चाहिये। जो गल्ला पैदा करते हैं वे कैटल, पोलटरी, पिगरी आदि भी रखें तो मुनाफ़ा उनको हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, मैं कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय की डिमांड्स का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। मैं कृषि मन्त्री से कुछ निवेदन भी करना चाहता हू, जिस से कृषि इत्यादि में सुधार हो सके।

मैं आप के माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान उत्तरी बिहार की बागमती योजना की ओर ले जाना चाहता हूं। यह योजना करीब 29 करोड रुपए की लागत से बनाई जा रही है, जिस में से अभी तक

[श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव]

करीब 3 करोड रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन फिर भी बागमती की धारा में परिवर्तन हो गया है। भारत-नेपाल सीमा से करीब बीस मील उत्तर में नूनथर पहाड है। उस पहाड से बागमती निकलती है और उस के बगल में ही एक नदी मनुसमारा है। मनुसमारा और बागमती की धाराओं के मिलने में सिर्फ 150 गज की दूरी रह गई है। गत वर्ष उत्तरी बिहार में और खासकर सीतामढ़ि दरभंगा, मोतीहारी और मुजफ्फरपुर में जो फ्लड आया था, उस का कारण यह था कि गत वर्ष बागमती और मनुसमारा नदियों के मिलने में सिर्फ 400 गज की दूरी रह गई थी। उन नदियों की धाराओं के मिलने में 400 गज की दूरी होने पर उत्तरी बिहार के इन क्षेत्रों में एक प्रलयन्कर बाढ आई थी, जिस का निरीक्षण मंत्री महोदय ने भी किया था।

इस लिए अच्छा हो अगर मंत्री महोदय नेपाल के सिंचाई मंत्री को दिल्ली में बुलावें और सिंचाई विभाग के अन्य अधिकारियों तथा इंजीनियरों को दिल्ली में बुलायें या यदि सम्भव हो तो वह सैंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों तथा इंजीनियरों के साथ काठमांडू जायें और एक टेबल पर बैठ कर इस बारे में चर्चा करें। जिस तरह उन्होंने कोसी और गंडक योजना के लिए पहाड में बांध बनाने की व्यवस्था की है, उसी तरह वह इस योजना के सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था करें। यदि बागमती नदी और मनुसमारा नदी की धारायें इस साल बरसात में पहले मिल जाती हैं, तो उत्तरी बिहार में, खासकर दरभंगा, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मोतीहारी जिलों में पिछले वर्ष से भी अधिक प्रलयकारी फ्लड आयेंगे और उसी तरह करोड़ों रुपयों की क्षति होगी और इस योजना पर लगाया जाने वाला सब रुपया बर्बाद हो जायेगा।

इस लिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय नेपाल और भारत के सिंचाई सम्बन्धी टेकनिकल अधिकारियों की एक बैठक दिल्ली में संसद का सत्र खत्म होने से पहले, या उस के तुरन्त बाद जून के प्रथम सप्ताह में बुलायें। उस में वह उत्तरी बिहार के संसद सदस्यों को भी आमंत्रित करें। मैं समझता हूं कि आपस में विचार विमर्श करने से अच्छा नतीजा निकलेगा। अगर भारत-नेपाल सीमा से 20 मील उत्तर में ननथूर पहाड के नीचे बैरेज बनाया जायेगा, तो बागमती नदी सिंचाई योजना से लाखों लोगों को फायदा होगा।

इस योजना के बनने से सीतामढ़ी और मोतीहारी जिले की करीब ढाई लाख एकड जमीन की सिंचाई होगी। इसलिये मेरा फिर आप से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके आप बैठक की व्यवस्था दिल्ली में करें। (व्यवधान) ..

श्रीमन् मुझे इस संसद के अधिवेशन में पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसलिए मेरा निवेदन है कि दस मिनट कम से कम और समय मुझे दें।

सभापति महोदय यह मेरे वश में नहीं है। आप मंत्री जी से पूछिए।

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव : मैं कृषि मंत्री का ध्यान उत्तर बिहार और पंजाब में जो बड़े बड़े ओले गिरे हैं उन की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस से पंजाब में भी करोड़ों रुपए की क्षति हुई और उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार में भी क्षति हुई है। मेरा निवेदन है कि जहां भी ओले पड़ने से क्षति हुई है वहां किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए जिस से किसान अगली फसल में खेती करने लायक रह सकें और खेती कर सकें।

श्री जगजीवन राम राज्य सरकार देती है।

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव : मैं श्रद्धेय कृषि मंत्री का ध्यान भूमि सुधार की ओर ले जाना चाहता हूं। यह ठीक है कि मुझे ज्यादा तो हमारे कृषि मंत्री जी बिहार की बात जानते हैं लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि जो बिहार की स्थिति है उस में अभी भी गरीब किसान और गरीब मजदूर जो बटाई पर खेती करते हैं जिन के अधिकार में पचासों वर्ष से जमीन है उन को वहां के बड़े बड़े महंत जबर्दस्ती उस जमीन से बेदखल कर रहे हैं। खास कर के सीतामढ़ी में खरखी एक गांव है उस गांव की एक घटना की ओर मैं कृषि मंत्री का ध्यान ले जाना चाहता हूं। मैं ने टेलीग्राम भी दिया था वहां की घटना के बारे मे दिसम्बर की घटना है। वहां पा कर मठ के सेवइत, श्री राम मिलन साही है। उस मठ की जमीन वहां के गरीबी किसान और मजदूर बटाई पर पचासों वर्ष से जोत रहे थे। लेकिन उस महंत के सेवैत श्री राम मिलन साही वहां के अधिकारियों से मिल कर, अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी प्रखंड पदाधिकारी, थानेदार वघनाहा सभी को मिला कर रातों रात ट्रैक्टर से उन गरीब हरिजनों और किसानों की जमीन जोत कर उन को उस से बेदखल कर दिया। । मैं सूचना मिलने पर दिल्ली से गया था मेरे घर पर करीब पांच सौ हरिजन आए अपनी स्थिति से अवगत कराने के लिए। मैं गया खरखी गाव में और जब मैं गया तो महंत के करीब सौ लठैतों ने लाठी भाला और गड़ासा ले कर केवल मुझे ही नहीं घेरा बल्कि वहां के प्रखण्ड के जो सभापति देवी कांत झा जी थे उन को और जो हमारे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता थे उन सब को घेर लिया। संयोग से भाले से हम लोग बच गए नहीं तो उसी जगह हम लोग मर जाते। इतना होने पर भी आप को आश्चर्य होगा वहां पुलिस खड़ी थी लेकिन महंत के लठैतों ने जब भाले गड़ासे से लैस हो कर कांग्रेस और कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर अटैक किया तो वह खड़ी देखती रही। इस की सूचना टेलीग्राम से मैंने तुरन्त प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री, कांग्रेस के प्रेसीडेंट, चीफ मिनिस्टर बिहार और चीफ सेक्रेटरी बिहार सब को दी। करीब दो सौ रुपए टेलीग्राम पर मैंने खर्च किया। बिहार विधान सभा और कौंसिल में भी विधायकों ने और परिषद के मेम्बरों ने बिहार सरकार से डिमांड की कि वहां के दोषी अधिकारी, थानेदार, प्रखंड अधिकारी इन को मुअत्तल कर के हटाया जाय। लेकिन सैकड़ों विधायकों के अनुरोध के बावजूद अभी तक वहां के अनधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अभी थानेदार की बदली तक नहीं हुई है। प्रखण्ड पदाधिकारी, एव अन्य दोषी अधिकारी सब अभी भी मौजूद हैं। इस लिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर के पास हिदायत जानी चाहिए और तत्काल संसद सदस्यों की एक कमेटी वहां पर भेजी जाये जोकि खरखी गांव में जाकर इन्क्वायरी करे और जिन अधिकारियों का भी उसमें हाथ हो उनको तत्काल सस्पेंड किया जाये। डिसमिस किया जाये। (**व्यवधान**)

इस अधिवेशन मे सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला इसलिए मुझे तीन मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय : इसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हू ?

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव : जिस आसन पर आप आसीन है वहां भी आप समाजवाद लाने की व्यवस्था करें।

अब मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान भारत वर्ष के जो कृषक हैं उनकी दयनीय स्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आपने खरखी गांव के किसानों के बारे में ध्यान आकर्षित कर

[श्री सभापति महोदय]

दिया वह बहुत महत्व की बात थी। अब भारत के किसानों की दयनीय स्थिति का जहां तक सवाल है वह बाबूजी को मालूम है। आप थोड़ा समय दूसरों को भी दीजिए।

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव आप भी जब इस आसन पर होते हैं तो आप भी यही कहते हैं जो मैं कहता हू। जिस आसन पर आप हैं वहा भी आप समाजवाद लाइये।

सभापति महोदय · आप प्वाइन्ट्स ही बताइये ।

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव : वही बता रहा हू।

जहा तक शुगरकेन की कीमत की बात है आज जलावन की लकडी 6 रुपए प्रति मन बिकती है लेकिन शुगरकेन के ऊपर जो किसानों का खर्चा होता है, किसान का जो परिश्रम होता है उसके अनुपात मे कीमत नही मिलती है। उसलिए मेरा निवेदन है आगे जो सीलिंग आने वाली है उसमें शुगरकेन की प्राइस में भी वृद्धि होनी चाहिए जिनसे कि भारतवर्ष के किसान जिन्होंने शुगरकेन की खेती कम करनी प्रारम्भ करदी है उसके स्थान पर अधिक खेती कर सकें।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान भारतवर्ष मे जो शुगर मिलें हैं उनके राष्ट्रीयकरण करने की ओर दिलाना चाहता हू। जितनी जलदी हो सके कृषि मंत्री जी शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की व्यवस्था करें।

आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): Sir, I would not have been tempted to speak, but I thought I should also add my support after a national consensus has been reached for sugar nationalisation in addition to the commitment of the government and the Congress Party to it. Most of the members on the other side did not raise it, not because they did not want sugar nationalisation but because some sort of demoralisation is there since that subject is now pushed back. If experience is to be the teacher, at least this year, after so many concessions have been offered and after having increased the open market sugar from 30 to 35 per cent, most of the sugar factories have stopped taking cane from the growers two months earlier, even though sugarcane production has increased and people are ready to supply cane So, it is going to result in less production and there will be shortage. This is the creation of these sugar magnates Because of their actions, there will again be shortage and the prices will again be pushed up I want to say that this is treachery not only to the people or the Government but treachery to their own commitment They were committed to a production of 50 lakh tonnes but we are not going to reach that figure as far as this year is concerned 300 Members of Parliament have given a memorandum to the Government requesting them to take over the sugar industry Rs 74 crores have been set apart for modernisation With that money, you can take over the sugar industry Why don't you implement the Bhargava Committee's recommendations? Why don't you create a sugar corporation?

Secondly, arrears to the tune of Rs 55 crores have been accumulated with the mill owners but they are not paying any attention to pay the arrears I request the Government that they should be taken to task severely. This question is being raised every time in the AICC, AITUC and other trade union organisations but nothing has been done so far Why do not you do away with this thing? The entire aim of the 20-Point Economic Programme is to increase production but as far as sugar production is concerned, these magnates are coming in the way of increasing the production.

The National Commission has said:

> "It has been the experience that with every development in any part of the country, whether through better irrigation or adoption of improved techniques and practices, imbalances in incomes and capacities perpetuate "dual economics" (one monetised economy and my and the other, non-monetised subsistence economy) unless deliberate efforts are made to reduce inequality of opportunities to get credit and use it effectively."

17 hrs.

So, this leads to greater unemployment and under-employment and these problems have assumed so much of a serious proportion that unless you make a radical departure from the past and see that a credit system is specially evolved, it may not be possible to solve this problem. In spite of growth in the economy it has been said that there is a worsening of the employment situation in the rural sector. This is due to lack of adequate opportunities for agricultural development programmes. It says here:

> "Growth cannot be the sole object of development planning. It is the manner in which growth is obtained, from the point of view of employment generation and amelioration of the conditions of the rural poor...."

which is important. No doubt Rs. 870 crores have been pushed into this sector. There is no doubt that it is a big achievement. But the question is whether the benefits have accrued to the people in the rural sector who constitute the 72 per cent. I do not find an answer to this question anywhere. What per centage of all the loans, of all the aids, and of the results of technological development that have been provided to them and of the techniques made available to them, have benefited the 72 per cent people of that sector? I also want a categorical answer to this aspect of the question. Therefore, my suggestion will be this. In Orissa, there are 2,000 acres in one patch; and the landless people have occupied it. You will find several such patches in several districts. Why not develop them and why not have cooperatives of marginal farmers and agricultural labourers, so that the money can be invested there? They can have separate cooperatives. In page 18 of the Report, mention has been made of the Farmers' Service Societies and it has been said that all the cultivators will be there as members of such Societies, but that

> "control over management is required to be vested in the weaker sections which will have two-third seats on the board of management of the societies."

No; I oppose this. The rich farmers and the landlords who have turned out to be kulaks should not be allowed into such cooperatives. A separate cooperative, with all the money—whether it is adequate or not—should be there for agricultural labourers and small farmers. Phase by phase, there must be a separate sector, a separate cooperative and a separate service cooperative having these 72 per cent people as members, so that they can make a dent on their poverty. Otherwise, the problem cannot be solved. I want a categorical answer to these points.

MR. CHAIRMAN: There are 19 Members on the list; and I have 90 minutes. It comes to not even 5 minutes for each Member. What do you suggest? Either each one of you speak for 5 minutes; or some of you might forgo your chance, so that others can speak for 6 or 7 minutes. Otherwise, at the end of the fourth minute, I will ring the bell; and at the end of the fifth minute, I will close. It is not my duty to ring the bell. You can note it yourself. We are going up to 6.30 p.m., i.e beyond the scheduled time. Even then I can give only five minutes. If some Member forgoes his chance, then I can give to

· [Mr. Chairman]

some others, about 7 minutes. I cannot agree that some Members are not there. I have seen them; most of them have come.

Now, Mr. Jagannath Mishra. He should speak only for five minutes.

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान है। अगर कृषि की हालत ठीक रही तो देश की हालत ठीक है और अगर कृषि गडबडायी तो देश की भी हालत गडबडा जाती है। हम ने पिछले दिनों देखा कि कृषि के गडबडाने से देश में किस तरह का कोहराम मच गया था, महंगाई आकाश छूने लगी थी, और उस वक्त मैं प्रधान मंत्री महोदया को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने किस तरह से अपनी क्षमता का परिचय दिया और कैसे योग्य और अनुभवी और लब्ध प्रतिष्ठ मंत्री को इस विभाग में लाकर रख दिया, और उन्होंने अपने योग्य सहयोगियों के साथ जैसे अपने विभाग में काया पलट की यह सर्वत्र प्रशंसा का विषय है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस की प्रशंसा होती रही। जहां और देश महंगाई को संभाल नहीं सके, वहां हिन्दुस्तान ने अपनी महंगाई पर विजय पाई है।

श्रीमन् कृषि के विकास के लिए उन्होंने 69 करोड रुपए खर्च करने का विचार किया है, जिस में 19 करोड रुपए की धनराशि उपलब्ध सिंचाई साधनों के अधिकतम उपयोग करने पर खर्च की जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि को समतल किया जाएगा और पानी की नाली आदि बनाई जायेंगी।

इस के बाद फसलों की उपज बढाने के विशेष कार्यक्रम पर 15 करोड रुपए खर्च किये जायेंगे और किसानों को उन्नत बीज की आपूर्ति करने के लिए 10 करोड 58 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। यह धनराशि राजकीय फार्म निगम को विभिन्न फसलों के उत्पन्न करने के लिए ऋण एवं अनुदान के रूप में दी जाएगी।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वर्ष 1.1 मिलियन हैकटेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना में केवल 0.66 मिलियन हैक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हुई थी। यह बीस सूत्री कार्यक्रम का सुपरिणाम है।

श्रीमन् 1976–77 में 725 करोड रुपया खर्च कर के 1.25 मिलियन हैक्टेयर जमीन में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकेंगे, और पांचवी पंचवर्षीय योजना में 2401 करोड रुपए की व्यवस्था है।

श्रीमन् एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था ये करने जा रहे हैं और वह नेशनल कमीशन आन फलड्स की नियुक्ति की है। इस के बारे में बहुत से सदस्यों ने कहा है और मैं भी इस के बारे में जोर दे कर कहूंगा क्योंकि हाल ही में देश के कई भागों में फलड्स ने कोहराम मचा दिया था और हमारे यहां बिहार में पटना में इस बाढ से बहुत बर्बादी हुई थी। अगर देश की सारी बर्बादी को देखा जाए, तो यह 471 करोड रुपया कूती जा सकती है।

आधुनिक यंत्रों द्वारा ही कृषि में उन्नति कर सकते हैं, इस से मैं सहमत नहीं हूं। श्रीमन्, हमारे देश में जो जमीन है वह छोटे-2 टुकड़ों में बटी हुई है और अभी लैंड रिफार्मर्स और सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत जो एकट्ठा जमीन उपलब्ध की है, वह भी छोटे छोटे टूकडों में हैं। उस में आप ट्रैक्टर कैसे चला सकते हैं और कैसे ट्यूबवेल्स लगा सकते हैं और कैसे पम्पिंग सैट्स लगा सकते हैं। इसलिए जो पुरानी प्रथा है हल चलाने की है, वह भी अवश्य रखनी होगी। इसलिए

मेरा यह आग्रह है कि इस के लिए आप को गोपालन की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि अगर गो-पालन ठीक से होगा, तो बछड़े बजबूत होंगे ।

श्री जगजीवन राम : पंजाब में लोग गौ रखने लगे हैं ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : पंजाब में वे लोग तो फायदा उठा रहे हैं लेकिन हम नहीं उठा रहे हैं । लोग कहते हैं कि भैंसे से भी खेती का काम लिया जा सकता है लेकिन उस में गर्मी सहने की शक्ति कम है । हमें इसलिए बैल पर निर्भर करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि गो-पालन पर सब से ज्यादा ध्यान दिया जाए ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने दिल्ली के कुछ गावों में छोटे किसानों की सहायता के लिए उन की समस्याओं के समाधान के लिए एक वर्ष पूर्व एक परियोजना प्रारम्भ की थी और उन से यह पता चलाया था कि कैसे उन की पैदावार बढ़ाई जा सकती है । उन्होंने यह बताया था कि मिट्टी को कैसे उपयोगी बना सकते है और कैसे खारी पानी को सिंचाई के काम में ला सकते हैं । उन के बहुत सुपरिणाम निकले हैं । उससे किसान एक एकड़ में खर्चा काट कर एक हजार रुपए की आमदनी कर सकता है ।

मलमूत्र से बड़े पैमाने पर खाद बनाने की सलाह हमारे कृषि मंत्री जी ने 2 अप्रैल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दी थी । मैं 8 अप्रैल के हिन्दुस्तान से आप को पढ़ कर सुनाता हूं :

"कृषि तथा सिंचाई मंत्री श्री जगजीवन रामने आज यहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सलाह दी कि उसे भारत के 60 करोड़ जनसंख्या के मलमूत्र से बड़े पैमाने पर खाद तैयार कराने की ओर ध्यान देना चाहिए ।"

इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि खाद के लिए हमें केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं करना चाहिए । हमें खुद भी सोचना चाहिए और बाहर के देशों पर खाद के मामले में निर्भर न रह कर हम खुद भी खाद तैयार कर सकते हैं । इस से हम फारेन एक्सचेंज बचा सकते हैं और उस को बचा कर विकास के काम में लगा सकते हैं ।

कृषि के विकास की ओर आपका विशेष ध्यान देना चाहिए । राष्ट्रीय आय का सब से ज्यादा भाग आपको कृषि से प्राप्त होता है । इस वास्ते अगर कृषि को हम उन्नत न बना सके तो हमारा देश कभी भी उन्नतिशील नहीं बन पाएगा । उस अवस्था में गावों के लोग भाग भाग कर शहरों की तरफ आते रहेंगे । शहरों की जो दुर्दशा है वह आपको मालूम ही है । इससे उनकी हालत और भी बदतर हो जाएगी । इस वास्ते यह आवश्यक है कि हम उनके लिए वहां साधन उपलब्ध करें और वे खेती में ही लगे रहें और शहरों की तरफ न आएं ।

दवाइयां का भी आपको प्रबंध करना चाहिए सिंचाई के साधन भी उनको मुहैया आपको करने चाहिए । जमीन के नीचे काफी पानी है । हम उसको सिंचाई के काम में ला सकते हैं । कमजोर वर्ग के जो किसान हैं उनको बैंकों से कर्जों का भी प्रबंध आपको करना चाहिए । अभी गावों से बैंक बहुत दूर हैं । उन लोगों को बैंकों से पैसा मिलता भी नहीं है । इधर आपने बहुत से कानून बना दिए हैं । उनकी भलाई के । लेकिन वे कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं, जो आपकी घोषणाये हैं उन पर अमल नहीं हो रहा है । नतीजा यह हो रहा है कि भलाई भी बुराई में परिणत हो रही है । मेरा सुझाव है कि गाव के लोगों के वास्ते बीमे की परिपाटी आपको चलानी चाहिए फसलों आदि का बीमा आपको करना चाहिए । इसके लिए आप ग्रामीणों को ही तैयार करें । प्रीमियम देने की व्यवस्था गावों में ही हो ।

SHRI M. S. SANJEEVI RAO (Kakinada): I rise to support the Demands of the Agriculture Ministry.

Thanks to resolute and dynamic leadership, there has been an unprecedented sense of discipline and dedication throughout the country. I must congratulate the Ministry of Agriculture on taking advantage of this mood in the country, and because of the kindness of nature, they are able to build up a buffer stock of nearly 11 million tons. I must congratulate them on this. But I am afraid that in spite of their great success, the mood and the morale of the farmers in India are completely gone. It is high time that we realised what is wrong, what is happening to them. I am afraid they are terror-stricken and completely demoralised.

Shri Shinde is a very competent Minister and an able Parliamentarian He has given certain statistics. He said that we had to give nearly Rs. 149 crores or so as subsidy for fertilisers I am sure he is aware that last year the country was short of quality seeds This year, however, the National Seeds Corporation wants to export these quality seeds. Is it because we are surplus in them? I am afraid it is because our marginal farmers are not in a position to purchase them I am afraid the same situation will arise in fertilisers also.

This year we have produced 15 lakh tonnes of fertilisers. Next year we hope to produce 18 lakh tonnes. We are consuming about 25 lakh tonnes. I will not be surprised if, as in quality seeds, we are forced to export fertilisers, with the net result that the country will face the same situation as we were facing last year. So, my appeal to our able Jagjivan Ram Babu is that we must see that the prices of inputs for the farmers like fertilisers, insecticides and power should be reduced. He must be aware that we have spent nearly Rs. 800 crores in foreign exchange to import 400 million tonnes of wheat. Why should he grudge paying Rs. 200 crores more as subsidy for fertilisers? I appeal to him to think about it once again.

Now I come to sugar. Last year we produced 48 lakh tonnes and exported 13 lakh tonnes, earning a foreign exchange of Rs. 475 crores, but this year we could produce only 43 lakh tonnes. I am afraid we will come to a stage like that of jute. May I bring to your notice that the private sector in the jute industry has killed that industry? This year we could export only up to Rs. 239 crores. I can tell you that the jute industry is dead and gone and I appeal to you that since there can be no question of any retrenchment, they must have some alternative agricultural employment in West Bengal. They should slowly switch over to some other product

Why I am bringing this up is because it is just like cotton. The position in regard to cotton was also the same but, thanks to the timely intervention, the National Textile Corporation was created and I am happy to know that by next year we will be able to improve.

So I appeal once again to our able Jagjivan Ram Babu that we should look after our farmers. If we don't look after them, they will be finished. Now we have got Rs. 768 crores and we have decided to support agriculture and agriculture-based industries like fertilizers etc. in a massive way. But are we really doing it?

In this background, I would like to say that he should give more money for the big projects also. For example, in my State of Andhra Pradesh, the State has already spent about Rs. 300 crores and they have built a huge reservoir but we could use the water hardly for one million acres. Now, if you give us a little more money, we

can raise crops on 2 million acres. I want the Centre to be more sympathetic and to clear the Polavaram Barrage in Andhra Pradesh which will help us a great deal in the production of rice.

Since my time is short, I will come to the point about export-oriented agriculture. He has said that he has given a sum to the tune of a thousand crores, but I am afraid that when we have a deficit of Rs. 1400 crore this thousand crores is very meagre. We have done well in sugar and we have done well in tea, where it is 200 crores and in the case of coffee it is about 50 crores. But we must specialise in fisheries. We are happy that we have exported to the tune of Rs. 100 crores this year as compared to Rs. 60 crores, but it is a field where there are tremendous potentialities. We are on the fringe of it, but unfortunately, we are concentrating only on shrimps and lobsters It is high time that we concentrate on tuna fish.

In a country with a coastal area of 5,000 kilometres, we have only about 11000 motorised boats and they can operate only on on-shore. We should go ahead with buying big trawlers. They always say that we are importing 30 trawlers from Mexico, but what is 30 trawlers for a country with a coast of 5000 kilometres? I appeal to you that you should see that we buy more trawlers and that we also concentrate on tuna fish .

MR CHAIRMAN: Your time is up. Please sit down.

SHRI M S. SANJEEVI RAO: Just one minute more.

MR. CHAIRMAN: No, please sit down, I am standing.

श्री रामभगत पासवान (रोसेरा): सभापति महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर्वप्रथम मैं बाबूजी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने और विभागों में सफलता प्राप्त करने के बाद कृषि विभाग का कार्य भार सम्भाल कर चन्द बरसों में ही खाद्य की विकराल समस्या का समाधान कर के देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बना दिया है। कृषि राष्ट्र की एक बहुत महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। इसलिए उस की व्यवस्था भी समाजवादी ढग से होनी चाहिए। इस का अर्थ यह है कि जो खेती करना जानते हैं, उन्हें ही जमीन मिलनी चाहिए और जो खेती करना नहीं जानते हैं, उन को जमीन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में ठीक इस से उलटा तरीका है जो खेती करना नहीं जानते हैं, उन के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है। और जो खेती करना जानते हैं वे भूमिहीन हैं।

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्य क्रम के द्वारा देश की गरीबी मिटा कर एक खुशहाल समाज का निर्माण करना चाहती हैं जिस में भूमिहीनो को भूमि मिले, गृहहीनों को आवास के लिए जमीन मिले, मजदूरों को मजदूरी मिले और सभी को रोजी रोजगार का साधन मिले। 20 सूत्री कार्य क्रम को जनता श्रद्धा की दृष्टि से देख रही है और उस को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन उसके उल्टे कुछ पूजीपति और अफसरशाही के लोग उस में अड़ंगा लगा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि यह अफसरशाही और पूजीपति जो 20 सूत्री कार्य क्रम में अड़गा लगा रहे है उसे दूर करने के लिए उन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

भूमि हदबन्दी कानून तो आप ने पास कर दिया। लेकिन अभी तक भूमि सुधार के अंतर्गत गरीबों को जो भूमि मिली है वह नहीं के बराबर है। इस से गरीबों के बीच कुछ खतरा भी उपस्थित हो गया है इस सेंस में कि जो बड़े बड़े भूमिपति हैं वे जानते हैं कि हो सकता है कि हमारी जमीन सीलिंग के अंतर्गत छीन ली जाय, इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुत्ते बिल्लियों के नाम फर्जी अपनी जमीन करवा दी और अपने को लैंडलेस साबित

[श्री रामभगत पासवान]

कर दिया। लैंडलेस साबित कर के गरिबों को जमीन उन्होंने दे रखी थी वह उन से छीन दूसरों के हाथ बेच रहे हैं। यदि गरीब अपने हक के लिए लड़ते हैं तो उन पर पुलिस केस कर दिया जाता है और कई केसेज कर के उन्हें तबाह कर दिया जाता है। दरभंगा जिले के मधुबन ग्राम में 15 हरिजन परिवार हैं जिन के घर आगन केला बाडी और उन की जोत की जमीन जो सदियों से उन के कब्जे में है उस सब को इसी तरीके से छीन करके जमीदार ने कह दिया कि यह जमीन हमारी है। उसके लिए हाई लेवल इनक्वायरी भी हो गई फिर भी ये जमीदार उस जमीन का सैटलमेंट करना चाहते है। लोअर कोर्ट द्वारा हरिजन के पक्ष में निर्णय हो गया उसके बाद भी एडीशनल कलैक्टर ने जातीयता के आधार पर उनके नाम से सैटलमेंट कर दिया। उन जमीदारों के पास सैकडो एकड जमीन है। तो सीलिंग के अन्तर्गत उन मे उनकी जमीन लेनी चाहिये वह न करके उल्टे उनको और यह जमीन दे दी और उनके नाम सैटलमेंट कर दिया। इसकी आप हाई लेवल इनक्वायरी फिर कराए ताकि गरीबों का जो घर और भूमि पर है वह कायम रह सके।

भूमि सुधार का यह जो तरीका है इसे अमल में अफसरशाही द्वारा जो फाजल जमीन है वह प्राप्त नही की जा सकती। आप पचायत लेवल पर एक कमेटी बना दीजिए जिसमे भूमिहीन व्यक्ति जो पढे लिखे है उनको सदस्य बना दीजिये। वे तो जानते हैं कि पचायत मे किन के पास कितनी जमीन है, वे पता लगा कर जो फैसला करे उसको माना जाए।

जिस जमीन पर गरीब बसे हुए हैं उसके लिए उनको पर्ची दी जाती है लेकिन डिसप्यूट पर्ची उनको दी जा रही है। अगर उनका घर बेढ़ कट्ठे में है तो तीन घर की पर्ची दी जाती है और और बाकी जमीन जमीनदार ले लेते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसी डिसप्यूयटिड पर्ची उनको न दी जाए और जो अधिकारी ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सक्त कार्रवाई की जाए कोई केसिस हों तो उसका पूरा खर्च सरकार को गरीबों को देना चाहिये।

मैं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र से आता हू। मेरी आंखो देखी बाते हैं। हर साल वहां गरीबों के घर गिर जाते हैं और पचास परसेंट अपना गरीब घर छोड कर भाग जाते हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर यह भी आता है कि ऊंची जमीन पर गरीबो का घर बसाया जाए। लेकिन अधिकारी ऐसा नही करते। दरभगा जिले के मधुबन ग्राम का उदाहरण मैं देता हू 75000 रुपया हमने गवर्नमेंट से मजूर कराया। वह पडा हुआ है लेकिन अधिकारी उस पर अमल नही कर रहे है। मेरा आग्रह है कि जो गृह विहीन हैं उनको जल्दी बसाया जाए और नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनके घर ऊंचे स्थानो पर बनाए जाए।

उत्तर बिहार मे प्रतिवर्ष बाढ आती है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहा भयकर बाढ से हजारों एकड जमीन गरीब किसानो की बह जाती है। अभी तक फ्लड कट्रोल और प्रोटैक्शन के लिए कोई परमानेंट व्यवस्था नही की गई है। लाखों करोडों रुपया रिलीफ पर खर्च करते हैं। वह आप बन्द कर दे क्योंकि उसका 75 प्रतिशत कर्मचारी खा जाते हैं, 25 प्रतिशत गरीबों के पास मुश्किल से पहुचता है। आप परमानेंट सोल्यूशन करे। वहा पर कमला बालान बाध है जो दर्जिया तक स्थगित है। उसको आगरघाट तिलकेश्वर होते हुए कुरसेला तक बढ़ा कर गगा और कोसी की धारा में मिला दे ताकि फाजिल पानी चला जाए और जरूरत के अनुसार, कुछ कैनाल निकाल दें जिस के द्वारा सिंचाई हो सके और फ्लड कन्ट्रोल में सहायता मिल सके।

सभापति महोदय : मुझे दु:ख है इस तरह से मैं चला नहीं पाऊंगा। जो टाइम है वह सभी के लिए है। मेम्बर कहते हैं समाजवाद लाइये, मैं सभी को बराबर टाइम दूगा। 6 मिनट का टाइम है तो 6 मिनट ही हैं, उसके बाद

मैं समय नहीं दे पाऊंगा। कृपया मुझे मजबूर न करें कि मैं घंटी बजाऊं और जोर से बोलूं। कृपया आप नाराज मत हों।

SHRI S. N. SINGH DEO (Bankura) I am grateful to you that in spite of the short time you have given me this opportunity to speak. I will confine my speech only to the problems of my constituency.

We are all grateful to Babuji that under his able leadership there has been a marked progress in the development of agriculture and in food production. It is an admitted fact that irrigation is one of the major factors in agriculture and I will try to draw your attention to the districts of Purulia and Bankura in West Bengal, which I have the honour to represent. You know these two districts are situated at the eastern edge of Chota-Nagpur plateau where the land is rocky and undulating no big major irrigation work or big river valley projects could be taken up The only possibilities are minor irrigation, medium irrigation and wells and whatever sources of water in tanks are there in the villages should be tapped. I, therefore, request you that necessary provision for the same may please be made because it is a chronic drought-prone area So, under the drought-prone areas programme necessary funds should be allotted so that the derelict tanks and wells etc, can be repaired and on, small rivers where embankments can be constructed, can be taken up in a large number so that this area which is mostly inhabited by the tribal people and poor Harijans could get advantage of irrigation in their fields.

Shinde Sahib is not here but, during his speech he has already spoken about the large number of civil suits that are pending in the Calcutta High Court against the land reforms measures of West Bengal Government. So far as I know more than 50,000 cases are pending and as a result, the very purpose of land reforms have been frustrated. Times without number we have spoken regarding these difficulties and even in the recent Chief Ministers' Conference at Delhi this point was taken up by our Chief Minister, Mr. Sidhartha Shankar Ray. But, unless and until the Central Government come to our rescue, the very purpose of land reform measures will be frustrated If necessary, I will request that a suitable amendment in the Constitution should also be made so that these things could be expedited

I would not take, as already said, much of your time Now, I will only request our hon Minister to consider sympathetically about the Darkeshwar river project in the district of Bankura The necessary survey by the West Bengal Government has already been completed, but due to the paucity of funds, that is not being taken up But that will be of great advantage to this chronic drought-prone area and I request that allocation of necessary funds from the Centre may please be made so that these two districts of Purulia and Bankura may be benefited by that.

There is another project, the Kansavati River Project work of which is already under progress. Due to shortage of funds that has also not been taken up seriously. As a result of it the Upper Kansavati River Project programme has been delayed Necessary allocation of funds may be made for the said project, particularly for the upper Kansavati area immediately, so that the drought affected areas may be benefited

*SHRI R N BARMAN (Balurghat) Mr. Chairman Sir, I whole heartedly

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri R. N. Barman]

support the demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation and offer my compliments to Babuji and his colleagues for the wonderful performance they have shown this year. It would not be an exaggeration to say that wherever Babuji has gone sucess has followed him. This year we have made remarkable progress in so far as food production in the country is concerned. The food position is so encouraging that we are going to set up an all time record and with the favourable cooperation of nature we would perhaps be able to attain a real self-sufficiency in the food front within the next few years. We are trying to build up a buffer stock. In the newspaper of 4th April, I have found that the Government of India have entered into an agreement with the Government of America and according to this agreement America will be supplying us 4 lakh tons of wheat and one lakh ton of rice. In this conection I would like to seek a few clarifications. I would like to know whether the foodgrains under the agreement in question is being purchased at the international price or the real value of these foodgrains are somewhere near the cost incurred under the P L 480 Agreement. In case the hon Minister finds it difficult to divulge the rates I would request him to kindly inform this House that the agreement in question is in no way a replacement of the PL 480 agreement because we have repeatedly said on the floor of this House that we would not like to accept PL 480 donations of foodgrains from America as it involves our national prestige.

In this connection I would also like to sound the word caution to the Government. A few years ago wheat was imported from America and it was found to be mixed with Dhatura. In to day's paper I have found that the FCI has launched proceeding against 5 American companies and have claimed compensation worth 215 million dollars because during the last 15 years these companies were supplying us wheat which were found to be less in weight, contaminated and in many cases unfit for human consumption. On behalf of the Government of India the press note says that this theft could not be detected in time because the Government did not have adequate weighing facilities and gradation facilities. Perhaps the whole matter would not have seen the light of the day had it not been inquired into by the Government of America. It is indeed very surprising, Sir that we are being defrauded by these American companies for the last 15 years and our own officers who were sent for negotiating the deal and implement the transaction could not for once even detected it and report the matter to the Government for necessary action. They have failed totally in this matter. The federal inquiry has also revealed that these American companies were pursuing this game by bribing the officials and by adopting many under hand tactics. I would therefore request the Government to institute an inquiry to find out whether our officers were also involved in this shady transaction and if so what action should be taken against them. I would also urge upon the Government to take immediate action to improve the present weighing arrangements because unless this is done we will continue to be defrauded by the suppliers.

I would now like to say a few words about my own district. West Dinajpur is a district of North Bengal. It can be called the granary of North Bengal also. In this district we can raise only one crop in a year. Only in a few scattered places aus-paddy and jute are cultivated and in other places the cultivation of two crops is very poor. In this district we have not been able to make adequate supply of electricity and as a result of this other crops cannot be

raised because of lack of irrigation. There is also difficulty in installing shallow or deep tubewells because the water level is very low and unless electricity is provided this cannot be done. With adequate facilities of irrigation this district can raise three crops easily. There are places where some deep tubewells have been installed but the mechinemen are not there. At other places the machines are lying unutilised and cases of theft of parts of tubewells from solitary places are also being reported. It takes quite a long time, nearly one to two years, before defective tubewells which goes wrong are attended to. I would request the Central Government to kindly help the State Governments to set up an efficient organisation which can attend to these things. In this district there are many ponds, canals and rivers. If we can construct bunds on the rivers and get the ponds cleaned then this can help in growth of pisciculture and will also help the irrigation. There are forests too in this districts but they are not being properly maintained and utilised. It has also been found that seed is supplied to cultivators after the sowing season is over and even in some cases the price is more than the market rate. I hope the Government will take suitable steps to remedy the situation. In West Bengal particularly in North Bengal there is great potential for development of hydro electric power but the amount of electricity that is being generated against this potential capacity is indeed very meagre. Not only in West Bengal but the case of all the eastern States is the same. I would like to cite the example of pump sets alone. Andhra has 2 lakh pump sets, Tamil Nadu 7 lakh pump sets but as compared to these Assam has only 700 pump sets; West Bengal 7000 pump sets and Orissa 3000 only. Because of lack of electricity we are not able to improve the irrigation facilities and also our rate of production. I hope that the Central Government would give priority to this matter and they would be able to come to a settlement with the Government of Nepal and construct bunds on rivers which are flowing from Nepal side and augment production of hydro electricity.

Time being short I would like to conclude my speech by barely referring to two more issues. Cultivation of jute is falling in West Bengal because the cultivators are not getting remunerative price. The Jute Corporation of India is not able to purchase the total produce of jute because of the paucity of funds. As a result of this the middlemen are making hey while the cultivators are languishing. The situation, is no better with regard to cotton production but fortunately the cotton producers' have a very good lobby and their condition is not as bad as those of the jute cultivators. It is my sincere feeling that as long as jute, cotton and tea are not brought within the administrative control of the Ministry of Agriculture the lot of the cultivators of these crops cannot be improved because the Ministry of Commerce is more concerned about trading these commodities. They are more interested in the traders and they have hardly any time to think of the poor cultivators who produce them. I would request the Centre to set up a Commission to inquire why in West Bengal the number of landless cultivators is increasing year after year. With this I conclude my speech.

SHRI D. P. JADEJA (Jamnagar): I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture. I shall restrict myself to Chapter IX only a chapter which I consider is very important. This is something where the people of the country have always been interested. Those interested in fisheries and those who are concerned with fisheries will compliment and join me in congratulating Government for the wonderful job that they have been doing lately. Not dilating much of the achievements of this Ministry I would like to continue from where my friend Mr. Sanjeevi

[Shri D. P. Jadeja]

Rao ended. He mentioned about the in-shore fisheries which comprise only the 12 mile limit, which probably, is the 14, 15 fathom depth to which we go The official reports say that this is an area which has 0 21 million tonnes of fish available. It is only in this area that we have concentrated our attention Regarding off-shore and deep-sea fishing, if we take into account the Government report and the FAO report, it has been stated there that more than 12 to 13 times the amount of marine resources are available in that region than what is found in our in-shore waters To say that we have 11,000 mechanised boats only sounds big We can compare it with a country like Mexico whose coastal area is less than half of our area They had 13,000 such mechanised boats way back in 1965 I would not like to compare figures nor would I like to give statistics But what I would like to urge upon Government is this Only if we could concentrate more on our off-shore and our deep-sea fishing we will not only be bringing valuable foreign exchange to our country, but, we will also be helping the humanity at large These could be stored only for a few beyond that They decay, decompose and die a natural death Now, in that area, where our fisheries are plentiful to-day we find that there are foreign ships operating in that region And when we talk to these countries who are there about our tuna fishing resources they say that tuna available on the Indian coast is not suitable for the world market because they say that tuna fish in India has red meat If we have fish which has red meat then why are they operating in our waters? Further more when we go to those countries only for asking for joint collaboration, why would they be interested in having a collaboration with us, because, as it is they are already operating there? They have said this that they are beyond the 12 mile limit. But, they have bases in Singapore; they have bases in Ceylon and they have bases in Mauritius where they can feed back and come back for fishing off our coast for new catch They are interested only in seeing that we the Indian fishermen do not go into the deep seas for catching tuna as they are exploiting to-day

At this particular point, I would like to draw the attention of the Government to the fact that we have started encouraging the purchase and the manufacture of deep sea trawlers —thirty trawlers, as Mr Sanjeeva Rao said, are going to be imported The scheme mooted three years back is now being finalised to-day I do not know when the trawlers are going to come to India Why can't we allow the import of second hand trawlers? Why can't we allow the import of trawlers from other countries? Why can't we allow our Indian enterprises to go out to find trawlers and to find out fishing boats and bring them into our waters?

I would go a step further to say that if we are not able to exploit these marine resources fully then why can't we go in for a joint collaboration with certain countries—with certain foreign firms—and explore only those areas where to-day we are not fishing?

If we are going to have joint collaboration we may have conditions for fishing for two, three or five years till we find that we are strong enough to exploit our own marine resources and also to protect our own marine resources here?

I would request the Ministry of Agriculture to take a very serious view as far as the extension of our fishing limits is concerned On the East coast it is all right But, what about the West Coast? Pakistan has extended their limit upto 50 miles and they have come almost to the coast of Kutch and Saurashtra We should also immediately extend our fishing limits upto 50 miles going upto 100 miles

I have just to tell a few things for the consideration of this Ministry. We want our fishery industry to be developed. If we want to do that, then let us give more infra-structural facilities such as fishery harbour which is being neglected to-day. I have no time. Otherwise, I would have given you all the details of it. All mechanised fishing trawlers should be given duty-free fuel. All fishing crafts should be given the processing facility. Besides, let there be easy and quick transportation facilities also.

श्री तैयब हुसैन (गुडगांव) चेयरमैन साहब, मैं जरायत और आबपाशी की मांगों की हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं मोहनरिम बाबू जी और उन के साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि आज हम इस पोजीशन में आए हैं कि फूड के साथ साथ, जो खाने का मसला था उस को छोड़ कर—जैसा कि शिन्दे साहब ने कहा कि काफी सालों के बाद आज फूड का ऐसा मसला है जिस की तरफ लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान न दे कर दूसरी बातें कहीं हैं—दूसरे सवालों की तरफ तवज्जह हो रही है। पहले तो हम फूड में ही उलझ जाते थे और दूसरे मसलों की तरफ तवज्जह नहीं हो पाती थी। इस के लिए बाबू जी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक है।

आज हम इस पोजीशन में आए हैं कि दरअसल में जरायत मे काफी तरक्की की है चाहे वह गन्दम का मसला हो, चाहे चावल का मसला हो या और कोई मसला हो। मेरे पास वक्त बहुत कम है और घटी का भी डर है, इसलिए मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर की जो इनपुट स है, जैसे कि ट्रैक्टर हैं, खाद है या दूसरी चीजे है, उन को सस्ते से सस्त ामों पर दिया जाए और किसान की जो फसल बिकती है उस की कीमत के साथ उस को जोड़ा जाए।

यह एक मानी हुई बात है कि 80 परसेन्ट हमारी अबादी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं ऐसा समझता हू कि कि सारे हिन्दुस्तान का जो 80 परसेन्ट हिस्सा है, उस को अगर सही ढंग से कवर कर लिया जाए, तो सारे मसले हल हो सकते हैं। एग्रीकल्चर की तरफ आजादी के बाद हमारी ज्यादा तवज्जह नहीं गई और मेरे ख्याल में अगर शुरू से ही ज्यादा तवज्जह होती तो आज हम एक्सपोर्ट करते की हालत में होते। खैर, यह खुशी की बात है कि जो हमें इम्पोर्ट के लिए पैसा देना पड़ता था, आज वह वहां न जा कर डेवलपमेंट पर खर्च हो सकेगा।

एक बात यह है कि जो रेट आफ इन्ट्रैस्ट है वह इंडस्ट्री का बहुत कम है लेकिन काश्तकार को ट्रेक्टर के लिए या टयूबवेल के लिए जो लोन दिया जाता है, उस का रेट आफ इन्ट्रेस्ट बहुत ज्यादा है।

आपको याद होगा कि एमर्जेन्सी एग्रिकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम आपने बनाया था। उस पर पी ए सी ने कुछ सुझाव दिए है। मेरी प्रार्थना है कि इस तरह से जो भी प्रोग्राम आप बनाएं उनको अमल में लाने के वक्त आप पी ए सी के सुझावों को भी ध्यान मे रखे।

सीलिंग की बात भी यहा आई है। उससे कोई बहुत फायदा नही हुआ है। इस वास्ते नही हुआ है कि उनके पास जिन के पास जमीन है रिसोर्सिस में और कुछ हालात भी इस तरह के जो उनकी मदद करते हैं। इस वास्ते उससे कोई खास फायदा नही हो पाया है।

श्री जगजीवन राम : सरप्लस को डिफिसिट बना देते है।

श्री तैयब हुसैन पैसे के बल पर डिफिसिट बना देते हैं कानूनी ढंग से या वकील लोगों की वजह से ऐसा मुम्किन बना देते है।

गांवों में दो तिहाई आबादी ऐसी है जो लैंडलैस और हरिजनों की है जो मार्जिनल या स्माल फार्मर हैं या वे है जो अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जरूरी है कि फिशरीज से, एनीमल हसबैंडरी से या छोटी छोटी सनतों से हम उनके वास्ते रोजगार

[श्री तैयब हुसैन]

पैदा करने की कोशिश करें। इसके बिना यह मसला हल नहीं होगा।

जब हम शहरो की तरफ आते हैं तो वहां भी बहुत सी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। जब तक गांवों के लोगों को जो बेघर, बेजमीन है, कोई काम नहीं दिया जाएगा और ऐसा काम नहीं दिया जाएगा कि वे पेट भर रोटी पैदा कर सकें, वे शहरो की तरफ भागे हुए आएंगे और शहरों का जो मसला है वह हल नहीं होगा। लोग गांव को छोड़ छोड़ कर शहरों में आते चले जाएंगे और तब मुख्तलिफ किस्म की समस्यायें शहरों में पैदा होती रहेगी। इस वास्ते इस तरफ भी आपका खास ध्यान जाना चाहिये।

हरिजनों और दूसरे लोगों को जिन के पास हाउस साइट्स नही है, जमीन देने की बात आजकल हो रही है। कहीं दी जा रही है और कही नही भी दी जा रही है, कही काम तसल्लीबख्श तौर पर हो रहा है और कही तसल्लीबख्श तौर पर नहीं भी हो रहा है। यह तो सब हो रहा है। लेकिन शहर का जो हरिजन है उसके लिये अभी तक क्यों कोई पालिसी नही बनी है। मैं समझता हू कि शहरों में जो लोग रहते हैं इनको प्लाटंस देहातों में रहने वालो के मुकाबले में कही ज्यादा देने की जरूरत है। यह इसलिए कि कही कही जहा आपने कंसालिडेशन आफ होल्डिंग किया है वहां तो किसी को पांच बिसवा और किसी को कम या किसी को ज्यादा दे दिया है लेकिन शहरों में इस तरह के हालात पैदा नही हुए हैं कि उनको दी जाए। यह बात मेरी समझ में नही आती है कि इनकी तरफ आपका ध्यान क्यों नही जाता है।

पैदावार, बढ़ाने के लिए पानी और बिजली की बहुत जरूरत है। अगर ये आप किसान को दे दे तो पैदावार, कुदरती तौर पर बढ़ जाएगी यह ठीक है कि इस सबजेक्ट के जो माहिरीन है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके काम की वजह से भी हमारी पैदावार, बढ़ी है।

आपने सूबों के आपसी झगड़े भी सुलझाएं है। यह खुशी की बात है। रावी ब्यास का जो पानी का मसला था उसको भी आपने सुलझा दिया है। हम समझते हैं कि हम को ज्यादा मिलना चाहिये था। श्री मोर फूड कमेटी 1965 की यही सिफारिश थी, हरियाणा डिवेलेपमेंट कमेटी की रिपोर्ट भी थी, कामरेड राम किशन जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होने आन दी फ्लोर आफ दी हाउस कहा भी था कि बल्क आफ वाटर हरियाणा को जाएगा। हरियाणा का प्राबलैम यह है कि वहां रेत है और पंजाब का यह है कि वहां वाटर लागिंग है। वाटर एलाउंस हरियाणा का 1.9 है, पंजाब का 3.4 है......

श्री जगजीवन राम : फैसाला हो गया है, अब इसको क्यों छेड़ते हैं।

श्री तयब हुसैन : हम तो फैसला मानने वाले आदमी हैं। हम उसको मानते हैं।

जवाहरलाल कैनाल के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाये।

अब मैं अपनी कांस्टीटंयुएन्सी के दो तीन मसलों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरी कांस्टीटंयएन्सी एक तरफ राजस्थान से और दुसरी तरफ यू० पी० से घिरी हुई है। यू० पी० के साथ यह मसला है कि हमारे यहां जो आगरा कैनाल है, उस का पानी पलवल, बल्लबगढ़, और कुछ दूसरी तहसीलों के हिस्सो में आता है। उस नहर पर कंट्रोल यू० पी० गवर्नमेंट का है। इस का नतीजा यह है कि ठीक वक्त पर पानी नहीं मिलता है। इस के साथ जो ड्रेन्ज है, वे सिल्ट अप हो रही है. लेकिन यू० पी० गवर्नमेंन्ट इस तरफ तवज्जह नहीं देती है। इसी वजह से हमारे यहां वाटर रेट, आबियाना, हरियाणा के दूसरे एरियाज के मुकाबले में दुगना है। मैं कहना चाहता हू कि इस कैनाल का कन्ट्रोल हरियाणा को दिया जाये, ताकि हम हरियाणा के दूसरे हिस्सों के एटपार ट्रीट हो सकें।

फ्लड्ज में राजस्थान से पानी लंडोहा नाले से आता है। जब यह उजीना कामापहाड़ी ड्रेन से ही कर आता है, तो राजस्थान एथारिटीज रेगुलेटर को बन्द कर देते है। इसके नतीजे के तौर पर पिछली दफा जब पानी नहीं था, तो हमारे गांव डूब रहे थे। मैं मरकजी सरकार और डिपुटी मिनिस्टर, श्री के० एन० सिंह, का मशकूर हूं कि उन्होंने मदाखलत कर के हमारे नीमखेड़ा और डांडल गावों को बचा लिया, लेकिन वहां पर फसल नही हो पाई।

विकटी साइफन के बन्द होने से विकटी गांव डूब गया और उस के सारे घर गिर गये। यह साइफन जिस नहर पर बना हुआ है, वह राजस्थान को पानी ले जानें के लिए है। इस तरफ कोई तवज्जह नही हो पाई है।

इस लिए यह जरूरी है कि इस तरह के इन्टर स्टेट मामलों में हैडवर्क्स और रेगुलेटर्ज वगैरह पर सैंट्रल गवर्नमेंट का कन्ट्रोल होना चाहिए।

दरगहा शरीफ अजमेर एक इन्टरनेशनल रेप्यूट की दरगाह है। पिछले फ्लड् में उसके झालरे को नुक्सान पहुंचा था। सैंट्रल गवर्नमेंट में फ्लड्स कन्ट्रोल के लिए राजस्थान सरकार को ढाई करोड रुपया दिया है, लेकिन अभी तक उस की मरम्मत नहीं हुई है। अगर इस बरसात में उस की मरम्मत नही हुई तो दरगाह को नाकाबिले तलाफी नुक्सान पहुंचेगा।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें—श्री स्वामी ब्रहमानन्दजी।

श्री तैयब हुसैन : जितनी जल्दी हो सके शूगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जावे . . .

MR. CHAIRMAN: Now nothing will go on record.

شری طیب حسین (گوڑگاؤں) -

چیرمین صاحب - میں زراعت اور آبپاشی کی مانگوں کی حمایت کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور میں محترم بابوجی اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ فوڈ کے ساتھ ساتھ جو کھانے کا مسلئہ تھا اسکو چھوڑ کر جیسا کہ — شندے صاحب نے کہا ہے کہ کافی سالوں کے بعد آج فوڈ کا ایسا مسلئہ ہے جس کی طرف لوگوں نے بہت زیادہ دھیان نہ دے کر دوسری باتیں کہی ہیں — دوسرے سوالوں کی طرف توجہ ہو رہی ہے - پہلے تو اس فوڈ میں ہی الجھ جاتے تھے اور دوسرے مسلوں کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی تھی - اس کے لئے بابوجی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں -

آج ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ دراصل میں زراعت میں کافی ترقی کی ہے چاہے وہ گندم کا مسلئہ ہو، چاہے چاول کا مسلئہ ہو یا اور کوئی مسلئہ ہو - میرے پاس وقت بہت کم ہے اور گھنٹی کا بھی ڈر ہے، اس لئے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایگریکلچر کی جو اِنپٹس ہیں ، جیسے کہ ٹریکٹر ہیں، کھاد ہے یا دوسری چیزیں ہیں ، انکو سستے سے سستے داموں پر دیا جائے اور کسانوں کی جو فصل بکتی ہے اسکی قیمت کے ساتھ اسکو جوڑا جائے -

[شری طیب حسین]

یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ 80 فیصدی ہماری آبادی ایگریکلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے - تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ سارے ہندوستان کا جو 80 پرسینٹ حصہ ہے اسکو اگر صحیح ڈھنگ سے کور کر لیا جائے تو سارے مسلے حل ہو سکتے ہیں، ایگریکلچر کی طرف آزادی کے بعد ہماری زیادہ توجہ نہیں گئی اور میرے خیال میں اگر شروع سے ہی زیادہ توجہ ہوتی تو آج ہم ایکسپورٹ کرنے کی حالت میں ہوتے- خیر یہ خوشی کی بات ہے کہ جو ہمیں امپورٹ کے لئے پیسہ دینا پڑتا تھا آج وہ وہاں نہ جاکر ڈویلپمینٹ پر خرچ ہو سکے گا۔

ایک بات یہ کہ جو ریٹ آف انٹریسٹ ہے وہ انڈسٹری کا بہت کم ہے لیکن کاشتکاروں کو ٹریکٹر کے لئے یا ٹیوب ویل کے لئے جو قرض دیا جاتا ہے اسکا ریٹ آف انٹریسٹ بہت زیادہ ہے -

آپ کو یاد ہوگا کہ ایمرجینسی ایگریکلچر پرادکشن پروگرام آپنے بنایا تھا- اس پر پی اے سی نے کچھ سجھاو دیئے ہیں - میری پرارتھنا ہے کہ اس طرح سے جو بھی پروگرام آپ بنائیں انکو عمل میں لانے کے وقت آپ پی اے سی کے سجھاوؤں کو بھی دھیان میں رکھیں -

سیلنگ کی بات بھی یہاں آئی ہے - اُس سے کوئی بہت فائدہ نہیں ہوا ہے - اس واسطے نہیں ہوا ہے کہ اُن کے پاس جنکے پاس زمین ہے وسورسز ہیں اور کچھ حالت بھی اس طرح کے ہیں جو انکی مدد کرتے ہیں - اس واسطے اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو پایا ہے -

شری جگجیون رام - سرپلس کو تیدیبسٹ بنا دیئے ہیں -

شری طیب حسین - پیسے کے بل پر تیدیبسٹ بنا دیئے ہیں قانونی ڈھنگ سے یا وکیل لوگوں کی وجہ سے ایسا ممکن بنا دیئے ہیں-

گاؤں میں دو تہائی آبادی ایسی ہے جو لینڈ لیس اور ہریجنوں کی ہے جو مارجنل یا سمال فارمرز ہیں یا وہ ہیں جو اپنا گزارہ نہیں کر سکتے ہیں - اُنکے لئے ضروری ہے کہ فشریز سے اینیمل ہسبینڈری سے یا چھوٹی چھوٹی صنعتوں سے ہم انکے واسطے روزگار پیدا کرنے کی کوشش کریں - اسکے بنا یہ مسلہ حل نہیں ہوگا -

جب ہم شہروں کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی بہت سی سمسائیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں - جب تک گاؤں کے لوگوں کو جو بے گھر ہیں ؟ بے سہارا ہیں، کوئی کام نہیں

شہروں میں اسطرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ انکو دی جائے- یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ انکی طرف آپکا دھیان کیوں نہیں جاتا ہے -

پیداوار بڑھانے کے لئے پانی اور بجلی کی بہت ضرورت ہے - اگر یہ آپ کسان کو دے دیں تو پیداوار قدرتی طور پر بڑھ جائیگی - یہ ٹھیک ہے کہ اس سنچویشن کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے - انکے کام کی وجہ سے بھی ہماری پیداوار بڑھی ہے -

اپنے صوبوں کے آپسی جھگڑے بھی سلجھائے ہیں - یہ خوشی کی بات ہے - راوی بیاس کا جو پانی کا مسئلہ تھا اسکو بھی اپنے سلجھا دیا ہے - ہم سمجھتے ہیں کہ ہمکو زیادہ ملنا چاہیئے تھا - گرو مور فوڈ کمیٹی 1965 کی یہ سفارش تھی ، ہریانہ ڈولپمنٹ کمیٹی کی رپورٹ بھی تھی، کامریڈ رام کشن جب چیف منسٹر تھے تب انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا بھی تھا کہ بلک آف واٹر ہریانا کو جائیگا - ہریانہ کا پروبلم یہ ہے کہ وہاں ریت ہے اور پنجاب کا یہ ہے کہ وہاں واٹرلاگنگ ہے - واٹر الاؤنس ہریانہ کا ۱۰۹ ہے پنجاب کا ۳۰۴ ہے -

دیا جائے گا اور ایسا کام نہیں دیا جائے گا کہ وہ پھٹ بھو روٹی پیدا کر سکیں ، وہ شہروں کی طرف بھاگے ہوئے آئینگے اور شہروں کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا - لوگ گاؤں کو چھوڑ چھوڑ کر شہروں میں آتے چلے جائیں گے اور تب مختلف قسم کی سمسیائیں شہروں میں پیدا ہوتی رہیں گی - اس واسطے اس طرف بھی خاص دھیان جانا چاہیئے -

ہریجن اور دوسرے لوگوں کو جنکے پاس ہاؤس سائٹس نہیں ہیں زمین دینے کی بات آجکل ہو رہی ہے - کہیں دی جا رہی ہے اور کہیں نہیں بھی دی جا رہی ہے ، کہیں کام تسلی بخش طور پر ہو رہا ہے اور کہیں تسلی بخش طور پر نہیں بھی ہو رہا ہے - یہ تو سب ہو رہا ہے - لیکن شہر کا جو ہریجن ہے اسکے لئے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنی ہے - میں سمجھتا ہوں کہ شہروں میں جو یہ لوگ رہتے ہیں انکو پلاٹس دیہاتوں میں رہنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ دینے کی ضرورت ہے - یہ اس لئے کہ کہیں کہیں جہاں آپ نے کنسولیڈیشن آف ہولڈنگز کیا ہے وہاں تو کسی کو پانچ بسوا اور کسی کو کم یا کسی کو زیادہ دے دیا ہے لیکن

شری جگجیون رام - فیصلہ ہو گیا ہے؟ اب اسکو کیوں چھیڑتے ہیں؟

شری طیب حسین - ہم تو فیصلہ ماننے والے آدمی ہیں - ہم اسکو مانتے ہیں - جواہر لال کینال کے لئے زیادہ سے زیادہ پیسہ دیا جائے -

اب میں اپنی کانسٹی ٹیوینسی کے دو تین مسئلوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں - میری کانسٹی ٹیوینسی ایک طرف راجستھان سے اور دوسری طرف یو پی سے گھری ہوئی ہے - یو پی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو آگرہ کینال ہے اسکا پانی پلول، بلبھ گڈھ اور کچھ دوسری تحصیلوں کے حصوں میں جاتا ہے - اس نہر پر کنٹرول یو پی گورنمنٹ کا ہے - اسکا نتیجہ یہ ہے کہ ٹھیک وقت پر پانی نہیں ملتا ہے - اس کے ساتھ جو ٹریٹیز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں - لیکن یو پی گورنمنٹ اس طرف توجہ نہیں دیتی ہے - اس وجہ سے ہمارے یہاں واٹر ریسد آبیانہ ہریانہ کے دوسرے ایریاز کے مقابلے میں رکتا ہے - میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کینال کا کنٹرول ہریانہ کو دیا جائے تاکہ ہم ہریانہ کے دوسرے حصوں کے ایٹ پار ٹریٹ ہو سکیں -

الگر میں راجستھان سے پانی لنک ہوا نالے سے آتا ہے - جب وہ اتنا پہاڑی قوتوں سے ہو کر آتا ہے تو راجستھان اتھارٹیز ریگولیٹر کو بند کر دیتی ہیں اس کے نتیجے کے طور پر پچھلی دفعہ جب پانی نہیں تھا تو ہمارے گاؤں ڈوب رہے تھے - میں صوبائی سرکار اور ٹیکنیکل اسٹاف مسٹر شری کے ایس ملک کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مداخلت کر کے ہمارے نوح کھیڑا اور ڈانکل گاؤں کو بچا لیا لیکن وہاں پر فصل نہیں ہو پاتی -

وگٹی سائفن کے بند ہونے سے وگٹی گاؤں ڈوب گیا اور اسکے سارے گھر گر گئے - یہ سائفن جس نہر پر بنا ہوا ہے وہ راجستھان کو پانی لے جانے کے لئے ہے - اس طرف کوئی توجہ نہیں ہو پاتی ہے

اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے انٹرسٹیٹ معاملوں میں ہیڈورکس اور ریگولیٹرز وغیرہ پر سینٹرل گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیئے -

درگاہ شریف اجمیر ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ کی درگاہ ہے - پچھلے فلڈ میں اسکے جھالر کو نقصان پہنچا تھا - سینٹرل گورنمنٹ نے فلڈز کنٹرول کے لئے راجستھان کو ڈھائی کروڑ روپیہ دیا ہے - لیکن ابھی تک اسکی مرمت نہیں ہوئی ہے - اگر اس برسات میں اسکی مرمت

نہیں ہوئی ہے تو دیگا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا -

سبھاپتی مہودیہ - آپ مانیہ سدسیہ ختم کریں -

شری سوامی برہمانند جی ۔

شری طیب حسین - جلدی ہو سکے شوگر انڈسٹری کو نیشنلائز کیا جائے -

MR. CHAIRMAN: [Now nothing will gon on record.]

श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी (हमीरपुर) : सभापति महोदय, बाबूजी जिस विभाग में भी गये हैं, वहां उन्हें सफलता मिली है। यह उन के गुणों के कारण हैं।

ऐसा नहीं है कि हमारे कृषि विभाग द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। जैसे नौकर द्वारा खेती होती है, वैसे ही प्रबन्ध किया गया है। अभी तक हमारी सरकार ने नौकरों के बल पर काम किया हैं। उस ने खुद अपने शरीर से कुछ नहीं किया है।

एक बार मैं पंजाब में लाला लाजपत राय से मिला, जब कि वह अमरीका से आये थे। उन्होंने कहा कि हमारा देश गुलाम है, इस-लिए मैं अमरीका गया कि कुछ सीख आऊं। अमरीका में उन्होंने वहा के राष्ट्रपति से मिलने के लिए टाइम लिया। राष्ट्रपति ने उन्हें 5 बजे बुलाया। वह साढ़े चार बजे पहुंच गये। राष्ट्रपति एक घंटा फार्म में काम करते थे, मिट्टी खोदते थे, कृषि का काम करते थे। उन्होंने कहा कि मैं ने आप को 5 बजे बंगले पर बुलाया है।

कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग नौकरों से भी काम लेते और खुद काम करते, राष्ट्रपति से ले कर छोटा अधिकारी, सेनापति से ले कर सिपाही तक, हर एक आदमी अगर एक घंटा कृषि का काम करता, तो हमें अमरीका से गल्ला मंगाने की आवश्यकता न पड़ती। दिल्ली के बंगलों में गल्ला और फल नहीं पैदा किये जाते हैं। उन में फूलों की भरमार हैं। माला लिये खड़े हैं। उन फूलों की मालाओं में बेकार इस्तेमाल किया गया है जिसमें माला बनाने पहनाने में भी समय की बरबादी होती है। मैं जब कर्नाटक गया तो वहां पर फूलों की दूकानों का मेला लगा हुआ था। क्या मालाओं से पेट भरेगा। इसको कानूनन रोक देना चाहिए। फूलों की जगह पर पपीता बोया जाए फल बोए जायें। दिल्ली में अंग्रेजों के लगाए हुए वृक्ष खड़े हैं जो बिना फलों के हैं तथा छाया भी अच्छी नहीं है। अगर 25 साल पहले इनको खुदवा दिया जाता और इसकी जगह आम और जामुन लगा दिया जाता और हर बंगले में चाहे मुख्य मंत्री हो, प्रधान मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, फावड़ा ले कर अमरीका के प्रजीडेंट की तरह एक घंटा काम करते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। आज हम मछली को देखते हैं, जहां तक कि जिन बैलों को जोतते हैं और गाए बैल जो बूढ़े हो जाते हैं दूध देना बन्द कर देती हैं उनको भी मार कर खा जाते हैं, तब भी हमारा पेट नहीं भरता है तो हम और क्या कहें। यह नौकरों के द्वारा काम हुआ है। अगर हर आदमी एक घंटा खेती में काम करे तो हमें यह कमी नहीं हो सकती।

तम्बाकू में पच्चीस पानी लगता है। उसको बन्द किया जाए। उसकी जगह चार फसलें अन्न की हो सकती हैं। गल्ला ही गल्ला हमारे यहां पैदा हो सकता है। तरक्की की है। बाबू जी तो जहां भी जाते हैं तरक्की होती है बंगला देश में पाकिस्तान को उन्होंने उड़ा दिया। यह उनके गुणों की बात है। हमारे यहां कुछ विकास हुआ है। नलकूप कुछ लगाए गए हैं। लेकिन जहां के लिए कोई सिफारिशी नहीं है वहां वैसे ही खाली पड़ा हैं। सिंचाई में आप सुधार लाएं यह सम्भव है। नौकरों के

[श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी]

ऊपर भाप देखभाल कर सकते हैं । गरीब आदमी जिसे अच्छा भोजन नहीं मिलता साबुन नहीं लगाता वही खेती करता है । मेरा कृषि कालेज है । कई स्कूल हैं । नौकर काम करते हैं । मास्टर लोग दो दो हजार तनख्वाह लेते हैं । और एक घंटा पढ़ा कर चले जाते हैं । कागजों में गन्ना और गेहू बोते हैं । खेती में हमारी जो उन्नति हुई है यह नौकरों के द्वारा जैसी होती है वैसे हुई है । वे जितना करते हैं उतनी की है । खुद की तरह नही ।

बाबू जी की मांगों का मैं हार्दिक समर्थन करता हू और घंटी के पहले ही समाप्त करता हू ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : सभापति महोदय, नलकूप एक ऐसे विषय है है जो केवल राज्य सरकारो के अधिकार क्षेत्र में आता हैं । इनकी आवश्यकता देश भर में हैं । नहर का पानी या और सिचाई के साधन तो केन्द्रीय सरकार के हैं । मैं अपील करूगा कि राजकीय नलकूपों के निर्माण को जिम्मेदारी केन्द्र की भी राज्यों के साथ साथ होनी चाहिए ।

कृषि मंत्री जी को मै बधाई देता हूं खास तौर से श्री केदार नाथ सिंह को जिन के प्रयत्न से 1976 में हमारे सिरसिया क्षेत्र में हैवी रिग्ज भेजी गई और वहां प्रयोगात्मक नलकूप बनाए गए ।

राप्ती नदी का जिक्र कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में नहीं आया है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की यह एक शोक नदी है । इसकी बाढ़ से तमाम इलाके डूब जाते हैं । जलकुंडी डैम की योजना शायद स्वीकृत हो चुकी है । मैं चाहता हू कि उसको शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाए ताकि यू० पी० के पूर्वी जिलों के बाढ़ समस्या का समाधान हो सके ।

जो चेतावनी केन्द्र बाढ़ के हैं वे भीतर की भूमि में हैं लेकिन अधिकतर नदिया नेपाल से आती हैं और नेपाल की तराई के जंगल नेपाल की सरकार द्वारा काट दिए गए हैं । भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार के स्तर पर इस बात का समझौता होना चाहिए कि उनके यहा के जगल और हमारे जहा के जगल जिन के बीच में हो करके हिमालय पर्वत पर जो बारिश होती है उसका पानी नालों और नदियों से हो कर गुजरता है उन जंगलों को काटा न जाए बल्कि वहा और जगल लगाए जाए ताकि जमीन का कटाव न हो और बाढ़ का प्रकोप कुछ शान्त हो सके । वहा पर नेपाल राज्य में वार्निंग सेंटर भी नेपाल सरकार से मिल कर कायम होने चाहिएं । क्यों कि एकदम वहा से बाढ़ चलती है तो यहा भारत की भूमि पर पानी नीचे उतर आता है । यहा जो हमारे केन्द्र काम करते हैं उनको यहा का तो पता चलता है लेकिन नेपाल का पता नही चलता है ।

18 hrs.

चौथी चीज यह है जो स्माल फार्मर्स डवलपमेंट एजन्सी की योजना चलाई गई है वह योजना बहुत अच्छी है । इसमे प्राविधान रखा गया हैं कि जो स्थानीय संस्थायें हैं, जो इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई है उन को केन्द्रीय प्रतिनिधि की हैसियत इन्वाइटी बुलाना चाहिये । मेरे जिले में यह

योजना लागू की गई है, लेकिन केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई इन्वाइटी नहीं गया है। यह चीज, जैसे और ढीले-ढाले काम प्रदेश सरकारों के चलते हैं, उसी स्तर पर चलती है। इसको विशेष महत्व देना चाहिये और हर महीने इस की मीटिंग होनी चाहिये। जिले में या प्रदेश में जो सब से बहतरीन कार्यकर्ता हो, चाहे ग्रामसेवक हो, पंचायत मंत्री हो, या ब्लाक अधिकारी हों, जो सब से अच्छे हों, उन को इस काम में लगाना चाहिये और प्राथमिकता के आधार पर, सामरिक-स्तर पर इस स्कीम को लागू करना चाहिये।

एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वैसे बतलाया गया है कि देश में अन्न की कोई कमी नहीं है, अन्य के भण्डार बहुत हो गये है, लेकिन अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमरीका से एक समझौता हुआ है, उस के दूसरे डिप्लोमेटिक कारण हो सकते है, लेकिन आकड़े जो दिये गये है कि हमारे यहां देश में अन्न की प्रचुरता है, आधिक्य है, अन्न के दाम सस्ते हो गये हैं, इन सब बातो के होने हुए भी अभी अमरीका से समझौता किया गया है, जिस के अन्तर्गत चार लाख टन गेहूं जिस का मूल्य 8300 मिलियन डालर है, उस का आयात किया जायगा। 1975 में भी अमरीका से 46.31 लाख टन गेहूं मंगाया गया।

दूसरी चीज यह है कि जो दाम गिर गये हैं उन को बढ़ाने के लिये, कास्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिये, जो सिंगल स्टेट जोन्स बना दिये गये हैं, यानी गेहूं एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं भेजा जा सकता है, यह प्रतिबन्ध अगर हटा दिया जाय तो न केवल काश्तकारों को ज्यादा दाम मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं, उन को भी राहत मिलेगी। यदि देश भर का एक बाजार बना दिया जाय, तो यह दिक्कत नहीं होगी।

जहां तक खाद का सवाल है—सभी ने कहा है कि खाद बहुत महंगी है। हमारे मंत्री जी ने इस विषय में बहुत कुछ काम किया है। मैं भी अन्य साथियों के साथ उन की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाना चाहता हूं कि खाद के दाम घटे हैं जिससे काश्तकारों को फायदा हो।

फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया के जो कर्मचारी हैं, वे बिलकुल नवाब है। जिन को श्वेत हाथी कहा जाता है, वे बिलकुल वैसे ही हैं। न तो वे समय पर खरीदना शुरू करते हैं और न समय पर दाम देते है, इन की साठ गाठ और साजिश स्थानीय बनियो के साथ होती हैं। इस लिये आप इन के ऊपर कड़ी निगरानी रखने का प्रयास करें। वरना आप की यह स्कीम, जिस तरह से आप इस को कारगर बनाना चाहते हैं, कारगर नहीं हो पायगी।

18.04 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
(SIXTY-FIRST REPORT)

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Sir, I beg to present the Sixty-first Report of the Business Advisory Committee.

18.04-1/2 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—*contd*

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION —*Contd.*

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI (Lakhimpur): Mr. Chairman Sir, while standing to support the Demands of the Ministry of Agriculture & Irrigation, I express my deep sense of appreciation to the Ministry in general and Babuji in particular, who is presiding over this Ministry, for the marvellous job the Ministry has done which is felt in every day life by every section of the people of the country The price line of the foodgrains is steady and there is no scarcity of foodgrains or anything that is consumed by the people

It is proposed that agriculture will be put in the concurrent list but before that the Central Government has to take more responsibility in respect of production of food, procurement and distribution which constitutes the first item of the 20-Point Programme announced by our beloved Prime Minister So far as production is concerned it has gone ahead and procurement, the Minister of State, Shri Shinde, has said, has exceeded the target But I would like to point out that there is no adequate storage facility for want of which thousands of tonnes of paddy m my State is kept in the open under rain and sun This is a national wastage and this should be avoided

Apart from the commercial aspect, for maintaining an equilibrium m nature and from the ecological point of view, there should be good quantity of forests Therefore, I would urge upon the Ministry to take up a project for development of forests Our ancient civilisation had two major items, one was forests and the other was river For the Vedic age to the Puranic age forests did play a very major role in our civilisation. We have come across the discourse that took place in Naimisaranya, the record of which is the Mahabharata.

The country is divided into two parts, Dev Matrika and Nadi Matrika. The region which depends on monsoon is Dev Matrika and the other part is Nadi Matrika where irrigation is adopted. It is the tradition that the river acts as the mother and special attention should be paid for utilisation of the river water.

Assam is a flood-prone area The mightest river of the world, Brahmaputra, runs through the narrow strip of the valley of Assam It is an international river There should be a national effort, national attempt to control that international river This is a national problem and it should not be left to the slender resources of the State We have learnt two years back that a Bill has been drafted and it was to be introduced in Parliament for taking over the Brahamputra Flood Control Commission by the Centre but what has happened to that Bill we do not know Whatever may be the reason, I urge upon the Minister to allocate sufficient funds for controlling that river There are 37 major tributaries to that river and innumerable small tributaries If the major tributaries are controlled the Brahamputra will be controlled

There is a dispute regarding sharing of water in Farakka Barrage with Bangladesh If the Brahmputra river is controlled, Bangladesh will be benefited and I hope they will not dispute

The other day, when I had put a question regarding some major dams in the Sabansiri and other tributaries, the reply was that it was under investigation I have seen the preliminary report It will cost a colossal amount *viz.*, Rs. 1.000 crores. But when it is constructed it will have a greater potentiality than Bhakra-Nangal I would, therefore, urge upon the Minister to consider this matter

seriously and arrange for resources—if they are not adequate within the country, from the World Bank etc.

The Brahamaputra is threatening the existence of Dibrugarh, which is adjacent to my constituency. If the Brahamaputra is not controlled there, the medical college and the major part of the town will come under erosion very soon. Therefore, the town and the other parts of that State are to be protected from erosion.

I come to the next point, *viz.* irrigation. Assam is very poor in irrigation. We have learnt that there are more than 20 lakhs of pump sets all over the country; but in Assam, the number is less than a thousand; perhaps it is 500 or so; but I do not have the statistics with me at the moment. So far as irrigated land is concerned, this also is very poor. Therefore, it should be the policy of the Ministry to pay special attention to those States—not only to Assam but to other States also—where irrigation facilities are poor. It will not only help the growth of foodgrains and other commodities, but it will remove regional imbalances as well—which is complained about very much by the people. If special attention is paid in respect of agriculture in such State, regional imbalances will be removed.

Lastly, I come to the generation of power—though it does not come under this Ministry, this Ministry can help in generating power in many ways by controlling the rivers and by making irrigation available to the people and thereby help in the improvement of the eastern region. Most of the small rivers do flow from the Arunachal area. It is a Union Territory. It is under the direct control of the Central Government. De-forestation is going on there on a large scale. I would urge upon the Minister to visit that area when he finds time. If there is deforestation, nothing can be done in Assam, or in the area below it. Therefore, a big scheme for afforestation should be taken up there. Otherwise, de-forestation and denudation of the land will automatically wash away the valley in Assam, which is very narrow, i.e., only 50 to 75 miles. I would urge upon the Minister to take special care in this respect. With these words, I support the Demands for Grants. I also thank you, Sir, for giving me this opportunity, just when the House was about to rise.

MR. CHAIRMAN: The Minister, Shri Jagjivan Ram.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI JAGJIVAN RAM): I am grateful to the Members of the House for the rich tributes that they have paid to the Department of Agriculture and Irrigation.

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी कल अपना भाषण जारी रखेंगे। अब सदन की बैठक कल 6 मई दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

18.14 hrs.

The Lok Sabha then adjuorned till Eleven of the Clock on Thursday, May 6, 1976/Vaisakha 16, 1898 (Saka).

GMGIPND—M—657 LS—978